प्रश्न बैंक-सह-उत्तर पुस्तक

Question Bank–Cum–Answer Book

2023

Class-12

राजनीति विज्ञान
(POLITICAL SCIENCE)

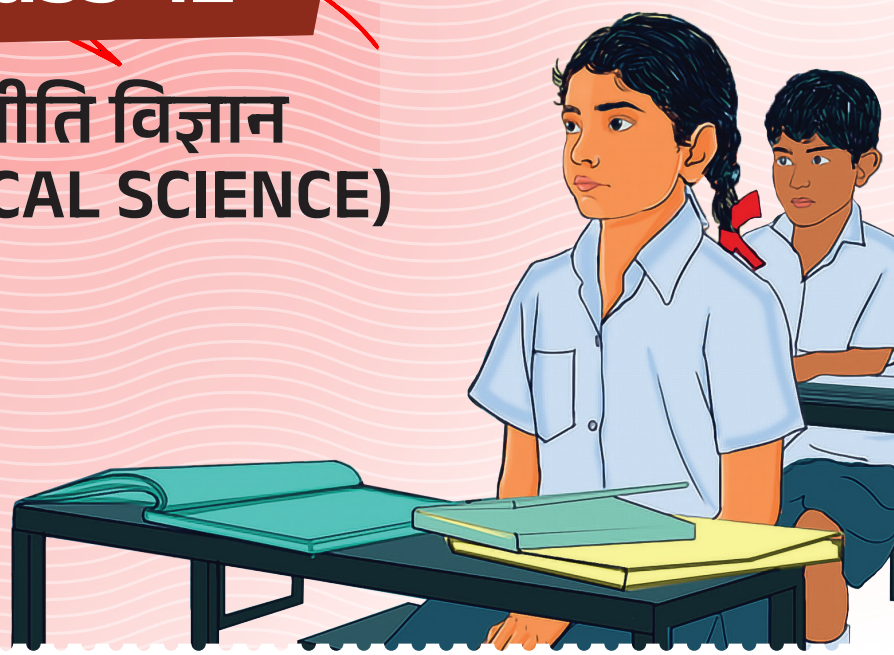

झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, राँची
Jharkhand Council of Educational Research and Training, Ranchi

Jharkhandlab.com

प्रश्न बैंक–सह–उत्तर पुस्तक
Question Bank-Cum-Answer Book

Class - 12

राजनीति विज्ञान
Political Science

- ⇨ समाकालीन विश्व राजनीति
- ⇨ स्वतंत्र भारत में राजनीति

Jharkhandlab.com

झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, राँची
नवोन्मेष शोध नेतृत्व
JCERT

2023

झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, राँची
Jharkhand Council of Educational Research and Training, Ranchi

प्रथम संस्करण : माह अगस्त 2023, श्रावण विक्रम संवत् 2080

© झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, राँची, झारखंड

jharkhandlab.com

सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस पुस्तक के किसी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी, छायाप्रतिलिपि अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है।

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण या जिल्द के साथ अथवा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।

- **क्रय–विक्रय दण्डनीय अपराध**

झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, राँची, झारखंड द्वारा प्रकाशित

प्राक्कथन

बच्चों के लिए निर्धारित अधिगम प्रतिफल प्राप्त करने का मार्ग सरल एवं सुगम होना आवश्यक है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, राँची, झारखंड के द्वारा कक्षा 12 के सभी विषयों के लिए प्रश्न बैंक–सह–उत्तर पुस्तक का निर्माण बच्चों के अधिगम कौशल को सुगमतापूर्वक विकसित करने एवं झारखंड अधिविद्य परिषद् द्वारा आयोजित वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए उन्हें तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है। इस प्रश्न बैंक–सह–उत्तर पुस्तक में सरल भाषा एवं रुचिकर ढंग से विषय–वस्तु को स्पष्ट करते हुए प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। इस प्रश्न बैंक–सह–उत्तर पुस्तक के माध्यम से बच्चों में न केवल ज्ञानजन्य प्रतिभा का विकास होगा बल्कि आज के इस प्रतियोगिता के दौर में भी वे अनुकूल सफलता पाएंगे। हमारे प्रयत्न की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि विद्यालय के शिक्षकवृन्द बच्चों की कल्पनाओं के साथ कितना जुड़ पाते हैं और विभिन्न प्रकार के प्रश्नोत्तरों को सीखने–सिखाने के दौरान अपने अनुभवों के साथ–साथ बच्चों के विचारों के साथ कैसे सामंजस्य बनाते हैं।

इस प्रश्न बैंक–सह–उत्तर पुस्तक में झारखंड अधिविद्य परिषद् द्वारा आयोजित वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के विविध प्रकारों यथा– बहुवैकल्पिक, अतिलघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आदि के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में प्रश्नोत्तर समाहित किए गए हैं ताकि इसके अध्ययन से छात्रों में ना केवल विषय–वस्तु की समझ विकसित हो बल्कि उन्हें सीखने के प्रतिफल की भी प्राप्ति हो, साथ ही वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए उनकी अच्छी तैयारी हो सके और वे परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करते हुए सफलता प्राप्त कर सकें।

अंत में मैं इन पुस्तकों के लेखकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

शुभकामनाओं के साथ।

के० रवि कुमार भा.प्र.से.
सचिव
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड

Jharkhandlab.com

भूमिका

प्रिय शिक्षक एवं विद्यार्थी,

जोहार !

हमें कक्षा 12 के विभिन्न विषयों के प्रश्न बैंक–सह–उत्तर पुस्तक से आपका परिचय कराने में प्रसन्नता हो रही है। इस प्रश्न बैंक–सह–उत्तर पुस्तक में झारखण्ड शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्, राँची द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तकों के विषयवार एवं अध्यायवार अधिगम बिन्दुओं को समायोजित करते हुए झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा आयोजित वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा में पूछे जानेवाले प्रश्नों के विविध प्रकारों के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में प्रश्नों का समावेश किया गया है। इस विषय आधारित प्रश्न बैंक–सह–उत्तर पुस्तक के निर्माण का उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक रुचिकर, सरल एवं प्रभावशाली बनाना तथा विद्यार्थियों को वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारियों में सहयोग प्रदान करना है, जिससे सकारात्मक रूप से छात्रों को सीखने के प्रतिफल प्राप्त हों और वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा में वे बेहतर प्रदर्शन कर सकें। राज्य के विभिन्न जिलों से चयनित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा इस प्रश्न बैंक–सह–उत्तर पुस्तक का निर्माण किया गया है।

इस प्रश्न बैंक–सह–उत्तर पुस्तक की प्रमुख विशेषताएँ यह है कि इनमें प्रश्नों के उत्तर को सरल भाषा में प्रस्तुत करते हुए वैचारिक समझ (Conceptual Understanding) विकसित करने पर जोर दिया गया है। साथ ही इन पुस्तकों में झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा आयोजित वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा – 2023 के प्रश्नोत्तर को भी समाहित किया गया है। इन पुस्तकों के माध्यम से न केवल विद्यार्थियों की प्रतिभा में निखार आएगा बल्कि वर्तमान समय के प्रतियोगिताओं के इस दौर में वे अनुकूल एवं अपेक्षित सफलता प्राप्त करने में भी सक्षम हो सकेंगे। आशा है कि यह प्रश्न बैंक–सह–उत्तर पुस्तक आपको पसंद आएगी एवं आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

शुभकामनाओं के साथ।

किरण कुमारी पासी भा.प्र.से.
निदेशक
झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्
राँची, झारखण्ड

jharkhandlab.com

पाठकों से अनुरोध

इस प्रश्न बैंक–सह–उत्तर पुस्तक के निर्माण में काफी सावधानियाँ बरती गई है। इसके बावजूद यदि किसी प्रकार की अशुद्धियाँ मिले या कोई सुझाव हो तो इस email ID :- jcertquestionbank@gmail.com पर सूचित करें, ताकि अगले मुद्रण में इसे शुद्ध रूप से प्रस्तुत किया जा सके।

Jharkhandlab.com

प्रश्न बैंक–सह–उत्तर पुस्तक निर्माण समिति

मुख्य संरक्षक

श्री के० रवि कुमार (भा.प्र.से.)
सचिव
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड

संरक्षक

श्रीमती किरण कुमारी पासी (भा.प्र.से.)
निदेशक
झारखण्ड शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्, राँची

अवधारणा एवं मार्गदर्शन

श्री मुकुंद दास उपनिदेशक (प्र.) झारखण्ड शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्, राँची	**श्री बाँके बिहारी सिंह** सहायक निदेशक (अ.) झारखण्ड शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्, राँची	**श्री मसुदी टुडू** सहायक निदेशक (अ.) झारखण्ड शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्, राँची

समन्वय एवं निर्देशन

डॉ0 नीलम रानी
संकाय सदस्य, जे.सी.ई.आर.टी., राँची
(टी.जी.टी., सामाजिक विज्ञान, राजकीयकृत उत्क्रमित उच्च विद्यालय पैतानो, जलडेगा, सिमडेगा)

सहयोग

श्री मणिलाल साव
संकाय सदस्य, जे.सी.ई.आर.टी., राँची
(पी.जी.टी. जीव विज्ञान, के. एन. +2 उच्च विद्यालय हरनाद, कसमार, बोकारो)

Jharkhandlab.com

प्रश्न बैंक निर्माण कार्य समिति

अनुप कुमार
PGT
S.S. +2 उच्च विद्यालय बेड़ो, राँची

सरोज सेठ
PGT
राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय राहे, राँची

श्रीपति मुण्डा
PGT
उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय परासी तमाड़, राँची

आनंद प्रसाद
PGT
S.S. +2 उच्च विद्यालय, सिल्ली, राँची

डॉ. नीलम रानी
TGT
राजकीयकृत उत्क्रमित उच्च विद्यालय पैतानो, जलडेगा, सिमडेगा

विनोद कुमार महतो
PGT
प्रोजक्ट +2 उच्च विद्यालय, सदमा, ओरमांझी, राँची

लालू तिर्की
PGT
शंकरी +2 उच्च विद्यालय ईटकी, राँची

कंचन टोप्पो
PGT
रमेश सिंह मुण्डा स्मारक +2 उच्च विद्यालय बुंडू, राँची

मोनालिसा बारला
PGT
उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय उचरी, मांडर, राँची

Jharkhandlab.com

Jharkhandlab.com

विषय सूची

भाग – 1 (समकालीन विश्व राजनीति)		पृष्ठ सं.
अध्याय – 01	शीत युद्ध का दौर	1–4
अध्याय – 02	दो ध्रुवीयता का अंत	5–7
अध्याय – 03	समकालीन विश्व में अमरीकी वर्चस्व	8–11
अध्याय – 04	सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र	12–16
अध्याय – 05	समकालीन दक्षिण एशिया	17–21
अध्याय – 06	अंतर्राष्ट्रीय संगठन	22–25
अध्याय – 07	समकालीन विश्व में सुरक्षा	26–30
अध्याय – 08	पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन	31–35
अध्याय – 09	वैश्वीकरण	36–40
भाग – 2 (स्वतंत्र भारत में राजनीति)		
अध्याय – 01	राष्ट्र–निर्माण की चुनौतियाँ	43–46
अध्याय – 02	एक दल के प्रभुत्व का दौर	47–49
अध्याय – 03	नियोजित विकास की राजनीति	50–52
अध्याय – 04	भारत के विदेश संबंध	53–56
अध्याय – 05	कांग्रेस प्रणाली : चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना	57–60
अध्याय – 06	लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट	61–63
अध्याय – 07	जन आंदोलनों का उदय	64–67
अध्याय – 08	क्षेत्रीय आकांक्षाएँ	68–72
अध्याय – 09	भारतीय राजनीति : नए बदलाव	73–75
	Solved Paper of JAC Annual Intermediate Examination - 2023	76–81

Jharkhandlab.com

Jharkhandlab.com

PART - I

jharkhandlab.com

Jharkhandlab.com

अध्याय - 1 शीत युद्ध का दौर

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है?
a. 1945 के बाद से b. 1947 के बाद से
c. 1950 के बाद से d. 1960 के बाद से

2. कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला?
a. जर्मनी -फ्रांस के बीच
b. भारत -चीन के बीच
c. अमेरिका -सोवियत संघ के बीच
d. अमेरिका- ब्रिटेन के बीच

3. निम्नलिखित में कौन शीतयुद्ध के प्रमुख कारण रहे हैं?
a. अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच सैद्धांतिक मतभेद
b. विजित प्रदेशों पर आधिपत्य संबंधी विवाद
c. युद्ध कालीन निर्णयों का अतिक्रमण
d. उपर्युक्त सभी

4. नाटो की स्थापना कब हुई?
a. अप्रैल1949 b. अगस्त 1947
c. अप्रैल 1945 d. जून 1975

5. नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था?
a. शीत युद्ध के प्रभाव को कम करना
b. अमेरिका में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना
c. पश्चिमी यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना
d. दुनिया को युद्ध की विभीषिका से बचाना।

6. नाटो की स्थापना के समय कितने सदस्य देश शामिल थे?
a. 15 b. 12
c. 10 d. 15

7. क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे?
a. जॉन एफ कैनेडी b. बैंस जॉनसन
c. ट्रूमैन d. जिम्मी कार्टर

8. शीत युद्ध के समय शक्ति के कितने केंद्र थे?
a. 5 b. 3
c. 2 d. 6

9. सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई?
a. 1917 b. 1922
c. 1925 d. 1916

10. 1917में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की थी?
a. मार्क्स b. एंजिल्स
c. लेनिन d. स्टालिन

11. क्यूबा के मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे?
a. जॉन एफ कैनेडी
b. स्टालिन
c. निकिता ख्रुश्चेव
d. उपर्युक्त में से कोई नहीं

12. नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है?
a. उत्तरी अमेरिका संधि संगठन
b. उत्तर अटलांटिक संधि संगठन
c. उत्तरी अमेरिका आतंक निरोधक संगठन
d. इनमें से कोई नहीं

13. किस के प्रयास से गुटनिरपेक्षता की नीति अस्तित्व में आई?
a. जवाहरलाल नेहरू
b. गमाल अब्दुल नसीर
c. मार्शल जोसेफ ब्रॉन्ज टीटो
d. उपर्युक्त सभी

14. मार्शल योजना क्या थी?
a. यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिकी सहायता
b. सोवियत संघ पर आर्थिक प्रतिबंध
c. अमेरिका में आतंकवादियों के समाप्ति के लिए योजना
d साम्यवादी शासन के विस्तार के लिए योजना

15. शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे माना जाता है?
a. ट्रूमैन सिद्धांत b. मार्शल योजना
c. क्यूबा मिसाइल संकट d. इनमें से कोई नहीं

16. प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे?
a. जवाहरलाल नेहरु b. सुकर्णो
c. अब्दुल नासिर d. मार्शल टीटो

17. किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया?
a. ब्रिटेन b. फ्रांस
c. पश्चिमी जर्मनी d. इटली

18. गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था?
a. महात्मा गांधी b. डॉ.बी आर अंबेडकर
c. जवाहरलाल नेहरू d. सरदार पटेल

19. गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था?
a. 1987 b. 1984
c. 1969 d. 1970

Jharkhandlab.com

20. पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है?

a. विश्वयुद्ध से b. शीत युद्ध से
c. तनाव शैथिल्य से d. उत्तर शीत युद्ध दौर से

बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर

1.a 2.c 3.d 4.a 5.c. 6.b 7.a 8.c9.a 10.c 11.c 12.b 13.d 14.a 15.c 16.d 17.b 18.c 19.c 20.b

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

1. पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कब और कहां हुआ था?

उत्तर- पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में युगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुआ था।

2. गुटनिरपेक्ष आंदोलन के किन्ही दो संस्थापक सदस्य देशों के नाम लिखिए?

उत्तर- गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य देशों के नाम-
भारत- पं. जवाहरलाल नेहरू

युगोस्लाविया- जोसिप ब्रोज टीटो

3. गुटनिरपेक्षता का क्या अर्थ है?

उत्तर- गुटनिरपेक्षता का अर्थ है किसी भी गुट में शामिल ना होना और अपनी स्वतंत्र नीतियों का अनुसरण करना।

4. शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है?

उत्तर- संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच वह तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति जो द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद 1945 ई. से 1990 ई. तक जारी रही, शीत युद्ध कहा जाता है।

5. शीत युद्ध के लिए कौन दो महाशक्तिशाली देश उत्तरदाई थे?

उत्तर शीतयुद्ध के लिए दो महाशक्तिशाली देश उत्तरदाई थे - सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका।

6. शीत युद्ध काल में पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन के क्या-क्या नाम थे?

उत्तर- शीत युद्ध काल में पश्चिमी गठबंधन को नाटो और पूर्वी गठबंधन को वारसा संधि के नाम से जाना जाता था।

7. द्वितीय विश्वयुद्ध के समय हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम को क्या नाम दिया गया था?

उत्तर- द्वितीय विश्वयुद्ध के समय हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम को लिटिल बॉय और फैटमैन नाम दिया गया था।

8. मार्शल योजना क्या था?

उत्तर 1947 ई. में अमेरिकी विदेश सचिव मार्शल ने यूरोप को अरबों डॉलर सहायता देने की योजना बनाई जिससे कि युद्ध के प्रभाव की क्षतिपूर्ति हो। उनका विचार था कि ऐसी सहायता नहीं करने से वैसे सभी देश जो आर्थिक रूप से एकदम कमजोर हो गए हैं सोवियत संघ में मिल जाएंगे, इसे ही मार्शल योजना कहा गया।

8. पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन सा देश का रहा था?

उत्तर पूंजीवादी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था।

9. ट्रूमैन सिद्धांत क्या था?

उत्तर सोवियत संघ के साम्यवादी विस्तार को रोकने के लिए राष्ट्रपति ट्रूमैन ने घोषणा किया कि अमेरिका स्वतंत्र देशों की रक्षा करेगा इसे ही ट्रूमैन सिद्धांत कहा गया।

10. मोलटोव योजना का क्या उद्देश्य था?

उत्तर अमेरिकी विदेश सचिव मार्शल की योजना के उत्तर में सोवियत विदेश मंत्री मोलटोव ने योजना बनाई मोलटोव योजना का उद्देश्य था पूर्वी यूरोप के देशों को वित्तीय सहायता देकर उनका आर्थिक सुधार किया जाए।

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. क्यूबा मिसाइल संकट का वर्णन करें?

उत्तर क्यूबा अमेरिका की तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है, क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से थाऔर सोवियत संघ के नेता उसे वित्तीय सहायता दिया करते थे। सोवियत संघ के नेता निकिता ख्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। 1962 ई. में ख्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिका को लगी और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने ख्रुश्चेव को मिसाइलें हटाने को कहा, ख्रुश्चेव ने कहा की यदि राष्ट्रपति केनेडी विश्वास दिलाय कि अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण नहीं करेगा और घेराबंदी हटा लेगा तो क्यूबा में मिसाइलें तैनात नहीं की जाएगी। केनेडी ने ख्रुश्चेव के प्रस्ताव को मान कर घेरा हटा लिया और ख्रुश्चेव ने भी मिसाइलें वापस भिजवा दिया इसे ही क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है।

2. नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या है?

उत्तर गुटनिरपेक्ष में शामिल अधिकांश देश आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे और इन्हें अल्पविकसित देश का दर्जा प्राप्त था इन देशों के सामने मुख्य चुनौती आर्थिक विकास कर अपनी जनता को गरीबी से उबारने की थी। ये देश बिना आर्थिक विकास की वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते थे, इसी भावना से प्रेरित होकर नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का जन्म हुआ।

3. उत्तर दक्षिण संवाद का क्या प्रमुख उद्देश्य था?

उत्तर 1980 ई. के दशक में विकसित देशों द्वारा किए जा रहे विरोध के चलते नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के प्रयास में कमियां आई। विश्व के अविकसित व विकासशील देशों ने अपने आर्थिक विकास के लिए विकसित देशोंसे सहयोग की कामना की। धनी या विकसित देश विश्व के उत्तरी भाग में हैं और निर्धन या अविकसित देश दक्षिणी भाग में । अतः इससे उत्तर दक्षिण संवाद का नाम दिया गया।

Jharkhandlab.com

4. कोरिया संकट का वर्णन करें?

उत्तर द्वितीय विश्वयुद्ध में जापान एवं कोरिया ने सोवियत संघ के समक्ष और दक्षिण कोरिया ने अमेरिका के समक्ष आत्मसमर्पण किया, उत्तर कोरिया में साम्यवादी और दक्षिण कोरिया में पूंजीवादी शासन की स्थापना हुई। 1950 में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया ,कोरियाई युद्ध वास्तव में दोनों कोरिया का युद्ध ना होकर पश्चिमी गुट और साम्यवादी गुट के बीच एक अप्रत्यक्ष सशस्त्र युद्ध था।अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में सोवियत रूस के बहिष्कार का लाभ उठाते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ से उत्तर कोरिया को आक्रमणकारी घोषित करवाया और विश्व शांति की रक्षा की आड़ में उसके विरुद्ध सैनिक कार्यवाही का प्रस्ताव पास करा दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यवाही जो वास्तव में अमेरिकी जनरल मैक आर्थर के नेतृत्व में किया गया आक्रमण था, यह युद्ध गुटनिरपेक्ष देशों की मध्यस्थता से 1953 ई. में समाप्त हुआ।

5. महाशक्तियां छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों की थी?

उत्तर छोटे देश कुछ महत्वपूर्ण कारणों से महाशक्तियों के लिए महत्वपूर्ण थे जैसे-

1. खनिज तेल जैसे प्राकृतिक संसाधनों की प्राप्ति
2. भूभाग की जरूरत
3. एक दूसरे के जासूसी हेतु सैनिक ठिकानों के लिए
4. गठबंधन में शामिल छोटे-छोटे देश के सैन्य खर्च में वाहन करने में सहायक हो सकते थे
5. छोटे राज्यों को महाशक्तिशाली देश अपने हथियार बेच सकती थीं।
6. विचारधारा की लड़ाई में वैचारिक सहयोग की प्राप्ति।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. तनाव-शैथिल्य क्या है?तनाव-शैथिल्य की स्थिति के उदय के क्या कारण थे?

उत्तर तनाव-शैथिल्य का शाब्दिक अर्थ है तनाव में शिथिलता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में सोवियत संघ एवं अमेरिकी तनाव में कमी और उनमें दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई मित्रता, सहयोग और शांतिपूर्ण सह- अस्तित्व की भावना को ही तनाव-शैथिल्य कहा गया है।

तनाव शैथिल्य की स्थिति के उदय होने के निम्नलिखित कारण थे-

1. <u>परमाणु यंत्रों के प्रयोग का भय-</u> संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने भयानक परमाणु शस्त्र बना लिए थे अब यह भय पैदा हुआ कि यदि ऐसे शश्त्रों का प्रयोग हुआ तो दोनों का विनाश सुनिश्चित है,अतः उन्होंने निशस्त्रीकरण की दिशा में अग्रसर होना उपयुक्त समझा।
2. <u>विचारधारा का अंत-</u> दोनों महाशक्तियां अपनी विचारधारा पर डटी हुईं थीं,लेकिन 1970 के बाद परिस्थितियां बदल गई ,उदारवाद एवं समाजवाद के बीच मिलन स्थापित होने लगा।
3. <u>गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सफलता-</u>1961 से गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू हो गया धीरे-धीरे गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या बढ़ती चली गई, सम्मेलनों में महाशक्तियों के सैनिक गुटों की कड़ी निंदा की गई । महाशक्तियों ने समझ लिया कि सैनिक गठबंधन की रणनीति विफल हो रही है।
4. <u>चीन की खुले द्वार की नीति-</u> अमेरिका ने चीन से संबंध स्थापित करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दृश्य ही बदल दिया अब सोवियत संघ ने भी चीन के साथ संबंध सुधारने का मार्ग अपनाया।

इन सभी कारणों से ही तनाव-शैथिल्य की स्थिति उत्पन्न हुई।

2. शीत युद्ध काल में भारत की भूमिका का वर्णन करें?

उत्तर शीत युद्ध काल में भारत की निम्नलिखित भूमिका थी -

1. भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध काल में अपनी भूमिका निभाई।
2. भारत ने स्वयं को दोनों महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ की गुटबंदी से अलग रखा।
3. भारत शीतयुद्ध कालीन प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप करने के पक्ष में था।
4. भारत ने दोनों महाशक्तियों के सैनिक गुटों तथा शस्त्रों की होड़ की कड़ी निंदा की और निःशस्त्रीकरण पर बल दिया।
5. भारत ने दोनों गुटों के बीच मौजूद मतभेदों को कम करने की कोशिश की और मतभेदों को पूर्णव्यापी युद्ध का रूप लेने से रोका।
6. भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अन्य सदस्यों को भी ऐसे कामों में लगाए रखा।
7. शीत युद्ध के दौरान भारत ने लगातार उन क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सक्रिय बनाए रखने की कोशिश की जो अमेरिका या सोवियत संघ के गुट से जुड़े नहीं थे।

भारत ने सदैव शीतयुद्ध की निंदा की तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा एवं सहयोग का समर्थन किया, जिनसे भारत को विश्व में अपनी महत्वपूर्ण पहचान बनाने का अवसर मिला।

3. शीत युद्ध के उदय के कारणों का वर्णन करें?

उत्तर शीत युद्ध के उदय के निम्नलिखित कारण थे-

1. याल्टा समझौता का निरादर

फरवरी 1945 के याल्टा सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल तथा सोवियत प्रधानमंत्री स्टालिन ने विचार-विमर्श के बाद कुछ समझौते किए परंतु सोवियत संघ ने इन समझौतों का निरादर किया।

2. ईरान में रूसी सेनाओं का जमवाड़ा

समय-समय पर सोवियत संघ ने ईरान की प्रभुता एवं उसकी प्रादेशिक अखंडता का आदर करने का वचन दिया था युद्ध के दिनों में ब्रिटेन की सहमति से उतरी ईरान में सोवियत सेनाओं का कब्जा था लेकिन 1942 की त्रिपक्षीय संधि के द्वारा जर्मनी के समर्थन के 6 महीनों के भीतर इन सेनाओं को वहां से हटा दिया गया युद्ध के बाद अमेरिकी एवं ब्रिटिश सेना उत्तरी

Jharkhandlab.com

ईरान से चली गई लेकिन सोवियत सेनाएं नहीं हटी। काफी विलंब के साथ सेनाओं ने उत्तरी ईरान छोड़ा।

3. **बर्लिन की नाकेबंदी**

पॉट्सडैम सम्मेलन में यह तय किया गया था कि जर्मनी के लोगों के मानव अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा फिर भी बहुत से जर्मन लोगों को पकड़कर सोवियत संघ लाया गया या शिविरों में बंद कर दिया गया। कुछ समय बाद सोवियत संघ ने अपने कब्जा ग्रस्त क्षेत्रों में नई मुद्रा चालू की तथा बर्लिन की नाकेबंदी कर दी।

4 **अमेरिका विरोधी प्रचार**

सोवियत संघ के समाचार पत्रों ने खुलकर अमेरिका की निंदा का अभियान शुरू कर दिया ऐसा करने का उद्देश्य यह था कि दुनिया के अन्य देशों की दृष्टि में अमेरिका को कलंकित करना,1947 में साम्यवादी सूचना विभाग की स्थापना हुई इसमें फ्रांस एवं इटली सहित अन्य देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों को शामिल किया गया।

5. **समाजवादी व्यवस्था का विरोध**

जब 1917 में सोवियत संघ में समाजवादी राज्य बना तो पूंजीवादी देशों में 1918 -19 में उसकी घेराबंदी की तथा उसे मिटाने का प्रयास किया जो लेनिन की कुशल कूटनीति के कारण सफल ना हो सका, 1933 तक अमेरिका ने सोवियत संघ को कूटनीतिक मान्यता नहीं दी तथा 1939 में पूंजीवादी शक्तियों ने उसे राष्ट्र संघ से बाहर कर दिया।

6. **पूर्वी यूरोप में सोवियत विस्तार वाद का विरोध**

स्टालिन के अनुसार याल्टा सम्मेलन में यह तय किया गया था कि सोवियत संघ अपने पश्चिमी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाएं तथा वहां महत्वपूर्ण शासन की स्थापना करें इसलिए पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, हंगरी एवं रोमानिया में स्टालिन ने जन लोकतंत्र की स्थापना की ।

सन 1946 के बाद दोनों महा शक्तियों के बीच दरारेंऔर बढ़ते चली गई। और शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई।

Jharkhandlab.com

अध्याय - 2 दो धुर्वीयता का अंत

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. बर्लिन की दीवार कब बनी थी?
a. 1961 b. 1965
c. 1978 d. 1967

2. सोवियत संघ कितने गणराज्य को मिलाकर बना था?
a. 18 b. 15
c. 19 d. 12

3. सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था?
a. कांग्रेस पार्टी b. कम्युनिस्ट पार्टी
c. रूसी पार्टी\ d. इनमें से कोई नहीं

4. सोवियत संघ में शामिल देश को क्या कहा गया है?
a. पहली दुनिया b. दूसरी दुनिया
c. तीसरी दुनिया d. इनमें से कोई नहीं

5. सोवियत संघ का विघटन कब हुआ?
a. 1991 b. 1985
c. 1987 d. 1998

6. सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता किसे दे दी गई?
a. पोलैंड b. यूक्रेन
c. बेलारूस d. रूस

7. बर्लिन की दीवार को किसने गिराया था?
a. देशद्रोहियों ने b. आम जनता ने
c. सरकार ने d. पुलिस ने

8. 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा?
a. जर्मनी b. इटली
c. अमेरिका d. चीन

9. सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन गलत है?
a. सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी।
b. उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व था।
c. जनता की आर्थिक आजादी थी।
d. अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था।

10. सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था?
a. ब्रजनेव b. येल्तसिन
c. स्टालिन d. गोर्बाच्योव

11. ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्पति थे?
a. अमेरिका b. इंग्लैंड
c. सोवियत संघ d. चीन

12. स्टालिन संविधान कब लागू हुआ?
a. 1973 b. 1936
c. 1977 d. 1935

13. ग्लावनोस्त व पेरेस्तोइका के मंत्र किसने दिए?
a. लेनिन b. स्टालिन
c. गोर्बाचोव d. ब्रजनेव

14. दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं?
a. पूंजीवादी देश b. विकासशील देश
c. गुटनिरपेक्ष देश d. साम्यवादी देश

15. पूर्व-साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई है?
a. समाजवादी b. मार्क्सवादी
c. उदारवादी d. फासीवाद

16. ख्रुश्चेव ने 1955 में किसे भारत का अभिन्न अंग बताया?
a. केरल b. गोवा
c. कश्मीर d. इनमें से कोई नहीं

बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर

1.b, 2.b, 3.b, 4.b, 5.a, 6.d, 7.b, 8.c, 9.c, 10.b, 11.c, 12.b, 13.c, 14.d, 15.c, 16.b

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

1. सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ?
उत्तर- सोवियत गुट से सबसे पहले युगोस्लाविया अलग हुआ।

2. तजाकिस्तान में कितने सालों से गृह युद्ध जारी था। यह कब समाप्त हुआ?
उत्तर- तजाकिस्तान में 10 सालों से गृह युद्ध जारी था यह 2001 में समाप्त हुआ।

3. सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था?
उत्तर- सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव था।

4. बर्लिन की दीवार को किसने गिराया था?
उत्तर- बर्लिन की दीवार को पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने 1989ई. में गिराया था।

5. बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक था?
उत्तर- बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक था। 1961 में बनी यह दीवार पश्चिम बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी।

Jharkhandlab.com

6. सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा किन गणराज्यों ने की थी?

उत्तर- 1991 में येल्तसिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के तीन बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की थी।

7. ग्लासनास्ते का अर्थ क्या है?

उत्तर- ग्लासनास्ते का अर्थ है खुलापन लाना। इस प्रक्रिया के तहत सोवियत संघ की व्यवस्था में खुलेपन की नीति अपनाई गई और शेष विश्व से उसके संपर्क को मजबूत करने का प्रयास किया गया।

8. भारत रूस मैत्री की किसी एक विशेषता का उल्लेख करें?

उत्तर- भारत रूस मैत्री की एक प्रमुख विशेषता है कि दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीमा पार आतंकवाद से निपटने की दिशा में प्रयासरत हैं।

9. दूसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं?

उत्तर- दूसरे विश्वयुद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए सोवियत सेना ने इन्हें फासीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया था इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था।

10. प्रथम एवं द्वितीय विश्वयुद्ध की अवधि बताइए?

उत्तर - प्रथम विश्वयुद्ध की अवधि 1914 से 1918 ई. तक तथा द्वितीय विश्वयुद्ध की अवधि है 1939से 1945 ई. तक।

11. सोवियत संघ के इतिहास की सबसे बड़ी 'गैराज सेल' क्या थी?

उत्तर- सोवियत संघ की आदेशित अर्थव्यवस्था खराब हुई तब उसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मांगी। उसे इस शर्त पर ऐसी मदद दी गई कि वह उदारीकरण की नीति अपनाए। इसी को आघात द्वारा उपचार (शॉक थेरेपी) कहा गया। साथ ही बड़े बड़े सरकारी उधम निजी लोगों को सस्ते दर पर बेच दिए गए इसी को गैराज सेल कहा गया।

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. एकध्रुववीयता,द्विध्रुवीयताऔर बहुध्रुवीयता से आप क्या समझते हैं? उल्लेख कीजिए।

उत्तर- एकध्रुववीयता, द्विध्रुवीयता और बहुध्रुवीयता विश्व राजनीति की विशेषताओं को अभिव्यक्त करने वाले शब्द हैं। द्विध्रुवीयता विश्व राजनीति में दो महाशक्तियों के अस्तित्व की परिचायक है जैसा कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद और 1991 में सोवियत संघ के पतन के पूर्व की विश्व राजनीति में देखा गया इस समय सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की वैश्विक भूमिका ने द्विध्रुवीयता की स्थिति उत्पन्न की है।1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति रह गया इस स्थिति को एकध्रुववीयता की स्थिति कहा गया। वर्तमान समय में चीन, रूस,भारत जैसे देश तेज गति से विकास कर रहें हैं तथा विश्वव्यापी मंदी के कारण अमेरिका की स्थिति कमजोर हुई है इससे भविष्य में बहुध्रुवीयता विश्व की संभावना बनती जा रही है।

2. शॉक थेरेपी क्या थी? इसके दो परिणामों को लिखिए।

उत्तर- साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी, समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का जो विशेष मॉडल अपनाया गया इसे ही शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है।

शॉक थेरेपी के परिणाम

1. शॉक थेरेपी के बड़े ही गंभीर परिणाम निकले इसके कारण रूस का पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा गया।
2. सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो चुकी थी और लोगों की खाद्य सुरक्षा मौजूद नहीं रह गई थी।

3. प्रथम खाड़ी युद्ध पर एक टिप्पणी लिखें?

उत्तर- प्रथम खाड़ी युद्ध- अगस्त 1990 में इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा कर लेने के बाद अमेरिका के अगुवाई में संयुक्त राष्ट्र संघ की सहमति से इराक के विरुद्ध जो सैन्य अभियान चलाया गया उसे ही प्रथम खाड़ी युद्ध के रूप में जानते हैं इस युद्ध में अमेरिका की भूमिका ने यह साफ कर दिया कि विश्व के अन्य देश सैन्य क्षमता के मामले में अमेरिका से बहुत पीछे हैं, इस युद्ध से अमेरिका को बहुत लाभ हुआ।

4. किन कारणों ने गोर्बाचोव को सोवियत संघ में सुधार करने के लिए बाध्य किया?

उत्तर- जब मार्च 1985 में गोर्बाचोव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने उस समय देश की आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं थी सारे अर्थव्यवस्था राज्य के हाथों में थी तथा देश में लोगों की स्वतंत्रता को कुचल दिया गया था, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति ने लोगों की स्वतंत्रता को बहाल करने तथा निजी अर्थव्यवस्था को पुनःस्थापित करने का रास्ता अपनाया।गोर्बाचोव ने आर्थिक और राजनीतिक सुधार के लिए ग्लास्नोस्ट तथा पेरेस्त्रोइका नीति अपनाई। ग्लास्नोस्ट का अर्थ था समाज को खोलो और पेरेस्त्रोइका का अर्थ था आर्थिक नवनिर्माण। गोर्बाचोव की दृष्टि में गिरते हुए समाजवादी राज्य को बचाने का यही रास्ता था।

5. नई विश्व व्यवस्था क्या है? वर्णन कीजिए।

उत्तर- सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा और और धीरे-धीरे विश्व व्यवस्था पर उसका वर्चस्व स्थापित हो गया 1991के सोवियत पतन के बाद बढ़ता हुआ अमेरिकी वर्चस्व जिस व्यवस्था की पुष्टि करता है उसे ही नई विश्व व्यवस्था के रूप में जाना गया।

6. ऑपरेशन डेजर्ट स्टर्म क्या था?

उत्तर- अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर उस पर कब्जा जमा लिया। जब इराक को समझाने बुझाने के तमाम राजनायिक प्रयास सफल नहीं हुए तो अंततः संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग के निर्णय को स्वीकार किया 34 देशों की मिली-जुली और 6लाख60हजार सैनिकों की भारी-भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला और उसे परास्त कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सैन्य अभियान को 'ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म' कहा जाता है, जो अमेरिकी सैन्य अभियान था।

Jharkhandjcert.com

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. सोवियत संघ के पतन के कारणों का वर्णन करें?

उत्तर- सोवियत संघ के पतन के निम्नलिखित कारण थे

1. <u>स्टालिनवादी संगठन की विफलता-</u> लेनिन नवंबर 1917 में रूस में समाजवादी राज्य स्थापित किया किंतु जनवरी 1924 में उसकी मृत्यु के बाद स्टालिन ने उसे अत्यंत सबल बना दिया। 1953 में स्टालिन की मृत्यु के बाद खुश्चेव ने सोवियत संघ की सत्ता हथिया ली और डिस्टालिनीकरण की नीति अपनाई। स्टालिन के अनुचित कार्यों की खुलकर निंदा की गई तथा उसके विश्वासपात्र अनुयायियों को पद से हटा दिया गया।
2. <u>आर्थिक असंतोष-</u> स्टालिन ने समाजवादी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए आदेशित अर्थव्यवस्था स्थापित की निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण तथा कृषि का सामूहिकरण किया गया सारे अर्थव्यवस्था राज्य के हाथों में आ गई।योजना आयोग द्वारा निर्मित पंचवर्षीय योजनाओं को बलपूर्वक लागू किया गया देश के संसाधनों का बहुत अधिक अंश सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च किया गया जिस कारण उत्पादन दर घटती चली गई जिससे देश में उपभोक्ता संबंधी वस्तुओं की कमी हो गई।
3. <u>सेवकतंत्रीय भ्रष्टाचार-</u> सत्ताधारी साम्यवादी दल तथा सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच सांठगांठ ने राजनीतिक एवं आर्थिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया देश में न स्वतंत्र प्रेस थी, न स्वतंत्र न्यायपालिका जो ऐसे भ्रष्टाचार को नियंत्रित कर सकती थी।सत्ताधारी दल के नेतागण एवं प्रभावशाली सरकारी अधिकारी घूसखोरी में लग गए,जिससे उनका जनसाधारण से संपर्क टूट गया, शासन के प्रति लोगों की आस्था कम होती चली गई।
4. <u>योग्य नेतृत्व का अभाव-</u> किसी व्यवस्था को स्थापित करने एवं उसकी कुशल एवं सफल संचालन के लिए योग्य नेतृत्व की आवश्यकता होती है। लेनिन स्टालिन, खुश्चेव एवं बर्जनेव कुशल नेता थे जिन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना करके अपनी व्यवस्था को बचाए रखा किंतु एंड्रोपोव एवं चर्नेनकोव अत्यंत अयोग्य एवं अकुशल नेता सिद्ध हुए। कम्युनिस्ट पार्टी में ऐसे योग्य सदस्य नहीं थे जो नेतृत्व का भार संभाल सकते थे।
5. <u>नस्लीय राष्ट्रवाद का उदय-</u> सोवियत संघ को बहुराष्ट्रीय राज्य कहते थे क्योंकि यहां अनेक राष्ट्रीय गांव के लोग रहते थे जैसे रूसी, बेलारूसी, जॉर्जियंस। मार्क्सवादी नेताओं ने सैद्धांतिक रूप में राष्ट्रीय आत्म निर्णय के सूत्र को मान्यता देते हुए हर राष्ट्रीयता को स्वतंत्र होने का अधिकार दिया और बड़े गर्व से यह आग्रह किया कि केवल सोवियत संघ में विभिन्न राष्ट्रीयता को यह अधिकार दिया गया है ।लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के जाल ने सभी राष्ट्रीयता को ऐसे फांस लिया कि कोई राष्ट्रीयता स्वतंत्र होने का साहस तक नहीं कर सकती थी।
6. <u>मानव पूंजी की हानि-</u> मानव राज्य की पूंजी की तरह है लेकिन सोवियत संघ में उसके व्यक्तित्व को कुचल दिया गया, उसे मशीन का पुर्जा बनाकर रखा गया। स्वतंत्र चिंतन एवं उपक्रम को वर्जित कर दिया गया। कोई बड़ा लेखक, साहित्यकार, चित्रकार, कवि य कलाकारपैदा नहीं हो सकता था, उन्हीं वैज्ञानिकों को महत्व मिला जिन्होंने नरसंहार के लिए विनाशकारी यंत्र बनाएं। रचनात्मक शक्तियों का अभाव हो गया जो किसी देश में नागरिक समाज की रचना करते हैं जिन के बीच विचारों का आदान-प्रदान होता है।
7. <u>पाश्चात्य उदारवाद का प्रभाव-</u> स्टालिन ने ऐसा कठोर नियंत्रण स्थापित किया था कि देश में बाहरी समाचारों का प्रवेश या देश के समाचारों का बाहर जाना असंभव था। इसी कठोर नियंत्रण को ब्रिटिश नेता चर्चिल ने लोह आवरण कहा था। लेकिन स्टालिन की मृत्यु के बाद यह स्थिति शिथिल होने लगी सोवियत संघ के लोग अन्य देशों की यात्रा करने लगे तथा अन्य देशों के लोगों ने इस लाल साम्राज्य को भीतर से देखना शुरू किया धीरे-धीरे उदारवाद की लहर का प्रवाह हुआ। सोवियत संघ के लिए साम्यवाद के प्रसार की बजाय आर्थिक विकास अधिक महत्वपूर्ण होता गया।

2. भारत जैसे देश के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए?

उत्तर- शीत युद्ध की समाप्ति एवं सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व एकध्रुवीय हो गया। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उदित हुआ भारत को अपने राष्ट्रीय हित में नीतियां बदलने पड़े भारत की विदेश नीति में अमेरिका समर्थक रणनीतियां शामिल की गई।लेकिन फिर भी रूस भारत का एक महत्वपूर्ण मित्र बना हुआ है मौजूदा अंतरराष्ट्रीय परिवेश में सैन्य हितों के बजाय आर्थिक नीति की घोषणा की जिसमें उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया।अब भारत विश्व आर्थिक शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है।

भारत ने साम्यवादी चीन के साथ भी बेहतर आर्थिक संबंध स्थापित किए हैं। भारत अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर बहुध्रुवीय विश्व की कामना करता है इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु भारत ने यूरोपीय संघ, चीन अमेरिका, जापान, रूस, आसियान के सदस्य देशों, अफ्रीकी देशों अपने पड़ोसियों सभी के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने की कोशिश की है, एकध्रुवीय जगत में ऐसा करना जरूरी है।

3. किन बातों के कारण गोर्बाचोव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए?

उत्तर- सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश अंश परमाणु हथियारों और सैन्य साजो समान पर व्यय किया उसने अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के देशों के विकास पर भी खर्च किए ताकि विस्तृत नियंत्रण में बने रहें इससे सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बना। इसी के साथ सोवियत संघ के आम नागरिकों की जानकारी बढ़ी कि वे पश्चिमी देशों की तुलना में पिछड़ चुके हैं इससे लोगों की मनोदशा प्रभावित हुई।

सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 1917 से 1991 तक शासन किया और यह पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी, गतिरुदध् प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार अपनी गलतियों को सुधारने में व्यवस्था की अक्षमता, शासन में ज्यादा खुलापन लाने के प्रति अनिच्छा, और देश की विशालता के बावजूद सत्ता का केंद्रीयकृत होना। इन सभी तत्वों के कारण आम जनता अलग-थलग हो गई।इससे भी बुरी बात यह थी कि पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों से ज्यादा विशेषाधिकार मिले हुए थे इससे लोगों में सत्ता के प्रति मोहभंग हो गया।

सोवियत गणराज्य में नस्लीयता और संप्रभुता के भाव के उभार ने भी मिखाइल गोर्बाचोव को सुधार के लिए बाध्य किया।

अध्याय - 3 समकालीन विश्व में अमरीकी वर्चस्व

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया?

A. रिचर्ड निक्सन B. जिम्मी कार्टर
C. जॉर्ज बुश D. रोनाल्ड रीगन

2. 1996 में तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया जिसे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया?

A. पाकिस्तान B. इराक
C. ईरान D. अफगानिस्तान

3. भारत के किस प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ असैनिक कार्यों के हितों परमाणु समझौते का सबल समर्थन किया?

A. मनमोहन सिंह
B. अटल बिहारी वाजपेयी
C. इंदिरा गांधी
D. राजीव गांधी

4. किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया?

A. चीन B. अमेरिका
C. फ्रांस D. रूस

5. किस देश के साथ संबंध स्थापित करके अमेरिका ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाया है जिससे एक - ध्रुवीयाता की प्रवृत्ति उभरी?

A. जापान B. ब्रिटेन
C. भारत D. चीन

6. नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई?

A. 1948 B. 1947
C. 1949 D. 1950

7. अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ?

A. 11 सितंबर2001 B. 11 नवंबर 2003
C. 21 जुलाई 2005 D. 30 अक्टूबर 2008

8. संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं?

A. 49 B. 50
C. 51 D. 52

9. विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है?

A. जापान B. चीन
C. भारत D. संयुक्त राज्य अमेरिका

10. संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है?

A. जॉर्ज बुश B. बिल क्लिंटन
C. डोनाल्ड ट्रंप D. जोसेफ रोबिनेट बाइडेन

11. परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया?

A. ईरान B. उत्तरी कोरिया
C. भारत D. चीन

12. द्वितीय विश्वयुद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था?

A. नागासाकी B. इतोशिमा
C. हाशिया D. मिजामिसोमा

13. निम्न में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई?

A. भारत B. ब्रिटेन
C. पाकिस्तान D. चीन

14. भारत ने पोखरण में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया।

A. 1995 B. 1997
C. 1998 D. 1996

15. एकध्रुवीयता का क्या अर्थ है?

A. अमेरिका के हाथों शांति B. एक दुनिया
C. रोमनो के हाथों शांति D. इनमें से कोई नहीं

बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर

1(C), 2(D), 3(A), 4(B), 5(D), 6(C), 7(A), 8(B), 9(D), 10(D), 11(C), 12(A), 13(D), 14(C), 15(A)।

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

1. "अमेरिका के हाथों शांति" का क्या अर्थ है?

उत्तर- दूसरे विश्वयुद्ध के बाद अमेरिका ने बहुत से देशों में अपना वर्चस्व स्थापित किया और अपने विरोधियों को कुचल कर वहां शांति स्थापित की इसे ही अमेरिका के हाथों शांति कहां जाता है।

2. "इतिहास के अंत"का क्या अर्थ है?

उत्तर- फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार इतिहास के अंत का अर्थ एक ऐसे राष्ट्र से लिया गया है जिसमें विधि का शासन चलता था। विश्व के सभी राष्ट्र स्वतंत्रता व न्याय को बनाए रखने में अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं।

3. G-7 क्या है?

उत्तर- G-7 प्रमुख औद्योगिक देशों का एक समूह है जिसका गठन 1975 में हुआ था इस संगठन में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन ,इटली, जर्मनी, फ्रांस व जापान शामिल है

JharkhandJac.com

4. इराक ने कुवैत पर कब आक्रमण किया और उस समय इराक का राष्ट्रपति कौन था?

उत्तर- इराक ने कुवैत पर 1990 में आक्रमण किया और उस समय इराक का राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन था।

5. अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया?

उत्तर- अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन एंडयूरिंग फ्रीडम नामक अभियान चलाया।

6. प्रथम खाड़ी युद्ध को "वीडियो गेम वार" क्यों कहा गया है?

उत्तर- प्रथम खाड़ी युद्ध को टेलीविजन पर व्यापक रूप से दिखाया गया और पूरे विश्व के लोगों ने इराकी सेना को टेलीविजन पर युद्ध में बूरी तरह हारते हुए देखा, इसलिए प्रथम खाड़ी युद्ध को "वीडियो गेम वार"कहा गया ।

7. नाटो का गठन कब हुआ और उसके सदस्य को किस नाम से जाना जाता है

उत्तर- नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 ई. को हुआ और इसके सदस्य को शांति के सहभागी के नाम से जाना जाता है

8. प्रथम खाड़ी युद्ध को और किन किन नामों से जाना जाता है?

उत्तर- प्रथम खाड़ी युद्ध को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है-

1. स्मार्ट बमों का प्रयोग
2. कंप्यूटर युद्ध
3. वीडियो गेम वार

9. नाटो (NATO) का पूरा नाम क्या है।

उत्तर- नाटो का पूरा नाम- उत्तरी अटलांटिक संधि

संगठन या North Atlantic Treaty Organizationl है ।

10. नाटो का मुख्यालय कहां है?

उत्तर- नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स (बेल्जियम) में है

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. ऑपरेशन एंडयूरिंग फ्रीडम क्या था?

उत्तर- 11 सितंबर 2001 को इस्लामी कट्टरवादयों ने अमेरिका के दो नगरों न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तथा वर्जीनिया में पेंटागन पर हमला किया। इस हमले के पीछे अलकायदा के नेता ओसामा बिन लादेन का हाथ था और उस समय अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था जहां ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था। अक्टूबर 2001 में अमेरिका व उसके कुछ सहयोगी देशों ने अफगानिस्तान पर आक्रमण करके वहां तालिबान का शासन मिटा दिया। और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने आरोप लगाया कि ऐसी आतंकवादी संगठनों को इराक की गुप्त सहायता मिल रही है इसलिए मार्च 2003 में इराक पर आक्रमण करके सद्दाम हुसैन के अधिनायकवाद शासन को मिटा दिया गया । इराक के खिलाफ इतनी बड़ी कार्यवाही सुरक्षा परिषद के समर्थन पर की गई थी।

2. अमेरिकी वर्चस्व की सैन्य शक्ति के रूप में व्याख्या कीजिए।

उत्तर- वर्तमान में अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है जिनके पास विशाल थल सेना ,जल सेना ,वायु सेना है। अपनी सैनिक क्षमता के बल पर वह कहीं भी बड़ी आसानी से हमला कर सकता है अमेरिका के पास हर प्रकार के परमाणु ,आधुनिक व परंपरागत हथियार है इस कारण उसने विश्व के कई देशों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है अमेरिका का रक्षा बजट विश्व के अन्य शक्तिशाली कही जाने वाले 12 देशों के संयुक्त रक्षा बजट से कहीं अधिक होता है अमेरिका अपनी सैनिक शक्ति पर अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक खर्च करता है वह अपनी बजट का एक बड़ा भाग सैन्य अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास पर खर्च करता है। और यह कहना उचित होगा कि अमेरिका की सैन्य क्षमता अतुलनीय है क्योंकि अफगानिस्तान और इराक पर आक्रमण करके वहां अपने विरोधियों का शासन मिटाने में अमेरिका ने अपने अद्वितीय सैन्य शक्ति का परिचय दिया।

3. ऑपरेशन "डेजर्टस्टाम "क्या था?

उत्तर- 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला किया और बड़ी तेजी से उस पर कब्जा जमा लिया। जब सभी राजनायिक इराक को समझाने में विफल रही तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दी तब 34 देशों की मिली-जुली और 6,60,000 सैनिकों की सेना ने इराक पर आक्रमण कर इराक की सेना को हरा दिया। 1991 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस सैन्य अभियान को खाड़ी युद्ध या "ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म" कहा।

4. 1991 में अमेरिका ने इराक पर आक्रमण क्यों किया?

उत्तर- अमेरिकी आक्रमण के मूल 1991 के खाड़ी युद्ध में रखे गए थे। उस समय इराक पर यह वैध आरोप लगाया गया था कि उसने कुवैत को हड़पकर उसे अपना 19वां प्रान्त बनाया, अतः कुवैत को मुक्त किया जाये। इस बार यह विचित्र स्थिति पैदा हुई कि फ्रांस के राष्ट्रपति शिराक तथा रूसी संघ के राष्ट्रपति पुतिन ने अमरीका के इराक पर आक्रमण करने का विचार किया और सुरक्षा परिषद् में ऐसे प्रस्ताव पर वीटो शक्ति के प्रयोग करने का मंतव्य स्पष्ट कर दिया। ऐसी आशंका को देखते हुए अमरीकी राष्ट्रपति बुश ने सुरक्षा परिषद् से अपना प्रस्ताव वापस कर लिया तथा उसकी उपेक्षा करते हुए 20 मार्च, 2003 को इराक पर आक्रमण कर दिया।

5. नई विश्वव्यवस्था क्या है?

उत्तर- अमेरिका एक नई विश्व व्यवस्था स्थापित करना चाहता था जो राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के शब्दों में आतंक के भय से मुक्त हो तथा जिस में शांति व सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। 2 अगस्त, 1990 को इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर मात्र छः घंटे में उस पर अधिकार कर लिया और उसे अपना 19वाँ प्रांत घोषित कर दिया। इराक को कुवैत खाली करने के लिए समझाने-बुझाने की राजनयिक कोशिशें जब नाकाम हो गईं तो संयुक्त राष्ट्रसंघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। शीतयुद्ध के समय वर्षों तक चुप्पी साधे रहने वाले संयुक्त राष्ट्र के लिहाज से यह उसका एक नाटकीय फैसला था। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे 'नई विश्व व्यवस्था' की संज्ञा दी।

Jharkhandi.com

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. अमेरिकी प्रभुत्व का क्या अर्थ है? इसके प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए।

उत्तर- शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व राजनीति में एकमात्र महाशक्ति अमेरिका बची उसके चारों ओर विश्व राजनीति घूम रही है अमेरिकी प्रभुत्व के कारण विश्व के सभी देश अमेरिका को केंद्र में रखकर अपनी कूटनीति का प्रयोग कर रहे हैं 1991 के बाद पूरी शक्ति अमेरिका में निहित हो गई और अपनी सैनिक ,आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति से विश्व के देशों को प्रभावित और नियंत्रित कर अमेरिका अपने वर्चस्व को बढ़ाता रहा।

1 **अमेरिकी प्रभुत्व के लक्षण** - अमेरिका एक नयी विश्व व्यवस्था स्थापित करना चाहता है जो राष्ट्रपति जार्ज बुश के शब्दों में आतंक के भय से मुक्त हो तथा जिसमें शान्ति व सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।11सितम्बर 1990 को कांग्रेस में बोलते उन्होंने कहा कि ऐसा विश्व हो जिसमें विधि का शासन प्रचलित हो तथा विश्व के सभी राष्ट्र स्वतंत्रता व न्याय को बनाए रखने में अपने दायित्व का निर्वहन करें।

2. संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था का स्वेचछाचारी संचालन - सोवियत संघ के विरोध के कारणअमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ का अपने तरीके से उपयोग नहीं कर सकता था। लेकिन 1990 में सोवियत संघ इतना कमजोर हो चुका था कि राष्ट्रपति बुश ने मनमाने तरीके से सुरक्षा परिषद् से प्रस्ताव पास कराए तथा खाड़ी युद्ध में सामूहिक सुरक्षा प्रावधानों को लागू किया । और 2003 ई० में अमेरिका ने सुरक्षा परिषद् की उपेक्षा कर इराक पर आक्रमण किया।

3. दमनकारी कूटनीति का प्रयोग- संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार किसी राज्य के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करना वर्जित है लेकिन अमेरिका द्वारा कभी मानव अधिकारों के हनन का बहाना तो कभी इस्लामी आतंकवाद को मिटाने के नाम पर दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाता रहा है उदाहरण के लिए -अमेरिका के दबाव में उत्तर कोरिया ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए।

4. सर्वसत्तावादी व्यवस्थाओं व आतंकवाद का निराकरण- इस्लामी कट्टरवाद ने विश्वव्यापी आतंकवाद को जन्म दिया है 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर आतंकवादी आक्रमण के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला करके वहां तालिबान के शासन को खत्म किया। इराक में सद्दाम हुसैन पर जन संहारक शस्त्र रखने का आरोप लगाकर अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया।

5. अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता- रास्तों के बीच विवादों को शांतिपूर्वक तरीके से निपटाया जाना चाहिए ऐसी ही एक साधन है। अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी असाधारण भूमिका निभाने को इच्छुक रहता है जैसा हम इजरायल और फिलिस्तीन के मामले में देख सकते हैं कई बार अमेरिकी प्रशासन ने कश्मीर की समस्या को सुलझाने के लिए अपनी मध्यस्था का विचार पेश किया लेकिन भारत उसे अस्वीकार कर दिया।

2. अमेरिका के साथ भारत के संबंधों पर एक लेख लिखें।

उत्तर- भारत व अमेरिका विश्व की महान लोकतांत्रिक देश है अमेरिका को विश्व का महानतम लोकतंत्र माना जाता है तो भारत को विश्व का विशालतम लोकतंत्र होने का श्रेय प्राप्त है भारत अमेरिका संबंधों के इतिहास को दो भागों में बांटा जा सकता है पहला -शीत युद्ध के काल में, दूसरा -शीत युद्ध की समाप्ति के बाद का काल।

भारत की आजादी के समय शीत युद्ध का काल प्रारंभ हो चुका था। पूरा विश्व दो गुटों में बँट चुका था लेकिन भारत ने दोनों गुटों में शामिल नहीं होने का निश्चय किया। भारत में गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनी विदेश नीति का आधार बनाया। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति तात्कालिक अंतरराष्ट्रीय परिवेश में अमेरिकीहितों के अनुरूप नहीं थी। भारत में 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई जिसके तहत भारत और अमेरिका का व्यापारिक संबंध बहुत तेजी से बढ़ा लेकिन इन दोनों देशों के बीच मनमुटाव के कुछ बिंदु ही बनी रहे जो निम्नलिखित है

1. कश्मीरी समस्या- जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है लेकिन पाकिस्तान इस तथ्य को स्वीकार नहीं करता। अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के पक्ष में समर्थन किया। सोवियत संघ ने भी तो सत्य के प्रयोग से हमारी रक्षा की और अब अमेरिकी प्रशासन मध्यस्था का प्रस्ताव पेश करता है जो भारत को स्वीकार्य नहीं है।

2. तिब्बत का मामला- अमेरिकी प्रशासन की इच्छा यह है कि भारत दलाई लामा को तिब्बत में पुनः स्थापित करके चीन के विस्तार वादी शक्ति पर रोक लगाएं। भारत ने ऐसे विचार को नहीं सराहा क्योंकि तिब्बत की स्वायत्तता का विषय चीन का घरेलू मामला है।

3. इस्लामी आतंकवाद- अफगानिस्तान से सोवियत संघ समर्थक नजीबुल्लाह के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान के माध्यम से तालिबान का सैनिक गुट तैयार किया 1996 ईस्वी में अफगानिस्तान पर इसका कब्जा हो गया तालिबान एवं उसके इस्लामी आतंकवादी संगठनों ने भारत पर आतंकवादी आक्रमण तेज कर दिया है भारत सरकार द्वारा आग्रह बना हुआ है कि अमेरिका इन आतंकवादी शक्तियों का दमन करें लेकिन इस दिशा में अमेरिकी सकारात्मक नहीं रहा है।

शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत अमेरिका संबंध में अनेक सैनिक सुधार हुआ।

1. भारत ने उदारीकरण की नीति अपनाकर विदेशी पूंजी के निवेश का मार्ग खोल दिया है जिससे अमेरिकी कंपनियां भारत में अपना काम फैला रहे है।

3. अमेरिकी वर्चस्व के मार्ग में अवरोधों का वर्णन कीजिए।

उत्तर- इतिहास में अब तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है कि किसी देश का विषय पर हमेशा के लिए वर्चस्व रहा है शक्ति संतुलन एक सामान्य घटना है और जब शक्ति असंतुलित हो जाती है तो बाद में घटनाक्रमों से संतुलित भी हो जाती है। शक्ति संतुलन की राजनीति वर्चस्वशील देश की ताकत को आने वाले समय में कम कर देती है।

sharkhandeb.com

यद्यपि वर्तमान में अमेरिकी वर्चस्व का विरोध कोई देश नहीं कर पाएगा पर अमेरिकी वर्चस्व की राह में तीन अवरोध हैं-

1. पहला अवरोध अमेरिका की स्वयं की संस्थागत संरचना है। सरकार के तीनों अंगों - व्यवस्थापिका ,कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच की शक्ति का विभाजन कार्यपालिका द्वारा सेना के अनियंत्रित और अमर्यादित प्रयोग पर प्रभाव कार्य रोक लगाता है।
2. अमेरिकी वर्चस्व पर दूसरा अवरोध भी आंतरिक है और अमेरिकी समाज की खुली प्रकृति से प्रकट होती है। अमेरिकी जनसंचार के साधन समय-समय पर उनकी जनमत को मोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति में शासन के उद्देश्य और तरीके को लेकर गहरा संशयवाद है। यह तत्व आगे चलकर अमेरिकी सैन्य कार्यवाही पर वैश्विक स्तर पर एक बड़ा अवरोध होगा।
3. अमेरिकी वर्चस्व की राह में तीसरा अवरोध अमेरिका द्वारा निर्मित उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो हो सकता है। अभी अमेरिका का बहुत बड़ा हित बाजार अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने वाले इन लोकतांत्रिक देशों के इस संगठन को बनाए रखने से जुड़ा हुआ है। इसलिए यह संभव है कि नाटो में शामिल इसके साथी देश इसके वर्चस्व पर अंकुश लगा सकें।

Jharkhandlab.com

अध्याय - 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. **यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई?**
   (A) 1957 (B) 1967
   (C) 1992 (D) 1968

2. **यूरोपीय संघ के कौन दो सदस्य सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं?**
   (A) ब्रिटेन और फ्रांस (B) ऑस्ट्रिया और इटली
   (C) पुर्तगाल और स्पेन (D) स्वीडन और फिनलैंड

3. **यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई?**
   (A) 1957 (B) 1948
   (C) 1952 (D) 1967

4. **यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई?**
   (A) 1957 (B) 1952
   (C) 1955 (D) 1991

5. **यूरोपीय संघ के दो सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस किसके स्थायी सदस्य हैं?**
   (A) सुरक्षा परिषद के (B) आसियान के
   (C) आर्थिक सहकार के (D) इनमें से कोई नहीं

6. **यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ?**
   (A) 1989 (B) 1969
   (C) 1979 (D) 1980

7. **जर्मनी का एकीकरण कब हुआ?**
   (A) अक्टूबर 1890 (B) नवंबर 1890
   (C) जनवरी 1890 (D) अक्टूबर 1990

8. **निम्नलिखित में से कौन सा देश परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है?**
   (A) भारत (B) पाकिस्तान
   (C) चीन (D) नेपाल

9. **नई मुद्रा यूरो को जनवरी 2002 में कितने देशों ने अपनाया था?**
   (A) 12 देशों ने (B) 10 देशों ने
   (C) 11 देशों ने (D) 5 देशों ने

10. **सन 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना क्यों हुई थी?**
    (A) राजनैतिक सहयोग (B) आर्थिक सहयोग
    (C) सैन्य सहयोग (D) इनमें से कोई नहीं

11. **यूरोपीय संघ 2005 ईस्वी तक दुनिया का-**
    (A) सबसे बड़ी राजनीतिक व्यवस्था थी,
    (B) सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बन गई,
    (C) सबसे बड़ी सैन्य व्यवस्था बन गई,
    (C) इनमें से कोई नहीं।

12. **किसने खुले द्वार की नीति अपनाई?**
    (A) चीन (B) यूरोपीय संघ
    (C) जापान (D) अमेरिका

13. **यूरोपीय संघ के झंडे में सितारों की संख्या है?**
    (A) 20 (B) 12
    (C) 30 (D) 5

14. **यूरोप में" यूरोपीय संघ" और एशिया में "आसियान" का उदय किस रूप में हुआ?**
    (A) एक दमदार शक्ति के रूप में
    (B) सामान्य रूप में
    (C) शांतिपूर्ण एवं सहकारी व्यवस्था के क्रम में
    (D) इनमें से कोई नहीं।

15. **सन 1978 ईस्वी में 'ओपन डोर' (खुले द्वार) की नीति किसने चलायी?**
    (A) लेनिन (B) कार्ल मार्क्स ने
    (C) देंग श्याओपेंग ने (D) इनमें से कोई नहीं।

16. **'आसियान वे' या आसियान शैली क्या है?**
    (A) आसियान के सदस्य देशों के जीवन शैली है।
    (B) आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोग पूर्ण कामकाज का स्वरूप है।
    (C) आसियान सदस्यों की रक्षा नीति है।
    (D) सभी आसियान सदस्य देशों को जोड़ने वाली सड़क है।

17. **निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य है?**
    (A) भारत (B) पाकिस्तान
    (C) इंडोनेशिया (D) चीन

18. **साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ?**
    (A) 1949 (B) 1939
    (C) 1957 (D) 1849

19. **एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेले G-7का सदस्य है?**
    (A) चीन (B) जापान
    (C) भारत (D) पाकिस्तान

बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर–

1-C, 2-A, 3-B, 4-A, 5-A, 6-C, 7-D, 8-D, 9-A, 10-A, 11-B, 12-A, 13-B, 14-C, 15 -C, 16- B, 17-C, 18-A, 19-B

Jharkhandlab.com

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

प्रश्न 1. आसियान की स्थापना कब हुई और इसके कितने सदस्य देश हैं?

उत्तरः- आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई। इसके पांच देश संस्थापक सदस्य हैं- इंडोनेशिया, मलेशिया,थाईलैंड,फिलीपींस और सिंगापुर। वर्तमान में आसियान के सदस्य संख्या 10 है।

प्रश्न 2. चीन ने "खुले द्वार" की नीति कब चलाई और उससे उसे क्या लाभ हुए?

उत्तरः- दिसंबर 1978 ईस्वी में देंग श्याओपेंग ने खुले द्वार की नीति चलाई। इसके कारण चीन अद्भुत प्रगति की और आने वाले सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा।

प्रश्न 3. यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई ? उसकी सामान्य नीतियां क्या थी?

उत्तरः- यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई।

इसकी सामान्य नीतियां-समान विदेश नीति, सुरक्षा नीति,अंतरिक्ष मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों में सहयोग और एक समान मुद्रा का प्रचलन।

प्रश्न 4. "आसियान" किस प्रकार "यूरोपीय संघ" से भिन्न है?

उत्तरः- बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन है तथा साथ ही सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देता है।

जबकि 'यूरोपीय संघ' आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था के साथ एक राजनीतिक संगठन है, जो राष्ट्र- राज्य की तरह काम करने लगा है। इसका अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा है।

प्रश्न 5. अमेरिकी वर्चस्व के विरुद्ध सत्ता के तीन वैकल्पिक केंद्र क्या है?

उत्तरः- अमेरिकी वर्चस्व के विरुद्ध सत्ता के तीन वैकल्पिक केंद्रः-
1. यूरोपीय संघ

2. आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन) एवं

3. चीन।

प्रश्न 6. यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन कब और किस संधि के द्वारा हुआ?

उत्तरः - यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन मार्च 1957 को "रोम की संधि"के द्वारा हुआ।

प्रश्न 7. यूरोपीय संघ में मतभेद के दो उदाहरण दीजिए।

उत्तरः - यूरोपीय संघ में मतभेद के दो उदाहरणः-

1. इराक पर अमेरिकी हमले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तो उसके साथ थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस हमले के खिलाफ थे।
2. यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो को लागू करने को लेकर असहमति थी।

प्रश्न 8. आसियान के सदस्य देशों का नाम बताएं?

उत्तरः- 1. इंडोनेशिया 2. मलेशिया
3. फिलीपींस 4. सिंगापुर
5. थाईलैंड 6. दारुस्सलाम
7. वियतनाम 8. लाओस
9. म्यानमार एवं 10. कम्बोडिया।

लघु उत्तरीय प्रश्नः-

प्रश्न 1. यूरोपीय संसद से आप क्या समझते हैं?

उत्तरः- यूरोपीय संघ के द्वारा निर्मित एक संसद(Parliament) है, जो एक राजनीतिक मंच का कार्य करती है इसमें सार्वजनिक महत्व के विषयों पर विचार विमर्श किया जाता है तथा परिषद और यूरोपीय आयोग के विषय में प्रश्नों को उठाया जाता है। यूरोपीय संसद ही यूरोपीय संघ की बजट को स्वीकार अथवा अस्वीकार करता है।

प्रश्न 2. आसियान के चार उद्देश्यों को लिखें।

उत्तरः- आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है। इसके चार उद्देश्य निम्नलिखित हैः-

1. अपने क्षेत्र में आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना।
2. अपने क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा स्थापित करना।
3. साझे हितों के मामलों में परस्पर सहायता को बढ़ावा देना।
4. समान उद्देश्यों वाले अन्य क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंध स्थापित करना।

प्रश्न 3. आसियान विजन -2020 की मुख्य बातें क्या है?

उत्तरः- आसियान विजन -2020 की मुख्य बातें निम्नलिखित है-

1. आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इसके विजन दस्तावेज -2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है।
2. इस दस्तावेज में इस बात पर विशेष बल दिया गया है, कि आसियान द्वारा टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी के मद्देनजर आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया, पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला है और पूर्व एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 से नियमित रूप से वार्षिक बैठक आयोजित की है।

प्रश्न 4. क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या है?

उत्तरः- क्षेत्रीय संगठन के निर्माण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैः-

1. संगठन में सम्मिलित देश परस्पर सहयोग से बहुमुखी विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। विकास के राह पर कई अवरोध ऐसे होते हैं इसे अकेले दूर करना कठिन हो जाता है। अतः कुछ देश संगठित होकर ऐसे अवरोधों को आसानी से दूर कर सकते हैं।

Jharkhandlab.com

2. संगठन का एक लाभ यह भी है कि आपसी तनाव को दूर करता है और एक दूसरे के प्रति विश्वास को बढ़ावा देता है। क्षेत्रीय संगठन अब से युद्ध को टालने में भी अहम भूमिका निभाती है।
3. यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए भी संगठित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन को प्रभावित करने की क्षमता रखती और अंतर्राष्ट्रीय कानून को अधिक न्याय संगत बनाने की मांग करती है।

प्रश्न 5. मार्शल योजना क्या था?

उत्तर: - यह योजना अमेरिकी विदेश मंत्री के नाम पर "मार्शल योजना"रखा गया। इस योजना को 1948 में लाया गया था। इस योजना के तहत अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के उन देशों को आर्थिक मदद दी, जिसकी अर्थव्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत अधिक नष्ट हो चुकी थी और युद्ध के पश्चात शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के पक्ष में थी। इस योजना के बाद पश्चिमी यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से विकास हुआ। सोवियत संघ ने इसे विस्तारवादी नीति कहकर इसकी आलोचना की थी।

प्रश्न 6. आसियान समुदाय के मुख्य स्तम्भों और उनके उद्देश्यो के बारे में बताएँ।

उत्तर- आसियान समुदाय के तीन मुख्य स्तम्भ है-

1. आसियान सुरक्षा समुदाय - यह समुदाय आसियान देशों के बीच होने वाले टकरावों को दूर करता है।
2. आसियान आर्थिक समुदाय - आसियान आर्थिक समुदाय आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तथा क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।
3. आसियान सामाजिक-सांस्कृतिक समुदाय - यह समुदाय आसियान देशों के बीच सामाजिक एंव सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देता है।

प्रश्न 7. आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरह अलग है?

उत्तर- आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से पूरी तरह अलग है। चीनी अर्थव्यवस्था की नीति विदेशी पूँजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त करना है। चीन ने वर्तमान समय में बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था को अपनाया है। चीन ने शोक थैरेपी" की अपेक्षा-चरणबद्ध ढंग से अपनी अर्थव्यवस्था बाजारोन्मुख बनाया। चीन ने 1982 में कृषि एवं 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया। आर्थिक विकास के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की गई। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वर्तमान चीनी अर्थव्यवस्था 1950 की चीनी अर्थव्यवस्था की अपेक्षा अधिक खुलापन लिए हुए हैं।

प्रश्न 8. यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) से आप क्या समझते है।

उत्तर: - यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC)- यूरोपीय आर्थिक समुदाय शीत युद्ध के दौरान हुए सभी समुदायों में सबसे अधिक प्रभावशाली समुदाय था। इसमें फ्रांस पश्चिमी जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम और लक्जमबर्ग शामिल थे।इस संगठन का निर्माण मार्च 1957 ईस्वी में रोम की संधि के माध्यम से किया गया। पहले पाँच वर्ष में ही इस्पात के उत्पादन में 50% से भी अधिक वृद्धि दर्ज की। यूरोपीय आर्थिक संघ के संस्थापक सदस्यों ने आपस में सभी प्रकार के सीमाकर समाप्त करके मुक्त व्यापार अथवा खुली स्पर्धा का मार्ग प्रशस्त किया। 1961 ई0 तक यूरोपीय आर्थिक संघ एक सफल संगठन बन गया।

प्रश्न- 9. पंचशील क्या है? इसके सिद्धांतों को लिखें?

उत्तर: - भारत के शुरुआती दौर में चीन के साथ मित्रता संबंध थी। इस मित्रता को बढ़ावा देने के लिए 1954 ई. में चीन के प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई भारत की यात्रा की। इसी दौरान भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते में पांच सूत्र रखे गये, जिसे पंचशील सिद्धांत के नाम से जाना जाता है

इसके पाँच सिद्धांत निम्नलिखित है-

1. एक दूसरे की प्रभुसत्ता व प्रादेशिकता एवं अखण्डता का सम्मान करना।
2. एक दूसरे पर आक्रमण न करना।
3. दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करना।
4. समानता व परस्पर लाभ।
5. शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का सिद्धांत।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न-1. किस तरह यूरोपीय देशों ने युद्ध के बाद की अपनी परेशानियाँ सुलझाई ? संक्षेप में उन कदमों की चर्चा करें, जिनसे होते हुए यूरोपीय संघ की स्थापना हुई ?

उत्तर: - द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद यूरोपीय देशों द्वारा अपनी परेशानियाँ सुलझाने के तरीके और यूरोपीय संघ की स्थापना के कदम-

1. द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में शीतयुद्ध का दौर आरम्भ हुआ, इससे यूरोपीय देशों को मेल मिलाप का अवसर मिल गया।
2. मार्शल योजना के अंतर्गत अमेरिका ने यूरोपीय देशों के पुनर्गठन के लिए आर्थिक सहायता की।
3. इसी योजना के अंतर्गत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग की स्थापना हुई ,जिसके माध्यम से यूरोपीय देशों को आर्थिक मदद मिली।
4. 1949 ई0 में राजनैतिक सहयोग के लिए यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई।
5. पूँजीवादी देशों के बीच आर्थिक एकीकरण बढ़ता गया और इसके परिणामस्वरूप 1957 में रोम की संधि द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई।
6. सोवियत संघ के विघटन के पश्चात इसका तेजी से राजनीतिकरण हुआ। 1992 में इस प्रक्रिया के फलस्वरूप यूरोपीय संघ की स्थापना हुई।
7. यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश -नीति और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और समान मुद्रा के चलन के लिए रास्ता तैयार हो गया।

jharkhandjac.com

प्रश्न 2. चीन की बढ़ती अर्थव्यवस्था के क्या कारण है? संक्षेप में वर्णन करें।

उत्तर- शक्ति का तीसरा विकसित केन्द्र- चीन है। 1978 के बाद-चीन की आर्थिक सफलता के कारण यह एक महाशक्ति के रूप में उदय हुआ। आर्थिक सुधारों की शुरूआत करने के बाद से चीन सबसे तेजी से विकास कर रहा है। तेज आर्थिक विकास के साथ-साथ इसकी विशाल आबादी, विस्तृत भूभाग, प्रचुर संसाधन, क्षेत्रीय अवस्थिति और राजनीतिक प्रभाव के कारण चीन और अधिक प्रभावशाली हो गया है। 1949 में माओ के नेतृत्व में चीनी क्रांति हुई। उस साम्यवादी क्रांति के बाद-चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना के समय यहाँ की अर्थव्यवस्था सोवियत मॉडल पर आधारित थी।-चीन आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था। इसने पूँजीवादी देशों से रिश्ते तोड़ लिए। ऐसे में चीन के सामने अपने संसाधनों से गुजारा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन चीनी नेतृत्व ने 1970 के दशक में दो बड़े फैसले लिए। चीन ने 1972 में अमेरिका से सम्बन्ध बनाकर अपने राजनैतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। 1978 में चीन के प्रधानमंत्री देंग श्याओपेंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। अब चीन ने बाहरी व्यापार शुरू किया। बाजारमूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए चीन ने अपना तरीका आजमाया। "शोक थेरेपी पर अमल करने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। 1982 ई. में कृषि का निजीकरण किया गया और उसके बाद 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया। उनके द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीति के कारण कृषि उत्पाद तथा ग्रामीण आय में वृद्धि हुई। फलस्वरूप चीन को विशाल विदेशी मुद्रा भण्डार प्राप्त हुआ। 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया तथा चीन ने दुनिया के बाजार में अपनी धाक जमाई।

प्रश्न 3. यूरोपीय संघ को क्या चीजें एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है।

उत्तरः - यूरोपीय संघ को प्रभावी बनाने वाले कारकः-

(1) यूरोपीय संघ को अनेक चीजें एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है। इस महाद्वीप के देशों की 'भौगोलिक निकटता' इस क्षेत्र को मजबूती प्रदान करती है।

(2) इस महाद्वीप के लंबे इतिहास ने सभी यूरोपीय देशों को सिखा दिया कि क्षेत्रीय शांति और सहयोग ही अंततः उन्हें समृद्धि और विकास दे सकता है। टकराव, संघर्ष और युद्ध विनाश और अवनति के मूल कारण है।

(3) एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था ने उन्हें बता दिया है कि यदि वे अमेरिका के वर्चस्व का सामना करना चाहते हैं तो उन्हें यूरोपीय संघ न केवल बनाना ही चाहिए बल्कि उसे सुदृढ़ और परस्पर हितों की कुर्बानी देकर पूरे यूरोप को सुदृढ़ करना चाहिए ताकि वे समय आने पर अमेरिका, चीन अथवा किसी विश्व की बड़ी शक्ति के सामने घुटने न टेकें और अपनी शर्तों पर उदारीकरण, वैश्वीकरण आदि को लागू करा सकें।

(4) यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत जबरदस्त है। वर्ष 2005 में यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और उसका सकल घरेलू उत्पादन 12000 अरब डालर से ज्यादा था, जो अमेरिका से भी थोड़ा ज्यादा था। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है।

(5) यूरोपीय संघ का राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव भी कम नहीं है। इसके 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। यूरोपीय संघ के कोई और देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में शामिल है। इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी मुल्कों की नीतियों को प्रभावित करता है।

(6) सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। यूरोपीय संघ के 2 देशों ब्रिटेन और फ्रांस के पास परमाणु हथियार है और अनुमान है कि इनके जखीरे में तकरीबन 550 परमाणु हथियार है। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है।

प्रश्न 4 चीन और भारत की उभरती अर्थव्यवस्था में मौजूदा एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती दे सकने की क्षमता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने तर्कों से अपने विचार को स्पष्ट करें।

उत्तर- हां, हम इस कथन से सहमत हैं। चीन और भारत की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मौजूदा एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती दे सकने की पूरी क्षमता है। हम इस विचार की पुष्टि के समर्थन में निम्न तर्क दे सकते हैं-

1. चीन और भारत दोनों एशिया के प्राचीन, महान शक्तिशाली एवं साधन संपन्न देश है। दोनों में परस्पर सुदृढ़ मित्रता और सहयोग अमरीका की चिंता का कारण बन सकता है। दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक मंचों पर एक से नीति और दृष्टिकोण अपनाकर एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के संचालन करने वाले राष्ट्र अमेरिका और उसके मित्रों को चुनौती देने में सक्षम है।
2. चीन और भारत दोनों की जनसंख्या 200 करोड़ से भी अधिक है। इतना विशाल जनमानस अमेरिका के निर्मित माल के लिए एक विशाल बाजार प्रदान कर सकता है। पश्चिमी देशों एवं अन्य देशों को कुशल और अकुशल सस्ते श्रमिक उपलब्ध करा सकते हैं।
3. दोनों ही राष्ट्र वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों में परस्पर सहयोग करके प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति कर सकते हैं।
4. दोनों देश नई अर्थव्यवस्था, मुक्त व्यापार नीति, उदारीकरण, वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के पक्षधर है। दोनों देश विदेशी पूंजी निवेश का स्वागत कर एक ध्रुवीय महाशक्ति अमेरिका और अन्य बहुराष्ट्रीय निगम समर्थक कंपनियां स्थापित और संचालन करने वाले राष्ट्रों को लुभाने, आंतरिक आवश्यक सुविधाऐं प्रदान करके अपने यहां आर्थिक विकास की गति को बढ़ा सकते हैं।
5. दोनों देश विश्व बैंक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेते समय अमेरिका और अन्य बड़ी शक्तियों की मनमानी शर्तें थोपने पर नियंत्रण रख सकते हैं।
6. चीन और भारत तस्करी रोकने, नशीली दवाओं के उत्पादन, वितरण, प्रदूषण फैलाने वाले कारकों,

Jharkhand.com

और आतंकवादियों की गतिविधियों को रोकने में पूर्ण सहयोग देकर भी विश्व व्यवस्था की चुनौतियों को कम कर सकते हैं। क्योंकि इन क्षेत्रों में सहयोग से न केवल कीमतों के बढ़ने की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है बल्कि लोगों का स्वास्थ्य और सुरक्षा बढ़ेगी। दोनों में अंतरिक्ष सद्भाव, शांति, औद्योगिक विकास के अनुकूल, वातावरण निःसंदेह विदेशी पूंजी, उद्यमियों, व्यापारियों,,नवीनतम प्रौद्योगिकी आदि के आने और नई नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना,विभिन्न प्रकार की सेवाओं की वृध्दि और विस्तार में मदद मिलेगी।

प्रश्नः-5. मुल्कों की शांति और समृद्धि क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों को बनाने और मजबूत करने पर टिकी है। इस कथन की पुष्टि करें।

उत्तरः- प्रत्येक मुल्क की शांति और समृद्धि क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों को बनाने और उन्हें सुदृढ़ करने पर टिकी है। क्योंकि क्षेत्रीय आर्थिक संगठन बनाने पर कृषि, उद्योग धंधों,व्यापार,यातायात,आर्थिक संस्थाओं आदि को बढ़ावा मिलता है। क्षेत्रीय आर्थिक संगठन बनेंगे तो लोगों को प्राथमिक ,द्वितीयक ,और तृतीयक क्षेत्रों में रोजगार मिलेगा। रोजगार गरीबी को दूर करता है। आर्थिक संगठनों के निर्माण से राष्ट्रों में समृद्धि आती है। समृद्धि का प्रतीक राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना प्रमुख सूचक है। जब लोगों को रोजगार मिलेगा, गरीबी दूर होगी तो आर्थिक विषमता कम करने के लिए साधारण लोग भी अपने-अपने आर्थिक संगठनों में आवाज उठाएंगे। श्रमिकों को उनका उचित हिस्सा, अच्छी मजदूरियों, वेतनो, भत्तों, बोनस आदि के रूप में मिलेगा तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। वे अपने परिवार के लोगों को शिक्षा,स्वास्थ्य, यातायात, आदि की अच्छी सुविधाएं प्रदान करेंगे। क्षेत्रीय आर्थिक संगठन बाजार शक्तियां और देश की सरकारों की नीतियों से गहरा संबंध रखते हैं। हर देश अपने यहां कृषि, उद्योगों और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए परस्पर क्षेत्रीय राज्यों से सहयोग मांगते हैं और उन्हें पड़ोसियों को सहयोग देना होता है। वे चाहते हैं कि उनकी उद्योगों को कच्चा माल मिले।वे अतिरिक्त संसाधनों का निर्यात करना चाहते हैं। यह तभी संभव होगा क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर शांति होगी। बिना शांति के विकास नहीं हो सकता। क्षेत्रीय आर्थिक संगठन पूरा व्यय नहीं कर सकते। पूरा उत्पादन हुए बिना समृद्धि नहीं आ सकती। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय आर्थिक संगठन विभिन्न देशों में पूंजी निवेश, श्रम गतिशीलता, यातायात सुविधाओं के विस्तार, विद्युत उत्पादन वृद्धि में सहायक होते हैं। यह सब मुल्कों की शांति और समृद्धि को प्रदान करते हैं।

प्रश्न 6. भारत और चीन के बीच विवाद के मामलों की पहचान करें और बताएं कि बेहतर सहयोग के लिए इन्हें कैसे निपटाया जा सकता है। अपने सुझाव भी दीजिए।

उत्तरः- भारत- चीन विवाद के क्षेत्र- भारत और चीन के बीच समय-समय पर मतभेद के कोई क्षेत्र रहे हैं जो इस प्रकार है-

1. सन 1950 51 में तिब्बत पर चीनी आक्रमण के समय तिब्बत के राजनीतिक तथा धार्मिक नेताओं ने भारत में शरण ली। अभी भी भारत में रह रहे हैं। इससे दोनों देशों में तनाव बना हुआ है।
2. दोनों देशों के बीच मैकमोहन रेखा जो दोनों देशों के बीच की सीमा रेखा है,पर विवाद है। चीन ने इस सीमा रेखा को मानने से इनकार कर दिया है।
3. पाकिस्तान ने 1965 तथा 1971 में भारत पर जब आक्रमण किया, तो चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया ,उसकी सहायता की तथा उसे हथियार भी दिए। इससे भी भारत चीन संबंधों में काफी तनाव पैदा हुआ।

वर्तमान समय में भी चीन,भारत के कुछ पड़ोसी देशों को इसमें पाकिस्तान के साथ म्यानमार भी शामिल है खतरनाक हथियारों के निर्माण में मदद दे रहा है।

साल 1975 में दोनों देशों के बीच राजदूत स्तर पर कूटनीतिज्ञ संबंध फिर से स्थापित किए गए। साल 1988 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी चीन के दौरे पर गए। सन 1991 में चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग भारत की यात्रा पर आए। साल 1996 में चीन के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान भारत तथा चीन के बीच चार समझौतों पर दस्तखत किए गए परंतु भारत द्वारा मई 1998 ईस्वी में परमाणु परीक्षणों के पश्चात दोनों देशों के बीच में फिर कटुता पैदा हो गई। जुलाई 2000 में चीन के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए और इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार वृद्धि तथा सीमा विवाद को हल करने के बारे में सहमति हुई। परंतु सीमा विवाद अभी तक हल न हो पाने के कारण दोनों देशों के संबंध मित्रता पूर्ण नहीं कहे जा सकते हैं।

वैसे पिछले कुछ वर्षों से चीन ने उदारवादी नीति को अपनाया हुआ है और अपने आंतरिक प्रशासन तथा साम्यवादी दल के संगठन में सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत का समर्थन कर रहा है। आज चीन विदेशी शक्तियों से भी मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के पक्ष में है। नवंबर 2002 में चीन का एक शिष्टमंडल भारत आया था और दोनों देशों के बीच सीमा संबंधी विवाद को सुलझाने पर बातचीत चली।

वर्तमान समय में भी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति के द्वारा दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के साथ-साथ अन्य विवादों को भी सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।यदि दोनों देशों को सीमा विवाद के साथ-साथ अन्य विवादों को सुलझाना है ;तो दोनों राष्ट्राध्यक्षों को एक साथ एक मंच में बातचीत करनी होगी।दोनों देशों के बीच जो पंचशील समझौता हुआ था उसको अमल में लाना होगा। आशा है निकट भविष्य मेंदोनों देश सभी विवादों को सुलझा लेंगे।

jharkhandjcert.com

अध्याय - 5 समकालीन दक्षिण एशिया

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. **दक्षिण एशियाई देशों में सबसे बड़ा देश कौन सा है?**
   A. भारत B. पाकिस्तान
   C. बांग्लादेश D. नेपाल

2. **दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ?**
   A. नेपाल B. श्रीलंका
   C. पाकिस्तान D. भूटान

3. **दक्षेस का पहला सम्मेलन कहां हुआ?**
   A. भारत B. बांग्लादेश
   C. पाकिस्तान D. श्रीलंका

4. **दक्षेस में कुल कितने देश शामिल है?**
   A. 8 B. 5
   C. 6 D. 7

5. **1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ?**
   A. भारत और नेपाल B. भारत और पाकिस्तान
   C. भारत व बांग्लादेश D. भारत व चीन

6. **लिट्टे किस देश में एक आतंकवादी संगठन है?**
   A. श्रीलंका B. पाकिस्तान
   C. भारत D. रूस

7. **दक्षेस की स्थापना कब हुई ?**
   A. 1980 B. 1985
   C. 2008 D. 1990

8. **बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी?**
   A. 1972 B. 1971
   C. 1967 D. 1970

9. **निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य देश नहीं है?**
   A. भारत B. पाकिस्तान
   C. श्रीलंका D. इंडोनेशिया

10. **सार्क 1985 में स्थापित किया गया था, इस संगठन का पूर्ण रूप क्या है?**
    A. दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ
    B. दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ
    C. क्षेत्रीय सहयोग के दक्षिणी एशिया प्रशांत संघ
    D. क्षेत्र और सहयोग के लिए दक्षिणी एशियाई सहयोगी

11. **निम्नलिखित में कौन से देश में राजतंत्र, लोकतंत्र - समर्थक समूहों और अतिवादियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना हुआ था?**
    A. भारत B. पाकिस्तान
    C. बांग्लादेश D. नेपाल

12. **निम्न में से कौन चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ देश है ?**
    A. नेपाल B. बांग्लादेश
    C. भारत D. पाकिस्तान

13. **दक्षिण एशिया का वह देश जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया?**
    A. श्रीलंका B. बांग्लादेश
    C. भारत D. पाकिस्तान

14. **निम्न में से कौन से देश में सेना और लोकतंत्र - समर्थक समूहों के बीच संघर्ष में सेना ने लोकतंत्र के ऊपर बाजी मारी?**
    A. भारत B. पाकिस्तान
    C. बांग्लादेश D. भूटान

15. **दक्षिण एशिया के केंद्र में अवस्थित कौन से देश की सीमाएँ दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों से मिलती हैं।**
    A. भारत B. मालदीव
    C. पाकिस्तान D. बांग्लादेश

बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर:

1-A, 2-C, 3-B, 4-D, 5-B, 6-A,7-B,8-B,9-D, 10-A, 11-D, 12-A13-A, 14-B, 15- A.

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

1. **कौन से द्वीप में शासन की बागडोर सुल्तान के हाथ में थी?वर्तमान में यह एक गणतांत्रिक देश है।**

उत्तर : वर्तमान में मालदीव लोकतांत्रिक देश है जहां पहले सत्ता सुल्तान के हाथ में थी।

2. **कौन से देश में ग्रामीण क्षेत्र में छोटी बचत और सहकारी ऋण की व्यवस्था के कारण ग़रीबी कम करने में मदद मिली है?**

उत्तर : बांग्लादेश में ग्रामीण क्षेत्र में छोटी बचत और सहकारी ऋण की व्यवस्था के कारण गरीबी कम करने में मदद मिली है

3. **कौन एक हिमालयी देश जहाँ संवैधानिक राजतंत्र है? यह देश भी हर तरफ भूमि से घिरा हुआ है।**

उत्तर : भूटान एक हिमालयी देश है जहां संवैधानिक राजतंत्र है तथा चारों तरफ यह भूमि से घिरा हुआ है।

Jharkhandlab.com

4. गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मामले पर भारत और बांग्लादेश के बीच कौन से संधि पर हस्ताक्षर हुए?

उत्तर : गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मसले पर भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का संधि पर हस्ताक्षर हुए।

5. अफगानिस्तान दक्षेस (सार्क) का सदस्य कब बना?

उत्तर : अफगानिस्तान दक्षेस का सदस्य 2007 ई. में बना।

6. अतीत में कौन सा देश एक हिंदू राष्ट्र था?

उत्तर : अतीत में नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था।

7. विकासशील देशों में जनसंख्या की वृद्धि दर पर नियंत्रण करने वाले देश में प्रथम कौन है?

उत्तरः विकासशील देशों में जनसंख्या की वृद्धि दर पर नियंत्रण करने वाले प्रथम देश श्रीलंका है।

8. 1948 के भारत-पाक युद्ध के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर का हिस्सा किस नाम से जाना जाता है?

उत्तर : 1948 के भारत-पाक युद्ध के बाद पाकिस्तान के कब्जे में आया कश्मीर का हिस्सा 'पाक अधिकृत कश्मीर'(POK) के नाम से जाना जाता है।

9. सियाचिन ग्लेशियर का विवाद किन दो देशों के बीच का है?

उत्तर : सियाचिन ग्लेशियर का विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच का है।

10. विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान के बीच 'सिंधु जल संधि' पर हस्ताक्षर कब हुआ?

उत्तर विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान के बीच 'सिंधु जल संधि' 1960 ई. में हुआ।

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. दक्षिण एशियाई संगठन दक्षेस (सार्क)पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

उत्तरः सार्क दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। जिसका पूरा नाम'साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन (SAARC)' है। इसे हिंदी में 'दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन' (दक्षेस) कहा जाता है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। इसका सचिवालय काठमांडू में स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना दक्षिण एशिया के 7 देशों- बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान ने मिलकर की थी। 2007 ई. में अफगानिस्तान दक्षेस का आठवां सदस्य देश बना।

इस संगठन को बनाने का उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों में बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग,अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा मैत्रीपूर्ण संबंध रखा गया हैं।

दक्षेस के सदस्य देशों ने आपसी संबंध को मैत्रीपूर्ण बनाने की दिशा में 'दक्षिण एशिया मुक्त- व्यापार क्षेत्र' (SAFTA) नामक समझौते पर 2004 में हस्ताक्षर किए हैजो 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हो गया है। इस समझौते में इन देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क को कम कर दिया गया है।

2. श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किन की भूमिका प्रमुख है?

उत्तरः श्रीलंका को आजादी 1948 में प्राप्त हुई।आजादी के बाद से वहाँ सक्रिय लोकतंत्र कायम है लेकिन श्रीलंका में एक कठिन चुनौती जातीय संघर्ष है।जिससे गृह युद्ध की स्थिति बनी रहती है। श्रीलंका में सबसे अधिक आबादी 'सिंहली समुदाय' की है। यह समुदाय भारत से आकर श्रीलंका में बसने वाले तमिल समुदाय के विरोधी हैं। उनका मानना हैकि श्रीलंका सिर्फ सिंहली लोगो की है तथा तमिलों को श्रीलंका में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जानी चाहिए।

तमिल भारतवंशी लोगों के प्रति उपेक्षा के भाव के कारण उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा को बल मिला और श्रीलंका में 'लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम' (लिट्टे) नामक एक संगठन 1983 के बाद से श्रीलंका की सेना से सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। यह संगठन श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश 'तमिल ईलम' की मांग कर रहा है उनका नियंत्रण श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी हिस्से पर है।

भारत की तमिल भाषी जनता का भी भारत सरकार पर दबाव रहता है कि श्रीलंका के तमिल लोगों के हितों की रक्षा करें। इसके लिए भारत सरकार भी प्रयासरत रहती है। अंततः श्रीलंका में 2009 में 'लिट्टे' को समाप्त कर दिया गया और सशस्त्र संघर्ष समाप्त हो गया है।

3. पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन-कौन सी कठिनाइयां है?

उत्तरः पाकिस्तान में लोकतंत्र के सफल नहीं होने में निम्नलिखित कठिनाइयां है -

1. पाकिस्तान में सेना,धर्मगुरु और अभिजात भू-स्वामी वर्ग का सामाजिक दबदबा है।उनके वजह से कई बार निर्वाचित सरकार को गिरा कर सैनिक शासन कायम किया गया है।
2. पाकिस्तान की भारत के साथ युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती है। इस कारण सेना समर्थक समूह ज्यादा मजबूत है। यह समूह लोकतंत्र और राजनीतिक दलों के विरोधी हैं।
3. पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन के लिए कोई अंतरर्राष्ट्रीय समर्थन भी नहीं मिलता है जिसके कारण सेना को अपना प्रभुत्व कायम रखने में बढ़ावा मिलता है।
4. अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देश अपने स्वार्थ वश पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा देते हैं क्योंकि उन्हें 'विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद' से खतरा है।

इस प्रकार पाकिस्तान में कभी भी लोकतंत्र शासन स्थाई नहीं रहा हैं। यहां कभी लोकतंत्र शासन तो कभी सैन्य शासन चलता है लेकिन इस देश के लोगो मेंलोकतंत्र के प्रति विश्वास है तथा यहां स्वतंत्र प्रेस और मजबूत मानवाधिकार संगठन काफी मजबूत है।

4. बांग्लादेश की स्थापना कैसे हुई?

उत्तर 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। ब्रिटिश राज के समय बंगाल और असम के हिस्सों से

Jharkhandone.com

पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र बना था। पाकिस्तान का निर्माण पश्चिमी पाकिस्तान तथा पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) दोनों को मिलाकर किया गया था।पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में भौगोलिक दूरी तथा दोनों में संस्कृति एवं भाषा का अंतर हैं।पश्चिमी पाकिस्तान का हमेशा से सरकार में दबदबा रहा था। पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ दुर्व्यवहार तथा राजनीतिक सत्ता मेंसमुचित हिस्सेदारी की मांग को पश्चिमी पाकिस्तान के लोग जो सत्ता में बैठे थे। उनके मांग को ठुकराते आ रहे थे। इस कारण दोनों के बीच तनाव थे।पूर्वी पाकिस्तान में जन संघर्ष का नेतृत्व शेख मुजीबुर्ररहमान ने किया तथा 1970 के चुनाव में इनकी पार्टी अवामी लीग ने बहुमत हासिल किया लेकिन उनकी जीत को स्वीकार नहीं किया गया और पाकिस्तान की सरकार ने शेख मुजीबुर्रहमान को गिरफ्तार कर लिया तथा जनरल याहिया खान के सैनिक शासन में पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली जनता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया जिसके फलस्वरूप हजारों लोग भारत में पलायन किए। भारतसरकार ने पूर्वी पाकिस्तान की आजादी की मांग का समर्थन किया और उन्हें वित्तीय तथा सैनिक सहायता प्रदान किया ।जिसके परिणाम स्वरूप 1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध हुआ। युद्ध की समाप्ति पाकिस्तान के आत्मसमर्पण से हुई तथा एक स्वतंत्र राष्ट्र 'बांग्लादेश' का निर्माण हुआ जिसे भारत सरकार ने मान्यता प्रदान किया।

5. दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक से राजनीतिक प्रणाली नहीं है? विवेचना कीजिए।

उत्तर दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है।

1. अनेक समस्याओं के बावजूद भारत और श्रीलंका में ब्रिटेन से आजाद होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम हैं।
2. पाकिस्तान में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह का शासन कायम रहा है। 2008 से पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता शासन कर रहे हैं।
3. बांग्लादेश में भी लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह का शासन रहा है।1991 के बाद से बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कायम है।
4. नेपाल अतीत में एक हिंदू राष्ट्र रहा है तथा आधुनिक काल में भी कई वर्षों तक संवैधानिक राजतंत्र रहा है। 2008 में नेपाल में राजतंत्र समाप्त हुआ और लोकतांत्रिक गणराज्य बना।
5. भूटान 2008 से संवैधानिक राजतंत्र है। राजा के नेतृत्व में यहां बहुदलीय लोकतंत्र है।
6. मालदीव में1968 तक सल्तनत शासन था।1968में ही गणतंत्र बना तथा यहां शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई है।

इस प्रकार दक्षिण एशिया में एक जैसी शासन व्यवस्था नहीं रहने के बावजूद लोकतंत्र एक स्वीकृत मूल्य है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. दक्षिण एशिया में भारत और उसके अन्य पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की विवेचना करें।

उत्तर: दक्षिण एशिया शब्द बांग्लादेश,भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल,पाकिस्तान और श्रीलंका के लिए किया जाता है। उपर्युक्त देशों के साथ भारत के संबंध निम्न प्रकार के हैं-

1. भारत और बांग्लादेश- भारत के बांग्लादेश के साथ संबंध पिछले दो दशकों में सुधरे हैं। फिर भी उनके बीच कई मुद्दे तनाव के हैं,

जो निम्न है -

A. गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी।
B. अवैध रूप से भारत में बांग्लादेशियों का घुसपैठ।
C. भारत विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी समुदायों का बांग्लादेश के द्वारा समर्थन।
D. भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए बांग्लादेश द्वारा रास्ता देने से इनकार करना ।
E. ढाका के प्राकृतिक गैस भारत को निर्यात नहीं करना।
F. भारत को बांग्लादेश की भूमि से होकर म्यांमार को प्राकृतिक गैस निर्यात नहीं करने देना।

2. भारत और भूटान-भारत के भूटान के साथ अच्छे रिश्ते हैं। इन दोनों के बीच कोई बड़ा झगड़ा नहीं है। भारत भूटान में पनबिजली की बड़ी परियोजनाओं में सहयोग कर रहा है।भूटान के विकास कार्यों के लिए सहायता अनुदान सबसे ज्यादा भारत के द्वारा दिया जाता है।
3. भारत और मालदीव-भारत के मालदीव के साथ संबंध सौहाद्रपूर्ण तथा गर्मजोशी से भरे हैं। 1988 में श्रीलंका के तमिल सैनिकों ने जब मालदीव पर हमला किया था। तब मालदीव सरकार के भारत से मदद मांगने पर भारत सरकार ने वायुसेना और नौसेना के माध्यम से तुरंत कार्रवाई की थी। इसके साथ ही भारत मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में मदद करता है।
4. भारत और नेपाल - भारत और नेपाल के बीच संबंध मधुर एवं शांतिपूर्ण है।दोनों देशों के बीच एक संधि है।जिसके तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट(वीजा) के आना- जाना तथा काम कर सकते हैं। दोनों देश व्यापार,वैज्ञानिक सहयोग,साझे प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन, और जल प्रबंधन ग्रिड के मसले पर एक साथ है।

फिर भी इन दोनों देशों के बीच तनाव के मुद्दे जो निम्न है-

A. व्यापार से संबंधित मनमुटाव रहते है।
B. नेपाल का चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार के द्वारा आपत्ति है।
C. नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करती है। इससे भी भारत नाराज रहता है।
D. नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलन को भारत अपने खिलाफ खतरा मानती है।

5. भारत और पाकिस्तान- भारत का पाकिस्तान के

Jharkhandjac.com

साथ संबंध संघर्ष और शांति वार्ताओं के बीच रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच चार लड़ाईयां हुई है।

इन दोनों देशों के बीच तनाव के मुख्य मुद्दे निम्न है-

A. भारत का अभिन्न अंग कश्मीर है।इस बात का पाकिस्तान के द्वारा विरोध और युद्ध करके कब्जा करने का प्रयास करना।

B. सामरिक महत्व के स्थल सियाचिन ग्लेशियर जो कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है। उसे पाकिस्तान द्वारा कब्जा करने का प्रयास करना।

C. पाकिस्तान द्वारा कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार,प्रशिक्षण एवं धन देना तथा उन्हें भारत पर आतंकवादी हमले करने के लिए सुरक्षा प्रदान करना।

D. पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी अभियान में शामिल रहना।

E. सिंधु नदी के जल बंटवारे तथा कच्छ के रन (गुजरात) में सर क्रीक की सीमा को लेकर मतभेद है।

भारत-पाकिस्तान विभाजन के बाद से ही दोनो के बीच संघर्ष और वार्ताओं के दौर चलते आ रहे हैं।

6. भारत और श्रीलंका- अतीत में भारत और श्रीलंका के बीच में अच्छे संबंध रहे हैं।दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता है और आपसी संबंध मजबूत है किंतु वर्तमान समय में कुछ मुद्दों के कारण दोनों के बीच तनाव हुए।

जो निम्न है-

A. श्रीलंका में हो रहे जातीय संघर्ष में भारत का हस्तक्षेप करना।

B. श्रीलंका सरकार द्वारा पाक जलडमरूमध्य में भारतीय मछुआरों को समुद्र में मछली मारने से रोकना

इस प्रकार दक्षिण एशिया के केंद्र में स्थित भारत एक बड़ा देश है। जिसकी सीमाएं दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों के साथ लगती है लेकिन अनेक समस्याओं के बावजूद दक्षिण एशिया के देश आपस में दोस्ताना रिश्ते तथा सहयोग की दिशा में प्रयासरत रहते हैं।

प्रश्न 2. दक्षिण एशिया के अपेक्षाकृत छोटे देशों के भारत के प्रति आशंका भरे व्यवहार के क्या कारण हैं ?

उत्तर: दक्षिण एशिया के छोटे-छोटे पड़ोसियों के साथ भारत को अक्सर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन पड़ोसियों के द्वारा भारत के प्रति आशंका भरे व्यवहार के निम्नलिखित कारण है -

A. विशाल आकार - भारत का आकार बड़ा है और वह शक्तिशाली भी है।इस कारण उनके छोटे पड़ोसी देश भारत को शक की नजर से देखते हैं।

B. भौगोलिक विशिष्टता- दक्षिण एशिया के सभी बड़े झगड़े भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच है।इसका एक कारण दक्षिण एशिया काभूगोल भी है। जहां भारत बीच में स्थित है और बाकी देश भारत की सीमा के इर्द-गिर्द पड़ते हैं।

C. अत्यधिक जनसंख्या - भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। यह मानव संसाधन से संपन्न देश है।जिसके कारण भीछोटे पड़ोसी देशों को आशंका होती है।

C. विशालकाय अर्थव्यवस्था- भारत दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। कुछ छोटे देशों का मानना है कि भारत उनके बाजार में सेंध लगाकर उनके समाज और राजनीति पर असर डालना चाहता है।

D. बड़ी सैन्य शक्ति-भारत दक्षिण एशिया में एक बड़ी सैनिक शक्ति वाला देश है इस वजह से छोटे देशों को आशंका बनी रहती है।

E. प्रौद्योगिकी (तकनीक) में बाकी से आगे- भारत तकनीकी विकास में दक्षिण एशिया के देशों में काफी आगे हैं। साथ हीपरमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र भी है। इस कारण पड़ोसी देशों को आशंका होती है।

F. अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान-शीत युद्ध के बाद विश्व के दो गुटों में बट जाने के बाद भी भारत के द्वारा एक संतुलित राजनीति किया गया है। इस कारण भारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

G. भारत में बारे में दुष्प्रचार -चीन, पाकिस्तान,पश्चिमी मीडिया के द्वारा भारत के खिलाफ अनेक प्रकार के दुष्प्रचार कर भारत के पड़ोसी देशों को भड़काया जाता है।

इस प्रकार अनेक कारणों से भारत को उसके पड़ोसी देश आशंका भरी नजरों से देखकर विभिन्न आरोप लगाते हैं जैसे बांग्लादेश नदी जल हिस्सेदारी में भारत को इलाके के मालिक की तरह व्यवहार करनेवाला कहा जाता है। छोटे देशों को लगता है कि भारत दक्षिण एशिया में अपना दबदबा कायम करना चाहता है। वही भारत नहीं चाहता कि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो ऐसी स्थिति में बाहरी ताकतों को इस क्षेत्र में प्रभाव जमाने में मदद मिलेगी।

3. एक नए राष्ट्र बांग्लादेश के निर्माण के बाद वहां लोकतंत्र कैसे कायम हुआ? स्पष्ट करें।

उत्तर- बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर अपने को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित किया। 1975 में शेख मुजीबुर्रहमान ने संविधान में संशोधन करके संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को मान्यता दिलाया। शेख मुजीबुर्रहमान ने अपनी पार्टी 'अवामी लीग'को छोड़कर अन्य सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया इससे तनाव और संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। अगस्त 1975 में सेना ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया और इस घटनाक्रम में शेख मुजीबुर्रहमान सेना के हाथों मारे गए। नए सैनिक शासक जियाउर रहमान बने तथा उनकी पार्टी 'बांग्लादेश नेशनल पार्टी' 1979 के चुनाव में विजयी हुई।बाद में जियाउर रहमान की हत्या हो गई और लेफ्टिनेंट जनरल एच एम इरशाद के नेतृत्व में बांग्लादेश में एक बार फिर से सैनिक शासन स्थापित हुआ। बांग्लादेश की जनता लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन करना शुरू कर दी।जिससे बाध्य हो कर राजनीतिक गतिविधियों की छूट दी गई। जनरल इरशाद 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए किंतु जनता के व्यापक विरोध के कारण उन्हें 1990 में राष्ट्रपति का पद छोड़ना पड़ा तथा पुनः 1991 में चुनाव हुए। उसके बाद से बांग्लादेश में बहुदलीय चुनावों पर आधारितप्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कायम है।

Jharkhandlab.com

4. पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र का शासन किस प्रकार रहा है? स्पष्ट करें।

उत्तर - पाकिस्तान में संविधान के बनने के बाद देश की शासन की बागडोर जनरल अयूब खान ने अपने हाथों में ले ली और शीघ्र ही निर्वाचन भी करा लिया। उनके शासन के खिलाफ जनता का विद्रोह हुआ और उन्हें पद छोड़ना पड़ा। एक बार फिर से सैनिक शासन जनरल याहिया खान के नेतृत्व में पाकिस्तान में शुरू हुआ। याहिया खान की सैनिक शासन के दौरान 1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध हुआ परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान टूटकर एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश बना।

1971 से 1977 तक जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में पाकिस्तान में एक निर्वाचित सरकार बनी। 1977 में जनरल जियाउल- हक ने इस सरकार को गिरा दिया और सैनिक शासन कायम किया ।1982 के बाद से जनरल जियाउल-हक को लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का सामना करना पड़ा।

फलस्वरुप 1988 में एक बार फिर से बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी।

बेनजीर भुट्टो की पार्टी 'पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी'और मुस्लिम लीग के बीच लोकतांत्रिक सत्ता 1999 तक कायम रही।

1999 में एक बार फिर से सेना ने दखल दिया और जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा दिया।2001 में परवेज मुशर्रफ ने अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में कराया। पाकिस्तान पर सेना की हुकूमत थी। हालांकि सैनिक शासकों ने अपने शासन को लोकतांत्रिक जताने के लिए चुनाव कराएं हैं। 2008 से पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता शासन कर रहे हैं।

jharkhandlab.com

अध्याय - 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. संयुक्त राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया?
a. 1 जनवरी 1945 b. 1 जून 1945
c. 26 जून 1945 d. 24 अक्टूबर 1945

2. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है?
a. हेग b. लंदन
c. पेरिस d. न्यूयॉर्क

3. वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है?
a. कोजी ए अन्नान b. वान की मून
c. बराक ओबामा d. एंटोनियो गुटीरेश

4. संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य है?
a. 5 b. 15
c. 10 d. 12

5. विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई?
a. 1945 b. 1965
c. 1975 d. 1995

6. भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना?
a. 1945 b. 1947
c. 1950 d. 1952

7. संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है?
a. सचिवालय b. सुरक्षा परिषद
c. महासभा d. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय

8. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां है?
a. मनीला में b. पेरिस में
c. वाशिंगटन में d. जकार्ता में

9. निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थाई सदस्य नहीं है?
a. फ्रांस b. ब्रिटेन
c. चीन d. इटली

10. संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है?
a. 2 b. 3
c. 4 d. 6

11. मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब हुई?
a. 2006 b. 2009
c. 2008 d. 2005

12. एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है?
a. मानव अधिकार b. आतंकवाद
c. लोगों का स्वास्थ्य d. आर्थिक विकास

13. क्यूबा संकट किस वर्ष हुआ?
a. 1960 b. 1961
c. 1962 d. 1963

14. वीटो के प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में किया गया?
a. याल्टा b. लंदन
c. सन फ्रांसिस्को d. ब्रिटेन

15. परमाणु अप्रसार संधि कब अस्तित्व में आई?
a. 1982 b. 1965
c. 1971 d. 1968

उत्तर-

1(d) , 2(a), 3(d), 4(b), 5(d), 6(a), 7(b), 8(c), 9(d), 10(d), 11(a), 12(a), 13(c), 14(a), 15(d)

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

1. सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार अर्थात वीटो का क्या अर्थ है?

उत्तर- सुरक्षा परिषद के पांच स्थाई सदस्य अमेरिका ,रूस ,ब्रिटेन ,फ्रांस और चीन को वीटो पावर प्राप्त है अगर कोई स्थाई सदस्य किसी प्रस्ताव से असमहत हो तो अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर प्रस्ताव को खारिज या नकार सकता है।

2. संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है?

उत्तर- सुरक्षा परिषद की सिफारिश के आधार पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है।

3. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं और उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?

उत्तर- अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं और उनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है।

4. वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है ?

उत्तर- वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की कुल संख्या 193 है।

5. संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे और वह किस देश के निवासी थे?

उत्तर- संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रिगवी ली थे। वे नॉर्वे के निवासी थे।

6. "ह्यूमन राइट्स वाच" क्या है?

उत्तर- ह्यूमन राइट्स वॉच अमेरिका का सबसे बड़ा गैर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो मानव अधिकारों की वकालत करता है और उनसे संबंधित अनुसंधान करता है।

jharkhandlab.com

7. संयुक्त राष्ट्र संघ के दो उद्देश्य बताएं।

उत्तर- संयुक्त राष्ट्र संघ के दो उद्देश्य-

1. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की रक्षा करना
2. सभी राष्ट्रों के बीच समान अधिकारों और आत्म निर्णय के सिद्धांतों के आधार पर मैत्रीपूर्ण सहयोग का विकास करना।

8. "एमनेस्टी इंटरनेशनल" क्या है?

उत्तर- यह एक गैर-सरकारी संगठन है जो मानव अधिकारों की रक्षा के लिए पूरे विश्व में अभियान चलाकर मानवाधिकारों से जुड़े प्रतिवेदन तैयार कर प्रकाशित करता है।

9. संयुक्त राष्ट्र संघ के चार प्रमुख अंग के नाम बताएं।

उत्तर- संयुक्त राष्ट्र संघ के चार प्रमुख अंग-

1. महासभा
2. सुरक्षा परिषद
3. न्याय परिषद
4. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय

10. संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान प्रतिनिधि क्या कहलाता है?

उत्तर- संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान प्रतिनिधि महासचिव कहलाता है।

11. सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन कब हुआ और उसमें कितने राज्य के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था?

उत्तर- सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 25 अप्रैल 1945 को हुआ था और इसमें 50 राज्यों के प्रतिनिधियो ने भाग लिया था।

12. विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है?

उत्तर- विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डी.सी में है।

13. WTO का पूरा नाम क्या है?

उत्तर- WTO का पूरा नाम -विश्व व्यापार संगठन या world Trade organization है।

14. संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे?

उत्तर- संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले अध्यक्ष ट्रिगवी ली थे।

15. "अंतर्राष्ट्रीय आण्विक ऊर्जा एजेंसी "के दो महत्वपूर्ण कार्य लिखें।

उत्तर-
1. यह संगठन परमाण्विक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है।
2. संगठन के अधिकारी नियमित रूप से विश्व की परमाण्विक सुविधाओं की जांच करते हैं ताकि नागरिक परमाणु संयंत्रो का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्य के लिए न हो।

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या उद्देश्य है?

उत्तर- चार्टर के अनुच्छेद 1 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

1. संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना।
2. राष्ट्रों के बीच लोगों के समान अधिकारों तथा आत्मनिर्णय के सिद्धांतों के प्रति सम्मान पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंधों को विकसित करना तथा विश्व शांति को सुंदर बनाने के लिए अन्य समुचित उपाय करना।
3. आर्थिक, सामाजिक ,सांस्कृतिक तथा मानवीय चरित्र की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करना तथा मानव अधिकारों व नस्ल, लिंग, भाषा अथवा धर्म के आधार पर भेदभाव के बिना सबके लिए मौलिक स्वतंत्रताओं को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना।
4. इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न राज्यों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना।

2. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई. एम.एफ.)पर एक लघु निबंध लिखें।

उत्तर- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्थापना 1945 ई. में हुई 1947 ई. में यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट अभिन्न अंग बन गया। इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा संबंधी सहयोग को प्रोत्साहन करना है। यह देशों की मुद्रा संबंधी समस्याओं का समाधान करता है, ताकि उनका भुगतान संतुलन बना रहे यदि किसी देश की वित्तीय स्थिति डांवाडोल हो रही है तो यह उन्हें अपनी शर्तों पर ऋण देता है। इस के कुल सदस्यों की संख्या 189 है। लेकिन हर सदस्य के मत का वजन बराबर नहीं होता है 10 सदस्यों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली कनाडा रूस, सऊदी अरब और चीन के पास 55% मताधिकार है लेकिन अकेले अमेरिका के पास 17.4% मताधिकार है।

3. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है?

उत्तर- सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली अंग है यह संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका है जिस पर विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने का दायित्व है। पामर और पार्किनस ने इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहा है।

सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं जिसमें 5 स्थाई और 10 अस्थाई सदस्य होते हैं। ब्रिटेन, अमेरिका ,फ्रांस ,रूस और चीन इसके स्थाई सदस्य हैं। प्रारंभ में सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्यों की संख्या 6 थी जिसे 1966 में बढ़ाकर 10 कर दी गई । इन सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा 2 वर्षों के लिए किया जाता है अपनी अवधि समाप्त होने के बाद कोई भी सदस्य फिर तुरंत निर्वाचित नहीं हो सकता। महासभा के एक प्रस्ताव के अनुसार अस्थाई सदस्य एक विशेष फार्मूले के अनुसार चुने जाते हैं एफ्रो एशियाई देशों से पांच, पश्चिमी यूरोप से दो ,पूर्वी यूरोप से एक, तथा लैटिन अमेरिकी देशों से 2 सदस्य चुने जाते हैं। यह भी ध्यान रखा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखने में इनका क्या योगदान रहा है। साधारण विषयों पर कहीं 9 सदस्यों की सहमति से निर्णय लिए जाते हैं पर महत्वपूर्ण विषयों में 9 सदस्यों के स्वीकारातमक मतों में पांच स्थाई सदस्यों का मत आवश्यक होता है यदि एक भी स्थाई सदस्य किसी मामले के विरुद्ध मत देता है तो उस मामले

Jharkhandeb.com

पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है इसे सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्यों का निषेधाधिकार या वीटो पावर कहा जाता है।

4. भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थाई सदस्यता के पक्ष का समर्थन आप कैसे करेंगे अपने प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध कीजिए।

उत्तर- भारत का नागरिक होने के नाते मेरा मानना है कि भारत को सुरक्षा परिषद का स्थाई सदस्य होना चाहिए। इसके समर्थन में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत हैं-

1. भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रारंभिक सदस्यों में से एक है।
2. भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है।
3. भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अगुवा रहा है और इस आंदोलन ने शीत युद्ध के समाप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
4. भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति अभियानों के लिए कई बार अपनी सेना भेजी है। साथ ही इन अभियानों में महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका अदा की है।
5. भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों ,उद्देश्यो,और कार्यों में पूर्ण विश्वास करता है इसलिए भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयों की उपेक्षा या उल्लंघन नहीं करता, चाहे वह कश्मीर के मामले का ही प्रश्न क्यों ना हो।
6. भारत विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश है। यहां विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5 भाग निवास करता है।
7. भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किए गए शांतिमय कार्यो,वैज्ञानिक अनुसंधानों और आर्थिक एवं सामाजिक कार्यों में सदैव भागीदारी रही है।
8. भारत छः बार सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य रह चुका है।

5. संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के क्या कार्य हैं?

उत्तर- सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसके अध्यक्ष को महासचिव कहा जाता है। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। सुरक्षा परिषद के परामर्श पर पांच स्थाई सदस्यों की सहमति आवश्यक है। महासचिव दोबारा नियुक्त हो सकता है वह सचिवालय का प्रधान होता है और संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी अंगो का महासचिव होता है। महासचिव के कई कार्य हैं जो इस प्रकार हैं-

1. संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्मचारियों की नियुक्ति करता है और उनके वेतन ,भत्ते ,छुट्टी आदि के संबंध में नियम बनाता है।
2. वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण रखता है।
3. वह संयुक्त राष्ट्रसंघ का बजट तैयार करता है।
4. महासचिव महासभा व सुरक्षा परिषद की बैठकें बुलाता है तथा उनके निर्णयों को क्रियान्वित करता है।
5. वह शांति स्थापित करने के लिए सेनाओं का गठन करता है तथा निरीक्षण, नियंत्रण व निर्देशित करता है।
6. वह अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय सम्मेलनों में संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधित्व करता है तथा प्रेस व मीडिया के माध्यम से अपने विचारों तथा उपलब्धियों की जानकारी प्रदान करता है।
7. वह गंभीर समस्याओं की जांच-पड़ताल करता है और अपने सद्भाव या मध्यस्यता से स्थिति को संभालते हैं तथा इस बारे में सुरक्षा परिषद व महासभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. सुरक्षा परिषद के संगठन एवं कार्यों का वर्णन करें।

उत्तर- सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली अंग है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका है जिस पर विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने का दायित्व है। पामर और पार्किनस ने इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहा है।

सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। 5 स्थाई सदस्य और 10 अस्थाई सदस्य। ब्रिटेन अमेरिका फ्रांस रूस और चीन इसके स्थाई सदस्य हैं प्रारंभ में सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्यों की संख्या 6 थी

जिसे 1966 में बढ़ाकर 10 कर दी गई। इन सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा 2 वर्षों के लिए किया जाता है अपनी अवधि समाप्त होने के बाद कोई भी सदस्य फिर तुरंत निर्वाचित नहीं हो सकता। महासभा के एक प्रस्ताव के अनुसार अस्थाई सदस्य एक विशेष फार्मूले के अनुसार चुने जाते हैं एफ्रो एशियाई देशों से पांच ,पश्चिमी यूरोप से दो ,पूर्वी यूरोप से एक तथा लैटिन अमेरिकी देशों से दो सदस्य चुने जाते हैं। यह ध्यान रखा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखने में इनका क्या योगदान रहा है

प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार है साधारण विषयों पर कहीं 9 सदस्यों की सहमति से निर्णय लिए जाते हैं पर महत्वपूर्ण विषयों में 9 सदस्यों को स्वीकारात्मक मतों में पांच स्थाई सदस्यों का मत आवश्यक होता है। कि यदि एक भी स्थाई सदस्य किसी मामले के विरुद्ध मत देता है तो उस मामले पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है इसे सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्यों का निषेधाधिकार (वीटो पावर) कहा जाता है। हर महीने सुरक्षा परिषद के सदस्यों में से ही परिषद का अध्यक्ष देश के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अक्षर के क्रम के अनुसार चुना जाता है।

सुरक्षा परिषद के निम्नलिखित कार्य हैं-

1. अंतर्राष्ट्रीय शांति व व्यवस्था की स्थापना करना।
2. ऐसे किसी भी विवाद यह स्थिति की जांच करना जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरे की संभावना हो।
3. झगड़ों के निपटारे के लिए शांतिमय उपायो या समझौतो की शर्तों की सिफारिश करना।
4. आक्रामक राज्यों के विरुद्ध असैनिक एवं सैनिक कार्रवाई करना और इसके लिए सदस्य राज्यों से सिफारिश करना।
5. महासचिव की नियुक्ति के लिए महासभा से सिफारिश करना और महासभा के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना।

Jharkhandlab.com

6. राज्यों की राष्ट्रसंघ की सदस्यता के लिए महासभा से सिफारिश करना।
7. महासभा के साथ मिलकर चार्टर में संशोधन करना।

2. संयुक्त राष्ट्र संघ का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर- 1945 से अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ की गतिविधियों का आलोचनात्मक प्रशिक्षण किया जाए तो उनके पक्ष व विपक्ष में पर्याप्त सामग्री मिल सकती है । एक ओर निराशावादी थे जिन्होंने इस संगठन की असफलताओं व दुर्लभताओ पर प्रहार किया तो दूसरी ओर आशावादियों ने राष्ट्र संघ की उपलब्धियों को सहारा तथा उसके बेहतर भविष्य की कामना की।

पहले हम इस यह संघ की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को लेते हैं जब 1945 में संयुक्त राष्ट्रसंघ बना । उस समय चार्टर पर 50 राज्यों ने हस्ताक्षर किये किन्तु धीरे-धीरे इसकी सदस्य संख्या बढ़ती गई जो 2011 में 193 तक पहुँच गई। जब बार-बार वीटो शक्ति के दुरुपयोग ने सुरक्षा परिषद् को निष्क्रिय बना दिया तो अचेसन सन्धि योजना ने महासभा को सक्रिय कर दिया जो शान्ति स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था उदाहरण के लिए स्वेज नहर व कांगो संघ के संकटमें देखे जा सकते हैं। उपनिवेशवाद के अन्त का अभियान चलता रहा जिससे इण्डोनेशिया, अल्जीरिया, कैमरून्स टोगोलैंड, टैगानाइका, रुएंडा-उरुंडी तथा नामीबिया जैसे क्षेत्र स्वतन्त्र राज्य बन गए। ईरान से सोवियत सेनाएँ हट गयी , फिलीस्तीन में युद्ध विराम हो गया। जब कोरिया की लड़ाई हुई तो सामूहिक सुरक्षा के प्रावधानों का आह्वान किया गया जिससे यह युद्ध रोका जा सके। 1991 में ऐसी कार्यवाहीसे कुवैत की स्वतन्त्रता बहाल की गई। 1960 के बाद नयी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था लाने का अभियान चला जिसने उत्तर-दक्षिण संवाद का सूत्रपात किया। व्यापार व विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन आयोजित हुआ। दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति की कटु आलोचना हुई जिसके कारण उस अमानवीय स्थिति का अन्त हुआ। इस अद्भुत विकास ने दुनिया के छोटे व कम महत्वपूर्ण देशों को अपनी पहचान बनाने का अवसर दिया।

यदि हम चित्र के दूसरी ओर देखें तो संघ की विफलताओं की लम्बी सूची तैयार की जा सकती है। शीत युद्ध की चपेट आने के कारण संयुक्त राष्ट्संघ को वांछित सफलता नहीं मिली। कोरिया की लड़ाई रुकी लेकिन वियतनाम की लड़ाई को रोकने में यह संघ विफल रहा। महासभा में गुटबन्दी शुरू हो गई। 1972 तक उसने साम्यवादी चीन के प्रवेश को असम्भव बनाए रखा तथा महासचिव की बढ़ती हुई सक्रिय भूमिका की कटु आलोचना की। कश्मीर व फिलिस्तीन की जटिल समस्याएँ सुलझ न सकीं जिसकी वजह से भारत व पाकिस्तान तथा इजराइल व अरब देशों के बीच युद्ध चलते रहे। निःशस्त्रीकरण की दिशा में कोई उल्लेखनीय सफलता न मिल सकी। जर्मनी के एकीकरण का मुद्दा भी लटक गया।

फिर भी यह जाना चाहिए कि 1945 से विश्व में ऐसे परिवर्तन होते रहे हैं जिन्होंने आशावादी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया है। शीतयुद्ध का प्रभाव धीरे-धीरे कम होती गई। दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के निकट आने लगी जिनकी वजह से 1962 का क्यूबा का गंभीर खतरा टला तथा 1960 में परमाणु अप्रसारण संधि अस्तित्व में आई।

3. महासभा के अधिकार एवं कार्यों का वर्णन कीजिए।

उत्तर- महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग है जिसमें सभी सदस्यों को समान प्रतिनिधित्व और मताधिकार प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। इसमें प्रत्येक सदस्य राज्य को अपने 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है लेकिन उनका मत 1 ही होता है। महासभा का साल में एक नियमित अधिवेशन आमतौर पर सितम्बर महीने में तीसरे मंगलवार को शुरू होता है जो लगभग तीन महीने तक चलता है। बहुमत की राय पर इसकी विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती है। महासभा संयुक्त राष्ट्रसंघ की व्यवस्थापिका सभा है जिसमें साधारण विषयों पर साधारण बहुमत से और महत्वपूर्ण विषयों पर 2/3 बहुमत से निर्णय लिये जाते हैं। महासभा अपने सदस्यों में से ही प्रति एक वर्ष के लिए अपना सभापति और उपसभापति चुनती है। परन्तु यह पद सुरक्षा परिषद् के किसी स्थायी सदस्य को नहीं दिया जा सकता है।

महासभा के अधिकारी एवं कार्य-

चार्टर के प्रावधानों के अनुसार महासभा की शक्तियां व कार्य निम्नलिखित है-

1. चार्टर के अंतर्गत आने वाले किसी भी विषय पर विचार विमर्श करना।
2. अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा पर खतरे की स्थिति में सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित करना।
3. सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव की नियुक्ति करना।
4. सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान करना।
5. निशस्त्रीकरण व शास्त्रों के विनियमन प्रभावित करने वाले सूत्रों पर विचार करना तथा सुरक्षा परिषद या अपने सदस्यों को ऐसे सूत्रों के बारे में अपनी सिफारिश भेजना।
6. सामान्य कल्याण या राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को घातक या चार्टर के उद्देश्य व सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाली समस्या की उत्पत्ति के कारणों की परवाह ना करते हुए उसकी शांतिपूर्ण समाधान हेतु सिफारिश करना।
7. सुरक्षा परिषद के 10 अस्थाई सदस्यों ,आर्थिक व सामाजिक परिषद के 54 सदस्यों तथा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के 15 जजों का निर्वाचन करना।
8. न्याय परिषद ,आर्थिक और सामाजिक परिषद ,सुरक्षा परिषद एवं अन्य अंगों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना।
9. संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट को मंजूरी देना।
10. सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर चार्टर में संशोधन का अधिकार।

jharkhandlab.com

अध्याय - 7 समकालीन विश्व में सुरक्षा

बहुविकल्पीय प्रश्न-

1. **संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है?**
   A. सत्ता का सन्तुलन B. शान्ति निर्माण
   C. शान्ति स्थापना D. सामूहिक सुरक्षा

2. **दो महाशक्तियों की भूमिका ने कौन-सी स्थिति पैदा की जिससे तीसरा महायुद्ध घटित न हो सका?**
   A. सत्ता का सन्तुलन B. शीत युद्ध
   C. आतंक का सन्तुलन D. तनाव शैथिल्य

3. **किस सन्धि ने परमाणु परीक्षणों को पूर्णतया वर्जित किया?**
   A. परमाणु अप्रसारण सन्धि
   B. पाक्षिक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि
   C. व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि
   D. दक्षिण-पूर्व एशियाई परमाणु शस्त्रों से मुक्त क्षेत्र संधि

4. **शान्ति हेतु एकजुट हो जाओ योजना का प्रस्तावक कौन था?**
   A. डीन अचेसन B. ए. ग्रोमाइको
   C. एन्थोनी एडिन D. मार्शल टीटो

5. **नव-उपनिवेशवाद पदबन्ध किसने गढ़ा ?**
   A. मिस्र के कर्नल नासिर
   B. भारत के जवाहरलाल नेहरू
   C. धाना के क्वामे नक्रूमा
   D. चीन के माओ जेदुग

6. **निःशस्त्रीकरण आयोग की गठन कब हुई?**
   A. 1945 में B. 1952 में
   C. 1960 में D. 1965 मे

7. **नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया?**
   A. संयुक्त राज्य अमरीका
   B. सोवियत संघ
   C. चीन
   D. अमरीका व सोवियत संघ

8. **शान्ति-निर्माण की विधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ?**
   A. खाड़ी युद्ध में B. कोरिया के युद्ध में
   C. कांगो के गृह युद्ध में D. इराक युद्ध में

9. **निम्नलिखित में से नाटो का सदस्य देश कौन सा नहीं है?**
   A. भारत B. ब्रिटेन
   C. अमेरिका D. पोलैंड

10. **कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौते (बी.डब्ल्यू.सी.) पर हस्ताक्षर किए गए?**
    A. 150 B. 152
    C. 154 D. 155

11. **किसने कहा था हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं।**
    A. जवाहर लाल नेहरू B. इन्दिरा गाँधी
    C. चन्द्रशेखर D. इन्द्र कुमार गुजराल

12. **शीतयुद्ध कब आरंभ हुआ?**
    A. प्रथम विश्वयुद्ध के बाद
    B. राष्ट्रसंघ के निर्माण होते ही
    C. द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद
    D. इनमें से कोई नहीं

13. **सुरक्षा धारणा के तहत रासायनिक हथियार संधि कब हुए?**
    A. 1992 में B. 1993 में
    C. 1995 में D. 1991 में

14. **मानवता की रक्षा का व्यापक अर्थ है**
    A. युद्ध से मुक्ति B. अभाव से मुक्ति
    C. भय से मुक्ति
    D. अभाव और भय से मुक्ति

15. **सुरक्षा धारणा के तहत जैविक हथियार संधि किस वर्ष सम्पन्न हुई?**
    A. सन् 1970 में B. सन् 1972 में
    C. सन् 1975 में D. सन् 1980 में

16. **विश्व राजनीति में प्रत्येक देश की सुरक्षा का दायित्व व्यावहारिक रूप से किसे करना पड़ता है ?**
    A. संयुक्त राष्ट्र संघ B. स्वयं प्रत्येक देश
    C. सुरक्षा परिषद् D. इनमें से कोई नहीं

17. **सुरक्षा का क्या अर्थ है ?**
    A. खतरे से मुक्त रहना B. खतरा मंडराना
    C. दूसरों का सहयोग करना
    D. इनमें से कोई नहीं

18. **किसी भी युद्ध में नुकसान होता है**
    A. सिर्फ सैनिकों का B. स्त्री-पुरूषों को
    C. सैनिक एवं जान-माल का
    D. इनमें से कोई नहीं

19. **वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर' पर आतंकवादियों ने कब हमला किया ?**
    A. 11 अक्टूबर 2000 B. 10 नवम्बर 2001
    C. 11 सितम्बर 2001 D. इनमें से कोई नहीं

jharkhandlab.com

20. **सुरक्षा परिषद् में कुल कितने सदस्य होते हैं ?**

A. 5 B. 8

C. 12 D. 15

बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तरः-

1-D,2-C,3-C,4-A,5-C,6-B,7-A,8-C,9-A,10-D11-A,12-C,13-C,14-D,15-B,16-B,17-A,18-C19-C,20-D

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

प्रश्न 1. निःशस्त्रीकरण का क्या अर्थ है?

उत्तर- निःशस्त्रीकरण का मतलब होता है बनाए गए शस्त्रों को कम करना। इसके अंदर दो या दो से ज्यादा देशों के बीच बातचीत के द्वारा ऐसे हथियारों को खत्म करने का फैसला लिया जाता है जो कि भविष्य में जाकर उन दोनों के लिए खतरनाक हो सकते हैं।

प्रश्न 2. आंतरिक सुरक्षा क्या है?

उत्तर- आंतरिक सुरक्षा के अंदर उन सभी खतरों को शामिल किया जाता है जो एक देश की सीमा के अंदर होते हैं यानी की उसी के यहां रहने वाले लोगों से इसके अंदर जातिवाद की वजह से होने वाले दंगे गृहयुद्ध या इसी तरह के अन्य खतरों को शामिल किया जाता है।

प्रश्न 3. नवस्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की क्या चुनौती थी?

उत्तर- 1. इन देशों के आंतरिक भागों में अलगाववादी आंदोलन चल रहे थे। ऐसे में देश का बंटवारे का भय था।

2. इन देशों को यह भी डर था कि कोई अन्य देश इन अलगाववादी आंदोलनों को समर्थन ना दे दे क्योंकि फिर पड़ोसी देश के साथ संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार पड़ोसी देशों से युद्ध और आंतरिक संघर्ष नव स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती थी।

प्रश्न 4. भारत द्वारा परमाणु परीक्षण करने की क्या उद्देश्य हैं?

उत्तर- भारत द्वारा परमाणु परीक्षण करने के पीछे मुख्य उद्देश्य अपने दुश्मनों से अपने क्षेत्र की रक्षा करना था जो परमाणु तकनीकी रूप से समृद्ध देश भी हैं।

प्रश्न 5. क्षेत्रीय आतंकवाद क्या है?

उत्तर- आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र में फैला नक्सलवाद क्षेत्रीय आतंकवाद कहलाता है। यह मुख्य रूप से गरीब और आदिवासियों से संबंधित है और यह जमींदारों का विरोध करता है।

प्रश्न 6. शक्ति संतुलन का क्या महत्व है?

उत्तर- 1. प्रत्येक देश के आसपास कोई न कोई शक्तिशाली देश होता है और उससे हमले की आशंका बनी रहती है। इसलिए प्रत्येक देश कि सरकार दूसरे देश से अपने शक्ति संतुलन को लेकर बहुत संवेदनशील होती है ।

2. प्रत्येक देश शक्ति संतुलन का पलड़ा अपने पक्ष में करने का प्रयास करती है ताकि उसकी स्थिति मजबूत बनी रहे।

प्रश्न 7. एंटी बेलेस्टिक मिसाइल संधि क्या है?

उत्तर- 1. यह संधि 1972 में हुई थी। इसके अंतर्गत अमेरिका और सोवियत संघ को बैलेस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के रूप में प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

2. संधि में दोनों देशों को सीमित संख्या में ऐसी रक्षा प्रणाली तैनात करने की अनुमति थी लेकिन इस संधि ने दोनों देशों को ऐसी रक्षा प्रणाली के व्यापक उत्पादन पर रोक लगा दी।

प्रश्न 8. आतंकवाद क्या है? इसके कुछ उदाहरण दीजिए।

उत्तर- 1. आतंकवाद का आशय उस राजनीतिक हिंसा से है जो जानबूझकर और बिना किसी सहानुभूति के नागरिकों को अपना निशाना बनाता है।

2. उदाहरण- विमान अपहरण अथवा भीड़ भाड़ भरी जगहों में जैसे रेलगाड़ी होटल बाजार या ऐसे स्थानों पर बम लगाना।

अमेरिका में 9/11 की घटना भी इसी का उदाहरण है।

प्रश्न 9. क्योटो प्रोटोकॉल क्या है?

उत्तर- 1. 1997 में क्योटो प्रोटोकोल पर भारत सहित कई राष्ट्रों के हस्ताक्षर हुए। इसमें वैश्विक ताप वृद्धि पर काबू रखने के लिए ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के संबंध में दिशा निर्देश बताए गए हैं।

2. सहयोग मुलक सुरक्षा की पहल करने के कदम के समर्थन में भारत ने अपनी सेना संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाली के मिशन में भेजी है।

प्रश्न 10. अपरोध का क्या अर्थ है?

उत्तर- युद्ध में कोई देश भले ही आत्मसमर्पण कर दे परंतु वह इससे अपने देश की नीति के रूप में फैलाना नहीं चाहती है इसलिए सुरक्षा की नीति का एक प्रमुख उद्देश्य युद्ध की आशंका को रोकने में होता है जिससे अपरोध कहते हैं।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. सुरक्षा की पारंपरिक धारणा या राष्ट्रीय सुरक्षा को स्पष्ट कीजिए ।

उत्तरः सुरक्षा की पारंपरिक धारणा या राष्ट्रीय सुरक्षा-

1. पारंपरिक अवधारणा में किसी राष्ट्र को सबसे बड़ा खतरा सेना से होता है।

2. इस खतरे का स्रोत कोई दूसरा राष्ट्र होता है जो सैनिक हमले की धमकी देकर संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखण्डता जैसे किसी देश के केन्द्रीय मूल्यों के लिए खतरा पैदा करता है।

3. सैनिक कार्रवाई से आम नागरिकों के जीवन को भी खतरा होता है। सैनिक कार्रवाई में सैनिकों के साथ नागरिक भी मारे जाते हैं।

4. युद्ध में निहत्थे स्त्री-पुरुषों को निशाना बनाया जाता है।

5. इसमें नागरिकों और उनकी सरकार के साहस को तोड़ने का प्रयास किया जाता है।

Jharkhandlab.com

प्रश्न 2. परम्परागत सुरक्षा नीति के तत्वों का संक्षिप्त विवरण दीजिए।

उत्तर: परम्परागत सुरक्षा नीति के तत्त्वः

1. आत्मसमर्पण-परम्परागत सुरक्षा नीति का प्रथम तत्व आत्मसमर्पण है। इसमें विरोधी पक्ष की बात बिना युद्ध किए मान लेना अथवा युद्ध से होने वाले नाश को बढ़ा चढ़ाकर संकेत देना ताकि दूसरा पक्ष डर जाए और आक्रमण न करे। युद्ध होने पर उसे पराजित करना।
2. शक्ति संतुलन परम्परागत सुरक्षा नीति का दूसरा तत्व शक्ति संतुलन है। इसके अंतर्गत किसी को अपनी शक्ति को विरोधी ताकतवर देश के बराबर करनी होती है और शक्ति संतुलन का पलड़ा अपने पक्ष में करना होता है।
3. सैन्य शक्ति में वृद्धि शक्ति संतुलन के लिए किसी देश को अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी होती है। इसका आधार आर्थिक और प्रोद्योगिकी ताकत है।
4. गठबंधन निर्माण पारंपरिक सुरक्षा नीति का चौथा तत्त्व गठबंधन है। इसके अंदर कई देश होते हैं जो सैन्य हमले को रोकने अथवा उससे रक्षा करने के लिए एक साथ कदम उठाते। हैं।

प्रश्न 3. शक्ति संतुलन के महत्त्व को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: शक्ति संतुलन का महत्त्व-

1. सुरक्षा नीति का एक महत्त्वपूर्ण तत्व शक्ति संतुलन है। इसके अंतर्गत किसी देश को अपनी शक्ति को विरोधी ताकतवर देश के बराबर करना होता है और शक्ति संतुलन का पलड़ा अपने पक्ष में करना होता है।
2. यदि कोई देश ऐसा नहीं करता है कि ताकतवर देश उसके ऊपर आक्रमण कर सकता है। और उसको विनाश की ओर ले जा सकता है।
3. शक्ति संतुलन के प्रति सभी सरकारें संवेदनशील होती है। कोई भी सरकार दूसरे देशों से शक्ति संतुलन का पलड़ा अपने पक्ष में बैठाने के लिए जी तोड़ कोशिश करती है।
4. पड़ोसी, शत्रु या जिन देशों के साथ अतीत में लड़ाई हो चुकी हो, उनके साथ शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने पर विशेष जोर दिया जाता है।
5. शक्ति संतुलन बनाये रखने के लिए गठबंधन स्थापित करना जरूरी हो गया है। पूर्व सोवियत संघ और अमरीका के गठबंधन के कारण विश्व में शक्ति संतुलन कायम था।

प्रश्न 4. किसी देश के लिए आंतरिक सुरक्षा क्यों जरूरी है? अथवा पारंपरिक अवधारणा की आंतरिक सुरक्षा के महत्व को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: किसी देश के लिए आंतरिक सुरक्षा की आवश्यकता-

1. प्रत्येक देश के लिए आंतरिक शांति और कानून व्यवस्था अति आवश्यक है। आंतरिक शांति के अभाव में बाहरी आक्रमणों का सामना नहीं किया जा सकता।
2. द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् इस पर जोर नहीं दिया गया। वस्तुतः इसका कारण यह था कि ताकतवर देशों में लगभग आंतरिक शासन स्थापित था।
3. 1945 के पश्चात् संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ अपनी सीमा के अंदर एकीकृत और शांति संपन्न हैं।
4. अधिकांश यूरोपीय देशों विशेष रूप से पश्चिमी देशों के सामने अपनी सीमा के भीतर बसे समुदायों अथवा वर्गों से कोई गंभीर खतरा नहीं था इसलिए इन देशों ने सीमा पार के खतरों पर ध्यान दिया।
5. कुछ यूरोपीय देशों को अपने उपनिवेशों में जनता से हिंसा का भय था क्योंकि अब ये लोग आजादी चाहते थे।

प्रश्न 5. नव स्वतंत्र देशों की सुरक्षा के क्या खतरे हैं?

उत्तर: नव स्वतंत्र देशों को सुरक्षा के खतरेः

1. इन देशों को बढ़ते शीतयुद्ध से डर था क्योंकि कुछ नवस्वतंत्र देश यूरोपीय शक्तियों के समान शीतकालीन गुटों में किसी न किसी के सदस्य बन गये थे।
2. दूसरे गुटों में जाने वाले अपने पड़ोसी देश अथवा दूसरे गुट के नेता (अमरीका या सोवियत संघ) से शत्रुता मोल लेना था।
3. अमरीका अथवा सोवियत संघ के किसी साथी देश से शत्रुता ठाननी थी। वस्तुतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने युद्ध हुए उसमें एक तिहाई युद्धों के लिए शीतयुद्ध जिम्मेदार रहा।
4. नव स्वतंत्र देशों को उसके यूरोपीय ओपनिवेशिक शासकों के आक्रमण का भय था। ऐसे में इन देशों को एक साम्राज्यवादी युद्ध से अपनी रक्षा के लिए तैयारी करनी पड़ी।
5. नवस्वतंत्र देशों में आंतरिक सैन्य संघर्ष भी चल रहा था। अलगाववादी आंदोलन तेज हो रहे

प्रश्न 6. सुरक्षा के पारंपरिक तरीके कौन-कौन से हैं?

उत्तर: सुरक्षा के पारंपरिक तरीकेः

1. किसी देश को युद्ध उचित कारणों या आत्मरक्षा अथवा दूसरों को जनसंहार से बचाने के लिए करना चाहिए।
2. युद्ध में युद्ध साधनों का सीमित इस्तेमाल करना चाहिए।
3. आक्रमक सेना को चाहिए कि वह युद्ध न करने वाले शत्रु, निहत्थे व्यक्ति अथवा आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु पर आक्रमण न करे।
4. सेना को उतने ही बल का प्रयोग करना चाहिए। जितना एक सीमा तक आवश्यक हो और उसे एक सीमा तक ही हिंसा का सहारा लेना चाहिए।
5. बल प्रयोग तभी करना चाहिए जब अन्य सभी उपाय असफल हो गये हों।

प्रश्न 7. सुरक्षा की परम्परागत धारणा में राष्ट्रों में किस प्रकार का आपसी सहयोग होना चाहिए।

उत्तर: राष्ट्रों में आपसी सहयोग-

1. राष्ट्रों में आपसी सहयोग निरस्तीकरण अस्त नियंत्रण तथा विश्वास की बहाली में होना चाहिए।
2. निरस्त्रीकरण के अंतर्गत सभी राज्य चाहे उनका आकार, ताकत और प्रभाव कुछ हो कुछ खास किस्म

jharkhandlab.com

के हथियारों का निर्माण नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए जैविक और रासायनिक हथियार।

3. अस्त्र नियंत्रण के अंतर्गत हथियारों को विकसित करने अथवा उनको हासिल करने के संबंध में कुछ नियमों कानूनों का पालन करना चाहिए।

4. सुरक्षा को पारंपरिक धारणा में विश्वास की बहाली भी महत्त्वपूर्ण है। विश्वास बहाली की प्रक्रिया में सैन्य टकराव और प्रतिद्वन्द्विता वाले देश सूचनाओं तथा विचारों के नियमित आदान-प्रदान का निर्णय करते हैं।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1 भारत की सुरक्षा रणनीति क्या है ? व्याख्या करें।

उत्तर: -भारत की सुरक्षा नीति के घटक- भारत ऐसा देश है जो दोनों प्रकार पारंपरिक और अपारंपरिक खतरों का सामना कर रहा है। ये खतरे सीमा के अंदर और बाहर दोनों ओर से हैं। भारत की सुरक्षा नीति के चार घटक हैं जो निम्नलिखित हैं–

1. सैन्य क्षमता
2. अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संस्थाओं को मजबूत करना
3. देश की अंदरूनी सुरक्षा समस्यायें
4. गरीबी और अभाव से छुटकारा

1. सैन्य क्षमता:--

पड़ोसी देशों के हमलों से बचने के लिए भारत को अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करना जरूरी है। भारत पर पाकिस्तान के कई आक्रमण हुए हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में उसके चारों और परमाणु शक्ति सम्पन्न देश है, इसलिए भारत ने 1974 और 1998 में परमाणु परीक्षण किया था।

2. अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संस्थाओं को मजबूत करना:-

भारत ने अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संस्थाओं को मजबूत करने में सहयोग दिया है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने एशियाई एकता,अनोपनिवेशीकरण और निरस्त्रीकरण के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतिम मंच मानने पर जोर दिया। उसका मानना है कि हथियारों और परमाणु शस्त्रों की दृष्टि से सभी देशों को समान अधिकार होना चाहिए। भारत ने नव-अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग उठाई।

3. देश के अंदरूनी सुरक्षा समस्यायें:--

भारत की नीति का तीसरा महत्वपूर्ण घटक देश के अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी है। भारत के कई राज्यों नागालैंड, मिजोरम, पंजाब और कश्मीर आदि राज्यों में अलगाववादी संगठन सक्रिय रहे हैं। इसलिए भारत ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का प्रयास किया है। उसने देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का पालन किया है। उसने सभी समुदाय के लोगों और जनसमूह को अपनी शिकायतें रखने का मौका दिया है।

4. गरीबी और अभाव से छुटकारा:--

भारत ने ऐसी व्यवस्थायें करने का प्रयास किया है जिससे बहुसंख्यक नागरिकों को गरीबी और अभाव से छुटकारा मिल सके तथा नागरिकों के मध्य आर्थिक असमानता समाप्त हो सके।

प्रश्न 2. तीसरी दुनिया के देशों और विकसित देशों की जनता के सामने मौजूद खतरों में क्या अंतर है?

उत्तर- तीसरी दुनिया के देशों और विकसित देशों की जनता के सामने खतरों में काफी अंतर विद्यमान है, जो निम्न हैं-.

(A) तीसरी दुनिया का अर्थ है विकासशील देशों से है, जिसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के देश शामिल हैं विकसित देशों में अमरीका, यूरोपीय देश एवं उत्तरी ध्रुव के देश सम्मिलित हैं। उत्तरी गोलार्ध के देशों को विकसित तथा दक्षिणी गोलार्ध के देशों को अविकसित या तीसरी दुनिया के देश कहा जाता हैं।

(B) तीसरी दुनिया के सामने बाहरी तथा आंतरिक खतरे विद्यमान हैं, जबकि विकसित देशों के सामने ये खतरे न के बराबर हैं।

तीसरी दुनिया के सामने बेरोजगारी, भुखमरी, महामारी जैसे समस्याएँ हैं, जबकि विकसित देशों ने कुछसीमा तक इन पर नियंत्रण कायम कर लिया है।

(C) विकासशील या तीसरी दुनिया के देशों के सामने सुरक्षा का प्रश्न मुख्य चुनौती के रूप में विद्यमान है जो विकसित देशों के सामने नहीं है।

(D) तीसरी दुनिया की जनता के सामने अप्रवासी और शरणार्थियों की समस्या विद्यमान है। यह विकसित देशों में न के बराबर है।

(E) तीसरी दुनिया के देशों के सामने आतंकवाद का एक प्रमुख खतरा विद्यमान हैं। यह विकसित देशों को भी चनौती दे रहा हैं।

नरसंहार, रक्तपात, गृहयुद्ध तीसरी दुनिया के देशों की मुख्य समस्याएँ है, जो विकसित देशों में कम हैं।

प्रश्न 3. शक्ति संतुलन क्या है? कोई देश इसे कैसे कायम करता है?

उत्तर- शक्ति संतुलन का अर्थ है, कोई भी एक पक्ष या राज्य इतना बलशाली न हो कि वह अन्य राज्यों पर हावी हो जाए या दूसरे पर हमला करने, उसे दबाने या हराने में समर्थ हो। जिस तरह एक तुला के दो पलड़े समान भार होने पर संतुलित बने रहते हैं, वही स्थिति अलग-अलग राज्यों के मध्य होती है। यदि कोई देश अन्य देशों की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली होता है तो वह अन्य देशों के लिए संकट और चिंता का विषय बन सकता है।

शक्ति संतुलन के अंतर्गत अनेक राष्ट्र अपने आपसी शक्ति संबंधो को बिना किसी बड़ी शक्ति के हस्तक्षेप के स्वतंत्रतापूर्वक संचालित करते हैं।

क्लॉड के अनुसार, "शक्ति संतुलन एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें विभिन्न स्वतंत्र राष्ट्र अपने आपसी शक्ति संबंधों को बिना किसी बड़ी शक्ति के हस्तक्षेप के स्वतंत्रतापूर्वक संचालित करते हैं। इस प्रकार यह एक विकेंद्रित व्यवस्था हैं, जिसमें शक्ति व नीति निर्णायक इकाइयों के हाथों में ही रहती हैं।"

Jharkhandlab.com

शक्ति संतुलन कायम रखने के उपाय-

(क) शक्ति संतुलन को कायम रखने के लिए सैन्य-शक्ति में लगातार वृद्धि होते रहनी चाहिए।

(ख) शक्ति संतुलन के लिए आर्थिक और प्रौद्योगिकी की ताकत होने चाहिए, तभी शक्ति संतुलन कायम रह पाएगा।

(ग) शत्रु देश की शक्ति को कम करने के लिए अनेक उपाय करने चाहिए, जैसे शत्रु देश के मित्र देशों की संख्या कम करना।

(घ) शस्त्रीकरण भी शक्ति संतुलन का एक जरिया है। शक्ति संतुलन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में बना हुआ था, जैसे अमरीका व सोवियत संघ दोनों शक्तिशाली विरोधी देश थे। यदि शक्ति संतुलन न होता तो तृतीय विश्व युद्ध हो सकता था। यह संतुलन 1945 से 1990 तक बना रहा।

प्रश्न 4. सैन्य गठबंधन के क्या उद्देश्य होते हैं? किसी ऐसे सैन्य गठबंधन का नाम बताइए जो अभी मौजूद है? इस गठबंधन के उद्देश्य भी बताएँ।

उत्तर- सैन्य गठबंधन में कई देश सम्मिलित होते हैं। सैन्य गठबंधन हमले को रोकने, हमला करने और रक्षा के उद्देश्य को लेकर बनाए जाते हैं। सैन्य गठबंधन बनाकर एक विशेष क्षेत्र में सैन्य शक्ति संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान में नाटो (NATO) नाम का एक सैन्य गठबंधन मौजूद हैं। सैन्य गठबंधनों का निर्माण अनेक देशों के माध्यम से अपने किसी विशेष क्षेत्र के लिए किया गया था, जैसे-द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमरीका के नेतृत्व में नाटो, सोवियत संघ के नेतृत्व में वारसा पैक्ट तथा यूरोपीय देशों व अमरीका ने मिलकर सिएटो की स्थापना की।

नाटो एक गैर साम्यवादी सैन्य गठबंधन है। नाटो में सबसे शक्तिशाली तथा केंद्रीय शक्ति अमरीका रहा है। नाटों की स्थापना 4 अप्रैल, 1949 को की गई थी। अमरीका ने सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए नाटों की स्थापना की। इसमें मुख्यतः अमरीका व यूरोपीय देश शामिल थे।

नाटो के उद्देश्य निम्न थे-

(a) यूरोप पर आक्रमण के समय अवरोधक की भूमिका अदा करना।

(b) सैन्य और आर्थिक विकास के लिए यूरोपीय राष्ट्रों के लिए कोई एक सुरक्षा छतरी बनना।

(c) भूतपूर्व सोवियत संघ के साथ संभावित युद्ध के लिए लोगों को, विशेषकर अमरीका के लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना।

(d) नाटो का प्रमुख औचित्य यूरोप की प्रतिरक्षा को सुदृढ़ करना है।

5. भारतीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए किस किस्म की सुरक्षा को वरीयता दी जानी चाहिए-पारंपरिक या अपारंपरिक? अपने तर्क की पुष्टि में आप कौन-से उदाहरण देंगें?

उत्तर- भारतीय परिदृश्य को देखते हुए भारत को पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों तरह की सुरक्षा को वरीयता देनी चाहिए। भारत न तो सैनिक दृष्टि से सुरक्षित हैं और न ही अपारंपरिक सुरक्षा के खतरों से। भारत के दो पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार हैं जो भारत पर कभी भी हमला कर सकते हैं। हमले के अलावा भारत-चीन, भारत-पाकिस्तान सीमाओं पर लगातार विवाद बना हुआ है, जिससे आत्मरक्षा के लिए भारत के पास सैनिक शक्ति व परमाणु हथियारों का होना महत्वपूर्ण हैं। इसलिए भारत द्वारा पारंपरिक सुरक्षा को महत्व दिया जाना चाहिए।

भारत अपारंपरिक सुरक्षा के खतरों से परे नहीं है। पर्यावरण संरक्षण, गरीबी, आतंकवाद, ओजोन परत में छेद ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़, सूखा, सभी देशों की समस्याएँ हैं, भारत भी उनमें से एक है। इन खतरों से जूझना भारत के लिए उतना ही जरूरी है, जितना सैनिक खतरों से। इसी कारण भारत को पारंपरिक सुरक्षा के साथ ही अपारंपरिक सुरक्षा को भी वरीयता देनी चाहिए।

Jharkhandlab.com

अध्याय - 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. पर्यावरण सुरक्षा संबंधी पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ?
(A) 1990 में (B) 1991 में.
(C) 1992 में. (D) 1995 में

2. क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का सम्बन्ध निम्न- लिखित में से किससे है?
(A) जलवायु संरक्षण से
(B) वायुमण्डल संरक्षण से
(c) पर्यावरण संरक्षण से
(D) वन संरक्षण से

3. ओजोन परत का नुकसान निम्नलिखित में से किस गैस के ज्यादा उत्सर्जन से हो रहा है?
(A) ऑक्सीजन गैस (B) क्लोरिन गैस
(C) हाइड्रोजन गैस (D) नाइट्रोजन गैस

4. ओजोन परत के नुकसान से मानव में निम्नलिखित में किस प्रकार के रोग हो सकते हैं?
(A) मस्तिष्क रोग (B) एड्स रोग
(c) त्वचा कैंसर रोग (D) किड्नी संबंधी रोग

5. क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत कब हस्ताक्षर किया?
(A) 1997 में (B) 1998 में
(C) 2002 में (D) 2005 में

6. किस दशक में पर्यावरण से संबंधित मामले राजनीति के मामले बने?
(A) 1960 के दशक (B) 1980 के दशक
(C) 1990 के दशक (D) 1950 के दशक

7. पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां हुआ था?
(A) रियो डी जेनेरो (B) क्योटो
(C) स्टॉकहोम (D) बाली

8. क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर हुआ था?
(A) 1997 (B) 1992
(C) 1998 (D) 2000

9. 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था?
(A) रियो डी जेनेरो (B) क्योटो
(C) जिनेवा (D) न्यूयॉर्क

10. विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?
(A) 10 मई (B) 5 जनवरी
(C) 5 जून (D) 5 अगस्त

11. विश्व की साझी समस्या कौन है?
(A) वायुमंडल (B) समुद्री सत्तह
(C) बाह्य अंतरिक्ष (D) उपर्युक्त सभी।

12. ग्रीन हाउस गैस संबंधित है-
(A) वैश्विक ताप वृद्धि से
(B) विश्व बाजार से
(C) वैश्विक व्यापार से
(D) उपर्युक्त सभी से

13. वैश्विक मामलों से सरोकार रखने वाले एक विद्वत समूह "क्लब ऑव रोम"ने कब'लिमिट्स टू ग्रोथ' शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की?
(A) 1962 (B) 1972
(C) 1982 (D) 1992

14. किस दशक के मध्य में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद की खोज, एक आँख खोल देने वाली घटना है?
(A) 1960 के दशक (B) 1970 के दशक
(C) 1980 के दशक (D) 1990 के दशक

15. झारखंड में " पावन वन प्रांतर" को किस नाम से जाना जाता है?
(A) केकड़ी और ओरान (B) लिंगदोह
(C) काव
(D) जाहेरा थान और सारना

16. पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकारों का क्या कारण है? निम्नलिखित में सबसे बेहतर विकल्प चुने।
(A) विकसित देश प्रकृति की रक्षा को लेकर चिंतित है।
(B) पर्यावरण की सुरक्षा मूलवासी लोगों और प्राकृतिक पर्यावासोंके लिए जरूरी है।
(C) मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान हुआ है और यह नुकसान खतरे की हद तक पहुंच गया है।
(D) इनमें से कोई नहीं।

बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर

1- C, 2-C, 3-B, 4-C, 5-C, 6-A, 7-C, 8-A, 9-A, 10-C, 11-D, 12-A, 13-B, 14-C, 15-D, 16-C

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1 एजेंडा- 21 क्या है?

उत्तर:- एजेंडा -21 टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए विकसित प्रथाओं की परिस्थितिक जिम्मेदारी की एक सूची है।

Jharkhandlab.com

प्रश्न 2 ग्लोबल कॉमन्स से आप क्या समझते हैं?

उत्तर: -ग्लोबल कॉमन्स उन क्षेत्रों या क्षेत्रों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा सामान्य शासन है, जो किसी एक राज्य या प्राधिकरण के संप्रभु अधिकार क्षेत्र के बाहर स्थित है।

प्रश्न 3 साझी संपदा का क्या अर्थ है?

उत्तर- साझी संपदा ऐसी संपदा को कहते हैं जिस पर किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व हो। इसके पीछे मूल तर्क यह है कि ऐसे संसाधन की प्रकृति, उपयोग और रखरखाव के संदर्भ में समूह के प्रत्येक सदस्य को समान अधिकार प्राप्त होंगे और समान उत्तरदायित्व निभाने होंगे।

प्रश्न 4 ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते है?

उत्तर:- ग्लोबल वार्मिंग अथवा वैश्विक ताप वृद्धि का अर्थ विश्व में तापमान में वृद्धि से है। यह कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन और हाइड्रोफ्लोरो कार्बन आदि जैसे इसके उदाहरण है। विश्व का तापमान बढ़ने से धरती के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। विभिन्न देश इस संबंध में वार्तालाप कर रहे हैं। क्योटो प्रोटोकॉल नामक समझौते में विभिन्न देशों की सहमति बन गई है।

प्रश्न 5 मूलवासी कौन लोग हैं?

उत्तर: किसी देश के मूलवासी वह लोग हैं जो उस देश में एक लंबे समय से निवास कर रहे हैं। मूलवासी आज भी उस देश के संस्थाओं के अनुरूप आचरण करने से ज्यादा अपनी परंपरा, सांस्कृतिक रिवाज तथा अपने खास सामाजिक, आर्थिक ढर्रे पर जीवन यापन करना पसंद करते हैं।

प्रश्न 6 वैश्विक सुरक्षा के लिए कौन-कौन से समझौते हुए हैं?

उत्तर:-
1 अंटार्कटिक संधि -1959
2 मॉन्ट्रियल प्रोटोकोल -1987
3 अंटार्कटिक पर्यावरणीय प्रोटोकॉल-1991,

प्रश्न 7 विश्व में खाद्य उत्पादन की कमी के क्या कारण है?

उत्तर:- विश्व में खाद्य उत्पादन की कमी के कारण-

1. विश्व के कृषि योग्य भूमि में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जबकि मौजूदा उपजाऊ भूमि के एक बड़े हिस्से की उर्वरा शक्ति कम हो रही है।
2. चरागाह समाप्त होने को हैं,मत्स्य भंडार घट रहा है और जलाशयों में प्रदूषण बढ़ रहा है।

प्रश्न 8 'ओजोन परत में छेद' से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:- पृथ्वी की ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है इसे ओजोन परत में छेद होना भी कहते हैं। इससे परिस्थितिकी तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक वास्तविक खतरा मंडरा रहा है।

प्रश्न 9 पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन क्या है?

उत्तर:- 1992 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रिक एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। इसे ही पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. ' विश्व की साझी विरासत ' का क्या अर्थ है? इसका दोहन और प्रदूषण कैसे होता है?

उत्तर- साझी संपदा, उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। इसी प्रकार विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं। इसीलिए उनका प्रबंधन साझे तौर पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। इन्हें वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत कहा जाता है।

विश्व की साझी विरासत के दोहन और प्रदूषण के तरीके- पृथ्वी की ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है। ऐसा औद्योगिकरण के कारण हो रहा है। पश्चिमी देशों का इस कार्य में अधिक हाथ रहा है।

अंटार्कटिका क्षेत्र के कुछ हिस्से अवशिष्ट पदार्थों जैसे तेल के रिसाव के दबाव में अपने गुणवत्ता खो रहे हैं। संपूर्ण विश्व में समुद्र तटों का प्रदूषण बढ़ रहा है ।इसका तटवर्ती जल ग्रीन हाउस क्रियाकलाप से प्रदूषित हो रहा है तथा अंतरिक्ष में विभिन्न देश तेजी से प्रयोग कर रहे हैं और उसे प्रदूषित कर रहे हैं।

प्रश्न 2. "साझी परंतु अलग-अलग जिम्मेवारियां"से क्या अभिप्राय है? हम इस विचार को कैसे लागू कर सकते हैं।

उत्तर- पर्यावरण संरक्षण को लेकर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के विचारधारा अलग-अलग हैं। उत्तर के विकसित देश पर्यावरण के मसले पर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस दशा में पर्यावरण आज मौजूद है। यह देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की भागीदारी बराबर हो। दक्षिण के विकासशील देशों का तर्क है, कि इस समय परिस्थितिकी को नुकसान अधिकांशतया विकसित देशों के औद्योगिक विकास से पहुंचा है। यदि विकसित देशों में पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो उन्हें उस नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी भी ज्यादा उठानी चाहिए। विकासशील देश अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और जरूरी है कि उन पर वे प्रतिबंध ना लगे जो विकसित देशों पर लगाए जाने हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के निर्माण, प्रयोग और व्याख्या में विकासशील देशों की विशिष्ट जरूरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए। 1992 में हुए पृथ्वी सम्मेलन में इस तर्क को मान लिया गया और इसे" साझी परंतु अलग-अलग जिम्मेदारियां" का सिद्धांत कहा गया।।

पर्यावरण संरक्षण से जुड़े निर्णय या सुझाव-

जलवायु परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमाचार के अनुसार सभी देश अपनी क्षमता के अनुरूप पर्यावरण के अपक्षय में अपनी-अपनी भूमिका निभाते हुए पर्यावरण सुरक्षा में योगदान दें। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे ज्यादा हिस्सा विकसित देशों का है। इसी कारण भारत ,चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से अलग रखा गया है।विकसित देशों के समाजों का वैश्विक पर्यावरण पर दबाव ज्यादा है और इन देशों के पास पर्याप्त प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय संसाधन है। ऐसे में टिकाऊ विकास के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में विकसित देश अपने विशेष जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे।

jharkhandlab.com

प्रश्न 3. वैश्विक तापवृद्धि क्या है?

उत्तर: -वैश्विक तापवृद्धि का मतलब है हमारी धरती के औसत तापमान में बढ़ोतरी। सामान्यतया प्राकृतिक कारणों से और मानवीय गतिविधियों से भी तापमान में बढ़ोतरी होती है। ये बढोतरी असल में वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढोतरी के कारण होती है। ग्रीन हाउस गैसें बहुत सारी होती है। उदाहरण के लिए कार्बनडाइऑक्साइड (CO2),CFC आदि।

प्रश्न4. एजेंडा-21 के मुख्य बिन्दु क्या-क्या है?

उत्तर: - एजेंडा- 21 के मुख्य विन्दु निम्नलिखित हैं

1. पर्यावरण और विकास के बीच सम्बंध के मुददों को समझा जाय।
(2) ऊर्जा का अधिक कुशल तरीके से इस्तेमाल किया जाए।
(3) किसानों को पर्यावरण सम्बन्धी जानकारी दी जाए।
(4) प्रदूषण फैलाने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जाए।
(5) कूड़े कचरे के प्रबन्ध के लिए राष्ट्रीय योजनाएँ तैयार की जाए।

प्रश्न 5. ओजोन परत में छिद्र का वर्णन करें।

उत्तर- वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जिसे ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों को सोख लेती है। यदि अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे धरती पर पहुंचने लगे तो त्वचा संबंधी अनेक बीमारियों का खतरा हो सकता है। यह पृथ्वी की सुरक्षा कवच है। परंतु उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर एक बड़ा छिद्र पाया गया है ,इसे ओजन परत में छेद होना भी कहते हैं। इससे परिस्थितिकी तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि रेफ्रिजरेटरों और अन्य कूलिंग उपकरणों में प्रयोग होने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन(CFC) गैसों में शामिल क्लोराइड गैस ओजोन परत के लिए काफी खतरनाक है।

प्रश्न 6- क्योटो प्रोटोकॉल का वर्णन करें।

उत्तर- क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। जो जलवायु परिवर्तन के संबंध में जापान के क्योटो शहर में 1997 को एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। परंतु इसमें विकसित और विकासशील देशों के बीच भारी मतभेद उत्पन्न हो गए। विकसित देश पर्यावरण के मसले पर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस दशा में पर्यावरण आज मौजूद है। यह देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण मेंहर देश की भागीदारी बराबर हो। विकासशील देशों का तर्क है कि परिस्थितिकी को नुकसान अधिकांशतया विकसित देशों के विकास से पहुंचा है। यदि विकसित देशों ने पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो उन्हें इस नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी भी ज्यादा उठानी चाहिए। विकासशील देश अभी औद्योगीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और जरूरी है कि उन पर वह प्रतिबंध ना लगे, जो विकसित देशों पर लगाए जाने हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के निर्माण, प्रयोग और व्याख्या में विकासशील देशों की विशिष्ट जरूरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए। जापान के क्योटो में1997 में इस प्रोटोकॉल में सहमति बनी।

प्रश्न 7. वैश्विक संपदा का अर्थ स्पष्ट करें।

उत्तर- वैश्विक संपदा अथवा साझी संपदा ऐसी संपदा को कहते हैं जिस पर समूह के प्रत्येक सदस्य का अधिकार हो। इसके पीछे मूल तर्क है कि ऐसे संसाधन की प्रकृति, उपयोग के स्तर और रख-रखाव के संदर्भ में समूह के हर सदस्य को अधिकार प्राप्त होंगे और समान जिम्मेदारी निभाने होंगे। संयुक्त परिवार का चूल्हा, चरागाह, मैदान, कुंआ, या नदी साझी संपदा का उदाहरण है। इसी तरह विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश की संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं। इसीलिए उनका प्रबंधन साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीयसमुदाय द्वारा किया जाता है। उन्हें वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत कहा जाता है। इसमें पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष शामिल है।

प्रश्न 8. वैश्विक पर्यावरण पर किन्हीं चार खतरों को बताइए।

उत्तर- वैश्विक पर्यावरण के चार खतरे-

(क) तापमान वृद्धि से तूफान,बाढ़,जंगल की आग,सुखा और लू के खतरे की आशंका बढ़ जाती है।

(ख) ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता के कारण ओजोन परत में छिद्र हो गया है, जिससे मानवीय जीवन में खतरा मंडरा रही है।

(ग) वैश्विक ताप वृद्धि के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप समुद्री जल की स्तर बढ़ रही है।

(घ) वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रो-फ्लोरो कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन जैसी गैसों की अधिकता के कारण अम्लीय वर्षा हो सकती है जो कृषि के लिए हानिकारक है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. संसाधनों की भू राजनीति की व्याख्या करें।

उत्तर- संसाधनों की भू- राजनीति, किसे, क्या, कब और कैसे सवालों से जुझती है। यूरोपीय ताकतों के विश्व व्यापी प्रसार का एक मुख्य साधन और मकसद संसाधन रहे हैं। संसाधनों से जुड़ी भू-राजनीति को पश्चिमी दुनिया ने ज्यादातर व्यापारिक संबंध, युद्ध तथा ताकत के संदर्भ में सोचा। पूरे शीत युद्ध के दौरान उत्तरी गोलार्ध के विकसित देशों ने इन संसाधनों की सतत आपूर्ति के लिए कई तरह के कदम उठाए। किसके अंतर्गत संसाधन दहन के इलाकों तथा समुद्री परिवहन मार्गों के इर्द-गिर्द सेना की तैनाती, महत्वपूर्ण संसाधनों का भंडारण, तथा बहुराष्ट्रीय निगम और अपने हित साधक, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को समर्थन देना शामिल है। पश्चिमी देशों के राजनीतिक चिंतन का केंद्रीय सरोकार यह था कि संसाधनों तक पहुंच अवाध रूप से बनी रहे। क्योंकि सोवियत संघ इस खतरे में डाल सकता था।

बीसवीं सदी के अधिकांश समय में विश्व की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर रही। तेल के साथ विपुल संपदा जुड़ी है और इसी कारण इस पर कब्जा जमाने के लिए राजनीतिक संघर्ष छिड़ता है। पेट्रोलियम का इतिहास युद्ध और संघर्षों का भी इतिहास है। यह बात पश्चिम एशिया और मध्य

Jharkhandlab.com

एशिया में सबसे स्पष्ट रूप से नजर आती है। पश्चिम एशिया खासकर खड़ी क्षेत्र विश्व के कुल तेल उत्पादन का 20% मुहैया कराता है। इस क्षेत्र में विश्व के ज्ञात तेल भंडार का 64 प्रतिशत हिस्सा मौजूद है और इस कारण यही इकलौता क्षेत्र है जो तेल की मांग में खास बढ़ोतरी होने पर उसकी पूर्ति कर सकता है। सऊदी अरब के पास विश्व के कुल तेल भंडार का एक चौथाई हिस्सा मौजूद है। सऊदी अरब विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है इसके बाद इराक दूसरे नंबर पर हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, जापान, चीन और भारत में इस तेल की खपत होती है। परंतु ये देश इस इलाके से बहुत दूरी पर है।

विश्व राजनीति के लिए पानी एक और महत्वपूर्ण संसाधन है। विश्व की कुछ भागों में साफ पानी की कमी हो रही है। साथ ही विश्व के हर हिस्सों में स्वच्छ जल समान मात्रा में मौजूद नहीं है। संभव है कि साझे जल संसाधन 21वीं सदी में युद्ध के कारण बने। जलधारा के उद्गम से दूर बसा देश उद्गम के नजदीक बसे हुए देश द्वारा इस पर बांध बनाने, इससे अधिक सिंचाई करने या प्रदूषित करने पर आपत्ति जताता है। देशों के बीच स्वच्छ जल संसाधनों को हथियाने या उनकी सुरक्षा करने के लिए हिंसक झड़पें हुई हैं। 1950-60 के दशक में इजराइल,सीरिया और जॉर्डन के बीच नदी जल को लेकर विवाद रहा। भारत-पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल बंटवारा, गंगा नदी जल बंटवारा का विवाद रहा। भारत-बांग्लादेश के बीच गंगा नदी, मुहरी नदी, तीस्ता नदी आदि का जल विवाद रहा। फिलहाल चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी की धारा मोड़ने और बांध बनाने की बात का भारत ने विरोध प्रकट किया है।

इस प्रकार बहुत से देशों के बीच नदियों के जल को लेकर विवाद है और उनके बीच सैन्य संघर्ष होते रहते हैं।

प्रश्न 2. मूलवासी लोगों और उनके अधिकारों के बारे में लिखें।

उत्तर- मूलवासी हम किसको कहेंगे, यह सवाल पर्यावरण,संसाधन और राजनीति को एक साथ जोड़ देती हैं। 1982 मे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मूलवासियों को ऐसे वंशज बताया गया जो किसी मौजूद देश में बहुत दिनों से रहते आ रहे थे, फिर किसी दूसरे संस्कृति या जातीय मूल के लोग विश्व के दूसरे हिस्से से उस देश में आये और उन लोगों को अधीन बना लिया। किसी देश के मूलवासी आज भी उस देश की संस्थाओं के अनुरूप आचरण करने से ज्यादा अपनी परंपरा, संस्कृति, रिवाज तथा अपने खास सामाजिक, आर्थिक ढर्रे पर जीवन-यापन करना पसंद करते हैं।

भारत सहित विश्व के विभिन्न हिस्सों में लगभग 30 करोड़ मूलवासी निवास करते हैं। फिलीपिन्स के कोरडिलेरा क्षेत्र में 20 लाख मूलवासी लोग रहते है। चिली में मापुशे नामक मूलवासियों की संख्या 10 लाख है। बांग्लादेश के चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में 6 लाख आदिवासी रहते हैं। उत्तर अमेरिका में मूलवासियों की संख्या 3 लाख 50 हजार है। पनामा नहर के पूरब में कुना नामक मूलवासी 50 हजार की तादाद में हैं औरउत्तरी सोवियत में ऐसे लोगों की संख्या लगभग 40 लाख है। दूसरे सामाजिक आन्दोलनों की तरह मूलवासी भी अपने संघर्ष, एजेंडा और अधिकारों की आवाज उठाते हैं।

मूलवासियों के अधिकार एवं मांगे निम्नलिखित है:-

(1) विश्व राजनीति में मूलवासियों की मांग है, कि उन्हें विश्व बिरादरी में बराबर का दर्जा मिले।

(2) सरकारों से इनकी मांग है कि उन्हें मूलवासी कौम के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय माना जाय।

(3) अपने मूल वास स्थान पर हक की दावेदारी में विश्वभर के मूलवासी यह जुमला इस्तेमाल करते हैं कि हम यहाँ अनंत काल से रहते चले आ रहे हैं। अतः हमें अपने मूल स्थान से नहीं हटाया जाय।

(4) मूलवासियों के आर्थिक संसाधन का अधिक दोहन न किया जाय।

(5) राजनीति में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसी संदर्भ में संविधान के द्वारा मूल वासियों(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) को राज्य विधानसभा एवं लोकसभा में आरक्षित स्थान आवंटित किया गया है तथा साथ ही उनकी कला, संस्कृति और भाषा को सरकार के द्वारा संरक्षण किया जाता रहा है।

1970 के दशक में विश्व के विभिन्न भागों के निवासियों के नेताओं के बीच संपर्क बढ़ा है तथा इससे इनके साझे अनुभवों और सरोकारों को एक शक्ल मिली है। 1975 में "वर्ल्ड काउंसलिंग आफ इंडिजिनस पीपल्" का गठन हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले इस परिषद को परामर्शदायी परिषद का दर्जा दिया गया। इसके अतिरिक्त आदिवासियों के सरोकारों से संबद्ध 10 अन्य स्वंयसेवी संगठनों को भी यह दर्जा दिया गया है।

प्रश्न-3. भारत के पावन वन प्रान्तर के बारेमें विवेचना करें।

उत्तरः -भारत में बहुत से पुराने समाजों में धार्मिक कारणों से प्रकृति की रक्षा करने का प्रचलन है। इस प्रथा में वनों के कुछ हिस्सों को काटा नहीं जाता है। ऐसा माना जाता है, कि इन स्थानों पर देवता अथवा पुण्यात्मा का वास होता है। इन्हें ही "पावन वन प्रान्तर या देवस्थान"कहा जाता है। इन पावन वन प्रान्तरों के देशव्यापी फैलाव का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है, कि देशभर की भाषाओं में इनके लिए अलग-अलग शब्द हैं। इन देव स्थानों को राजस्थान में वानी,कैंकड़ी और ओरान; झारखण्ड में जाहेरा थान और सारना; मेघालय में लिंगदोह; ' केरल में कावः उतराखण्ड में थान या देव भूमि और महाराष्ट्र में देव रहतिस आदि सैकड़ों नामों से जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े साहित्य मेंदेवस्थान के महत्व को अब स्वीकार किया जा रहा है। और इसे समुदाय आधारित संसाधन प्रबन्धन के रूप में देखा जा रहा है। देवस्थान को हम ऐसी व्यवस्था के रूप में देख सकते हैं। जिसके अंतर्गत पुराने समाज प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल इस तरह करते हैं, कि पारिस्थितिकीतंत्र का संतुलन बना रहे। कुछ अनुसंधानकर्ताओं का विश्वास है कि देवस्थान की मान्यता से जैव-विविधता और पारिस्थितिकी-संरक्षण में ही नहीं सांस्कृतिक वैविध्य को भी कायम रखने में मदद मिल सकती है। देव स्थान की व्यवस्था वन संरक्षण के विभिन्न तौर-तरीकों से सम्पन्न है और इस व्यवस्था की विशेषताएं साझी संपदा के संरक्षण की व्यवस्था से मिलीजुलती है। देवस्थान के महत्व का परंपरागत आधार ऐसे क्षेत्र की आध्यात्मिक अथवा सांस्कृतिक विशेषताएँ हैं।

हिन्दु समवेत् रूप से प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा करते हैं। जिसमें पेड़ और वन प्रान्तर भी शामिल हैं। बहुत से मंदिरों में का निर्माण देवस्थान में हुआ है। संसाधनों की विरलता नहीं

Jharkhandlab.com

प्रकृति के प्रति गहरी श्रद्धा ही वह आधार थी, जिसने इतने युगों से वनों को बचाए रखने की प्रतिबद्धता कायम रखी। बहरहाल हाल के सालों में मनुष्यों की बसावट के विस्तार ने धीरे-धीरे ऐसे देवस्थानों पर कब्जा कर लिया है।

नई राष्ट्रीय वन नीतियों के आने के साथ कई जगहों पर इन परंपरागत वनों की पहचान मंद पड़ने लगी है। देवस्थान के प्रबन्धन में एक कठिन समस्या तब आती है जब ऐसे स्थान का कानूनी स्वामित्व एक के पास हो और व्यावहारिक नियंत्रण किसी दूसरे के हाथ में हो; यानी कानूनी स्वामित्व राज्य का हो ,और व्यावहारिक- नियंत्रण समुदाय के हाथ में। इन दोनों के नीतिगत मानक अलग- अलग हैं और देवस्थान के उपयोग के उददेश्य में भी इनके बीच कोई मेल नहीं।

प्रश्न4: पर्यावरण के सम्बन्ध में भारत के पक्ष का वर्णन करें।

उत्तर- भारत प्रारंभ से ही संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है तथा उसका समर्थक है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी कार्यक्रमों में सक्रिय भाग लेता आया है और उसके कानूनों, नियमों तथा प्रस्तावों का पालन करता है। लेकिन वह सभी मुद्दों पर खुले मन से तथा पक्ष पात रहित दृष्टिकोण अपनाकर किसी भी घटना का विरोध या समर्थन करता है। उदाहरण के लिए भारत ने परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि को स्वीकार नहीं किया है। यही दृष्टिकोण भारत ने पर्यावरण संबन्धी मुद्दों पर अपनाया है। पर्यावरण की रक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पास किए गए प्रस्तावों तथा सुझावों को भारत ने स्वीकारा है, परंतु कुछ प्रस्तावों का आंशिक रूप से विरोध भी किया है,जो उसके अनुसार विकासशील देशों के हित में नहीं समझे जाते तथा पश्चिमी विकसीत देशों द्वारा विकासशील देशों पर थोपे जाने के रूप में देखे जाते हैं।

भारत ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में निम्नलिखितपक्ष रखा है-

(क) भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल (1997) पर हस्ताक्षर किए और उसका अनुमोदन किया।

(ख) 2005 के जून में G-8 देशों की बैठक हुई। इसमें भारत ने ध्यान दिलाया कि विकासशील देशों में ग्रीन हाऊस गैसों की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर विकसीत देशों की तुलना में नाममात्र है। साझी परंतु अलग-अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत के अनुरूप भारत का विचार है कि उत्सर्जन दर में कमी करने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी विकसीत देशों की है; क्योंकि इन देशों ने एक लम्बी अवधि तक बहुत ज्यादा उत्सर्जन किया है।

(ग) संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत चर्चा चली कि तेजी से औद्योगिक होते देश जैसे ब्राजील,चीन और भारत नियमाचार (प्रोटोकॉल) की बाध्यताओं का पालन करते हुए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करें। परंतु भारत इस बात के खिलाफ है।उनका मानना है कि यह बात इस नियमाचार की मूल भावना के विरुद्ध है।

(घ) भारत सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरण से संबंधित वैश्विक प्रयासों में शिरकत कर रही है। उदाहरण के लिए भारत ने अपने "नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी" के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य कर दिया है।

(ड) 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। इसमें ऊर्जा के ज्यादा कारगर इस्तेमाल की पहल की गई है।

(च) 2003 के बिजली अधिनियम में पुनर्नवा (renewable) ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया है।

(छ) भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौते को अनुमोदन किया।

(ज) भारत का यह भी मानना है कि दक्षेस (SAARC) में शामिल देश पर्यावरण के प्रमुख वैश्विक मसलों पर एक समान राय बनावें ताकि उस क्षेत्र की आवाज को जोरदार ढंग से उठाया जाए।

Jharkhandlab.com

अध्याय - 9 वैश्वीकरण

बहु विकल्पीय प्रश्न

1. **वर्ल्ड सोशल फोरम(WSF) की पहली बैठक कब हुई?**
   a. 2000 b. 2001
   c. 2002 d. 2003

2. **भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर आधारित है?**
   a. समाजवाद b. साम्यवाद
   C. उदारवाद d. इनमें से कोई नहीं

3. **विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई**
   a. जनवरी 1956 b. जनवरी 1995
   c. फरवरी 1999 d. अप्रैल 2000

4. **वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई?**
   a. ब्राज़ील b. भारत
   c. अमेरिका d. केन्या

5. **वैश्वीकरण के कारण भारत का स्वरूप किस प्रकार का हो गया है?**
   a. वैश्विक गांव का b. मुख्य बाजार का
   c. अंतर्राष्ट्रीय बाजार का d. किसी का नहीं

6. **वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक नकारात्मक रूप से कौन प्रभावित हुए ?**
   a. गरीब b. पूंजीपति
   c. मध्यम वर्ग d. कोईनहीं

7. **निम्नलिखित में कौन वैश्वीकरण का कारक नहीं है?**
   a. प्रौद्योगिकी b. संचार साधन
   c. खेल d . पूंजी

8. **प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था ?**
   a. रेशम मार्ग b. सूती मार्ग
   c. उत्तराखंड d. दक्षिणापथ

9. **आईएमएफऔर विश्व बैंक कब से काम शुरू किया?**
   a. 1945 b. 1947
   c. 1951 d. 1972

10. **गिरमिटिया किसे कहा जाता था?**
    a. रोगियों को
    b. अनुबंधित मजदूरों को
    c. अंग्रेजों को
    d. एक प्रकार के पक्षी को

11. **" सोचो विश्व के संदर्भ में और देश का हित करो" यह कथन किस विद्वान का है?**
    a. अमर्त्य सेन b. यूनुस खान
    c. मनमोहन सिंह d. रोमिला थापर

12. **आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है?**
    a. औद्योगिक क्रांति b. समाजवादी क्रांति
    c. भौगोलिक क्रांति d. वाणिज्यिक क्रांति

13. **विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ ?**
    a. 1914 b. 1922
    c. 1927 d. 1929

14. **कॉर्न लॉ किस देश से संबंधित है ?**
    a. भारत b. ब्रिटेन
    c. अमेरिका d. ब्राजील

15. **भारत में वैश्वीकरण के जनक कौन थे?**
    a. नरसिम्हा राव b. जवाहरलाल नेहरू
    c. राजेंद्र प्रसाद d. मनमोहन सिंह

बहु विकल्पीय उत्तर

1b2c 3b 4a 5a 6a 7c 8a 9a 10b 11c 12d 13d 14b 15d

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

1. **वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं?**

उत्तर: वैश्वीकरण का तात्पर्य विश्व के विभिन्न समाजों और अर्थव्यस्थाओं के एकीकरण से है। यह उत्पादों, विचारों, दृष्टिकोणों, विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं आदि के आपसी विनिमय के परिणाम से उत्पन्न होता है।

2. **सामाजिक सुरक्षा कवच से आपका क्या अभिप्राय है?**

उत्तर : आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को वैश्वीकरण के बुरे प्रभावों से बचाने के संस्थानिक उपाय।

3. **सांस्कृतिक समरूपता तथा सांस्कृतिक विभिन्नता से आपका क्या आशय है?**

उत्तर सांस्कृतिक समरूपता विश्व संस्कृति के नाम पर दूसरे देशों पर अमेरिका की संस्कृति लादना।

सांस्कृतिक विभिन्नता में विभिन्न संस्कृतियाँ दूसरे संस्कृतियों की अच्छी बातों को अपनी संस्कृति में शामिल करती है जिस कारण प्रत्येक संस्कृति अनूठी बन जाती है।

Jharkhandlab.com

4. सोशल फोरम के तहत कौन-कौन से समूह वैश्वीकरण का विरोध कर रहे हैं?

उत्तर : मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी,, मजदूर तथा युवा कार्यकर्ता आदि एकजुट होकर वैश्वीकरण का विरोध कर रहे हैं।

5. बहुराष्ट्रीय निगम से आप क्या समझते हो?

उत्तर वह कम्पनी जो एक से अधिक देशों में आर्थिक गतिविधियां चलाती हैं।जैसे कोका कोला, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट आदि

6. क्या साम्राज्यवाद ही वैश्वीकरण है ?

उत्तर नहीं, सामाज्यवाद में एक देश अपनी सीमा के बाहर के क्षेत्र के लोगों पर आर्थिक तथा राजनीतिक कब्जा करता है जबकि वैश्वीकरण में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता है।

7. कल और आज के वैश्वीकरण में क्या अन्तर है?

उत्तर पहले के समय में वस्तु तथा तैयार माल का आवागमन होता था। परन्तु अब व्यक्ति ,वस्तु ,विचार ,पूंजी, तकनीक तथा कच्चे अन्तर्राष्ट्रीय माल का भी आवागमन होता है।

8. दो महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं के नाम बताइए?

उत्तर- क. मुद्रा कोष।

ख. विश्व व्यापार संगठन।

9. भारत वैश्वीकरण को किन तरीको से प्रभावित कर रहा है। कोई दो कारण दीजिए?

उत्तर- क. भारतीय लोग विदेशों में जाकर अपनी संस्कृति व रीति-रिवाज को बढ़ावा दे रहे है।

ख. भारत में उपलब्ध सस्ते श्रम ने विश्व को आकर्षित किया है।

10. वैश्वीकरण से विश्व में वस्तुओं के व्यापार पर क्या प्रभाव हुआ है?

उत्तर. क. विभिन्न देशों में अपने आयात प्रतिबंधों मेंकमी।

ख. पूंजी के आवागमन पर रोक कम हुई।

11. "यूट्यूब वैश्वीकरण का प्रतीक नहीं है" तथा "होंडा मोटर बाइक्स वैश्वीकरण का प्रतीक है" इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य?

उत्तरः यूट्यूब वैश्वीकरण का प्रतीक है जबकि होंडा मोटर बाइक्स वैश्वीकरण का प्रतीक नहीं है।

12. आर्थिक बैश्विकरण के तीन तत्व लिखें।

उत्तरः क. अंतर्राष्ट्रीय व्यापर

ख. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

ग. पूंजी बाजार प्रवाह।

13. "ग्लोकल" पदबंध का अर्थ क्या होता है?

उत्तरः ग्लोकल पदबंध का आशय है विदेशी वस्तुओं को अपनाने के साथ-साथ स्वदेशी भी बने रहना।

14. भारत और चीन को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट क्यों दी गई है?

उत्तर भारत और चीन को क्योटो प्रोटोकॉल के बाध्यताओं से विकासशील देश होने के कारण छूट प्राप्त है।

15. खुली अर्थव्यवस्था क्या है?

उत्तर खुली अर्थव्यवस्था का आशय होता है अर्थव्यवस्था पर राज्य का कम से कम हस्तक्षेप तथा विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ स्वतंत्र लेनदेन व्यवस्था।

16. उदारीकरण क्या है?

उत्तर उदारीकरण एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति और विचार को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने अथवा आने जाने की छूट हो। उदारीकरण को वैश्वीकरण का सैद्धांतिक पक्ष कहा जा सकता है।

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है?

उत्तरः वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का योगदान महत्वपूर्ण है। वैश्वीकरण के विकास में सबसे अधिक योगदान प्रौद्योगिकी का ही माना जाता है क्योंकि इसने ही विश्व के लोगों को इतना करीब ला दिया की पूरी विश्व एक वैश्विक गांव के रूप में उभर कर सामने आई।

निम्न बिंदुओं से वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी के योगदान को समझा जा सकता है।

1. प्रौद्योगिकी प्रगति ने सारे संसार में लोगों वस्तुओं पूंजी और विचारों के प्रवाह में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि की है।
2. प्रौद्योगिक की प्रगति के कारण आज संसार के किसी भी भाग में बैठा व्यक्ति हजारों लाखों मील की दूरी पर घटने वाली घटनाओं से तुरंत ही परिचित हो जाता है। लगता है कि वह उसी स्थान पर मौजूद है और उसके आसपास की घटना घट रही हैं।
3. प्रौद्योगिक में हुई प्रगति के कारण अपने घर में बैठा व्यक्ति सारे संसार से जुड़ा हुआ महसूस करता है वह घर बैठे ही विदेशों से व्यापार करता है धन का भुगतान करता है। आपस में बातचीत करता है यहां तक कि सम्मेलनों तथा बैठकों में भागीदारी भी करता है।
4. प्रौद्योगिकी विभिन्न देशों की संस्कृति की संस्कृतियों टीवी तथा इंटरनेट के माध्यम से अंतः क्रिया करने में भूमिका निभाई है और वे एक दूसरे को ऐसे प्रभावित करने लगी है जैसे लोग प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर बातचीत से प्रभावित होते हैं।

ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वैश्वीकरण के प्रसार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान प्रौद्योगिकी का है।

2. नव उपनिवेशवाद को परिभाषित करें।

उत्तर नव उपनिवेशवाद एक ऐसी अवधारणा है, जिसके अंतर्गत एक समृद्ध एवं शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर सीधे आर्थिक शोषण ना करके उसका अप्रत्यक्ष रूप से शोषण करता है। ऐसा वह कमजोर देश को आर्थिक सहायता देकर उस देश की नीतियों तथा उस देश में होने वाली राजनीतिक गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करता है तथा उन नीतियों एवं गतिविधियों को अपने लाभ हेतु लागू करता है अतः ऐसा माना जा सकता है कि नव उपनिवेशवाद पुराने उपनिवेशवाद का एक नया रुप है।

Jharkhandlab.com

3. वैश्वीकरण के आर्थिक पक्ष से आप क्या समझते हैं?

उत्तरः वैश्वीकरण के आर्थिक पक्ष से तात्पर्य हैवैश्वीकरण द्वारा विश्व में आने वाले बदलाव। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने दुनिया भर में कई प्रकार के महान आर्थिक परिवर्तन उत्पन्न कर दिए जिससे विश्व का आर्थिक ढांचा ही बदल गया।

आमतौर पर वैश्वीकरण के आर्थिक पक्ष के आधारित आधारभूत पहलू निम्नलिखित है ;

क. वस्तुओं सेवाओं और पूंजी तथा तकनीक का विश्वास विश्व में बाधा रहित प्रवाह का होना।

ख. वैश्विक आर्थिक संस्थाओं अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का बढ़ता हुआ प्रभाव।

ग. विश्व में बढ़ती आर्थिक समृद्धि के साथ बढ़ती आर्थिक विषमता बहुराष्ट्रीय कंपनी का फैलता हुआ प्रभाव।

4. वैश्वीकरण के विरोध में किन्हीं चार कारणों को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर वैश्वीकरण के विरोध के लिए निम्नलिखित तर्क दिया जाता है कि वर्तमान वैश्वीकरण विश्वव्यापी पूंजीवाद की एक विशेष व्यवस्था है जो अमीरों को और अमीर बना रही है और गरीबों को और गरीब बना रही है

दक्षिणपंथी आलोचक इसके राजनीतिक आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव के कारण चिंतित है इनका कहना है कि राजनैतिक रूप से राज्य के कमजोर होने से जनता को नुकसान होता है।

कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक निर्भरता का होना आवश्यक है क्योंकि वैश्वीकरण ने संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का भी कार्य कियाहै।

5. विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके मुख्य घटकों को लिखें।

उत्तर विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव का अर्थ है मानव समाज में इस भावना का विकास होना की सारे संसार के लोग वे चाहे किसी भी देश या क्षेत्र में रहते हों आपस में एक ही परिवार के सदस्य है और उन्हें एक-दूसरे से सहयोग करके ही जीवन व्यतीत करना है।

विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं।

1. संचार तथा परिवहन के शीघ्रगामी साधन जिन से व्यक्तियों, वस्तुओं तथा पूँजी के प्रवाह में गति आई है और पारस्परिक जुड़ाव संभव हुआ।
2. सूचना प्रसारण के साधन जैसे की टी.वी., इंटरनेट, कंप्यूटर आदि जिनके कारण संसार के लोग प्रत्येक घटना के बारे में सूचित रहते है और आपस में जुड़े महसूस करते हैं।
3. सामान्य अर्थव्यवस्था अर्थात बाजार पर आधारित अर्थव्यवस्था जो अब सभी देशों ने अपना ली है।
4. विश्वव्यापी समस्याओं जैसे की आतंकवाद, एड्स की बीमारी, प्राकृतिक आपदाएँ जैसे समुद्री तूफान, भूकंप आदि जिनका समाधान कोई देश अकेले नहीं कर सकता।।इस प्रकार के गंभीर समस्यायों के लिए एक दुसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है।

6. वैश्वीकरण के संदर्भ में विकासशील देशों में राज्य की बदलती भूमिकाको लिखें।

उत्तर वैश्वीकरण ने विकासशील देशों में राज्य की भूमिका को बहुत बहुत हद तक प्रभावित किया है। राज्य अब न्यूनतम हस्तक्षेपकारी धारणा का पालन करती है और मुख्य रूप से कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना तक ही सीमित है, इस प्रकार राज्य अब कई ऐसे लोग कल्याणकारी कार्यों का छोड़ दी है जिनका लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक तलाश करना था। लोक कल्याणकारी राज्य की जगह अब बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक हो गया है। आज विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय निगमों की भूमिका में वृद्धि हुई है जिससे सरकारों के अपने दम पर फैसले लेने की क्षमता में भी भारी कमी आई। ऐसा कहा जा सकता है कि कुछ अर्थों में वैश्वीकरण ने राज्य की सत्ता में बढ़ोतरी की है अब राज्य को आधुनिक प्रौद्योगिकी प्राप्त है जिसके माध्यम से वे अपने नागरिकों के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित कर सकती है। इसके माध्यम से ज्यादा बेहतर ढंग से अब कार्य करने में सक्षम है उनकी क्षमता में वृद्धि हुई है इस प्रकार नई प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप राज्य अब पहले की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली दिखलाई पड़ती है। परिणास्वरूप राज्य अब काफी हद तक अपने स्वरूप को बदलते हुए अपनी भूमिका में भी परिवर्तन कर ली है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. वैश्वीकरण क्या है ? वैश्वीकरण के गुणों और दोषों को विस्तार पूर्वक लिखें

उत्तरः वैश्वीकरण का तात्पर्य विश्व के विभिन्न समाजों और अर्थव्यस्थाओं के एकीकरण से है। यह उत्पादों, विचारों, दृष्टिकोणों, विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं आदि के आपसी विनिमय के परिणाम से उत्पन्न होता है।

वैश्वीकरण के गुण / लाभ अथवा महत्व :-

A. नवीन तकनीकों का आगमन

वैश्वीकरण द्वारा विदेशी पूँजी के निवेश मे वृद्धि होती है एवं नवीन तकनीकों का आगमन होता है, जिससे श्रम की उत्पादकता एवं उत्पाद की किस्म में सुधार होता है।

B. जीवन स्तर में वृद्धि

वैश्वीकरण से जीवन-स्तर मे वृद्धि होती है, क्योंकि उपभोक्ता को पर्याप्त मात्रा मे उत्तम किस्म की वस्तुएँ न्यूनतम मूल्य पर मिल जाती हैं।

C. विदेशी विनियोजन

वैश्वीकरण के विकसित राष्ट्र अपनी अतिरिक्त पूँजी अर्द्धविकसित एवं विकासशील राष्ट्रों मे विनियोग करते है। विदेशी पूँजी के आगमन से इन देशों का विनियोग बड़ी मात्रा मे हुआ है।

D. विदेशों में रोजगार के अवसर

वैश्वीकरण से एक देश के लोग दूसरे देशों मे रोजगार प्राप्त करने में सक्षम होते हैं।

E. विदेशी व्यापार मे वृध्दि

आयात-निर्यात पर लगे अनावश्यक प्रतिबन्ध समाप्त हो जाते है तथा संरक्षण नीति समाप्त हो जाने से

Jharkhandlab.com

विदेशी व्यापार मे पर्याप्त वृद्धि होती है।

F. **अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग मे वृध्दि**

जब वैश्वीकरण अपनाया जाता है, तो आर्थिक सम्बंधों मे तो सुधार होता ही है, साथ ही राजनीतिक सम्बन्ध भी सुधरते है । आज वैश्वीकरण के कारण भारत के अमेरिका, जर्मनी एवं अन्य यूरोपीय देशों से सम्बन्ध सुधर रहे हैं।

G. **तकनीकी ज्ञान में बढ़ोतरी**

तीव्र आर्थिक विकास वैश्वीकरण से प्रत्येक राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों से तकनीकी ज्ञान के आदान-प्रदान का अवसर मिलता है।

H.. **विदेशी मुद्रा कोष मे वृद्धि**

जिस राष्ट्र का उत्पादन श्रेष्ठ किस्म का, पर्याप्त मात्रा होता है, उसका निर्यात व्यापार तेजी से बढ़ता है। परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा कोष मे वृद्धि होती है एवं भुगतान सन्तुलन की समस्या का निदान होता है।

I. **उत्पादकता मे वृद्धि**

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के कारण देश मे अपनी वस्तुओं की मांग बनाये रखने एवं निर्यात मे सक्षम बनने के लिए देशी उद्योग अपनी उत्पादकता एवं गुणवत्ता मे सुधार लाते है। भारत मे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, कार उद्योग, टेक्सटाइल उद्योग ने इस दिशा मे प्रभावी सुधार किया है।

वैश्वीकरण के दोष (हानियाँ) एवं दुष्परिणाम :

A. **आर्थिक असन्तुलन**

वैश्वीकरण के कारण विश्व मे आर्थिक अन्तुलन पैदा हो रहा है। गरीब राष्ट्र अधिक गरीब एवं अमीर राष्ट्र अधिक सम्पन्न हो रहे हैं। इसी प्रकार देश मे भी गरीब एवं अमीर व्यक्तियों के बीच विषमता बढ़ रही हैं।

B. **देशी उधोगों का पतनः**

वैश्वीकरण के कारण स्थानीय उधोग धीरे-धीरे बन्द होते जा रहे हैं। विदेशी माल की प्रतियोगिता के सामने देशी उधोग टिक नही पाते हैं। उनका माल बिक नही पाता है या घाटे मे बेचना पड़ता है। परिणामस्वरुप कई उद्योग बंद होने के कगार पर हैं या बंद हो गए हैं।

C. **राष्ट्र प्रेम की भावना को आघातः**

वैश्वीकरण राष्ट्र प्रेम एवं स्वदेश की भावना को आघात पहुँचा रहा है। लोग विदेशी वस्तुओं का उपभोग करना शान समझते है एवं देशी वस्तुओं को घटिया एवं तिरस्कार योग्य समझते हैं।

D. अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं का दबाव अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, गैट (GATT) आदि अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के दबाव में सरकार काम कर रही हैं। हितों की अवहेलना करके सरकार को इनकी शर्तें माननी पड़ती हैं। भारत जैसे राष्ट्र को अपनी आर्थिक, वाणिज्यिक एवं वित्तीय नीतियाँ इन संस्थाओं के निर्देशों के अनुसार बनानी पड़ रही हैं।

E. **आर्थिक परतन्त्रता**

वैश्वीकरण अर्द्धविकसित एवं पिछड़े हुए राष्ट्रों को विकसित राष्ट्रों का गुलाम बना रहा है। इसके कारण पिछड़े हुए राष्ट्र अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्रों की हर उचित-अनुचित बात को बनाने के लिए मजबूर हो रहे है।

F. **घातक अन्तर्राष्ट्रीय कानून**

अन्तर्राष्ट्रीय पेटेन्ट कानून, वित्तीय कानून, मानव सम्पदा अधिकार कानूनों का दुरूपयोग किया जा रहा है। पेटेन्ट की आड़ में बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ शोषण कर रही है। कई परम्परागत उत्पादन पेटेन्ट के अंतर्गत आने के कारण महँगे हो गए है।

G. **विलासिता के उपयोग मे वृद्धि**

वैश्वीकरण के कारण पाश्चात्य राष्ट्रों मे प्रचलित विलासिता के साधन का भारतीय बाजारों में निर्बाध प्रवेश हो गया है। इससे सांस्कृतिक पतन का खतरा बढ़ गयाहै।

2. वैश्वीकरण की क्या आर्थिक परिनीतियां हुई हैं ?इस संदर्भ में वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर वैश्वीकरण का सर्वाधिक स्पष्ट प्रभाव किसी भी राष्ट्र के आर्थिक क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ती है। वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में बढ़ोतरी हुई है । इस प्रकार दुनिया में आर्थिक व्यापार पर अब पहले से कहीं कम प्रतिबंध है व्यवहारिक पटल पर इसका यह अर्थ है कि धनी देश अपना धन अपने देश की जगह कहीं औरभी निवेश कर सकते हैं खासकर विकासशील देशों में जहां उन्हें ज्यादा मुनाफा की संभावना रहती है। वैश्वीकरण के कारण पर्यटकों के सामने राष्ट्र की सीमाओं की बाधा नहीं रही। कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़ी सेवाओं का विस्तार इसका उदाहरण है विकसित देश अपनी वीजा नीति के जरिए अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को बड़ी सावधानी से बनाए रखते हैं ताकि दूसरे देशों के नागरिक रोजगार के तलाश में आसानी से उनके देश में ना प्रवेश कर जायें।

वैश्वीकरण के परिणाम विश्व के विभिन्न भागों में अलग-अलग हुए हैं आर्थिक वैश्वीकरण के कारण पूरे विश्व में जनमत गहराई से बढ गया है, सरकारें अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रही हैं. और इससे सामाजिक न्याय से संबंध रखने वाले लोग चिंतित हैं उनका कहना है कि वैश्वीकरण से आबादी की एक बहुत छोटे तबके को फायदा होगा जबकि एक बड़ा वर्ग और जनकल्याण जैसे शिक्षा स्वास्थ्य सफाई की सुविधा आदि के लिए सरकार पर आश्रितहै, बदहाल हो सकते हैं । सामाजिक न्याय के समर्थक इस बात पर बल देते हैं कि कुछ संस्थानिक उपाय किए जाने चाहिए या सामाजिक सुरक्षा कवच तैयार किया जाना चाहिए ताकि जो लोग आर्थिक दृष्टि से कमजोर है उन पर वैश्वीकरण के दुष्प्रभाव ना पड़े जबकि विश्व के अनेक लोगों की मान्यता है कि गरीब और गरीबी पर पहुंच जाएंगे। कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसे उपनिवेशीकरण की संज्ञा तक दे डाली है।

वैश्वीकरण का भारत परप्रभाव

आर्थिक वृद्धि - 1991 के बाद से हमने देखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में काफी वृद्धि हुई है। अगर हम पुराने आंकड़ों को देखें तो 1950 से 1980 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 3.5% थी। लेकिन 2002 और 2012 के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था 7% से 8% की गति से बढ़ी। इसका मतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय लोगों को वैश्वीकरण से लाभ हुआ हैं।

रेमिटेंस (Remittance) - विदेशों में रहने वाले भारत के नागरिकों द्वारा भारत को भेजा जाने वाला धन, जिसे हम प्रेषण (Remittance) कहते हैं। 1991 में, 2.1 बिलियन डॉलर

Jharkhandjac.com

का रेमिटेंस भारत में आया, लेकिन 2017 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में रेमिटेंस, 68 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। आज भारत दुनिया में रेमिटेंस का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है।

निवेश – भारत में विदेशी निवेश की वृद्धि बहुत तेजी से हुई है। 1991 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) भारत के GDP का केवल 0.1% था। लेकिन आज प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) भारत की जीडीपी का 2% तक पहुंच चुका है।

रोजगार - वैश्वीकरण के कारण भारत में लाखों नई नौकरियां पैदा हुई है। जैसे आउटसोर्सिंग वैश्वीकरण प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है। आउटसोर्सिंग में, एक कंपनी बाहरी स्रोतों से नियमित रूप से सेवा प्राप्त करती है, ज्यादातर अन्य देशों से, जो देश के कानूनी सलाह, विज्ञापन, IT सर्विसेज, और अन्य, सेवाओं देश के भीतर प्राप्त करती है।

3. भारत में वैश्वीकरण का विरोध होने का प्रमुख कारणों की विवेचना करें।

उत्तर भारत ने वैश्वीकरण के विकास में योगदान दिया है परंतु इसके साथ ही भारत में इसका विरोध भी दिखलाई पड़ता है जिसकी निम्नलिखित कारण माने जा सकते हैं

a. भारत के वामपंथी दल वैश्वीकरण का विरोध करते हैं क्योंकि इसे वे पूंजीवादी के प्रसारण तथा विस्तार का एक साधन मानते हैं।

b. भारत में कई वर्गों का यह मानना है कि वैश्वीकरण ने भारतीय संस्कृति पर नकारात्मक प्रभाव डाला है जिससे भारतीय संस्कृति का पाश्चात्यकरण होता जा रहा है जैसे भारत में वैलेंटाइन डे जैसे दिवस वर्तमान में मनाए जा रहे हैं जो भारतीय संस्कृति से बिल्कुल विपरीत है।

c. दक्षिणपंथी संगठन तथा कुछ समाजसेवी संस्थाएं भारत में टीवी पर विदेशी चैनलों के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं उनके अनुसार विदेशी चैनल विदेशी संस्कृति का प्रसारण करते हैं और कई बार भारत में ऐसे दृश्यों का प्रसारण करते हैं जिससे भारतीय युवा पीढ़ी पर बुरा प्रभाव पड़ता है

d. भारत में कई वर्ग विदेशी निवेश को भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं मानते और उन पर 49% से अधिक विदेशी निवेश की स्वीकृति दिए जाने के प्रबल विरोधी हैं

e. भारत में ऐसी धारणा है वैश्विकरण के अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से विकसित पाश्चात्य देश अपने हितों की सुरक्षा करना चाहते हैं और गरीब तथा विकासशील देशों के हितों की ओर ध्यान नहीं देते इसलिए भारत जैसे विकासशील देश में वैश्वीकरण का विरोध हो रहा है।

4. वैश्वीकरण के संदर्भ में विकासशील देशों में राज्य की बदलती भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।

उत्तर: वैश्वीकरण के संदर्भ में विकासशील देशों में राज्य की बदलती भूमिका की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं।

1. राज्य की अपनी अर्थव्यवस्था का निर्धारण करने की क्षमता में बहुत कमी आई है क्योंकि आज सभी देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मुक्त व्यापार खुली प्रतियोगिता आदि को अपनाया गया है अतः इस दृष्टि से राज्य की भूमिका में बदलाव आया है।

2. राज्य द्वारा आयात- निर्यात के कड़े नियम बनाने तथा उन्हें लागू करने की भूमिका में परिवर्तन आया है क्योंकि वैश्वीकरण में व्यक्तियों वस्तुओं पूंजी तथा विचारों के तीव्र प्रवाह की धारणा आधारभूत है। अतः परमिट पासपोर्ट लाइसेंस आदि की बाधाएं कम हुई है और राज्य की दृष्टि से भूमिका कम हुई है।

3. आज विकासशील देशों में भी सामाजिक कल्याण सामाजिक सुरक्षा आदि की प्राथमिकताएं बाजार द्वारा निश्चित होती है सरकारों ने इन क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों को सीमित किया है।

4. वैश्वीकरण के वातावरण में राज्यों की अपनी निर्भरता बढ़ी है इससे राज्य की स्वेच्छापूर्वक राष्ट्रीय तथा विदेश नीति के निधरिण की शक्ति भी कम किया है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की नीतियों तथा निर्णय को मानने के लिए बाध्य किया है।

5. वैश्वीकरण ने राज्य की प्रभुत्ता तथा राष्ट्रीय सीमाओं पर हो रहे उसके नियंत्रण को प्रभावित किया है।

Jharkhandlab.com

PART - II

Jharkhandlab.com

Jharkhandlab.com

अध्याय - 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ

वस्तुनिष्ठ प्रश्न-

प्रश्न 1. भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया?
A. 1947 B. 1949
C. 1955 D. 1956

प्रश्न 2. किस भाषा के आधार पर 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था?
A. तेलुगू B. मलयालम
C. कन्नड़ D. तमिल

प्रश्न 3. भारतीय संघ में शामिल होने वाले अंतिम देशी रियासत कौन थी?
A. जम्मू कश्मीर B. हैदराबाद
C. जूनागढ़ D. बीकानेर

प्रश्न 4. संविधान के किस भाग में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है?
A. पांचवी अनुसूची B. छठी अनुसूची
C. सातवीं अनुसूची D. आठवीं अनुसूची

प्रश्न 5. लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है?
A. सुभाष चंद्र बोस B. भगत सिंह
C. सरदार वल्लभभाई पटेल D. लाला लाजपत राय

प्रश्न 6. देश के विभाजन के समय नोआखाली नामक स्थान चर्चा में क्यों थी?
A. भारत पर पाकिस्तानी आक्रमण के कारण
B. सांप्रदायिक दंगों के कारण
C. महामारी के कारण
D. भारत एवं पाकिस्तान के बीच जल विवाद के कारण

प्रश्न 7. किस ब्रिटिश योजना के द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया?
A. माउंटबेटन योजना B. कैबिनेट मिशन योजना
C. क्रिप्स मिशन योजना D. शिमला प्रस्ताव

प्रश्न 8. भारत का पहला उप- प्रधानमंत्री कौन था?
A. सरदार वल्लभभाई पटेल B. चंद्रशेखर
C. चौधरी चरण सिंह D. लालकृष्ण आडवाणी

प्रश्न 9. आंध्र प्रदेश अलग राज्य की मांग को लेकर पोट्टी श्रीरामुलू की मृत्यु कितने दिनों के भूख हड़ताल के बाद हो गई?
A. 56 दिन B. 54 दिन
C. 57 दिन D. 50 दिन

प्रश्न 10. सीमांत गांधी किसे कहा जाता है?
A. सरदार बल्लभ भाई पटेल
B. चंद्रशेखर
C. खान अब्दुल गफ्फार खान
D. जवाहरलाल नेहरू

प्रश्न 11. भारत कब आजाद हुआ?
A. 15 अगस्त 1946 B. 15 अगस्त 1947
C. 26 जनवरी 1950 D. 26 जनवरी 1947

प्रश्न 12. महात्मा गांधी की हत्या कब हुई?
A. 30 जनवरी 1948 B. 30 जनवरी 1947
C. 30 जनवरी 1949 D. 30 जनवरी 1950

प्रश्न 13. हैदराबाद के शासक को किस नाम से जाना जाता था?
A. राजा B. सुल्तान
C. बादशाह D. निजाम

प्रश्न 14. मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही नामक आंदोलन कब चलाया?
A. 1942 B. 1945
C. 1946 D. 1943

प्रश्न 15. आजादी के समय जम्मू कश्मीर का शासक कौन थे?
A. हरि सिंह B. शेख अब्दुल्ला
C. रंजीत सिंह D. मुफ्ती महबूबा

प्रश्न 16. संविधान के किस संशोधन के द्वारा 4 भाषाओं- बोडो, डोंगरी, मैथिली, तथा संथाली को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया?
A. 42वां संशोधन 1976 B. 44 वां संशोधन 1978
C. 91 वां संशोधन 2002 D. 92 वा संशोधन 2003

उत्तर-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	A	B	D	C	B	A	A	A	C	B	A	D	C	A	D

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. सीमांत गांधी किसे कहा जाता है?
उत्तर- खान अब्दुल गफ्फार खान

प्रश्न 2. राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
उत्तर- न्यायधीश फजल अली

प्रश्न 3. भारत में किसे लौह पुरुष की संज्ञा दी गई है और क्यों?
उत्तर- भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा दी गई है क्योंकि सरदार पटेल ने देशी रियासतों के भारत में विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा अद्भुत सूझबूझ का परिचय दिया।

प्रश्न 4. बल्लभ भाई पटेल को सरदार क्यों कहा जाता है?
उत्तर- वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि 1928 के बारदोली सत्याग्रह के समय ग्रामीण महिलाओं के द्वारा दी गई क्योंकि सरदार वल्लभभाई पटेल ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी।

प्रश्न 5. मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया द्वि-राष्ट्र सिद्धांत क्या है?
उत्तर- मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया द्वि-राष्ट्र सिद्धांत एक विभाजनकारी नीति है। इस सिद्धांत का आशय यह है कि हिंदू और मुसलमान दो अलग-अलग समुदाय हैं उन दोनों के हित अलग-अलग हैं अतः वे एक साथ नहीं रह सकते अतः उनके लिए दो अलग-अलग राष्ट्र की जरूरत है।

jharkhandlab.com

प्रश्न 6. विलय से पहले जम्मू कश्मीर रियासत के शासक कौन थे?

उत्तर- हरि सिंह

प्रश्न 7. धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत क्या है?

उत्तर- धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है किसी भी धर्म के लोगों के साथ भेदभाव ना करना। सभी धर्म के लोगों को सामाजिक, आर्थिक,राजनीतिक, कानूनी एवं सरकारी नीतियों में धर्म के आधार पर भेदभाव ना करना, धर्मनिरपेक्षता का मूल सिद्धांत है।

प्रश्न 8. भारत की आजादी से पहले किन्ही तीन देशी रियासतों के नाम लिखें?

उत्तर- जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर

प्रश्न 9. राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ?

उत्तर- 1953 ईस्वी

प्रश्न 10. राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार 1956 में भारतीय संघ में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया?

उत्तर- 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. द्वि-राष्ट्र सिद्धांत क्या था?

उत्तर- द्वि-राष्ट्र सिद्धांत का अर्थ है कि हिंदू और मुसलमान दो अलग-अलग समुदाय हैं, उन दोनों के हित अलग-अलग हैं, अतः वे एक साथ नहीं रह सकते। उनके लिए दो अलग- अलग राष्ट्र की जरूरत है। मुस्लिम लीग ने 1946 में अपने लाहौर अधिवेशन में इसी सिद्धांत के आधार पर मुस्लिम राज्य की मांग कर दी। यह एक विभाजनकारी नीति है।

इसी के तहत आगे चलकर 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही के नाम पर व्यापक आंदोलन चलाया। इसकी परिणति हिंदू-मुस्लिम दंगों के रूप में सामने आई। अंततः इसी का परिणाम था 14 और 15 अगस्त 1947 को विभाजन पाकिस्तान और भारत के रूप में इसके बाद देश में जगह-जगह दंगे फैल गया और हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन बन गया।

प्रश्न 2. जम्मू और कश्मीर के भारत में विलय की परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए!

उत्तर- आजादी के समय जम्मू कश्मीर की जनसंख्या 42 लाख थी जिसमें करीब 76% मुसलमान तथा शेष हिंदू, सिख, व बौद्ध थे। स्पष्ट तौर पर जम्मू और कश्मीर में मुस्लिम समुदाय का बहुमत था तथा पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए देशी रियासत भारत और पाकिस्तान दोनों से अलग रहकर स्वतंत्र देश बने रहने की नीति अपनाई लेकिन पाकिस्तान किसी भी कीमत पर जम्मू व कश्मीर को अपने अधीन करना चाहता था। अतः पाकिस्तान के कबाइलों ने पाकिस्तान की फौजियों की सहायता से 24 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। जब कश्मीर के महाराजा ने भारत के सैनिक मदद की गुहार की तो भारत ने यह तर्क देकर सेना भेजने से मना कर दिया कि महाराजा हरि सिंह पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर करें। अतः 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए तथा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया।

प्रश्न 3. हैदराबाद विलय के लिए भारत सरकार को पुलिस कार्यवाही क्यों करनी पड़ी?

उत्तर- जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ उस समय हैदराबाद में एक मुस्लिम शासक था, जिसे निजाम कहा जाता था परंतु वहां की बहुसंख्यक जनता हिंदू थी। वहां के जनता के द्वारा निजाम के अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया गया। इस आंदोलन में साम्यवादी पार्टी तथा कांग्रेस पार्टी द्वारा नेतृत्व किया गया। आंदोलन को दबाने के लिए निजाम ने अर्द्धसैनिक बलों का प्रयोग किया। अर्द्धसैनिक बलों ने जनता पर हिंसा एवं अत्याचार का प्रयोग किया जिससे वहां शांति व्यवस्था बिगड़ गई। भारत सरकार की चेतावनी के बाद जब निजाम ने सरकार की शर्तें नहीं मानी तो 13 सितंबर 1948 को भारत सरकार द्वारा निजाम के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई की गई। 18 सितंबर 1948 को निजाम की सेनाओं ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया तथा इसी के साथ हैदराबाद भारतीय संघ का अंग बन गया।

प्रश्न 4. राज्य पुनर्गठन आयोग से क्या तात्पर्य है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ?

उत्तर- राज्य पुनर्गठन आयोग से तात्पर्य है कि जब भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के बाद अन्य राज्यों में भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग जोर पकड़ी। अतः केंद्र सरकार ने इस समस्या के स्थाई और तर्कसंगत समाधान के लिए 1953 ईस्वी में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। इस आयोग में दो अन्य सदस्य के. एम. पाणिक्कर तथा हृदयनाथ कुंजरू थे।

आयोग ने विस्तृत अध्ययन के उपरांत 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने सैद्धांतिक तौर पर भाषा को राज्य गठन का आधार मानते हुए निम्न कसौटियों के आधार पर नए राज्यों के गठन की संस्तुति की-

1. उस क्षेत्र में भाषाई और सांस्कृतिक एकता की स्थिति क्या है?
2. प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से नए राज्य का गठन उचित है अथवा नहीं?
3. नए राज्य का गठन आर्थिक और वित्तीय स्थिति की दृष्टि से उचित है अथवा नहीं?

राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया तथा उन्हें लागू करने के लिए संसद द्वारा 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया।

प्रश्न 5. लोकतांत्रिक गणराज्य से आप क्या समझते हैं?

उत्तर- लोकतांत्रिक गणराज्य का तात्पर्य है कि ऐसा देश जहां देश को सार्वजनिक मामला माना जाता है। वहां के अध्यक्ष वंशानुगत ना होकर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जो एक निश्चित समय सीमा के लिए चुने जाते हैं और जनता के अनुरूप अगर काम ना करें तो उन्हें चुनाव के माध्यम से हटा दिया जाता है।

लोकतांत्रिक राज्य में सत्ता किसी एक व्यक्ति या वंशानुगत तरीके से सत्ता पर काबिज नहीं रहता बल्कि जनता के द्वारा चुने जाते हैं अर्थात लोकतांत्रिक राज्य में कोई भी व्यक्ति सत्ता के शीर्ष पर पहुंच सकता है या देश का अध्यक्ष बन सकता है।

यह एक सरकार का रूप है जिसके अंतर्गत देश का प्रमुख राजा नहीं बल्कि जनता के द्वारा चुने और जनता के लिए चुनी गई बहुमत की सरकार है।

प्रश्न 6. कांग्रेस ने भारत के विभाजन के प्रस्ताव को क्यों स्वीकार किया?

उत्तर- विभाजन की पृष्ठभूमि की शुरुआत अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति से होती है। इस नीति का उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन तभी स्थाई हो सकती है जब हिंदू और मुस्लिम आपस में विभाजित रहे तथा राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर बना रहे। 1905 में बंगाल का विभाजन, 1906 में ढाका में ब्रिटिश सहयोग से मुस्लिम लीग की स्थापना, 1909 में मुसलमानों के लिए केंद्रीय विधानमंडल में सांप्रदायिक आधार पर अलग सीटों का आरक्षण आदि, ब्रिटिश नीति के प्रमुख अंग थे। ब्रिटिश सरकार ने इस तथ्य को बार-बार रेखांकित किया कि कांग्रेसी हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है तथा मुस्लिम लीग मुसलमानों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है यद्यपि कांग्रेस ने तथा विशेषकर महात्मा गांधी ने हिंदू

Jharkhandlab.com

और मुसलमानों के बीच एकता स्थापित करने का प्रयास किया लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली।

ब्रिटिश शासन के उक्त विभाजनकारी नीति का तार्किक परिणाम अंत में जिन्ना के द्वि-राष्ट्र सिद्धांत के रूप में देखने में आया। इस सिद्धांत का आशय यह है कि हिंदू और मुसलमान दो अलग-अलग समुदाय हैं, उन दोनों के हित अलग-अलग हैं, अतः वे एक साथ नहीं रह सकते। उनके लिए दो अलग अलग राष्ट्र की जरूरत है। मुस्लिम लीग ने 1940 में अपने लाहौर अधिवेशन में इसी सिद्धांत के आधार पर मुस्लिम राज्य की मांग कर दी। इस मांग को समय-समय पर दोहराया गया तथा इसे ब्रिटिश सरकार का भी समर्थन प्राप्त था। 1946 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही के नाम पर व्यापक आंदोलन चलाया। इसकी परिणिति हिंदू-मुस्लिम दंगों के रूप में सामने आई। इसे देखते हुए कांग्रेस ने भारत के विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

प्रश्न 7. विलय- पत्र किसे कहते हैं?

उत्तर- भारत के आजादी के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत सारे देशी रियासतें थी। जिसे भारत के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयासों तथा वार्ता कूटनीति के द्वारा भारतीय क्षेत्र में स्थित अधिकांश रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में सफलता प्राप्त हुई। इनके लिए एक तरीका अपनाया गया था कि बातचीत के द्वारा देशी रियासत के शासकों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए राजी किया जाए। भारत में शामिल होने के लिए उन्हें एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने होते थे। इस दस्तावेज को ही विलय- पत्र के नाम से जाना जाता था।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. आजादी के बाद भारत में राष्ट्र निर्माण की क्या चुनौतियां थी? उनके समाधान के लिए क्या उपाय अपनाए गए?

उत्तर- राष्ट्र निर्माण किसी नए राष्ट्र में एकीकरण, राजनीतिक स्थिरता तथा विकास की सुनियोजित प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया राष्ट्रीय जीवन के लिए सार्थक कतिपय मूल्यों, विश्वासों तथा आदर्शों पर आधारित होती है। राष्ट्र निर्माण वैसे भी एक जटिल प्रक्रिया है लेकिन 1947 में आजादी के समय सांप्रदायिक आधार पर देश के विभाजन के कारण इसकी जटिलताएं अधिक बढ़ गई थी। आजादी के समय भारत में राष्ट्र निर्माण की तीन प्रमुख चुनौतियां उपस्थित थी:-

1. राष्ट्रीय एकीकरण की चुनौती- इसके अंतर्गत विभाजन के बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर विभिन्न देशी रियासतों को भारतीय राष्ट्र के अंतर्गत एकीकृत करना था। ऐसा करना भारत की क्षेत्रीय अखंडता के लिए अत्यंत आवश्यक था। मुख्य चुनौतियां थी कि भारत की सांस्कृतिक, भाषायी तथा धार्मिक विविधताओं के बावजूद राष्ट्रीय अखंडता को कैसे संरक्षित किया जाए।

   इस संबंध में नेहरू का दृष्टिकोण उदारवादी था। यह नीति विभिन्नताओं को समाप्त कर एकता को थोपने की नीति ना होकर विभिन्नताओं का सम्मान करते हुए समायोजन के द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण की नीति थी।

2. लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती- भारत में ब्रिटेन की तर्ज पर संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था की गई थी। नए संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों व स्वतंत्रताओं के साथ-साथ प्रत्येक वयस्क नागरिकों के लिए सार्वभौमिक मताधिकार की व्यवस्था पहली बार की गई थी। बहुदलीय प्रणाली को अपनाया गया तथा नियमित अंतराल पर स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के संपादन के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। जाति, धर्म तथा अन्य परंपरागत विशेषताओं से युक्त भारतीय सामाजिक परिवेश में नए लोकतंत्र की सफलता व मजबूती एक गंभीर चिंता का विषय थी।

   नेहरू उदारवादी लोकतंत्र के समर्थक थे उनका विश्वास था कि जैसे-जैसे समानता व न्याय पर आधारित विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी भारत में लोकतंत्र की जड़ें भी मजबूत होते जाएंगे।

3. समता व न्याय पर आधारित तीव्र विकास की चुनौती- भारत में राष्ट्र निर्माण की तीसरी चुनौती विकास की ऐसी प्रक्रिया को सुनिश्चित करना था कि उसका लाभ केवल कुछ उच्च वर्गों तक सीमित ना होकर समाज के सभी वर्गों को प्राप्त हो सके। संविधान में कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के विशिष्ट हितों की रक्षा के साथ-साथ नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत एक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था की गई थी।

इस संबंध में नेहरू लोकतांत्रिक समाजवाद की धारणा से प्रभावित थे। इसके तहत जमींदारी उन्मूलन, मिश्रित अर्थव्यवस्था तथा उसमें सरकारी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका, योजनागत विकास प्रक्रिया, कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण आदि उपायों द्वारा समता व न्याय पर आधारित विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया।

प्रश्न 2. आजादी के समय देशी रियासतों की क्या स्थिति थी? देशी रियासतों के भारत के विलय में सरदार वल्लभभाई पटेल की योगदान का मूल्यांकन कीजिए!

उत्तर- सरदार बल्लभ भाई पटेल के प्रयासों के कारण 15 अगस्त 1947 तक 4 देशी रियासतों मणिपुर, हैदराबाद, जूनागढ़ तथा जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी देशी रियासतों ने भारतीय संघ में शामिल होने की घोषणा कर दी थी । पटेल की सूझ-बूझ तथा प्रयासों से बाद में इन चारों देशी रियासतों को भी भारतीय संघ में शामिल किया गया। इसका विवरण निम्नलिखित है-

1. जूनागढ़- जूनागढ़ में बहुसंख्यक जनता हिंदू थी, लेकिन वहां के शासक मुस्लिम थे। जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया। जिसमें वहां के लोगों ने भारत में रहने की इच्छा व्यक्त की तथा इस प्रकार जूनागढ़ को 31 दिसंबर 1948 को भारत में शामिल कर लिया गया।

2. मणिपुर- मणिपुर के देशी राजा बोधचंद्र सिंह ने 1947 में ही भारतीय संघ में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। लेकिन जनता के दबाव में आकर उन्होंने जून 1948 में वहां की विधानसभा के चुनाव करा दिए तथा संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की। वास्तव में आजादी के बाद मणिपुर पहला राज्य था जहां पर सार्वभौमिक मताधिकार पर चुनाव कराए गए थे। नवनिर्वाचित विधानसभा में भारत के साथ विलय को लेकर विभिन्न समूहों में तीव्र मतभेद थे। लेकिन भारत सरकार ने मणिपुर के महाराजा को विलय के लिए सहमत कर लिया तथा विलय संधि पर सितंबर 1949 में हस्ताक्षर किए गए। तब से मणिपुर भारतीय संघ का अभिन्न अंग बन गया ।

3. हैदराबाद- यहां भी हिंदू जनसंख्या बहुमत में था लेकिन हैदराबाद का शासक एक मुस्लिम था जिसे निजाम कहा जाता था। हैदराबाद के निजाम ने 29 नवंबर 1947 को भारत सरकार के साथ यथास्थिति समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसका तात्पर्य था कि हैदराबाद की कानूनी स्थिति वही रहेगी जो 15 अगस्त 1947 को थी। इसी बीच हैदराबाद की जनता ने निजाम के अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन में साम्यवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया। आंदोलन को दबाने के लिए निजाम ने अर्द्धसैनिक बलों का प्रयोग किया। जनता पर हिंसा व अत्याचार किया गया जिससे वहां की शांति व्यवस्था बिगड़ गई। भारत सरकार की चेतावनी के बाद जब निजाम ने सरकार की शर्तें नहीं मानी तो 13 सितंबर 1948 को भारत सरकार द्वारा निजाम के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही की गई। 18 सितंबर 1948 को निजाम की सेनाओं ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया तथा इसी के साथ हैदराबाद भारतीय संघ का अंग बन गया।

Jharkhandlab.com

4. जम्मू व कश्मीर- यहां मुस्लिम आबादी बहुमत में थी लेकिन यहां के शासक महाराजा हरि सिंह हिंदू थे तथा यह पाकिस्तान की सीमा से लगी हुई देशी रियासत थी। राजा हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान दोनों से अलग रहकर स्वतंत्र देश बने रहने की नीति अपनाई लेकिन पाकिस्तान किसी भी कीमत पर जम्मू और कश्मीर को अपने अधीन करना चाहता था। अतः पाकिस्तान के कबाइलों ने पाकिस्तान की फौजियों की सहायता से 24 अक्टूबर 1947 को जम्मू और कश्मीर पर सैनिक हमला कर दिया। जब कश्मीर के महाराजा ने भारत से सैनिक मदद की गुहार की तो भारत ने यह तर्क देकर सेना भेजने से मना कर दिया कि महाराजा हरि सिंह पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर करें। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया तथा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया।

प्रश्न 3. 1947 में ब्रिटिश इंडिया के विभाजन के किन्ही तीन परिणामों की व्याख्या कीजिए!

उत्तर- 1947 में ब्रिटिश इंडिया के विभाजन का आधार संप्रदायिक था। मानव इतिहास में इस तरह के अचानक, अनियोजित तथा व्यापक स्तर पर जनसंख्या के विभाजन का कोई दूसरा उदाहरण उपलब्ध नहीं है। विभाजन के निम्न परिणाम सामने आए:-

1. सांप्रदायिक दंगे- जब विभाजन की प्रक्रिया लागू की गई तो कई स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे अधिक तीव्र हो गए। पाकिस्तान में बड़ी संख्या में हिंदू और सिखों की हत्या की गई। इसी तरह भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की हत्या हुआ। उनके विरुद्ध अत्याचार किए गए, उनकी संपत्ति लूट ली गई तथा कई अमानवीय अत्याचार भी किए गए जिनमें महिलाओं का अपहरण तथा उनका धर्म परिवर्तन भी शामिल था।

2. जनसंख्या का विस्थापन तथा शरणार्थियों की समस्या- विभाजन के परिणाम स्वरूप करीब 80 लाख जनता का दोनों देशों में विस्थापन हुआ। कई सिख और हिंदू सदियों से पाकिस्तानी क्षेत्रों में निवास कर रहे थे लेकिन विभाजन के परिणाम स्वरुप अपनी संपत्ति व जायदाद छोड़कर के भारत चले आए तथा अपने ही देश में शरणार्थी की स्थिति में आ गए।

   इसी तरह लाखों की तादाद में भारत के मुसलमान अपनी संपत्ति छोड़कर पाकिस्तान को पलायन कर गए, वहां उन्हें भी विभिन्न शरणार्थी कैंपों में रखा गया था।

   वे रेलगाड़ी, बसों तथा अधिकांशतः पैदल ही पाकिस्तान अथवा भारत की सीमा में गए। उनके साथ इस दर्द भरी यात्रा में हत्या, लूटपाट व बलात्कार जैसी घटनाएं भी हुई।

3. भारत और पाकिस्तान के बीच संपत्ति का विभाजन- इस विभाजन में भारत और पाकिस्तान के बीच जमीन और जनता का विभाजन ही नहीं हुआ बल्कि दोनों देशों के मध्य प्रशासनिक उपकरणों, वित्तीय दायित्वों, परिसंपदाओं तथा रक्षा उपकरणों का भी बंटवारा किया गया। यह कार्य बहुत जटिल था।

4. अल्पसंख्यकों की समस्या- देश के विभाजन के उपरांत भी दोनों देशों में अल्पसंख्यकों की समस्या बनी रही। पाकिस्तान में हिंदू और सिख विभाजन के बाद भी वहां के नागरिक बने रहें। पाकिस्तान को एक मुस्लिम राज्य घोषित करने के बाद उनकी स्थिति द्वितीय स्तर के नागरिक की हो गई। आज भी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को तमाम भेदभाव और यातनाओं का सामना करना पड़ता है।

दूसरी तरफ भारत में भी विभाजन के बाद बड़ी संख्या में मुसलमान बच गए थे जिन्होंने भारत को ही अपना देश माना। उनकी जनसंख्या विभाजन के बाद देश की कुल जनसंख्या की 12% थी। भारत के संविधान में भारत को पंथनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया तथा अन्य अल्पसंख्यकों की भांति मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भी संविधान में शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किए गए। भारत में मुसलमानों के साथ बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार प्रदान किए गए हैं।

jharkhandjcrt.com

अध्याय - 2 एक दलीय प्रभुत्व का युग

वस्तुनिष्ठ प्रश्न-

प्रश्न 1. चुनाव आयोग का गठन कब हुआ?
A. जनवरी 1949 B. जनवरी 1950
C. फरवरी 1949 D. फरवरी 1950

प्रश्न 2. भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे?
A. विनोद कुमार B. राजेंद्र प्रसाद
C. सुकुमार सेन D. विनोद पांडे

प्रश्न 3. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ?
A. 1883 B. 1884
C. 1885 D. 1886

प्रश्न 4. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे?
A. दादा भाई नौरोजी B. ए .ओ.ह्यूम
C. राजगोपालाचारी D. एस. एन. बनर्जी

प्रश्न 5. भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है?
A. एक- दलीय B. द्वि-दलीय
C. बहु-दलीय D. निर्दलीय

प्रश्न 6. निर्वाचन आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के द्वारा की गई है?
A. अनुच्छेद 321 B. अनुच्छेद 322
C. अनुच्छेद 324 C. अनुच्छेद 325

प्रश्न 7. भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे?
A. जवाहरलाल नेहरू B. सरदार वल्लभभाई पटेल
C. भीमराव अंबेडकर D. राजेंद्र प्रसाद

प्रश्न 8. कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य लागू किया गया?
A. कोलकाता अधिवेशन 1928
B. लाहौर अधिवेशन 1929
C. कराची अधिवेशन 1931
D. दिल्ली अधिवेशन 1932

प्रश्न 9. कामराज योजना कांग्रेस द्वारा कब लागू किया गया था?
A. 1959 B. 1960
C. 1963 D. 1962

प्रश्न 10. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया?
A. मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद
B. ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद
C. लेनिन का समाजवाद
D. गांधी का सर्वोदय समाजवाद

प्रश्न 11. कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ?
A. 1966 B. 1907
C. 1968 D. 1969

प्रश्न 12. प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कौन सा राज्य में बना?
A. तमिलनाडु B. आंध्र प्रदेश
C. उड़ीसा D. केरल

प्रश्न 13. भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का कब अवसर मिला?
A. 1952 के पहले चुनाव के बाद
B. 1957 के दूसरे चुनाव के बाद
C. 1962 के तीसरे चुनाव के बाद
D. 1967 के चौथे चुनाव के बाद

प्रश्न 14. भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई?
A. 1950 B. 1951
C. 1980 D. 1981

प्रश्न 15. किस राजनीतिक दल ने भारत में पूंजीवाद तथा खुले बाजार की अर्थव्यवस्था का समर्थन किया?
A. स्वतंत्र पार्टी B. भारतीय जनता पार्टी
C. कांग्रेस पार्टी D. समाजवादी पार्टी

प्रश्न 16. भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना कब हुई थी?
A. 1948 B. 1949
C. 1950 D. 1951

प्रश्न 17. भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे?
A. श्यामा प्रसाद मुखर्जी B. लालकृष्ण आडवाणी
C. अटल बिहारी बाजपेयी D. मुरली मनोहर जोशी

उत्तर-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
B	C	C	B	C	C	A	B	C	D	B	D	D	C	B	D	A

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. एक दलीय प्रभुत्व किसे कहते हैं?
उत्तर- किसी भी देश में बहुत सारे दलों का होना, परंतु बहुत सालों तक एक ही पार्टी का वर्चस्व होना एक दलीय प्रभुत्व कहलाता है।

प्रश्न 2. प्रथम आम चुनाव में कौन सी पार्टी प्रमुख विपक्ष पार्टी के रूप में उभरी?
उत्तर- भारतीय साम्यवादी पार्टी।

प्रश्न 3. भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे?
उत्तर- सरदार वल्लभभाई पटेल

प्रश्न 4. 1952 के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी तथा भारतीय जन संघ के चुनाव चिन्ह क्या है?
उत्तर- 1952 के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह दो बैलों की जोड़ी थी और भारतीय जनसंघ के चुनाव चिन्ह दीपक था।

प्रश्न 5. लोकतांत्रिक चुनाव में संसार में पहली कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार कब और कहां बनी?
उत्तर- 1957 ई०, केरल।

प्रश्न 6. भारत में 1977 के चुनाव बाद किसे प्रधानमंत्री बनाया गया था?
उत्तर- मोरारजी देसाई।

प्रश्न 7. भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे?
उत्तर- मौलाना अबुल कलाम आजाद।

jharkhandlab.com

प्रश्न 8. राजग का पूरा नाम बताइए!

उत्तर- राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन।

प्रश्न 9. कामराज योजना का क्या उद्देश्य था?

उत्तर- कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण अपनी सरकारी सेवा छोड़कर कांग्रेस संगठन के लिए काम करें ताकि कांग्रेस को फिर से मजबूती मिल सके।

प्रश्न 10. भारत के चार राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखिए!

उत्तर- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय समाजपार्टी ।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. भारत के चुनाव आयोग के गठन व कार्यों पर प्रकाश डालिए!

उत्तर- भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया गया है। अतः इसके लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अनुच्छेद 324 के अंतर्गत एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है।

इसका मुख्य कार्य लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव का संपादन करना है। इसके साथ ही स्थानीय निकायों के चुनाव तथा पंचायत चुनाव भी कराना इसका जिम्मेवारी है। चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए मतदाता सूची तैयार करता है तथा चुनाव आचार संहिता को लागू करता है।

चुनाव आयोग का मुखिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा जिसे संसद द्वारा महाभियोग लगाकर ही विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है। संविधान में चुनाव आयोग को सरकार के नियंत्रण से मुक्त रखने का प्रयास किया गया है ताकि वह बिना किसी सरकारी दबाव के अपने कार्यों का संपादन निष्पक्ष रूप से कर सके।

प्रश्न 2. लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है?

उत्तर- लोकतांत्रिक सरकार को व्यावहारिक रूप देने में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनितिक दल की निम्नलिखित भूमिका महत्वपूर्ण है:-

1. राजनितिक दल चुनाव लड़ते हैं और जन समस्याओं को देश के समक्ष रखकर राजनीतिक जागरूकता पैदा करते हैं।
2. लोकतंत्र में जनता की भागीदारी को बढ़ाते हैं जो कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है।
3. राजनीतिक दल सरकार व जनता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं तथा जनता की समस्याओं से सरकार को अवगत कराते हैं।
4. विपक्षी दल के रूप में राजनीतिक दल सरकार की तानाशाही व मनमानी पर रोक लगाते हैं।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में राजनितिक दलों की भूमिका लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए एक विशेष कड़ी हैं।

प्रश्न 3. सार्वभौमिक मताधिकार से आप क्या समझते हैं? इसका क्या महत्व है?

उत्तर- सार्वभौमिक मताधिकार का तात्पर्य है सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार। चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और लिंग के हो।

इसके निम्नलिखित महत्व है:-

1. यह समानता की अवधारणा पर आधारित है। जैसे समस्त वयस्क नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि के हो। किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर मताधिकार देने में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।
2. यह लोकतंत्र के महत्वपूर्ण आयामों में से एक है।
3. यह सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाता है तथा लोकतंत्र में जनता की गरिमा और महत्व को सुनिश्चित करता है।

प्रश्न 4. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत में कब अपनाया गया? इसके क्या लाभ हैं?

उत्तर- भारत में 1990 के दशक में मतदान के लिए चुनाव आयोग द्वारा पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया। 2004 के लोकसभा चुनावों से सभी निर्वाचन क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाने लगा है। इसके निम्नलिखित लाभ है:-

1. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रयोग से फर्जी मतदान पर बहुत हद तक रोक लग गई।
2. मतपत्र के स्थान पर अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है।
3. इससे मतगणना में आसानी होती है।
4. इससे किसी का वोट बदला नहीं जा सकता है।
5. यह सुविधाजनक एवं इससे समय का बचत होता है।

प्रश्न 5. भारतीय जनसंघ के क्या उद्देश्य थे?

उत्तर- भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 ईस्वी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। वैचारिक समर्थन की दृष्टि से इसकी जड़े स्वतंत्रता आंदोलन के समय स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा हिंदू महासभा में निहित है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य थे:-

1. भारतीय जनसंघ भारत में एक राष्ट्र व एक संस्कृति के विचार का समर्थन करता है।
2. भारतीय संस्कृति और परंपराओं के आधार पर ही एक आधुनिक और मजबूत भारत का निर्माण हो सकता है।
3. यह अखंड भारत की कल्पना करता है जिसके अंतर्गत पाकिस्तान और भारत के पुनःविलय का समर्थन करता है।
4. हिंदी को राज भाषा बनाए जाने की प्रबल समर्थक थी।
5. अल्पसंख्यकों के प्रति कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति की विरोधी थी।
6. भारत को सैनिक रूप से मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए आणविक शस्त्रों के विकास का भी प्रबल समर्थन करता है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. एक दलीय प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं? कांग्रेस को एक दलीय प्रभुत्व की स्थिति कैसे प्राप्त हुई?

उत्तर- एक दलीय प्रभुत्व का तात्पर्य है, कई वर्षों तक किसी एक दल का ही पूरे देशभर में कोई प्रतिद्वंदी ना हो और वह कई दशकों तक प्रत्येक चुनाव को हमेशा जीतता रहा हो। ऐसा ही स्थिति भारत में 1952 से 1967 के बीच कांग्रेस को प्राप्त था। इसके वर्चस्व के लिए कई कारण उत्तरदायी हैं जो निम्नलिखित हैं-

क) राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत- कांग्रेस को अपना वर्चस्व बनाने में सफलता इसलिए प्राप्त हुई कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय उसे सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त था जो उसे विरासत में प्राप्त हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण नेता जैसे- जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदि को देश में व्यापक लोकप्रियता प्राप्त थी। क्योंकि कांग्रेस ने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया था अतः देश की जनता की सहानुभूति उसे प्राप्त थी।

ख) कांग्रेस का देशव्यापी संगठनात्मक विस्तार- राष्ट्रीय आंदोलन के समय कांग्रेस का देशव्यापी ढांचा तैयार हो चुका था। उसके संगठन की इकाइयां प्रदेश, जिला तथा ग्रामीण स्तर तक देश के

jharkhandlab.com

सभी भागों में विद्यमान थी । किसी भी पार्टी को चुनाव में जीत के लिए मजबूत संगठन की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत विपक्षी दलों का संगठनात्मक ढांचा अत्यंत सीमित था तथा देश के एकाध क्षेत्रों तक ही सीमित था।

ग) कांग्रेस का व्यापक सामाजिक समर्थन- कांग्रेस एक पार्टी के साथ-साथ समाज के विभिन्न वर्गों का गठबंधन था। उच्च वर्गों के साथ-साथ निम्न वर्गों, मुसलमानों, किसानों व जमींदारों सभी का समर्थन इसे प्राप्त था। इस व्यापक सामाजिक समर्थन की जड़े तो राष्ट्रीय आंदोलन में निहित थी, लेकिन इसका पूरा फायदा कांग्रेस को चुनाव के दौरान प्राप्त हुआ ।

घ) विपक्षी दलों की शैशवावस्था- दूसरी तरफ विपक्षी दलों को लोकतांत्रिक राजनीति का ना तो अनुभव प्राप्त था और ना ही उनकी संगठन क्षमता देशव्यापी थी। अतः लोकतंत्र के आरंभिक वर्षों में उनका प्रभाव मजबूत नहीं हो पाया।

ङ) मतदान प्रणाली का स्वरूप- भारत में निर्वाचन प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति के तहत होता है। इस पद्धति में किसी पार्टी को सबसे अधिक वोट मिलते हैं। उस सीट में उसे ही विजयी घोषित कर दिया जाता है, भले ही उस क्षेत्र के मतदाताओं के बहुमत का समर्थन उसे प्राप्त ना हो।

च) नेहरू का व्यक्तित्व- कांग्रेस का नेतृत्व आजादी के समय से ही जवाहरलाल नेहरू के हाथों में था तथा आरंभ से ही उन्हें महात्मा गांधी का भी समर्थन प्राप्त था। उनके उदारवादी व्यक्तित्व के कारण कांग्रेस में एक करिश्माई नेतृत्व उत्पन्न हो गया। इसका पूरा लाभ कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुआ।

इन सभी कारणों से कांग्रेस को एक दलीय प्रभुत्व की स्थिति प्राप्त हुई।

प्रश्न 2. भारत में साम्यवादी पार्टी की नीतियों व कार्यक्रमों पर प्रकाश डालते हुए 1964 में उसके विभाजन के कारणों का उल्लेख कीजिए!

उत्तर- भारत में साम्यवादी विचारधारा को रूस की 1917 की साम्यवादी क्रांति से प्रोत्साहन मिला। पहली बार मानवेंद्र नाथ राय ने मास्को में भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना की थी लेकिन वह आगे नहीं बढ़ सकी, तत्पश्चात 1925 में कानपुर में भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना की गई । राष्ट्रीय आंदोलन के समय 1941 तक साम्यवादियों ने कांग्रेस की व्यापक रणनीति के अंतर्गत ही स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। कांग्रेस तथा साम्यवादियों में मतभेद की स्थिति 1941 में तब उत्पन्न हुई जब रूस के प्रभाव में आकर भारत में साम्यवादियों ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन को समर्थन देने की घोषणा की जबकि इस मामले में कांग्रेस का रुख तटस्थता का था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी इसी कारण साम्यवादियों ने हिस्सा नहीं लिया। फिर भी आजादी के पूर्व ही साम्यवादीओं के संगठन का विस्तार हो चुका था। तथा पूरे देश में साम्यवादी पार्टी के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता भी विद्यमान थे।

भारत में प्रथम सप्ताहिक मार्क्सवादी पत्रिका 'सोशलिस्ट' के संपादन का श्रेय एस.ए.डांगे को जाता है। उन्होंने भारत के श्रमिक आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजादी के समय से एक मौलिक प्रश्न उठा कि भारतीय स्वतंत्रता का स्वरूप क्या है। साम्यवादी पार्टी के एक तबके का मानना था कि यह स्वतंत्रता वास्तविक नहीं है क्योंकि इसमें पूंजीपतियों और जमींदारों के हितों की पूर्ति होती है। इसलिए उन्होंने जमींदारों के विरुद्ध भारत के विभिन्न हिस्सों विशेषकर तेलंगना में हिंसक समाधि आंदोलन का समर्थन किया। प्रथम लोकसभा चुनाव के समय उनके सामने यह वैचारिक प्रश्न उत्पन्न हुई कि उन्हें समाजवाद की स्थापना के लिए हिंसात्मक क्रांति का सहारा लेना चाहिए अथवा लोकतांत्रिक समाजवाद को स्वीकार करते हुए चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए अंततः 1951 में साम्यवादी पार्टी ने हिंसात्मक क्रांति का मात्र छोड़कर संसदीय लोकतंत्र का रास्ता अपनाया तथा चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया पहले चुनाव में भारतीय साम्यवादी पार्टी को लोकसभा में 16 सीटें प्राप्त हुई तथा वह सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी तथा दूसरे और तीसरे चुनाव में भी उसकी यह स्थिति बनी रही।

साम्यवादी पार्टी का विभाजन सोवियत संघ तथा चीन में वैचारिक मतभेद होने के कारण 1964 में भारतीय साम्यवादी पार्टी का दो पार्टियों में विभाजन हो गया-1. भारतीय साम्यवादी पार्टी(C.P.I.) तथा मार्क्सवादी साम्यवादी पार्टी (C.P.M.)। इनमें भारतीय साम्यवादी पार्टी सोवियत संघ की विचारधारा की पक्षधर थी जबकि मार्क्सवादी पार्टी चीन की विचारधारा से प्रेरित थी। आज भी दोनों दलों के वैचारिक स्थिति यही है।

प्रश्न 3- भारतीय राजनीति में जनसंघ की नीतियों व कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए उसकी सफलताओं पर प्रकाश डालिए!

उत्तर- भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 ई० में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। वैचारिक समर्थन की दृष्टि से इसकी जड़े स्वतंत्रता आंदोलन के समय स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा हिंदू महासभा में निहित है। वैचारिक दृष्टि से भारतीय जनसंघ अन्य राजनीतिक दलों से इस अर्थ में भिन्न था कि इसने भारत में एक राष्ट्र, एक संस्कृति के विचार का समर्थन किया। राष्ट्रीय जनसंघ का मानना था कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं के आधार पर ही एक आधुनिक और मजबूत भारत का निर्माण हो सकता है। इस पार्टी ने अपनी अखंड भारत की कल्पना के अंतर्गत पाकिस्तान और भारत के पुनः विलय का समर्थन किया। पार्टी हिंदी को राजभाषा बनाये जाने की प्रबल समर्थक थी तथा अल्पसंख्यकों के प्रति सरकार की तुष्टीकरण की नीति की विरोधी थी। उन्होंने भारत को सैनिक रूप से मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए आणविक शस्त्रों के विकास का भी प्रबल समर्थन किया।

अगर हम भारतीय जनसंघ की राजनीति की बात करें तो आरंभिक चुनाव में भारतीय जनसंघ को कोई खास सफलता नहीं मिली। 1952 के लोकसभा चुनाव में उन्हें 3 सीटें, 1957 के चुनाव में 4 सीटें तथा 1962 के चुनाव में उन्हें 14 सीटें प्राप्त हुई। इस पार्टी का जनाधार मुख्यतः उत्तर भारत के राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि के शहरी क्षेत्रों में ही केंद्रित था। व्यापारी वर्ग को इस पार्टी का परंपरागत आधार माना जाता है। आरंभिक काल में भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेता थे- श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक आदि।

1977 में जब कांग्रेस के विरुद्ध विपक्षी दलों द्वारा एकत्र होकर जनता पार्टी का गठन किया गया तो जनसंघ का भी उस में विलय हो गया। लेकिन शीघ्र ही 2 वर्ष बाद जनता पार्टी का विघटन हो गया तथा भारतीय जन संघ के नेताओं ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया।भारतीय जनता पार्टी के आरंभिक नेताओं में अटल बिहारी बाजपेयी तथा लालकृष्ण आडवाणी प्रमुख है। अटल बिहारी वाजपेयी 1980 में भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने।

भारत में लोकतंत्र की जड़े जैसे- जैसे मजबूत होती गई तथा विपक्षी दलों का जनाधार बढ़ता गया वैसे- वैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में कांग्रेस का वर्चस्व भी कम होता रहा। 1989 के बाद राष्ट्रीय विपक्षी दलों के साथ-साथ क्षेत्रीय पार्टियों का भी प्रभाव बढ़ता गया। लेकिन कोई भी राष्ट्रीय पार्टी अकेले दम पर लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त करने की स्थिति में नहीं बन सकी। यद्यपि 2014 के 16वीं लोकसभा के लिए संपन्न चुनाव में एन.डी.ए को प्राप्त 337 सीटों में भाजपा ने अकेले ही 283 सीटों पर विजय प्राप्त कर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है और 2019 के चुनाव में भाजपा 303 लोकसभा सीट तक जीती।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में जनसंघ की शुरुआत 2 लोकसभा सीट से शुरू होकर 2019 में लोकसभा सीटों का संख्या 303 तक पहुंच गया। वर्तमान में यह भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है।

jharkhandjcert.com

अध्याय - 3 नियोजित विकास की राजनीति

वस्तुनिष्ठ प्रश्न-

प्रश्न 1. बाम्बे प्लान के बारे में कौन सा बयान सही नहीं है?
A. यह भारत के आर्थिक भविष्य का एक ब्लूप्रिंट था।
B. इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था।
C. इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने की थी।
D. इसमें नियोजन के विचार का पुरजोर समर्थन किया गया था।

प्रश्न 2. भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा है?
A. 1950 -1955 B. 1951-1956
C. 1952-1957 D. 1953-1958

प्रश्न 3. राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है?
A. राष्ट्रपति B. उपराष्ट्रपति
C. प्रधानमंत्री D. मुख्य न्यायाधीश

प्रश्न 4. योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी?
A. मार्च 1950 B. मई 1951
C. मार्च 1952 D. सितंबर 1954

प्रश्न 5. योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं?
A. राष्ट्रपति B. प्रधानमंत्री
C. मुख्यमंत्री D. गृह मंत्री

प्रश्न 6. किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से भी जाना जाता है?
A. प्रथम पंचवर्षीय योजना B. द्वितीय पंचवर्षीय योजना
C. तृतीय पंचवर्षीय योजना D. चतुर्थ पंचवर्षीय योजना

प्रश्न 7. भारत में नियोजन व्यवस्था किस देश की नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है ?
A. संयुक्त राज्य अमेरिका B. सोवियत संघ
C. फ्रांस D. ब्रिटेन

प्रश्न 8. राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ?
A. 1950 B. 1955
C. 1952 D. 1956

प्रश्न 9. किस पंचवर्षीय योजना को ओद्यौगिक एवं परिवहनीय योजना के नाम से जाना जाता है?
A. प्रथम पंचवर्षीय योजना B. द्वितीय पंचवर्षीय योजना
C. तृतीय पंचवर्षीय योजना D. चतुर्थ पंचवर्षीय योजना

प्रश्न 10. राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं?
A. सभी राज्यों के मुख्यमंत्री B. योजना आयोग के सदस्य
C. मंत्रिमंडल के मंत्री D. उपयुक्त सभी

प्रश्न 11. भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की?
A. डॉ मनमोहन सिंह B. नरसिम्हा राव
C. राजीव गांधी D. वी पी सिंह

प्रश्न 12. हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस फसल में हुआ?
A. मक्का B. दलहन
C. चावल D. गेहूं

प्रश्न 13. 'जय जवान जय किसान' का नारा किसने दिया?
A. सुभाष चंद्र बोस B. लाल बहादुर शास्त्री
C. जवाहरलाल नेहरू D. अटल बिहारी बाजपेई

प्रश्न 14. श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है ?
A. फूलों के उत्पादन से B. शहद की उत्पादन से
C. दूध के उत्पादन से D. तिलहन के उत्पादन से

प्रश्न 15. श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई?
A. राजस्थान B. गुजरात
C. केरल D. बिहार

उत्तर-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	B	C	A	B	A	B	C	B	D	B	D	B	C	B

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. हरित क्रांति क्या थी?
उत्तर- हरित क्रांति खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त की गई तकनीक थी। इसके अंतर्गत अपने देश की कृषि में आधुनिक विकास के लिए उन्नत बीज, कीटनाशक और रसायनिक उर्वरक का प्रयोग के परिणाम स्वरूप अनाजों के उत्पादन में वृद्धि हुई।

प्रश्न 2. मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है ?
उत्तर– मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवाद तथा पूंजीवाद दोनों की विशेषताओं को शामिल किया गया। देश में छोटे उद्योगों का विकास निजी क्षेत्र में किया गया तथा बड़े उद्योगों के विकास की जिम्मेवारी सरकार ने अपने कंधों पर ली।

प्रश्न 3. बॉम्बे प्लान क्या है?
उत्तर– 1944 में उधोग पतियों के एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक प्रस्ताव तैयार किया। जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। इसका उद्देश्य है सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाएं।

प्रश्न 4. योजना आयोग क्या है?
उत्तर- भारत के स्वतंत्र होते ही योजना आयोग अस्तित्व में आया। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा की गई। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता अपनाएगा। यह फैसला करने के लिए इस संस्था ने प्रभावशाली भूमिका निभाई।

प्रश्न 5. राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? इसके निर्माण के क्या उद्देश्य थे?
उत्तर- राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 में हुई थी। योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी हो ,इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया था।

Jharkhandlab.com

प्रश्न 6. द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी ? इसमें किस क्षेत्र पर जोर दिया गया था?

उत्तर– द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956-1961 तक थी। इस योजना में उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया । सरकार ने देशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया।

प्रश्न 7. विकास का केरल मॉडल क्या है?

उत्तर– केरल में विकास और नियोजन के लिए अपनाए गए ,इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए विकेन्द्रित योजना पर आधारित था। जिसमें पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर योजनायें बनाने में लोगो का शामिल करने की बात कही गयी है ।

प्रश्न 8. श्वेत क्रांति क्या है?

उत्तर– हरित क्रांति की भारी सफलता देखने के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की, जिसे श्वेत क्रांति के रूप में जाना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का उद्देश्य से हुई।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. पहली पंचवर्षीय योजना का किस चीज पर ज्यादा जोर था? दूसरी पंचवर्षीय योजना पहली से किन अर्थों में अलग थी?

उत्तर– पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में अधिक जोर दिया गया क्योंकि भारत के विभाजन का सबसे बुरा प्रभाव कृषि क्षेत्र पर पड़ा था ,अतः प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय एवं दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रमुख अंतर यह था कि जहां प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर अधिक जोर दिया गया वहीं दूसरी योजना में भारी उद्योग के विकास पर अधिक जोर दिया गया।

प्रश्न 2. हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति के दो सकारात्मक और दो नकारात्मक परिणामों का उल्लेख करें ।

उत्तर– हरित क्रांति खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त की गयी नई तकनीक थी। जिसके अंतर्गत अपने देश की खेती मे आधुनिक विकास के लिए मुख्यतः नए कीटनाशक और रसायनिक उर्वरक का प्रयोग करने के परिणाम स्वरूप अनाजों के उत्पादन में वृद्धि हुई जिसे हरित क्रांति कहा जाता है।

हरित क्रांति के दो सकारात्मक परिणाम–

A. हरित क्रांति में धनी किसानों और बड़े भूस्वामियों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। ज्यादातर गेहूं की पैदावार बड़ी और देश में खाद्यान्न उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई।

B. हरित क्रांति के कारण देश अनाज उत्पादन के मामले में में आत्मनिर्भर हो गया ।

हरित क्रांति के दो नकारात्मक परिणाम–

A. कृषि क्षेत्र के मशीनरी से रोजगार की अवसरों में कमी हुई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी फैली और ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन हुआ।

B. गरीब और भूमिहीन किसानों का शोषण और दमन हुआ जिससे देश में नक्सलवादी आंदोलन को बल मिला।

प्रश्न 3. दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास बनाम कृषि विकास का विवाद चला था? इस विवाद में क्या-क्या तर्क दिये गये थे?

उत्तर– दूसरी पंचवर्षीय योजना और औद्योगिक विकास बनाम कृषि विकास का विवाद–

1. स्वतंत्रता के बाद भारत जैसी पिछड़ी अर्थव्यवस्था कि देश में विवाद खड़ा हुआ कि उद्योग और कृषि में से किस क्षेत्र में ज्यादा संसाधन लगाएं।
2. अनेक लोगों का मानना था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की रणनीति का अभाव था और इस योजना के दौरान उद्योग पर जोर देने के कारण खेती और ग्रामीण इलाकों को चोट पहुंची।
3. जे सी कुमारप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्री ने एक वैकल्पिक योजना का खाका प्रस्तुत किया था। जिसमें ग्रामीण औद्योगीकरण पर ज्यादा जोर दिया गया था। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात बड़े सुनियोजित और दमदार ढंग से उठाई थी।
4. चौधरी चरण सिंह ने कहा कि नियोजन से शहरी और उद्योग -धंधे समृद्ध हो रहे हैं और इसकी कीमत किसानों और ग्रामीण जनता को चुकानी पड़ रही है।
5. तब कई अन्य लोगों का सोचना था कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर को तेज किए बगैर गरीबी की मकड़जाल से छुटकारा नहीं मिल सकता है ।

प्रश्न 4. मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं?

उत्तर– मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें आर्थिक गतिविधियां दोनों क्षेत्रों अर्थात निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र में की जाती है। निजी क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप एवं नियंत्रण न्यूनतम होता है एवं आर्थिक गतिविधियां खुली प्रतियोगिता के आधार पर की जाती है। यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जन्म देता है। दूसरी ओर सार्वजनिक क्षेत्र होता है। जहां पर आर्थिक गतिविधियों में राज्य का अधिक से अधिक नियंत्रण एवं हस्तक्षेप होता है। इसमें लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर चीजों का उत्पादन किया जाता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। 1990 तक भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में दबदबा रहा लेकिन 1990 के बाद भारत में निजी क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा है ।

प्रश्न 5. निजी क्षेत्र एवं सर्वजनिक क्षेत्र में मुख्य अंतर समझाइए?

उत्तर– निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है । दोनों की अपनी-अपनी विशेषताएं एवं क्षेत्र हैं। दोनों में मुख्य अंतर है–

1. निजी क्षेत्र उदारवादी पूंजीवादी चिंतन पर आधारित है। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र समाजवादी चिंतन पर आधारित है।
2. निजी क्षेत्र में आर्थिक क्षेत्रों का केंद्रीकरण होता है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में स्रोतों का विकेंद्रीकरण होता है।
3. निजी क्षेत्र में राज्य की भूमिका सीमित होती है। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
4. निजी क्षेत्र में व्यक्तिगत लाभ को महत्व दिया जाता है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में सर्वहित को महत्व दिया जाता है।
5. निजी क्षेत्र प्रतियोगिता पर आधारित होता है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र सभी के सहयोग पर आधारित होता है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. आजादी के समय विकास के सवाल पर प्रमुख मतभेद क्या थे? क्या इन मतभेदों को सुलझा लिया गया?

उत्तर– आजादी के समय भारत के सामने अनेक प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याएं थी। जिनका हल निकालने के लिए भारत ने नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया परंतु नियोजन की प्रक्रिया इतनी सहज एवं सही नहीं हो पाई एवं अनेक प्रकार के मतभेदों के दायरे में आ गई। सबसे पहले मतभेद वैचारिक थे। वैचारिक स्तर पर भारतीय नेतृत्व प्रमुख रूप से दो वर्ग में बंटे थे। प्रथम उदारवादी चिंतक जो विकास का पश्चिमी उदारवादी मॉडल

Jharkhandlab.com

अपनाना चाहते थे एवं दूसरा वर्ग उन नेताओं एवं चिंतकों का था जो साम्यवादी समाजवादी मॉडल को अपनाने के पक्ष में थे।

दूसरा मतभेद प्राथमिकताओं को लेकर था कुछ लोग निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दे रहे थे। तीसरा मुद्दा कृषि बनाम उद्योग था। जिस पर विभिन्न सोच के लोगों में मतभेद था। कुछ लोग जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की गरीबी, बेरोजगारी इस समस्या का हल औद्योगीकरण के द्वारा करना चाहते थे जबकि कुछ अन्य वर्ग के लोगों का मानना था कि ग्रामीण क्षेत्र में खेती की कीमत पर औद्योगिकरण किया जाता तो वह खेती क्षेत्र के लिए हानिकारक होगा। इसी संदर्भ में ग्रामीण बनाम शहरी मुद्दा भी उभर कर सामने आया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक निवेश एवं विकास की जरूरत है तथा शहरी विकास ग्रामीण विकास की कीमत पर नहीं होना चाहिए।

इस प्रकार से नियोजन की प्रक्रिया कई प्रकार की मतभेदों से घिरी रही क्योंकि सभी राष्ट्रीय हितों से प्रेरित थे। अतः मतभेद होते हुए भी समायोजन एवं आम सहमति के माध्यम से मतभेद दूर किए गए तथा उचित रास्ता अपनाया गया जैसे निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई। ग्रामीण क्षेत्र के साथ शहरी क्षेत्र का विकास भी निश्चित किया गया। इस तरह से कृषि विकास एवं औधोगिक विकास में भी संबंध स्थापित किया गया।

प्रश्न 2. योजना आयोग का गठन एवं कार्य समझाइए?

उत्तर– देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का वैज्ञानिक पद्धति से विकास करना चाहते थे। भारत की सामाजिक आर्थिक समस्याओं का क्रमबद्ध तरीके से हल करना चाहते थे।वे सोवियत संघ की योजना प्रक्रिया से अत्यंत प्रभावित थे। अतः वहां की तरह भारत में नियोजन प्रक्रिया प्रारंभ की। नियोजन की प्रक्रिया का संचालन करने के लिए उन्होंने 1950 में योजना आयोग का गठन किया। योजना आयोग का एक उपाध्यक्ष होता है। जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा योजना आयोग के कई सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्य होते हैं। कुछ मंत्री इसके पदेन सदस्य होते है। योजना आयोग का स्वरूप एक सलाहकार संस्था के रूप में होता है –

1. पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना।
2. स्रोतों का अवलोकन करना।
3. योजनाओं की प्राथमिकता निश्चित करना।
4. योजनाओं के लक्ष्य को प्राप्त करना।
5. योजनाओं के बीच में प्रगति प्राप्त करना एवं मूल्यांकन करना।
6. योजना की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को दूर करना।
7. राज्यों के विकास योजनाओं पर सहमति प्रदान करना तथा राज्यों का आवश्यक धन प्रबंध करना।

वर्तमान समय में योजना आयोग की भूमिका काफी व्यापक हो चुकी है। भारत के आर्थिक विकास में इसकी भूमिका एवं आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसकी कार्यक्षमता तथा कार्यशैली भी काफी उत्कृष्ट दिखाई पड़ती है। इसका कारण यह है कि यह संस्था प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री के साथ कार्य करती है।

प्रश्न 3. राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या कार्य है?

उत्तर– योजना आयोग के गठन के पश्चात प्रथम पंचवर्षीय योजना के निर्माण के समय यह अनुभव किया गया कि संघीय स्तर पर योजना निर्माण में राज्यों की सार्थक भूमिका आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया।

योजना आयोग की तरह राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय मंत्रीमंडल के सभी सदस्य तथा योजना आयोग के विशेषज्ञ सदस्य तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भी इसके सदस्य होते हैं।

राष्ट्रीय विकास परिषद के मुख्य कार्यों को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है –

1. पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक दिशा निर्देशन यह समिति तैयार करती है। इस समिति के दिशानिर्देशों का आधार बनाकर योजना निर्माण का कार्य पूरा किया जाता है।
2. योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाओं पर यह संस्था विचार विमर्श करती है।
3. यह समिति राष्ट्र के विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक आर्थिक नीतियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करती है एवं आवश्यकता के अनुसार महत्वपूर्ण निर्णय लेती है।
4. पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति तथा सफलता इत्यादि का मूल्यांकन करना इस समिति का एक महत्वपूर्ण कार्य है।
5. योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक संसाधनों का अनुमान लगाना तथा उन्हें वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय सुझाना इस समिति का एक महत्वपूर्ण कार्य है।

jharkhandlab.com

अध्याय - 4 भारत के विदेश संबंध

वस्तुनिष्ठ प्रश्न-

1. `स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे?
A. जवाहरलाल नेहरू
B. सरदार बल्लभ भाई पटेल
C. डॉ राजेंद्र प्रसाद
D. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

2. गुटनिरपेक्ष आंदोलन का स्थापना कब हुआ ?
A. 1955 B. 1961
C. 1965 D. 1966

3. स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे?
A. पंडित जवाहरलाल नेहरू
B. सरदार बल्लभ भाई पटेल
C. सर्वपल्ली राधाकृष्णन
D. डॉ0 राजेंद्र प्रसाद

4. शिमला समझौता कब हुआ था?
A. 1966 B. 1972
C. 1975 D. 1979

5. सिंधु जल संधि 1960 में किनके बीच हुआ था?
A. भारत-चीन B. भारत-पाकिस्तान
C. भारत-बांग्लादेश D. भारत-नेपाल

6. एफ्रो एशियाई सम्मेलन कब और कहां हुआ था?
A. 1945 बांडुंग B. 1955 बांडुंग
C. 1960 एशिया D. 1965 चीन

7. पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच कब हुआ था?
A. 20 अप्रैल 1951 B. 25 अप्रैल 1953
C. 27 अप्रैल 1952 D. 29 अप्रैल 1954

8. गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहां हुआ था?
A. ब्रिटेन B. बेलग्रेड
C. कंबोडिया D. जापान

9. चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया?
A. 1960 B. 1962
C. 1965 D. 1971

10. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी टूट कर कब अलग हुआ?
A. 1950 B. 1954
C. 1960 D. 1964

11. सिंधु नदी जल संधि के दौरान भारत और पाकिस्तान का नेतृत्व किसने किया था?
A. पंडित जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान
B. पंडित जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली
C. बल्लभ भाई पटेल और बेनजीर भुट्टो
D. श्रीमती इंदिरा गांधी और परवेज मुशर्रफ

12. शिमला समझौता मैं भारत और पाकिस्तान का नेतृत्व किसने किया था?
A. नेहरू और अयूब खान
B. श्रीमती इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो
C. श्रीमती इंदिरा गांधी और नवाज शरीफ
D. लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान

13. कारगिल युद्ध कब हुआ था?
A. 1971 B. 1999
C. 1995 D. 1991

14. भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था?
A. 1964 B. 1974
C. 1984 D. 1994

15. परमाणु अप्रसार संधि लाई गई थी?
A. 1968 B. 1988
C. 1978 D. 1991

उत्तर -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	A	B	B	B	B	D	B	B	D	A	B	B	B	A

16. इन कथनों के आगे सही या गलत का निशान लगाएँ:

A. गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने के कारण भारत, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमरीका, दोनों के सहायता हासिल कर सका।

B. अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध शुरूआत से ही तनावपूर्ण रहे।

C. शीतयुद्ध का असर भारत-पाक संबंधों पर भी पड़ा।

D. 1971 की शांति और मैत्री की संधि संयुक्त राज्य अमरीका से भारत की निकटता का परिणाम थी।

उत्तर:- A. सही, B. गलत, C. सही, D. गलत

17..निम्नलिखित का सही जोड़ा मिलाएँ:

A. 1950-64 के दौरान भारत की विदेश नीति का लक्ष्य-	(i) तिब्बत के धार्मिक नेता जो सीमा पार करके भारत चले आए।
B. पंचशील-	(ii) क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा तथा आर्थिक विकास।
C. बांडुंग सम्मेलन-	(iii) शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पाँच सिद्धांत
D. दलाई लामा-	(iv) इसकी परिणति गुटनिरपेक्ष आंदोलन में हुई।

उत्तर:- A.1950-64 के दौरान भारत की विदेश नीति का लक्ष्य-(ii) क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा तथा आर्थिक विकास।

B. पंचशील-(iii) शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पाँच सिद्धांत

C. बांडुंग सम्मेलन-(iv) इसकी परिणति गुटनिरपेक्ष आंदोलन में हुई।

D. दलाई लामा-(i) तिब्बत के धार्मिक नेता जो सीमा पार करके भारत चले आए।

Jharkhandgb.com

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. विदेश नीति से आप क्या समझते हैं?

उत्तर- जब एक देश विभिन्न देशों,अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों , अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों तथा आन्दोलनों व अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जिन नीतियों को अपनाता है। उन नीतियों को सामूहिक रूप से विदेश नीति कहा जाता है

2. पंडित जवाहरलाल नेहरू के विदेश नीति के उद्देश्य क्या थे?

उत्तर- नेहरू जी की विदेश नीति के तीन मुख्य उद्देश्य थे :-

1. संघर्ष से प्राप्त सम्प्रभुता को बचाए रखना ।
2. क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना ।
3. तेज गति से आर्थिक विकास करना ।

भारत की विदेश नीति पर देश के पहले प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री पं जवाहर लाल नेहरू की अमिट छाप है।

3. भारत के विदेश नीति के कौन-कौन से सिद्धांत थे?

उत्तर- भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धान्त :-

1. गुटनिरपेक्षता
2. निःशस्त्रीकरण
3. वसुधैव कुटुम्बकम
4. अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्रतापूर्वक एवं सक्रिय भागीदारी
5. पंचशील
6. साम्राज्यवाद का विरोध
7. अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान

4. ताशकंद समझौता कब और किसके बीच हुई थी?

उत्तर- ताशकन्द समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को हुआ एक शान्ति समझौता था। इस समझौते के अनुसार यह तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग एक दुसरे के खिलाफ नहीं करेंगे और अपने झगड़ों को शान्तिपूर्ण ढंग से तय करेंगे।

5. बांडुंग सम्मेलन क्या था?

उत्तर- बांडुंग सम्मेलन 1955 में 18-24 अप्रैल के मध्य इंडोनेशिया के बांडुंग में पांच देशों (बर्मा, श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया व पाकिस्तान) ने मिलकर एक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसे 'बांडुंग सम्मेलन' कहा जाता है।

6. 'जय जवान जय किसान' का नारा किसने दिया था?

उत्तर- जय जवान जय किसान भारत का एक प्रसिद्ध नारा है। यह नारा 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसे भारत का राष्ट्रीय नारा भी कहते हैं जो जवान एवं किसान के श्रम को दिखाता है।

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. गुटनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है?

उत्तर- गुटनिरपेक्षता का अर्थ है कि विभिन्न शक्ति गुटों से तटस्थ या दूर रहते हुए अपनी स्वतन्त्र निर्णय नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार सही या न्याय का साथ देना।अपनी संप्रभुता को बचाए रखना । और भारत को तीव्र आर्थिक व सामाजिक विकास के लक्ष्य को भी प्राप्त करना था। अतः इन दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनी और विदेश नीति के एक प्रमुख तत्व के रूप में अंगीकार किया । इसी कड़ी में 1955 में इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में एफ्रो - एशियाई सम्मेलन हुआ, जिसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 के सितंबर में बेलग्रेड में हुआ था, इसकी स्थापना में नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इस नीति के द्वारा भारत जहाँ शीतयुद्ध के परस्पर विरोधी खेमों तथा उनके द्वारा संचालित सैन्य संगठनों जैसे - नाटो(NATO) , वारसा पेक्ट आदि से अपने को दूर रख सका । वहीं आवश्यकता पड़ने पर दोनों ही खेमों से आर्थिक व सामरिक सहायता भी प्राप्त कर सका ।

2. पंचशील समझौता क्या था?

उत्तर- भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने चीन से अच्छे संबंध बनाने की पहल की ।1949 में चीनी क्रांति के बाद चीन की कम्यूनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाला भारत पहले देशों में एक था ।

29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री पं नेहरू तथा चीन के प्रमुख चाऊ एन लाई के बीच पांच बातों पर द्विपक्षीय समझौता हुआ।

1. एक दूसरे के विरूद्ध आक्रमण न करना ।
2. एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना ।
3. एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का आदर करना ।
4. समानता और परस्पर मित्रता की भावना
5. शांतिपूर्ण सह - अस्तित्व।

इस समझौता को पंचशील समझौता के नाम से जाना गया।

3. नेहरू विदेश नीति के संचालन को स्वतंत्रता का एक अनिवार्य संकेतक क्यों मानते थे? अपने उत्तर में दो कारण बताएँ और उनके पक्ष में उदाहरण भी दें।

उत्तर- भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में 1946 एवं 1964 तक उन्होंने भारत की विदेश नीति की रचना और क्रियान्वयन पर अपना अमिट छाप छोड़ा। पं नेहरू की विदेश नीति के तीन बड़े उद्देश्य थे- कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना और तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। पं नेहरू इन उद्देश्यों को गुटनिरपेक्षता की नीति अपना कर हासिल करना चाहते थे। पं नेहरू विदेश नीति के संचालन को स्वतंत्रता का एक अनिवार्य संकेत इसलिए मानते थे, क्योंकि विदेश नीति का संचालन वही देश कर सकता है, जो स्वतंत्र हो। जैसे आजादी से पहले भारत स्वयं अपनी विदेश नीति का संचालन नहीं कर पाता था, बल्कि ब्रिटिश सरकार करती थी।

4. विदेश नीति का निर्धारण घरेलू जरूरत और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के दोहरे दबाव में होता है। 1960 के दशक में भारत द्वारा अपनाई गई विदेश नीति से एक उदाहरण देते हुए अपने उत्तर की पुष्टि करें।

उत्तर- यह सही बात है कि विदेश नीति का निर्धारण घरेलू जरूरत और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के दोहरे दबाव में होता है। क्योंकि प्रत्येक देश राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। पहले भारत सोवियत संघ पर निर्भर था क्योंकि सोवियत संघ ने कश्मीर के मामले में भारत की सहायता की थी। 1962 में चीन के आक्रमण के समय भारत को अपनी सुरक्षा नीति, उत्तर-पूर्व के क्षेत्रों के प्रति अपनी नीति, सैनिक ढांचे के आधुनिकरण आदि के बारे में फिर से विचार करना पड़ा। और अपने रक्षा बजट में वृद्धि करनी पड़ी। साथ ही भारत ने 1960 के दशक में जो विदेश नीति अपनाई इस पर चीन और पाकिस्तान के युद्ध, राजनीतिक परिस्थितियाँ तथा शीतयुद्ध का प्रभाव साफ-साफ देखा जा सकता है।

Jharkhandlabs.com

5. भारत की परमाणु नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर- भारत ने 1974 में परमाणु परीक्षण किया। इसकी शुरूआत 1940 में होमी जहाँगीर भाभा के निर्देशन में हो चुकी थी। भारत शांतिपूर्ण उद्देश्यों में इस्तेमाल के लिए परमाणु ऊर्जा बनाना चाहता था। नेहरू परमाणु हथियारों के खिलाफ थे। उन्होंने महाशक्तियों पर व्यापक परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए जोर दिया। लेकिन, परमाणु हथियारों में बढ़ोत्तरी होती रही। चीन ने भी 1964 में परमाणु परीक्षण किया। अणुशक्ति-सम्पन्न राष्ट यानी संयुक्त राज्य अमेरीका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ने, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्य भी थे, दुनिया के अन्य देशों पर 1968 की परमाणु अप्रसार संधि को थोपना चाहा। भारत हमेशा से इस संधि को भेदभावपूर्ण मानता आया था। भारत ने इस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। भारत ने जब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो इसे उसने शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया। भारत का कहना था कि वह अणुशक्ति को सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों में उपयोग करने की अपनी नीति के प्रति कृतसंकल्प है।

6. क्या विदेश नीति के मामलों पर सर्व-सहमति आवश्यक है?

उत्तर- किसी भी देश के लिए विदेश नीति बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है इसलिए इसमें सर्व-सम्मति आवश्यक है क्योंकि यदि सर्व-सम्मति नहीं रहेगी तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना पक्ष प्रभावशाली तरीके से नहीं रख पायेंगे। भारत की विदेश नीति की विशेषताएँ जैसे- गुट-निरपेक्षता, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध, अन्य देशों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाना तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा आदि पर हमेशा सर्व-सम्मति रही है।

7. क्या भारत की विदेश नीति से यह झलकता है कि भारत क्षेत्रीय स्तर को महाशक्ति बनना चाहता है ? 1971 के बांग्लादेश युद्ध के संदर्भ में इस प्रश्न पर विचार करें।

उत्तर- भारत की विदेश नीति का संचालन इस प्रकार से किया गया है कि भारत विश्व में महाशक्ति बनकर उभरे। बांग्लादेश के निर्माण के लिए पाकिस्तान की पूर्वी पाकिस्तान के प्रति उपेक्षापूर्ण नीतियाँ थी। भारत हमेशा से शांतिपूर्ण नीतियों में विश्वास करता आया है। भारत ने बांग्लादेश युद्ध के समय भी पाकिस्तान को हराया परंतु उनके सैनिकों को सम्मान के साथ रिहा कर दिया। पाकिस्तान की भेदभावपूर्ण नीतियाँ और उपेक्षित व्यवहार के कारण ही पूर्वी पाकिस्तान की जनता विद्रोह कर बैठी और यह युद्ध का रूप ले लिया। भारत ने इसे अपना नैतिक समर्थन दिया।1971 के युद्ध के बाद एक नया देश बांग्लादेश के रुप में उभरा और भारत का भी विश्व में गौरव प्राप्त हुआ।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. भारत की विदेश नीति का निर्माण शांति और सहयोग के सिद्धांतों को आधार मानकर हुआ। लेकिन, 1962-1971 की अवधि यानी महज दस सालों में भारत को तीन युद्धों का सामना करना पड़ा। क्या आपको लगता है कि यह भारत की विदेश नीति की असफलता है अथवा आप इसे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का परिणाम मानेंगे ? अपने मंतव्य के पक्ष में तर्क दीजिए।

उत्तर– 1962- 1971 तक भारत को तीन युद्ध लड़ने पड़े। जिसमें कुछ हद तक भारत की विदेश नीति की असफलता भी मानी जाती है, तथा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का परिणाम भी। 1962 में चीन ने हिन्दी-चीनी भाई-भाई का नारा देकर भारत के साथ विश्वासघात किया। पंचशील के सिद्धान्तों पर हस्ताक्षर करने के बावजूद चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया। निःसन्देह यह भारत की विदेश नीति की एक तरह से असफलता थी।

हम उनकी मंशा को सही ढंग से भाँप नहीं पाए। भारतीय नेताओं को शान्ति दूत के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय छवि बनाने की ज्यादा चाहत थी। इस युद्ध से भारत के स्वाभिमान को चोट पहुँची लेकिन इसके साथ राष्ट्रीय भावना भी बलवती हुई। यदि नेहरू कूटनीति से काम लेकर दूरदर्शिता दिखाई होती हो तो हम चीनी आक्रमण का उपयुक्त जबाव दे सकते थे। शान्ति व सहयोग की नीति पर चलने के लिए हमें सशक्त होना भी जरूरी है।

1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन उस समय प्रधानमन्त्री लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को करारी शिकस्त दी। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की विदेश नीति की धाक जमी। इसे असफल नहीं माना जा सकता ।

1971 में बांग्लादेश के मामले पर तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गाँधी ने एक सफल कूटनीतिज्ञ के रूप में बांग्लादेश की स्वतन्त्रता का समर्थन किया और स्थायी रूप से युद्ध में सब जायज है और राजनीति में कोई स्थायी शत्रु या मित्र नही होता,बल्कि परिस्थितियों के अनुसार राष्ट्रीय हित में विदेश नीति का संचालन किया जाता है। इस प्रकार से इन्दिरा गांधी ने अपनी सफल कूटनीति का परिचय दिया।

युद्ध में इस निर्णायक जीत से देश में उत्साह की लहर दौड़ गई और अधिकांश भारतवासियों ने इसे गौरव की घड़ी के रूप में देखा। यह भारतीय विदेश नीति का सफल प्रदर्शन था।

2. भारत चीन संबंधों का वर्णन करें।

उत्तर– भारत ने चीन के साथ अपने रिश्तों की शुरुआत बड़े ही दोस्ताना ढंग से की। चीनी क्रांति 1949 में हुई थी। इस क्रांति के बाद भारत, चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाले पहले देशों में एक था। पश्चिमी प्रभुत्व के चंगुल से निकलने वाले इस देश को लेकर नेहरू के हृदय में गहरे भाव थे और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फ़लक पर इस सरकार की मदद की।

शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के पाँच सिद्धांतों यानी पंचशील की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रमुख चाऊ एन लाई ने संयुक्त रूप से 29 अप्रैल 1954 में की। दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध की दिशा में यह एक अगला कदम था। भारत और चीन के नेता एक-दूसरे के देश का दौरा करते थे और उनके स्वागत में बड़ी भीड़ जुटती थी ।

लेकिन चीन के साथ भारत के इस दोस्ताना रिश्ते में कुछ कारणों से खटास आई। चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्ज़ा कर लिया। इससे भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक रूप से जो एक मध्यवर्ती राज्य बना चला आ रहा था, वह खत्म हो गया।

शुरू-शुरू में भारत सरकार ने चीन के इस कदम का खुले तौर पर विरोध नहीं किया। बहरहाल, तिब्बत की संस्कृति कुचलने की खबरें जैसे-जैसे सामने आने लगी, वैसे वैसे भारत की बेचैनी भी बढ़ी। तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने भारत से राजनीतिक शरण माँगी और 1959 में भारत ने शरण दे दी। चीन ने इसे अपने अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप का आरोप लगाया।

इससे कुछ दिनों पहले भारत और चीन के बीच एक सीमा विवाद भी उठ खड़ा हुआ था। भारत का दावा था कि चीन के साथ रेखा का मामला अंग्रेजी शासन के समय सुलझाया जा चुका है। लेकिन चीन की सरकार का कहना था कि अंग्रेजी शासन के समय का फ़ैसला नहीं माना जा सकता।

चीन ने भारतीय भू-क्षेत्र में पड़ने वाले दो इलाकों जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले हिस्से के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर अपना अधिकार जताया। अरुणाचल प्रदेश को उस समय नेफा या उत्तर-पूर्वी सीमांत कहा जाता था।

1957 से 1959 के बीच चीन ने अक्साई चीन इलाके पर कब्जा कर लिया। दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीमा पर कई बार झड़प हुई।

jharkhandlab.com

चीन ने 1962 के अक्तूबर में दोनों विवादित क्षेत्रों (अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश) पर बड़ी तेजी तथा व्यापक स्तर पर हमला कर दिया। और अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया तथा असम के मैदानी हिस्से के प्रवेशद्वार तक चीनी सेना पहुँच गई। और चीन ने एकतरफा युद्धविराम घोषित कर दिया ।

चीन युद्ध से भारत की छवि को देश और विदेश दोनों ही जगह धक्का लगा। चीन युद्ध से भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट पहुँची, लेकिन इसके साथ-साथ राष्ट्र-भावना भी बलवती हुई।

कुछ प्रमुख सैन्य कमांडरों ने या तो इस्तीफा दे दिया या अवकाश ग्रहण कर लिया। नेहरू के नजदीकी सहयोगी और रक्षामंत्री वी. के. कृष्णमेनन को भी मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा। नेहरू की छवि भी थोड़ी धूमिल हुई। चीन के इरादों को समय रहते न भाँप सकना और सैन्य तैयारी न कर पाने को लेकर नेहरू की बड़ी आलोचना हुई। पहली बार उनके सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया ।

भारत और चीन के बीच संबंधों को सामान्य होने में करीब दस साल लग गए। 1976 में दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल हो सके। शीर्ष नेता के तौर पर पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी (वे तब विदेश मंत्री थे) 1979 में चीन के दौरे पर गए। बाद में, नेहरू के बाद राजीव गाँधी बतौर प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर गए। इसके बाद से चीन के साथ भारत के संबंधों में ज्यादा जोर व्यापारिक मसलों पर रहा है।

2003 में भी अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के तौर पर चीन की यात्रा की जिसमें प्राचीन सिल्करूट (नाथूला दर्रा) को व्यापार के लिए खोलने पर सहमति हुई जो 1962 से बंद था । इससे यह मान्यता भी मिली कि चीन सिक्किम को भारत का अंग मानता है।

3. भारत-पकिस्तान संबंध का वर्णन करें।

उत्तर– भारत एवं पाकिस्तान का उदय सांप्रदायिक दंगों के बीच हुआ जिसमें दोनों ही देशों का सबसे बड़ा मुद्दा कश्मीर मुद्दा रहा। कश्मीर मसले को लेकर पाकिस्तान के साथ बँटवारे के तुरंत बाद ही संघर्ष छिड़ गया । 1947 के इस संघर्ष के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दा को अंतर्राष्ट्रीयकरण किया। संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन एवं अमेरिका का साथ पाकिस्तान को मिला और पाकिस्तान का पक्ष भारी रहा। कश्मीर के सवाल पर हुए संघर्ष के बावजूद भारत और पाकिस्तान ने मिल-जुल कर प्रयास किया कि बँटवारे के समय जो महिलाएँ अपहृत हुई थीं। उन्हें अपने परिवार के पास वापस लौटाया जा सके। विश्व बैंक की मध्यस्थता से नदी जल में हिस्सेदारी को लेकर चला आ रहा एक लंबा विवाद सुलझा लिया गया। नेहरू और जनरल अयूब खान ने सिंधु नदी जल संधि पर 1960 में हस्ताक्षर किए। भारत-पाक संबंधों में गरमा - गरमी के बावजूद इस संधि पर ठीक-ठाक अमल होता रहा ।

दोनों देशों के बीच 1965 में कहीं ज्यादा गंभीर किस्म के सैन्य संघर्ष की शुरुआत हुई।इस वक्त लालबहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। 1965 के अप्रैल में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ इलाके के रन में सैनिक हमला बोला। इसके बाद जम्मू-कश्मीर में उसने अगस्त-सितंबर के महीने में बड़े पैमाने पर हमला किया। पाकिस्तान के नेताओं को उम्मीद थी कि जम्मू-कश्मीर की जनता उनका समर्थन करेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कश्मीर के मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना की बढ़त को रोकने के लिए प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री ने पंजाब की सीमा की तरफ से जवाबी हमला करने के आदेश दिए। दोनों देशों की सेनाओं के बीच घनघोर लड़ाई हुई और भारत की सेना आगे बढ़ते हुए लाहौर के नजदीक तक पहुँच गई।संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से इस लड़ाई का अंत हुआ। बाद में भारतीय प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच सोवियत संघ के मध्यस्थ में 1966 में ताशकंद समझौता हुआ।

बांग्लादेश युद्ध, 1971

1970में पाकिस्तान के पहले आम चुनाव में खंडित जनादेश आया। जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी पश्चिमी पाकिस्तान में विजयी रही जबकि मुजीबुर्रहमान की पार्टी अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में जोरदार कामयाबी हासिल की।मुजीबुर्रहमान की पार्टी ने पूर्वी पाकिस्तान के लिए अलग परिसंघ की मांग करने लगी । जिससे पाकिस्तानी सेना ने 1971 में शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म ढाने शुरू किए। जवाब में पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने अपने इलाके यानी मौजूदा बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए संघर्ष छेड़ दिया।

भारत ने बांग्लादेश के 'मुक्ति संग्राम' को नैतिक समर्थन और भौतिक सहायता दी। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत उसे तोड़ने की साजिश कर रहा है और इस तरह से भारत एवं पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया और 1971 के दिसंबर में भारत और पाकिस्तान के बीच एक पूर्णव्यापी युद्ध छिड़ गया। दस दिनों के अंदर भारतीय सेना ने ढाका को तीन तरफ से घेर लिया। जिससे पाकिस्तान को 90,000 सैनिकों के साथ आत्म समर्पण करना पड़ा। बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय के साथ भारतीय सेना ने अपनी तरफ से एकतरफा युद्ध-विराम घोषित कर दिया। बाद में 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गाँधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौते पर दस्तखत हुए और इससे अमन की बहाली हुई। 1998 में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत एवं पाकिस्तान के आपसी संबंध में विश्वास बढ़ेI अमृतसर एवं लाहौर के बीच बस सेवा प्रारंभ किया गया ताकि भारत एवं पाकिस्तान की जनता को एक दूसरे की यहां आने-जाने एवं आपसी संबंधों को मजबूत करने का मौका मिले और आपसी भाईचारे बढ़े। लेकिन यह संबंध भी अधिक दिनों तक स्थाई नहीं रह पाया और 1999 ई० में कारगिल युद्ध के रूप में सामने आया और दोनों देशों का संबंध वहीं पहुंच गया जहां से शुरू हुआ था।

Jharkhandstudy.com

अध्याय - 5 कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और स्थापना

वस्तुनिष्ठ प्रश्न-

1. **जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया ?**
   A. जवाहरलाल नेहरू B. इंदिरा गांधी
   C. 'लाल बहादुर शास्त्री D. जयप्रकाश नारायण

2. **काँग्रेस के किस नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए निर्विरोध चुना गया था?**
   A. श्रीमती इंदिरा गाँधी B. मोरारजी देसाई
   C. लाल बहादुर शास्त्री D. इनमें से कोई नहीं

3. **भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जनवरी 1966 ई० में कहां पर हुई थी?**
   A. ताशकंद B. शिमला
   C. पेरिस समझौता में D. इनमें से कोई नही

4. **शास्त्रीजी के पश्चात् श्रीमती इंदिरा गाँधी किस नेता को हराकर प्रधानमंत्री बनी थी।**
   A. के कामराज B. मोरारजी देसाई
   C. राम मनोहर लोहिया D. इनमें से कोई नहीं

5. **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी?**
   A. इंदिरा गांधी B. सोनिया गांधी
   C. एनी बेसेंट D. सरोजनी नायडू

6. **श्रीमती इंदिरा गाँधी दुबारा प्रधानमंत्री कब बनी थी ?**
   A. 1980 B. 1985
   C. 1975 D. इनमें से कोई नहीं

7. **इंदिरा गांधी के संबंध में कौन-सी बातें सही है ?**
   A. सन् 1966-1977 और सन् 1980 से 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रही ।
   B. सन् 1964 से 1966 में मंत्रिमंडल में केन्द्रीय मंत्री पद पर रही
   C. सन् 1967 सन् 1971 और 1980 में अपने नेतृत्व में काँग्रेस पार्टी को विजयी बनायी।
   D. उपरोक्त तीनों ।

8. **स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी?**
   A. इंदिरा गांधी B. एनी बेसेंट
   C. सोनिया गांधी D. सरोजिनी नायडू

9. **गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया ?**
   A. लाल बहादुर शास्त्री B. डॉ . राजेन्द्र प्रसाद
   C. राम मनोहर लोहिया D. इंदिरा गांधी

10. **20वीं सदी के किस दशक को भारत का खतरनाक दशक कहा जाता है ?**
    A. सन् 1950 के दशक B. सन् 1960 के दशक
    C. सन् 1970 के दशक D. सन् 1980 के दशक

11. **नेहरू जी के मृत्यु के समय काँग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन थे ?**
    A. जवाहरलाल नेहरू B. लाल बहादुर शास्त्री
    C. महात्मा गांधी D. कामराज

12. **'राजनीतिक भूकम्प' की संज्ञा किसे दिया गया ?**
    A. तीसरा आम चुनाव B. चौथा आम चुनाव
    C. जवाहरलाल की मौत D. इनमें से कोई नहीं

13. **1967 ई० के चुनावों के बारे में निम्नलिखित में कौन-कौन से कथन सही हैं?**
    A. काँग्रेस लोकसभा के चुनाव मेंसभी सीटों पर विजयी रही, लेकिन कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव वह हार गई।
    B. काँग्रेस लोकसभा के चुनाव भी हारी और विधानसभा के भी।
    C. कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला, लेकिन उसने दूसरी पार्टियों के समर्थन से एक गठबंधन सरकार बनाई।
    D. काँग्रेस केंद्र में सत्तासीन रही और उसका बहुमत भी बढ़ा।

14. **राम मनोहर लोहिया के संबंध में कौन सा तथ्य सही है ?**
    A. समाजवादी नेता एवं विचारक थे।
    B. पहले सोशलिस्ट पार्टी एवं बाद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता बने।
    C. पिछड़े वर्गों के आरक्षण की वकालत किये।
    D. उपरोक्त में से सभी।

15. **1971 ई० के चुनावों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-कौन से कथन सही हैं ?**
    A. इस चुनाव से पहले ही काँग्रेस विभाजन के कारण इंदिरा गाँधी की सरकार अल्पमत में आ गई
    B. इस चुनाव में चुनावी मुकाबला काँग्रेस (आई) और जनता दल में था
    C. इस चुनाव के दौरान इंदिरा गाँधी ने पूरी तरह प्रिवी पर्स की समाप्ति संबंधी अपने विचार को बिल्कुल त्याग दिया था
    D. उपरोक्त में कोई नहीं

16. **1971 ई के 'ग्रैंड अलायंस' के बारे में कौन-सा कथन ठीक है ?**
    A. इसका गठन गैर-कम्युनिस्ट और गैर-काँग्रेसी दलों ने किया था
    B. इसके पास एक स्पष्ट राजनीतिक तथा विचारधारात्मक कार्यक्रम था
    C. इसका गठन सभी गैर-काँग्रेसी दलों ने एकजुट होकर किया था
    D. उपरोक्त में कोई नहीं

17. **शास्त्री जी के संबंध में कौन-सा तथ्य असंगत है ?**
    A. भारत के दूसरे प्रधानमंत्री
    B. काँग्रेस पार्टी के महासचिव पद पर भी रहे
    C. स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके
    D. रेल दुर्घटना में नैतिक जिम्मेदारी लेकर रेल मंत्री पद से इस्तीफा

18. **सिंडिकेट नाम से किसे सम्बोधित किया गया ?**
    A. समाजवादियों के समूह को
    B. साम्यवादियों के समूह को
    C. काँग्रेसी नेताओं के एक समूह को
    D. इनमें से कोई नहीं

19. **आजादी के बाद शुरूआत में काँग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था ?**
    A. गाय बछड़ा B. दो बैलों की जोड़ी
    C. जलता दीया D. कोई नहीं

20. **मैनकाइड एवं जन के संस्थापक सम्पादक थे।**
    A. राममनोहर लोहिया B. इंदिरा गाँधी
    C. वी.वी. गिरि D. मोरारजी देसाई।

उत्तरः- 1-C,2-B,3-A,4-B,5-C,6-A,7-D,8-A, 9-D,10-B,11-D,12-B,13-C,14-D, 15-A,16-A,17-C,18-C,19-B,20-A.

jharkhandlab.com

अतिलघु उत्तरीय प्रश्नः-

1. ग्रैंड अलांयस से क्या अभिप्राय है?

उत्तर- 1971 के चुनाव के समय सभी बड़ी गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों द्वारा बनाया गया गठबंधन को ग्रैंड अलायंस कहा जाता था।

2. प्रारंभ में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था?

उत्तर- प्रारंभ में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह दो बैलों की जोड़ी थी। आजादी के लगभग 22 वर्ष गुजरते गुजरते कांग्रेस में फुट पड़ गई थी। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह पंजा छाप है।

3. 1960 के दशक को किन कारणों से खतरनाक दशक कहा जाता था?

उत्तर- इस समय गरीबी, असमानता, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीय विभाजन, युद्धों का सामना आदि समस्याये विद्यमान थी। इसीलिए 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता था।

4. चौथे आम चुनावों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी गई?

उत्तर- इस चुनाव में कांग्रेस की प्राप्त मत प्रतिशत तथा सीट संख्या में कमी आई और कांग्रेस 09 राज्यों में चुनाव हारी थी। अचानक इस परिवर्तन को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई।

5. युवा तुर्क कौन थे ?

उत्तर : यह कांग्रेस के कनिष्ठ व युवा वर्ग के नेताओं का समूह था। जिन्होंने पुराने नेतृत्व को चुनौती देकर इंदिरा गांधी को चुनावी संघर्ष में विजयी बनाया। ये युवा तुर्क के नाम से मशहूर हुए।

6. गरीबी हटाओ का नारा के पीछे क्या राजनीति थी?

उत्तर– गरीबी हटाओ की राजनीति जिसे काँग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी ने 1971 के फरवरी माह में लोकसभा के पाँचवें आम चुनाव के लिए उत्पन्न किया था। इसने काँग्रेस पार्टी की पुनः राजनीतिक शक्ति हथियाने में मदद की। इस नारे ने कांग्रेस पार्टी को भारी विजय दिलवायी। इस नारे का उद्देश्य समाजवादी व्यवस्था को व्यापक स्तर पर लागू करना था।

7. कांग्रेस सिंडिकेट से क्या आशय है?

उत्तर - काँग्रेस सिंडीकेट से आशय काँग्रेस के पुराने एवं वरिष्ठ नेताओं के गुट से था। जिसने इन्दिरा गाँधी को सत्ता से वंचित करने हेतु उन्हें दल की प्राथमिक सदस्यता से हटा दिया।

लघु उत्तरीय प्रश्नः-

1. 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी ?

उत्तर : कांग्रेस को इंदिरा गांधी के रूप में एक क्रांतिकारी नेता मिल गया। इंदिरा को जवाहरलाल नेहरू की राजनीतिक विरासत मिली थी, साथ ही उन्होंने अधिक प्रगतिशील कार्यक्रम जैसे गरीबी हटाओ, बैंक राष्ट्रीयकरण, कल्याणकारी सामाजिक एवं आर्थिक घोषणाएं की जिससे उन्हें लोकप्रियता मिली। इंदिरा गांधी की समाजवादी नीति लोगों को अधिक अच्छी लगी साथ ही देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने के कारण वह महिला मतदाताओं में अधिक लोकप्रिय हुई।

2. भारत में द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री की भूमिका समझाइए।

उत्तर- लाल बहादुर शास्त्री नेहरू के देहांत के समय उनके मंत्रिमंडल में मंत्री थे। सिंडिकेट के निर्णय के अनुसार लाल बहादुर शास्त्री को पंडित जवाहरलाल नेहरू का उत्तराधिकारी चुना गया। लाल बहादुर शास्त्री एक सरल, व इमानदार व्यक्ति थे।

लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उन्हें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा उन्होंने अत्यंत हिम्मत से सामना किया। भारत-चीन के बीच 1962 के युद्ध का भारत की आर्थिक व्यवस्था बहुत सोचनीय था। ख़राब मानसून हो जाने से खाद्य पदार्थों का संकट पैदा हो गया क्योंकि सूखा पड़ने से कृषि पैदावार में भारी कमी हो गई थी। 1965 का भारत- पाकिस्तान युद्ध उनके लिए दूसरी बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा लगाया। उन्होंने इस चुनौती से निपटने के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए। उन्होंने देशवासियों से हिम्मत रखने की अपील की।

3. 1971 में कांग्रेस की पुनर्स्थापना के कारण बताइए।

उत्तरः स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार में रही। 1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद उसके पास चमत्कारी नेतृत्व न रहा। 1967 के चुनावों में उसे हार का मुंह देखना पड़ा लेकिन किसी तरह से केंद्र पर इंदिरा गांधी की सरकार बनी रही, लेकिन राज्यों में दल - बदल के कारण कांग्रेस की सरकार गिरी। कांग्रेस विरोधी पार्टियां व गुटों ने एकजुट होकर कई राज्यों में अपनी सरकारी बनाई। लेकिन इंदिरा गांधी की चमत्कारी नेतृत्व ने 1971 के चुनावों में कांग्रेस को पुनः विशाल बहुमत मिला। केंद्र पर उसकी सबल सरकार बनी। और कांग्रेस खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त किया तथा इंदिरा गांधी की प्रभाव में वृद्धि हुआ।

4. लाल बहादुर शास्त्री पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें.

उत्तरः: श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 1904 में हुआ। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी की और उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के महासचिव का पदभार संभाला। वह 1951 से 56 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री पद पर रहे। इसी दौरान रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने रेल मंत्री से इस्तीफा दे दिया।

1957 से 1964 के बीच में मंत्री पद पर रहे। उन्होंने जय जवान, जय किसान का मशहूर नारा दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में 1964 से 1966 तक कार्यरत रहे।

5. प्रीवि पर्स से आप क्या समझते हैं?

उत्तरः श्रीमती इंदिरा गांधी के अनेक साहसिक कदमों में से प्रीवि पर्स को समाप्त करना एक साहसिक कदम था। जिसका उद्देश्य समाजवादी विचारधारा पर समाज का निर्माण करना था।प्रीवि पर्स व्यवस्था राजा महाराजाओ को कुछ निजी संपदा रखने का अधिकार दिया गया साथ-साथ सरकार की ओर से उन्हें कुछ विशेष भत्ते दिए जाते थे। इस प्रकार से प्रिवी पर्स उन राजा महाराजाओं को दी गई विशेष आर्थिक सुविधा थी। जिन्होंने सुरक्षा कारणों से अपने राज्यों को भारतीय संघ में विलय करना स्वीकार कर लिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरु जी प्रीवि पर्स के खिलाफ थे। परंतु कई नेताओं की ओर से समाप्त करने का विरोध होता रहा था। इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में 1971 में समाप्त कर दिया।

6. के कामराज कौन थे? संक्षिप्त विवरण दें।

उत्तरः के कामराज का जन्म 1903 में हुआ था। वे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने कांग्रेस के एक नेता के रूप में अत्यधिक ख्याति

Jharkhandlab.com

प्राप्त की। उन्हे मद्रास (तमिलनाडु) के मुख्यमंत्री के पद पर रहने का सौभाग्य मिला। मद्रास प्रांत के शिक्षा का प्रसार और स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन देने का योजना लागू करने के लिए उन्हे अत्यधिक ख्याति प्राप्त हुई। वह पार्टी के अध्यक्ष भी रहे।उन्होंने 1963 में कामराज योजना नाम से मशहूर प्रस्ताव रखा जिसके अंतर्गत उन्होंने सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को त्यागपत्र दे देने का सुझाव दिया। ताकि वह अपेक्षाकृत कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ताओ को पार्टी के कमान संभाल सके और कांग्रेस पार्टी को आगे ले जा सके।1975 में उनका देहांत हो गया।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्नः-

1. चौथे आम चुनाव 1967 पर एक लेख लिखें.

उत्तर- चौथा आम चुनाव 1967 में हुआ जो भारतीय राजनीति के लिहाज से बहुत ही ज्यादा अहम था। पहली बार पंडित जवाहर लाल नेहरू की अनुपस्थिति में चुनाव हुआ। चुनाव बाद कांग्रेस लगातार चौथी बार सरकार बनाने में तो सफल रही। लेकिन उसका प्रदर्शन पिछले चुनावों के मुकाबले फीका रहा । आम चुनाव के साथ राज्य विधानसभा चुनाव भी हुआ। राज्य विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा और 6 राज्य उससे छिन गए। यह चुनाव इंदिरा युग की शुरुआत का भी चुनाव था। इंदिरा गांधी अपने दिवंगत पति फिरोज की सीट रायबरेली से पहली बार चुनाव लड़ीं और जीत हासिल की।

तीसरी लोकसभा का कार्यकाल युद्ध, खाद्यान्न की कमी, सामाजिक तनाव और राजनीतिक उथल-पुथल के दौर के रूप में याद किया जाता है। जो1962 के भारत -चीन युद्ध , 1965 की भारत-पाक जंग, खाद्य संकट, आदि जैसी संकट की सदमे से बीमार हुए नेहरू का 1964 में देहांत हो गया तो उधर 1966 में ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो चुकी थी । हिंदुस्तान 1962 से 1966 के बीच ही 4-4 प्रधानमंत्रियों का गवाह बन चुका था। पंडित जवाहर लाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा (दो बार), लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री का पद संभाले हुए अभी पूरा एक साल भी नहीं गुजरा था साथ ही इंदिरा गांधी को राजनीति के लिहाज से कम अनुभवी माना जा रहा था और सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को अनुभवहीन साबित करने में लगे हुए थे। गुजरे वक्त में भी कांग्रेस के भीतर इस तरह के मतभेद उठ चुके थे लेकिन इस बार मामला कुछ अलग ही था। दोनों गुट चाहते थे कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में ताकत को आजमा ही लिया जाए। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने सभी कांग्रेसी सांसद और विधायको को पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार संजीव रेड्डी को वोट डालने का व्हिप जारी किया। उधर इंदिरा गांधी के समर्थक गुट ने वी वी गिरी का छुपे तौर पर समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुलेआम अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने को कहा। इसका मतलब यह था कि कांग्रेस के सांसद और विधायक अपनी मनमर्जी से किसी भी उम्मीदवार को वोट डाल सकते थे। अतः वीवी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार होते हुए भी विजयी हुए। जबकि संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार होते हुए भी हार गए। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार की हार से पार्टी का टूटना तय हो गया कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी से निष्कासित प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी ही असली कांग्रेस है और 1969 के नवंबर तक सिंडिकेट की अगुवाई वाले कांग्रेसी खेमे को कांग्रेस ऑर्गनाइजेशन, और इंदिरा गांधी की अगुवाई वाले कांग्रेस खेमे को कांग्रेस रिक्वेस्ट कहा जाने लगा था।

2. गैर-काँग्रेसवाद का अर्थ व प्रभाव समझाइए ।

उत्तर- आजादी के बाद से ही कुछ समाजवादी नेताओं ने देश में गैर-कांग्रेसवाद का राजनैतिक माहौल बनाने का प्रयास किया। वास्तव में, भारत विभिन्नताओं वाला एक विशाल देश था, जो आज भी है। देश में सारा राजनीतिक माहोल और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी हुई स्थिति देश की दलगत राजनीति से अलग-थलग नहीं रह सकती थी। विपक्षी दल जनविरोध की अगुआई कर रहे थे और सरकार पर दबाव डाल रहे थे। काँग्रेस की विरोधी पार्टियों ने महसूस किया कि उसके वोट बंट जाने के कारण ही काँग्रेस सत्तासीन है।

(ii) राजनैतिक दल जो अपने कार्यक्रम अथवा विचारधाराओं के धरातल पर एक-दूसरे से अलग थे, सभी दल एकजुट हुए और उन्होंने कुछ राज्यों में एक काँग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया तथा अन्य राज्यों में सीटों के मामले में चुनावी तालमेल किया। इन दलों को लगा कि इंदिरा गाँधी की अनुभवहीनता और काँग्रेस की अंदरूनी मतभेद से उन्हें काँग्रेस को सत्ता से हटाने का एक अवसर हाथ लगा है।

(iii) समाजवादी नेता राममनोहर लोहिया ने इस रणनीति को 'गैर-काँग्रेसवाद' का नाम दिया। उन्होंने 'गैर-काँग्रेसवाद' के पक्ष में सैद्धांतिक तर्क देते हुए कहा कि काँग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक और गरीब लोगों के हितों के खिलाफ है। इसलिए गैर-कांग्रेसी दलों का एक साथ आना जरूरी है, ताकि गरीबों के हित में लोकतंत्र को वापस लाया जा सके।

गैर-काँग्रेसवाद का प्रभाव - 1967 के आम चुनाव में यही हुआ कि गैर-कांग्रेसी वोट विभिन्न उम्मीदवारों में बँट जाने के बजाय एक ही उम्मीदवार को मिला जिससे काँग्रेस को सीटों व मतों के प्रतिशत में भी गिरावट आ गई। इस चुनाव में कॉग्रेस को 9 राज्यों में सरकारें खोनी पड़ी व केन्द्र में भी काँग्रेस को केवल साधारण बहुमत ही प्राप्त हुआ।

3. कांग्रेस पार्टी किन मसलों को लेकर 1969 में टूट की शिकार हुई?

उत्तर- 1967 के चुनावों के बाद केंद्र में कांग्रेस की सत्ता कायम रही, लेकिन पहले जैसा बहुमत नहीं मिला। साथ ही अनेक राज्यों में इस पार्टी के हाथ से सत्ता जाती रही। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया कि कांग्रेस को चुनावों में हराया जा सकता है। सिंडिकेट और इंदिरा गाँधी के बीच की गुटबाजी 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनाव के समय खुलकर सामने आ गई। तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण उस साल राष्ट्रपति का पद खाली था। इंदिरा गाँधी की असहमति के बावजूद उस साल सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन. संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करवाने में सफलता पाई। एन. संजीव रेड्डी से इंदिरा गाँधी की बहुत दिनों से राजनीतिक अनबन चली आ रही थी। ऐसे में इंदिरा गाँधी ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वी.वी. गिरि को बढ़ावा दिया कि वे एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन भरें। गुजरे वक्त में भी कांग्रेस के भीतर इस तरह के मतभेद उठ चुके थे, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग ही था। दोनों गुट चाहते थे कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में ताकत को आज़मा ही लिया जाए। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष एस.निजलिंगप्पा ने व्हिप जारी किया कि सभी कांग्रेसी सांसद और विधायक पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार संजीव रेड्डी को वोट डाले। उधर प्रधानमंत्री इंदिरा गाधी ने वी.वी. गिरी का छुपे तौर पर समर्थन करते हुए अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने को कहा। अंततः राष्ट्रपति चुनाव में वी.वी. गिरि ही विजयी हुए। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार की हार से पार्टी का टूटना तय हो गया। पुरानी कांग्रेस तथा नयी कांग्रेस दो दल बन गए। इंदिरा गाँधी ने पार्टी की इस टूट को विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में पेश किया और इस टूट का असर 1971 की आम चुनाव में भी दिखा।

4. प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद राजनीतिक उत्तराधिकार का वर्णन करें।

उत्तर- आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु बने। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कद्दावर नेता भी थे और पहले से ही उन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का समर्थन भी प्राप्त था। उन्होंने 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भारत को आगे ले जाने का प्रयास किया। लेकिन मई 1964 में उनकी मृत्यु के बाद यह प्रश्न उठने लगा कि नेहरू के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा।

पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कामराज थे। अब उत्तराधिकार का सारा दारोमदार कमराज पर था क्योंकि प्रधानमंत्री पद के लिए मोरारजी देसाई और जगजीवन राम खुलकर मैदान में आ गए थे। उधर कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा भी प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी इच्छा व्यक्त कर दी थी। जनवरी 1964 में जब नेहरू जी गंभीर बीमारी में पड़े हुए थे तब उन्होंने जयप्रकाश नारायण से संपर्क साधने की प्रयास किया था। लेकिन जयप्रकाश नारायण ने सक्रिय राजनीति में आने से साफ मना कर दिया। तब नेहरू जी ने अपना विश्वासी और करीबी व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री की ओर संकेत किया था।

अतः जब उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था तो पार्टी अध्यक्ष के कामराज ने पंडित नेहरू के संकेत का मान रखते हुए लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष को मजबूत किया। अनौपचारिक रूप से मोरारजी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री के बीच मुकाबला हुआ जिसमें लाल बहादुर शास्त्री को बहुमत प्राप्त हुआ अतः शास्त्री जी ने पंडित नेहरू जी के उत्तराधिकार के रूप में प्रधानमंत्री पद को संभाल लिया। शास्त्री जी ने जून 1964 से जनवरी 1966 तक भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में लगभग 18 महीना तक कार्यरत रहे। उनके शासनकाल में 1965 का भारत-पाक युद्ध शुरू हो गया। इससे पूर्व 1962 का भारत चीन युद्ध में भारत हार चुका था। शास्त्री जी ने अप्रत्याशित रूप से भारत के लिए उत्तम नेतृत्व प्रदान किया और पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। अतः पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान एवं भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद में एक समझौता के तहत जनवरी 1966 में हस्ताक्षर कर इस युद्ध का अंत किया। इसे ताशकंद समझौता के नाम से जाना जाता है। ताशकंद समझौता में हस्ताक्षर होने के पश्चात 11 जनवरी 1966 की रात में ही रहस्यमय परिस्थिति में उनकी मृत्यु हो गई । एक ईमानदार सादगी पूर्ण एवं उच्च कोटि की नेतृत्व प्रदान करने वाले महान व्यक्ति भारत ने सदा के लिए खो दिया। उनकी सादगी देशभक्ति और ईमानदारी के लिए मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

Jharkhandlab.com

अध्याय - 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट

वस्तुनिष्ठ प्रश्न-

1. **जब 1977 के चुनाव में जनता पार्टी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री का पद किसे मिला ?**
   A. मोरारजी देसाई B. जगजीवन राम
   C. चरण सिंह D. जयप्रकाश नारायण

2. **भारतीय संविधान का 42वाँ संशोधन कब हुआ ?**
   A. 1971 में B. 1976 में
   C. 1977 में D. 1978 में

3. **देश में 'आन्तरिक गड़बड़ी' के कारण आपातकाल की घोषणा कब हुई ?**
   A. 1975 में B. 1974 में
   C. 1972 में D. 1977 में

4. **संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया?**
   A. आचार्य कृपलानी B. राजनारायण
   C. चन्द्रशेखर D. जयप्रकाश नारायण

5. **1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन है ?**
   A. फखरूद्दीन अली अहमद B. जाकिर हुसैन
   C. ज्ञानी जैल सिंह D. इनमें से कोई नहीं

6. **भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है ?**
   A. भारतीय जनसंघ B. भारतीय क्रांति दल
   C. भारतीय लोक दल D. भारतीय जनता दल

7. **1971 के चुनाव में कांग्रेस का नारा क्या था?**
   A. जय जवान जय किसान B. गरीबी हटाओ
   C. उद्योग हटाओ D. अशिक्षा मिटाओ

8. **1974 में रेल हड़ताल रेलवे कर्मचारियों किसके नेतृत्व में शुरू किया था ?**
   A. जयप्रकाश नारायण B. महात्मा गांधी
   C. जॉर्ज फर्नांडिस D. राजेंद्र प्रसाद

9. **1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी के खिलाफ बतौर उम्मीदवार चुनाव में कौन खड़े हुए थे?**
   A. राज नारायण B. जयप्रकाश नारायण
   C. ए. एन. रे D. जगमोहन लाल सिन्हा

10. **पद्मश्री से सम्मानित किस हिंदी लेखक ने लोकतंत्र के दमन के विरोध में अपनी पदवी सरकार को लौटा दी?**
    A. शिवराम कारंत B. फणीश्वरनाथ रेणु
    C. माखनलाल चतुर्वेदी D. सुमित्रानंदन पंत

11. **आपातकाल के दौरान हुई गड़बड़ियों की जांच के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया था?**
    A. शाह आयोग B. हंटर आयोग
    C. नानावती आयोग D. लिब्रहान आयोग

12. **किसके नेतृत्व में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक पार्टी का गठन किया गया?**
    A. चौधरी चरण सिंह B. मोरारजी देसाई
    C. जयप्रकाश नारायण D. जगजीवन राम

13. **स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में पहले श्रम मंत्री कौन थे?**
    A. बी.आर. अंबेडकर B. जयप्रकाश नारायण
    C. जगजीवन राम D. मोरारजी देसाई

14. **नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई?**
    A. पश्चिम बंगाल B. बिहार
    C. उत्तर प्रदेश D. मध्य प्रदेश

15. **भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सवादी लेलिनवादी) की स्थापना किसने किया था?**
    A. लेनिन B. के करुणाकरण
    C. कार्ल मार्क्स D. चारू मजूमदार

उत्तरः

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	B	A	D	A	A	B	C	A	B	A	D	C	A	D

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

1. **इंदिरा इज़ इंडिया इंडिया इज़ इंदिरा का नारा किसने दिया था?**
   उत्तरः इंदिरा इज़ इंडिया,इंडिया इज़ इंदिरा का नारा कांग्रेस अध्यक्ष डीके बरुआ ने दिया था।

2. **किस पद्मभूषण से सम्मानित कन्नड़ लेखक ने आपातकाल के दौरान अपनी पदवी सरकार को वापस लौटा दिया?**
   उत्तरः पद्म विभूषण से सम्मानित कन्नड़ लेखक शिवराम कारंत ने अपनी पदवी सरकार को वापस लौटा दिया था।

3. **भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई?**
   उत्तर : 25 जून 1975 ई. को भारत में आपातकाल की घोषणा की गई।

4. **भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने?**
   उत्तरः भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने।

5. **संविधान के किस अनुच्छेद के तहत1975 में आपातकाल की घोषणा की गई।**
   उत्तरः संविधान के 352 अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा की गई।

6. **चारु मजूमदार कौन थे ?**
   उत्तरः चारु मजूमदार एक कम्युनिस्ट क्रांतिकारी और नक्सलबाड़ी विद्रोह के नेता थे। उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) की स्थापना की थीं।

7. **भारतीय संविधान के किस संशोधन को 'लघु संविधान' कहा जाता है?**
   उत्तरः भारतीय संविधान के 42वां संविधान संशोधन को 'लघु संविधान' कहा जाता है।

Jharkhandlab.com

8. सर्वोच्च न्यायालय ने अपने किस वाद में "संविधान के बुनियादी ढांचा"का सिद्धांत दिया?

उत्तरः सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती के मुकदमे में संविधान के बुनियादी ढांचा का सिद्धांत दिया।

9. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1975 में भारत के किस प्रधानमंत्री के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया था?

उत्तरः इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया था।

10. 1975 में आपातकाल की घोषणा भारत के किस राष्ट्रपति ने किया?

उत्तरः 1975 में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने की।

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. नक्सलवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं?

उत्तरः 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी थाने में एक किसान विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के स्थानीय कैडर के लोगों ने किया था। नक्सलबाड़ी थाने से शुरू हुआ यह आंदोलन भारत के कई राज्यों में फैल गया। इस आंदोलन को नक्सलवादी आंदोलन कहा जाता है।

1969 में नक्सलवादी सीपीआई (एम) से अलग हो गए और उन्होंने सीपीआई (मार्क्सवादी-लेलिनवादी) नाम से एक नई पार्टी चारू मजूमदार के नेतृत्व में बनाई इस पार्टी ने कहा भारत में लोकतंत्र एक छलावा है तथा उसने क्रांति करने के लिए गोरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। वर्तमान में 9 राज्यों के लगभग 75 जिले नक्सलवादी हिंसा से प्रभावित है।

2. संविधान के बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का क्या अर्थ है?

उत्तरः सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती के मशहूर मुकदमे में संविधान के बुनियादी ढांचा से संबंधित फैसला सुनाया जिसके अंतर्गत संसद संविधान के ढांचागत विशेषताओं में कोई संशोधन नहीं कर सकती है।

यधपि सर्वोच्च न्यायालय ने बुनियादी ढांचा को परिभाषित नहीं किया हैं फिर भी इसके आशय को यही समझा जा सकता है कि संसद मूल संविधान के मौलिक गुणों को जैसे मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, आदि अधिकार तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता आदि से संबंधित मूल चारित्रिक गुणों में संविधान संशोधन नहीं कर सकती हैं।

3. 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए थें ?

उत्तरः सरकार ने 25 जून 1975 के दिन आपातकाल की घोषणा कर दी, जिसके निम्नलिखित कारण सरकार ने बतलाई -

1. संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत 'आंतरिक गड़बड़ी' के कारण आपातकाल की घोषणा की गई।
2. कानून के शासन को खतरा उत्पन्न हो रहा हैं।
3. सरकार का तर्क था कि चुनी हुई सरकार को काम करने से रोका जा रहा है।
4. जगह-जगह आंदोलन एवं धरना का प्रदर्शन किया जा रहा है जिससे सरकार के कामकाज ठप्प हो रहे है।
5. अनेक आंदोलनों में हिंसक घटनाएं हो रही थी।
6. सेना, पुलिस जैसे सरकारी कर्मचारियों को विद्रोह के लिए उकसाया जा रहा था।
7. सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा था।
8. राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खतरा हो रहा था।
9. राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न करने का प्रयास हो रहा था।
10. अर्थव्यवस्था का संकट बढ़ते जा रहा था।

4. 1975 में आपात स्थिति लागू होने के क्या परिणाम थे?

उत्तरः आपातकाल लागू होने के बाद निम्न परिणाम सामने आए-

1. नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए गए।
2. देश की सभी शक्तियां केंद्र के पास आ गई संविधान का संघीयस्वरूप एकात्मक हो गया।
3. केंद्र सरकार की शक्तियां राज्यों पर हावी हो गई।
4. देश का लोकतांत्रिक स्वरूप बिगड़ गया।
5. संसद का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया।
6. संविधान में 42वां संशोधन किया गया जिसमें अनेक कानूनों को बदल दिया गया।
7. लोगों की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई।
8. प्रेस में सेंसरशिप लगाकर विचारों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित किया गया।
9. राष्ट्रपति की स्थिति कमजोर कर दी गई।
10. देश में कई प्रकार से डर एवं भय का माहौल पैदा हो गया।

5. शाह आयोग की नियुक्ति का क्या उद्देश्य था?

उत्तरः आपातकाल के बाद 1977 में चुनाव कराई गई जिसमें जनता पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार का गठन किया।

मई 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री जे सी शाह की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इसे शाह आयोग के नाम से जाना जाता है।इस आयोग का गठन आपातकाल के दौरान की गई कार्यवाही तथा सत्ता के दुरुपयोग, अतिचार और कदाचार के विभिन्न आरोपों के जांच के लिए किया गया था। आयोग में विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों की जांच की।हजारों गवाहों के बयान दर्ज किए।इन गवाहों में इंदिरा गांधी भी शामिल थी लेकिन वह आयोग के सामने नहीं उपस्थित हुई। आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौप दी।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. मध्यावधि चुनाव से क्या आशय है? किन कारणों से 1980 में मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े।

उत्तरः यदि लोकसभा या विधानसभा अपना निर्धारित कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व ही किन्ही विशेष परिस्थिति में भंग हो जाय और राष्ट्रपति शासन लग जाए। ऐसी परिस्थिति में निर्वाचन आयोग नई सरकार के गठन के लिए समय पूर्व चुनाव करवाती है।यह चुनाव मध्यावधि चुनाव कहलाता है।

भारत में आपातकाल 1975 ई में आंतरिक गड़बड़ी के कारण लागू की गई जो 1977 ई में समाप्त हुई। 1977 में लोकसभा के चुनाव हुए। इस चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ प्रमुख विरोधी दलों ने मिलकर जनता पार्टी का गठन किया जिसमें प्रमुख दल सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ,कांग्रेस ओल्ड तथा भारतीय लोकदल थे। बाद में जगजीवन राम की पार्टी "कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी"जनता पार्टी में शामिल हो गई।

1977 के चुनाव में जनता पार्टी और उसके साथी दलों को 330 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने।

जनता पार्टी की सरकार के पास किसी दिशा, नेतृत्व अथवा एक साझा कार्यक्रम का अभाव था। यह सरकार कांग्रेस द्वारा अपनाई गई नीतियों में कोई बुनियादी बदलाव नहीं ला सके। मोरारजी

Jharkhandlab.com

देसाई की नेतृत्व वाली सरकार ने 18 माह में ही अपना बहुमत खो दिया।

चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में दूसरी सरकार का गठन हुआ जिसे बाहर से कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन प्राप्त था लेकिन कांग्रेस पार्टी द्वारा 4 महीने के बाद समर्थन वापस लेने के कारण चौधरी चरण सिंह ने समय पूर्व लोकसभा भंग करके नए चुनाव कराने की सिफारिश की जिसको तत्कालीन राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी ने स्वीकार कर लिया इस प्रकार 1980 में मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े।

2. 1977 के चुनाव के बाद पहली दफा केंद्र में विपक्षी दल की सरकार बनी। ऐसा किन कारणों से संभव हुआ?

उत्तर: सरकार ने जनवरी 1977 में 18 महीने के आपातकाल के बाद चुनाव कराने का फैसला किया। चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस विरोधी दलों ने मिलकर जनता पार्टी नामक एक दल बनाया। इस नई पार्टी का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। कांग्रेस के कुछ नेता भी जो आपातकाल के विरोधी थे,इस पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेसी नेता जगजीवन राम की 'कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी' पार्टी भी जनता पार्टी में शामिल हो गई।

जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार में कांग्रेस की लोकतांत्रिक चरित्र और आपातकाल की यातना को जनता के सामने रखा तथा चुनाव को आपातकाल के खिलाफ जनमत संग्रह कहा। जनता पार्टी का गठन करके एक बात यह स्पष्ट हो गई थी कि गैर कांग्रेसी वोट अब एक ही जगह पड़ेंगे। इस लोक सभा के चुनाव परिणाम में कुल 542 सीटों में से 330 की सीटें जनता पार्टी एवं साथी दलों को प्राप्त हुई। यह एक स्पष्ट बहुमत था वहीं दूसरी ओर इंदिरा गांधी रायबरेली से तथा उनके पुत्र संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे। 1977 के चुनाव में पहली बार विपक्षी दल की सरकार बनने केनिम्नलिखित कारण थे -

1. देश में आर्थिक संकट व्याप्त था।
2. आवश्यक चीजों की कीमतों में वृद्धि।
3. सभी कांग्रेस विरोधी दलों का एकजुट होकर जनता पार्टी का निर्माण करना।
4. आपातकाल के दौरान की गई कार्यवाही।
5. देश की स्वतंत्रता पर हमला।
6. नागरिकों की स्वतंत्रता पर हमला।
7. मौलिक अधिकारों का हनन।

3. भारत की दलीय प्रणाली पर आपातकाल का किस तरह असर हुआ?अपने उत्तर की पुष्टि उदाहरणों से करें।

उत्तर:

1. दलीय व्यवस्था में गैर कांग्रेसवाद की राजनीति का विकास हुआ उन्हें यह विश्वास हो गया कि यदि विपक्षी दलों को अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उन्हें आपस में मिलकर कांग्रेस का मुकाबला करना जरुरी है।
2. आपातकाल के बाद सभी विपक्षी दलों ने यह निश्चय किया की आने वाल चुनाव में गैर- कांग्रेसी वोट बिखरने नहीं चाहिए। यदि गैर- कांग्रेसी वोट बिखर गए तो कांग्रेस को सत्ता से हटाना कठिन होगा।
3. आपातकाल के बाद देश में जनता पार्टी का गठन हुआ जिसमें सभी सभी प्रमुख दलों ने सम्मिलित होना स्वीकार किया और अपने स्वतंत्र अस्तित्व तथा अलग पहचान को समाप्त करके एक दल बनाने पर सहमत हुए। कई लेखक 1977 को भारतीय दलीय प्रणाली में दो दलीय व्यवस्था के आरंभ को देखते हैं। उनका ऐसा विचार था की अब देश में दो दलीय व्यवस्था विकसित होगी। परन्तु यह बात सत्य नहीं निकली और जनता पार्टी 18 माह में ही बिखर गई।
4. आपातकाल के बाद कांग्रेस जो अपने को असली कांग्रेस कहती थी उसमे भी विभाजन हुआ। इसके कई नेता जो आपातकाल के समर्थन नहीं करते थे परन्तु आपातकाल में विरोध प्रकट करने का साहस नहीं कर सके थे। आपातकाल के बाद बाबू जगजीवन राम के नेतृत्व में कांग्रेस से अलग हो गए और उन्होंने 'कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी' नामक अपना अलग दल बना लिया।
5. आपातकाल के बाद सभी दल जनमत की परिपक्वता में विश्वास करने लगे और पिछड़े वर्गों की भलाई की नीति लगभग सभी दलों ने अपनाई।
6. आपातकाल के बाद कई राज्यों में भी विपक्षी दलों ने एकजुट होकर कांग्रेस का मुकाबला किया और कई राज्यों में विधान सभा चुनावों में उन्होंने आपस में मिलकर चुनाव लड़कर कांग्रेस को सत्ताहीन किया। दलीय व्यवस्था में गैर-कांग्रेसवाद की राजनीति का विकास हुआ। उन्हें यह विश्वास हो गया की यदि विपक्षी दलों ने अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उन्हें आपस में मिलकर कांग्रेस से मुकाबला करना जरूरी है।

Jharkhandmap.com

अध्याय - 7 जन आन्दोलनों का उदय

वस्तुनिष्ठ प्रश्न-

1. चिपको आन्दोलन किस राज्य में हुआ ?
(A) कर्नाटक (B) महाराष्ट्र
(C) उत्तराखण्ड (D) गुजरात।

2. चिपको आन्दोलन के प्रणेता कौन है?
(A) मेधा पाटकर (B) सुन्दर लाल बहुगुणा
(c) अन्ना हजारे (D) विमल जोगी

3. "चिपको आन्दोलन" कब हुआ?
(A) 1971 ई. में (B) 1972 ई. में
(C) 1973 ई0 में (D) 1974 ईस्वी में

4. उतराखण्ड के गाँव वालों ने वन विभाग से खेती बाड़ी के औजार बनाने के लिए किस पेड़ को काटने की अनुमति माँग रहे थे ?
(A) अंगू के पेड़ (B) आम के पेड़
(C) साल के पेड़ (D) अर्जुन के पेड़

5. किसे नए सामाजिक आन्दोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता ?
(A) चिपको आन्दोलन (B) नर्मदा बचाओ आंदोलन
(c) टेहरी बाँध आन्दोलन (D) गृह स्वराज आंदोलन

6. दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना कब की गई?
(A) 1972 ईस्वी में (B) 1950 ईस्वी में
(C) 1947 ईस्वी में (D) 1942 ईस्वी में

7. दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना कहां की गई?
(A) महाराष्ट्र (B) उत्तराखंड
(C) गुजरात (D) इनमें से कोई नहीं

8. दलित पैंथर्स की मुख्य नीतियां क्या थी?
(A) दलित पर हो रहे अत्याचारों से बचाना,
(B) विधान मंडलों में दलितों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिलाना,
(C) दलित आरक्षण की मांग,
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

9. भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख मांगे क्या थी?
(A) गन्ने एवं गेहूं की सरकारी खरीद मूल्यों में बढ़ोतरी,
(B) समुचित उचित मूल्य पर बिजली की आपूर्ति,।
(C) किसानों का बकाया कर्ज माफ हो
(D) इनमें से सभी।

10. भारतीय किसान यूनियन का गठन कहां हुआ?
(A) महाराष्ट्र में (B) उत्तर प्रदेश में
(C) उत्तराखंड में (D) हरियाणा में

11. ताड़ी विरोधी आंदोलन भारत के किस राज्य का आंदोलन था?
(A) आंध्र प्रदेश (B) गुजरात
(C) बिहार (D) उत्तर प्रदेश

12. चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था?
(A) कृषि का विकास
(B) पर्यावरण की रक्षा
(C) गांधीवादी विचारों का प्रचार-प्रसार
(D) इनमें से कोई नहीं।

13. एपिको आंदोलन कहां चलाया गया था?
(A) आंध्र प्रदेश (B) कर्नाटक
(C) केरल (D) उत्तराखंड

14. सितंबर 1983 ईस्वी में किस सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा एपिको आंदोलन चलाया गया?
(A) सुंदरलाल बहुगुणा (B) मेधा पाटेकर
(C) पांडुरांग हेगड़े (D) महात्मा गांधी

15. सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया?
(A) 2003 (B) 2004
(C) 2005 (D) 2006

16. मेधा पाटेकर निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित हैं?
(A) नर्मदा बचाओ आंदोलन (B) टेहरी बांध आंदोलन
(C) चिपको आंदोलन (D) ताड़ी विरोधी आंदोलन

उत्तरः-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	B	C	A	D	A	A	A	D	B	A	B	B	C	C	A

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. चिपको आंदोलन से क्या अभिप्राय है?

उत्तर- चिपको आन्दोलन एक पर्यावरण-रक्षा का आन्दोलन था। यह भारत के मौजूदा उत्तराखण्ड राज्य में स्त्री और पुरुषों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परम्परागत अधिकार जता रहे थे। गांव के लोगों ने अपने विरोध को जताने के लिए एक नई तरकीब अपनाई। स्त्री - पुरुष पेड़ों से चिपक जाते थे ताकि पेड़ों को न काटा जा सके इसलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है।

प्रश्न 2. 1970 के दशक में पेड़ों को कटने से बचाने के लिए किस आंदोलन की शुरुआत हुई तथा आंदोलन का क्षेत्र वर्तमान में किस राज्य के अंतर्गत आता है?

उत्तर- चिपको आंदोलन। यह आंदोलन वर्तमान उत्तराखंड राज्य में चलाया गया था।

प्रश्न 3. ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ और क्यों चलाया गया?

उत्तर- ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में महिलाओं ने शराब माफियाओं के खिलाफ आंदोलन किया था क्योंकि ग्रामीणों को शराब की गहरी लत लग चुकी थी। इसके चलते वे शारीरिक और मानसिक रूप से भी कमजोर हो गए थे। शराबखोरी से क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। शराब खोरी के बढ़ने से कर्ज का बोझ बढ़ा। पुरुष अपने काम से लगातार गैरहाजिर रहने लगे। ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा था-' ताड़ी की बिक्री बंद करो।'

jharkhandlab.com

प्रश्न 4. किस वर्ष भारत के किस राज्य में ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था?

उत्तर- 1992 के सितंबर- अक्टूबर माह में आंध्र प्रदेश राज्य में ताड़ी विरोधी आंदोलन चलाया गया था।

प्रश्न 5. भारतीय किसान यूनियन देश के किन क्षेत्रों में अधिक सक्रिय हैं?

उत्तर- भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब व राजस्थान में अधिक सक्रिय हैं।

प्रश्न 6. सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? क्या इस अधिनियम के दायरे में गैर सरकारी संस्थान भी आते हैं?

उत्तर- सूचना का अधिकार अधिनियम जून 2005 में लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत सरकारी संस्थान के साथ-साथ सरकार से वित्त पोषित गैर-सरकारी संस्थान भी आते हैं।

प्रश्न 7. भारतीय किसान यूनियन के बारे में आप क्या समझते हैं?

उत्तर- भारतीय किसान यूनियन पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा और पंजाब के किसानों का एक संगठन था। 80 के दशक के किसान आंदोलन के अग्रणी संगठनों में से एक था। यह संगठन विभिन्न तरीकों से समय-समय पर प्रभावित करता रहा है।

प्रश्न 8. "दलित पैंथर्स " क्या है?

उत्तर- दलित पैंथर्स महाराष्ट्र के दलित युवाओं का एक संगठन है। इसका गठन 1972 में किया गया। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था जातिवाद, छुआछूत व इन आधारों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ लड़ना और भारतीय संविधान में इन कुरीतियों को दूर करने के लिए विभिन्न प्रावधानों, सरकारी नीतियों और कानूनों को लागू करना था।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. जन आंदोलन से क्या अभिप्राय है?दल आधारित सामाजिक आंदोलनों तथा राजनीतिक दलों से स्वतंत्र सामाजिक आंदोलनों के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर- 'जन आंदोलन' जब किसी समस्या या मांग को लेकर लोगों द्वारा एक साथ आंदोलन किया जाता है तो उसे जन आंदोलन कहते हैं।जन आंदोलन करने के कई कारण हो सकते हैं जैसे गरीबी,बेरोजगारी या लोगों की कोई मांग पूरी ना हो पाना।

जन आंदोलनों के दो प्रकार होते हैं-

(क) दल आधारित जन आंदोलनः- जो आंदोलन किसी राजनीतिक दल के सहयोग से शुरू किए जाते हैं अर्थात वह आंदोलन जिनमें राजनीतिक दल शामिल होते हैं।ऐसे आंदोलनों को दल आधारित आंदोलन कहा जाता है। जैसे नक्सलवादी आंदोलन।

(ख) राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलनः- वह आंदोलन जिनमें कोई भी राजनीतिक दल शामिल नहीं होता; उन्हें राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन कहते हैं। जैसे दलित पैंथर्स, चिपको आंदोलन ताड़ी विरोधी आंदोलन आदि।

प्रश्न 2. भारतीय किसान यूनियन की किन्ही चार मांगों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर- भारतीय किसान यूनियन की चार मुख्य माँगे निम्नलिखित है-।

(क) बिजली की बढ़ाई गई दरों को कम करना।

(ख) गन्ने ओर गेहूं के सरकारी मूल्य को बढ़ाना।

(ग) किसानो के लिए पेंशन की व्यवस्था करना एवं

(घ) किसानों को बचा हुआ क़र्ज़ माफ़ करना।

प्रश्न 3. क्या चिपको आन्दोलन को महिला आन्दोलन कहा जा सकता है ? कारण बताइए ।

उत्तर - चिपको आंदोलन को महिला आंदोलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया व पर्यावरण की सुरक्षा व पेड़ों की सुरक्षा के मुद्दो के साथ - साथ महिलाओं से जुड़े अनेक मुद्दों को भी उठाया। चिपको आंदोलन में महिलाओं ने शराब, ताड़ी, दहेज, महिलाओं पर पुरुषों के द्वारा किये गये शारीरिक व मानसिक शोषण जैसे मुद्दे भी उठाये। इस आंदोलन से महिलाओं ने वन अधिकारियों व ठेके द्वारा किये गये गलत कार्यों को भी उजागर किया तथा उनके परिवार के पुरुषों को नशे की लत डालकर किस प्रकार से उनके परिवारों को आर्थिक संकट में डाल रहे थे। अतः ये सभी प्रश्न महिलाओं को प्रभावित कर रहे थे जिससे महिलाओं ने इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका अदा की।

प्रश्न4. सरदार सरोवर परियोजना से क्या तात्पर्य है?

उत्तर- 1980 के दशक के प्रारंभ में भारत के मध्य भाग में स्थित नर्मदा घाटी के विकास परियोजना के तहत मध्यप्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र से गुजरनेवाली नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर 30 बड़े, 135 मझले आकार के व 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया। गुजरात के सरदार सरोवर व मध्य प्रदेश के नर्मदा सागर बांध के रूप में दो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना का निर्धारण किया।

इस परियोजना के निम्न उद्देश्य थे -

(क) पीने के पानी, व सिंचाई के लिए सुनिश्चित करना।

(ख) बिजली उत्पादन के उद्देश्य से।

(ग) कृषि विकास को बढ़ाने व कृषि की पैदावार को बढ़ाने के लिए।

(घ) बाढ़ और सूखे की आपदाओं पर अंकुश लगाना।

प्रश्न5. सूचना के अधिकार का आन्दोलन पर प्रकाश डालिए।

उत्तर- सूचना के अधिकार का अर्थ है जानने का अधिकार, जो प्रजातंत्र के विकास में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। सूचना के अधिकार को प्राप्त करने के लिए आंदोलन का प्रारम्भ 1990 में हुआ और इसका नेतृत्व किया मजदूर किसान शक्ति संगठन ने। राजस्थान में काम कर रहे इस संगठन ने सरकार के सामने यह मांग रखी कि अकाल, राहत कार्य और मजदूरों को दी जाने वाली पगार के रिकार्ड का सार्वजनिक खुलासा किया जाये। धीरे -धीरे यह आंदोलन मजबूत हुआ और सरकार को इस आंदोलन की मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी पड़ी। वर्ष 2004 में सूचना के अधिकार के विधेयक को सदन में रखा गया। जून, 2005 में विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी हासिल हुई।

प्रश्न 6. दलित पैंथर आंदोलन किस राज्य में हुआ? इसकी प्रमुख मांगे क्या थी?

उत्तर- 1972 में महाराष्ट्र में शिक्षित दलित युवाओं ने दलित पैंथर्स नाम से एक संगठन बनाया। इन्होंने दलितों के खिलाफ हो रह भेदभाव का विरोध किया। इनके विरोध का तरीका अन्य आंदोलनों से अलग रहा। साहित्य और बड़े बड़े मंचो पर आवाज़ उठा कर इन्होंने लोगों को दलितों पर हो रहे अत्याचारों से परिचित करवाया। दलित युवकों ने भी अत्याचार का बढ़ चढ़ कर विरोध किया।

दलित पैंथर्स की मुख्य मांगें:-

(क) जाति - आधारित असमानताओं का विरोध ।

(ख) भौतिक संसाधनों के मामले में अपने साथ हो रहे अन्याय का विरोध।

(ग) दलित महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोका जाए।

(घ) सामाजिक न्याय की नीतियों का कारगर क्रियान्वयन हो, आदि।

Jharkhandone.com

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में (अब उत्तराखंड) 1970 के दशक में किन कारणों से चिपको आंदोलन का जन्म हुआ? इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा?

उत्तर- चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के दो-तीन गांव से हुई थी। गांव वालों ने वन विभाग से मांग किया,कि खेती-बाड़ी के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ काटने की अनुमति दिया जाए। इस पर वन विभाग ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। परंतु वन विभाग ने खेल सामग्री के लिए एक विनिर्माता को व्यवसायिक इस्तेमाल के लिए पेड़ काटने की अनुमति दी। इससे गांव वालों में रोष पैदा हुआ और उन्होंने सरकार की इस कदम का कड़ा विरोध किया। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी सक्रिय भागीदारी की। महिलाएं पेड़ों से चिपक जाती थी, ताकि पेड़ कटने से बचाया जा सके। इसलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन कहते हैं।

चिपको आंदोलन का प्रभाव:-

1. यह आंदोलन बहुत जल्दी उत्तराखंड के अन्य इलाकों में भी फैल गया। क्षेत्र की परिस्थितिकी और आर्थिक शोषण के सवाल उठाए जाने लगे।
2. चिपको आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभायी। इस क्षेत्र में जंगल कटाई ठेकेदार यहां के पुरुषों को शराब की आपूर्ति करते थे। महिलाओं ने शराबखोरी ठेकेदारों के खिलाफ लगातार आवाज उठायी। इससे आंदोलन का दायरा विस्तृत हुआ और इसमें कुछ और सामाजिक मसले आकर जुड़ गए।
3. सरकार ने 15 सालों के लिए इस क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी ताकि इस अवधि में क्षेत्र का वनाच्छादन फिर से ठीक अवस्था में आ जाए।
4. यह आंदोलन 1970 के दशक और उसके बाद के सालों में देश के विभिन्न भागों में उठने लगे।

प्रश्न 2. भारतीय किसान यूनियन किसानों की दुर्दशा की तरफ ध्यान आकर्षित करने वाला अग्रणी संगठन है। 90 के दशक में इसने किन मुद्दों को उठाया और कहां तक सफलता मिली?

उत्तर- भारतीय किसान यूनियन पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा और पंजाब के किसानों का एक संगठन था। 1980 के दशक के किसान आंदोलन के अग्रणी संगठनों में से एक था। यह संगठन विभिन्न तरीकों से समय-समय पर प्रभावित करता रहा है।

भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे निम्नलिखित थी:-

1. गन्ने और गेहूं की सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करना।
2. कृषि उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगे प्रतिबंध को हटाना।
3. समुचित दर पर गारांटीशुदा बिजली आपूर्ति करना।
4. किसानों के बकाया कर्ज माफ करना।
5. किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान करना।

भारतीय किसान यूनियन की सफलता-

1. बिजली की दर में की गई बढ़ोत्तरी सरकार द्वारा वापस लिया गया।
2. 1990 के दशक के शुरुआती सालों में भारतीय किसान यूनियन ने अपने को सभी राजनीतिक दलों से दूर रखा।
3. यह अपने सदस्यों की संख्या बल के दम पर एक दबाव समूह की तरह सक्रिय रहा।
4. इस संगठन ने राज्यों में मौजूद अन्य संगठनों को साथ लेकर अपनी कुछ मांगे मनवाने में सफलता पाई।

इस प्रकार 1980 के दशक में सबसे ज्यादा सफल सामाजिक आंदोलन था। इस आंदोलन की सफलता के पीछे इसके सदस्यों की राजनीतिक मोल - भाव की क्षमता का हाथ था।

प्रश्न 3. आंध्र प्रदेश में चले शराब विरोधी आंदोलन ने देश का ध्यान कुछ गंभीर मुद्दों की ओर खींचा। यह मुद्दे क्या थे?

उत्तर- आंध्र प्रदेश में महिलाओं का एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन चल पड़ा। ये महिलाएं अपने आस -पड़ोस में मदिरा की बिक्री पर पाबंदी की मांग कर रही थी। 1992 की सितंबर अक्टूबर माह में ग्रामीण महिलाओं ने शराब के खिलाफ लड़ाई छेड़ रखी थी।यह लड़ाई शराब माफिया और सरकार दोनों के खिलाफ थी। इस आंदोलन ने ऐसा रूप धारण किया कि इसे राज्य में ताड़ी विरोधी आंदोलन के नाम से जाना गया।

आंदोलन का उदय

आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले के दूर दराज के गांव दुबरगंटा में महिलाओं के बीच प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें महिलाओं ने घर के पुरुषों द्वारा देशी शराब,ताड़ी आदि पीने की शिकायत की। ग्रामीणों को शराब की गहरी लत लग चुकी थी। इसके चलते वे शारीरिक और मानसिक रूप से भी कमजोर हो गए थे। शराब खोरी से क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। शराब खोरी के चलते कर्ज का बोझ बढ़ा। पुरुष अपने काम से लगातार गैरहाजिर रहने लगे। जिससे महिलाओं को दिक्कत होने लगी।

मेला में महिलाएं शराब की बिक्री के खिलाफ आगे आई और उन्होंने शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। यह खबर आग की तरह फैली और 5000 गांव की महिलाओं ने इस आंदोलन में भाग लिया। नेल्लोर जिले का यह आंदोलन धीरे-धीरे पूरे राज्य में फैल गया।

आंदोलन के मुख्य मुद्दे :-

1. ताड़ी की बिक्री पर रोक लगाना।
2. इसकी मांग ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मसलों के बहुत बड़े वर्ग को छुआ। जिससे ताड़ी व्यवसाय को लेकर अपराध एवं राजनीति के बीच गहरा नाता बन गया था।
3. महिलाओं ने खुले तौर पर घरेलू हिंसा जैसे दहेज,यौन उत्पीड़न आदि का विरोध करनी शुरू कर दी।
4. 1990 के दशक आते-आते महिला आंदोलन समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग की।
5. विधानसभा और संसद में महिला आरक्षण की मांग।

प्रश्न 4. नर्मदा बचाओ आंदोलन ने नर्मदा घाटी की बांध परियोजनाओं का विरोध क्यों किया?

उत्तर- 1980 के दशक के प्रारंभ में भारत के मध्य भाग में स्थित नर्मदा घाटी में विकास परियोजना के तहत मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाली नर्मदा और उसके सहायक नदियों पर 30 बड़े, 135 मझोले तथा 300 छोटे बाँध बनाने का प्रस्ताव रखा गया। गुजरात के सरदार सरोवर और मध्य प्रदेश के नर्मदा सागर बाँध के रूप में दो सबसे बड़ी और बहु-उददेश्यीय परियोजनाओं का निर्धारण किया गया। नर्मदा नदी के बचाओ में नर्मदा बचाओ आन्दोलन चला। इस आन्दोलन ने बाँध के निर्माण का विरोध किया। नर्मदा बचाओ आन्दोलन इन बाँधों के निर्माण के साथ साथ देश में चल रही विकास परियोजनाओं के औचित्य पर भी सवाल उठाया –

Jharkhandlab.com

1. नर्मदा बचाओ आंदोलन' सरदार सरोवर परियोजना को विकास परियोजनाओं के बृहत्तर मुद्दों से जोड़कर देखता रहा है। यह आदोलन विकास के मॉडल और उसके औचित्य पर भी सवाल उठाता रहा है और इसके अनुसार इस बात का भी जायजा लिया जाना चाहिए कि समाज के विभिन्न वर्गों को इन परियोजनाओं का क्या खामियाज़ा भुगतना पड़ा है।

2. इसने माँग की कि अब तक की सभी विकास परियोजनाओं पर हुए खर्च की जांच किया जाए, क्योंकि बाँध के निर्माण की वज़ह से राज्यों के 245 गाँव डूबने के क्षेत्र में आ रहे थे और प्रभावित गाँवों के करीब ढाई लाख लोगों के पुनर्वास का मुद्दा भी सामने था।

3. आन्दोलन ने इन परियोजनाओं के निर्माण की वजह से प्रभावित लोगों के उचित पुनर्वास की भी माँग की।

4. आन्दोलन के लोगों ने इन महाकाय विकास परियोजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए।

5. इस आन्दोलन में इस बात पर बल दिया गया कि ऐसी परियोजनाओं की निर्णय-प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों की भागीदारी होनी चाहिए और जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर उनका प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए।

6. 2003 में सरकार द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को नर्मदा बचाओ जैसे सामाजिक आंदोलन की उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है।

Jharkhandlab.com

अध्याय - 8 क्षेत्रीय आकांक्षाएं

वस्तुनिष्ठ प्रश्न-

1. **सन् 1986 में नेशनल फ्रंट ने किस पार्टी को गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतारा ?**
   a. जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट
   b. अकाली दल
   c. कांग्रेस
   d. कम्युनिस्ट पार्टी

2. **शेख अब्दुल्ला की मृत्यु कब हुई ?**
   a. सन् 1981 में b. सन् 1982 में
   c. सन् 1984 में d. सन् 1980 में

3. **भारत का 29 वां राज्य कौन है ?**
   a. झारखंड b. छत्तीसगढ़
   c. उत्तरांचल d. तेलंगाना

4. **जम्मू कश्मीर किस वर्ष तक उग्रवादी आंदोलन की गिरफ्त में आ चुका था ?**
   a. सन् 1989 तक b. सन् 1980 तक
   c. सन् 1985 तक d. सन् 1995 तक

5. **धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से हैं ?**
   a. उत्तर प्रदेश b. जम्मू और कश्मीर
   C. उत्तराखंड d. बिहार

6. **भारतीय आंदोलन में क्षेत्रीयतावादी भावनाओं की सर्वप्रथम और प्रबल आंदोलन किसे माना जाता है ?**
   a. आर्य आंदोलन b. खालिस्तान आंदोलन
   c. द्रविड़ आंदोलन d. असम आंदोलन

7. **सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया ?**
   a. बिहार b. पश्चिम बंगाल
   c. महाराष्ट्र d. तमिलनाडु

8. **संविधान की किस धारा के तहत कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है?**
   a. धारा 370 b. धारा 372
   c. धारा 374 d. धारा 380

9. **डी० एम० के० का संस्थापक कौन था ?**
   a. सी० अन्नादुर b. ई० वी० रामास्वामी
   c. सर सी० वी० रमन d. इनमें से कोई नहीं

10. **सन् 1920 के दशक में अकाली दल का गठन हुआ जिसके द्वारा कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ ?**
    a. केंद्र में किसानों की मांग का
    b. अलग पंजाबी सुबे की गठन का
    c. खालिस्तान की मांग का
    d. उपरोक्त में कोई नहीं

11. **"कश्मीर मुद्दा" भारत और किस देश के बीच एक विवाद है?**
    a. बांग्लादेश। b. श्रीलंका।
    c. पाकिस्तान। d. चीन।

12. **मास्टर तारा सिंह किसके नेता थे?**
    a. एसजीपीसी। b. एआईएडीएमके।
    c. एमडीएमके। d. पीडीपी।

13. **पूर्वोत्तर भारत के सात बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है ?**
    a. मणिपुर b. मिजोरम
    c. नागालैंड d. पंजाब

14. **किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ ?**
    a. तमिल b. मलयालम
    c. कन्नड़ d. तेलुगू

15. **नागा राष्ट्रीय परिषद के नेता कौन थे?**
    a. वी.पी. सिंह b. लाई डेंगा
    c. करुणानिधि d. अंगमे ज़ापू फ़िज़ो

16. **देश में भाषा के आधार पर निम्न में से किस राज्य के गठन की माँग की गई थी ?**
    a. आंध्र प्रदेश b. कर्नाटक
    c. महाराष्ट्र d. उपरोक्त सभी

17. **हिन्दी को राजभाषा बनाने के खिलाफ निम्न में से किस राज्य में विरोध आंदोलन चला?**
    a. तमिलनाडु b. पंजाब
    c. हरियाणा d. गुजरात

18. **पंजाबी भाषी लोगों ने अपने लिए अलग राज्य बनाने की माँग कब प्रारंभ की?**
    a. 1960 के दशक में b. 1950 के दशक में
    c. 1970 के दशक में d. 1980 के दशक में

19. **पंजाब और हरियाणा राज्यों का गठन कब हुआ?**
    a. 1950 मे b. 1947 में
    c. 1966 में D. 1977 में

20. **जम्मू एवं कश्मीर में निम्न में से कौन-सा क्षेत्र शामिल है ?**
    a. जम्मू b. कश्मीर
    c. लद्दाख d. उपरोक्त सभी

21. **कश्मीर में अधिकतर किस धर्म के लोग रहते हैं?**
    a. मुस्लिम b. हिन्दू
    c. सिख d. बौद्ध

22. **शेख अब्दुल्ला को जम्मू-कश्मीर राज्य का प्रधानमंत्री कब बनाया गया?**
    a. मार्च 1948 b. अक्टूबर 1947
    c. मार्च 1947 d. मार्च 1974

jharkhandlab.com

23. पूर्वोत्तर क्षेत्र में कितने राज्य हैं?

a. पाँच b. दो

c. सात d. ग्यारह

Ans- 1c.2b 3d 4a 5b 6c 7a 8a 9a 10b 11c 12a 13d 14d 15d 16d 17a 18b 19c 20d 21a 22a 23c

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

1. आजाद कश्मीर क्या है?

उत्तर- 31दिसम्बर 1948 के भारत-पाक युद्ध विराम के पश्चात् विराम के परिणामस्वरूप जो सेनाएँ जिस क्षेत्र में थीं वही क्षेत्र उनके अधिकार में रह गया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला क्षेत्र आजाद कश्मीर कहलाता है।

2. रोजा फिल्म किस पृष्ठभूमि पर बनी थी?

उत्तर- भारत पाकिस्तान विवाद पर।

3. आपरेशन ब्लू स्टार क्या था?

उत्तर- आपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना द्वारा 1 से 8 जून 1984 को अमृतसर (पंजाब, भारत) स्थित हरमंदिर साहिब परिसर को ख़ालिस्तान समर्थक जनरैल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए चलाया गया अभियान था।

4. क्षेत्रवाद और पृथकतावाद में क्या अंतर है?

उत्तर- **क्षेत्रवाद** - क्षेत्रीय आधार पर राजनीतिक,आर्थिक एवं विकास सम्बन्धी मांग उठाना।

पृथकतावाद - किसी क्षेत्र का देश से अलग होने की भावना होना या मांग उठाना ।

5. स्वायत्तता से आप क्या समझते हैं?

उत्तर- किसी दूसरे के हस्तक्षेप के बगैर व्यक्ति विशेष, संस्था, राज्य का देश के अधिकार क्षेत्र में विषयों और मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेना।

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. क्षेत्रीय असंतुलन से आप क्या समझते हैं?

उत्तर- क्षेत्रीय असंतुलन का आशय है भारत के विभिन्न राज्यों तथा क्षेत्रों का विकास का एक जैसा नहीं होना है। कुछ राज्यों का आर्थिक विकास दुसरे राज्यों की अपेक्षा बहुत तेजी से हुआ है। परिणामस्वरूप वहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी ऊँचा है जबकि कुछ राज्यों का जिनका विकास बहुत कम हुआ है। वहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी बहुत निम्न स्तर का है । भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विकास स्तर और लोगों के जीवन स्तर में पाए जाने वाले अंतर को क्षेत्रीय असंतुलन का नाम दिया जाता है। । उदाहरण के तौर पर पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल आदि राज्य अत्यधिक विकसित हैं जबकि बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश आदि अति पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। भारत की भौगोलिक विषमताओं ने क्षेत्रीय असंतुलन पैदा किया है। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भी क्षेत्रीय अंसतुलन हुई है भारत में एक ओर राजस्थान जैसा मरुस्थल है जो कम उपजाऊ है तो दूसरी ओर पंजाब जैसे उपजाऊ क्षेत्र हैं।

2. मिजोरम के नेता लालडेंगा का परिचय दीजिए।

उत्तर- लालडेंगा का जन्म 1937 में हुआ। वह मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक और एक ख्याति प्राप्त नेता थे। 1959 में मिजोरम में पड़े भयंकर अकाल और उस समय की असम सरकार द्वारा उस समय के अकाल की समस्या के समाधान में विफल होने के कारण वे देश-विद्रोही बन गए। वे अनेक वर्षों तक भारत के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष करते रहे। यह संघर्ष लगभग बीस वर्षों तक चला। वे पाकिस्तान में एक राज्य शरणार्थी के रूप में रहते हुए भी भारत विरोधी गतिविधियाँ चलाते रहे। अंत में वे प्रधानमंत्री राजीव गाँधी के बुलाने पर स्वदेश लौटे और 1986 में राजीव गाँधी के साथ उन्होंने सुलह की और दोनों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और मिजोरम को नया राज्य बनाया गया। लालडेंगा नवनिर्मित मिजोरम के पहले मुख्यमंत्री बने ।1990 में उनका निधन हो गया।

3. ई.वी.रामास्वामी नायकर का परिचय संक्षेप में दें।

उत्तर- ई. वी.रामास्वामी नायकर एक तमिल समाज सुधारक थे। इन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। द्रविड़ आंदोलन के प्रणेता के रूप में भी जाने जाते हैं। राजनीतिक जीवन की शुरुवात इन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में किए । ये "आत्मसम्मान आंदोलन (1925) के जनक थे। उत्तर भारतीय लोग एवम ब्राह्मण द्रविड़ से अलग आर्य हैं" इस मत का भी प्रतिपादन इन्होंने किया।

4. क्षेत्रीयता अथवा क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं?

उत्तर- क्षेत्रीयता का आशय उस प्रवृति से है जिसके अंतर्गत एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के समान उद्देश्य व आकांक्षाएँ होती हैं। इस प्रकार जब किसी भौगोलिक दृष्टि से पृथक् भूखंड में रहने वाले मानव समूह में धार्मिक, सांस्कृतिक भाषायी, आर्थिक-सामाजिक, राजनीतिक तथा ऐतिहासिक आदि दृष्टि से उसी प्रकार के अन्य भूखंड से पृथकता उत्पन्न हो जाती है तथा स्वयं की एकरूपता व समानता का विकास हो जाता है तब उस मानव समूह में अपने क्षेत्रों के हितों के प्रति पैदा हुई जागरूकता को क्षेत्रीयता या क्षेत्रवाद कहा जाता है ।

5. "ऑपरेशन विजय" का संक्षिप्त विवरण दें ।

उत्तर- भारत ने गोवा की आजादी के लिए एक सैनिक कार्यवाही चलाई ताकि गोवा के साथ-साथ दमन दीव को पुर्तगालियों के अत्याचारी शासन से छुड़ाया जा सके । इसे ऑपरेशन विजय कहा गया।

ऑपरेशन विजय नामक कार्यवाही 17-18 दिसंबर, 1961 को शुरू की गई। इस कार्यवाही के कमांडर जनरल जे. एन. चौधरी थे। 19 दिसंबर, 1961 को 'ऑपरेशन विजय' नामक कार्यवाही समाप्त हो गई।

यह कार्यवाही भारतीय स्वतंत्रता को पूर्ण करने वाली कार्यवाही थी। गोवा, दमन, दीव हवेली आदि में भारत का तिरंगा फहराया गया निःसंदेह गोवा की स्वतंत्रता ने भारतीयों का स्वाभिमान बढ़ाया और उन्हें सुशोभित किया। वे भारत के अंग बन गए। भारत की भूमि से विदेशियों की अनाधिकृत उपस्थिति और वर्चस्व पूर्णतया समाप्त हो गया

6. अंगमी जापू फिजो कौन थे ? संक्षेप में परिचय दीजिए।

उत्तर- अंगमी जापू फिजो का जन्म 1904 ई. में हुआ। वे पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड की आज़ादी के आंदोलन के नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। वे नागा नेशनल काउंसिल के अध्यक्ष बने उन्होंने नागालैंड को भारत से अलग देश बनाने के लिए भारत सरकार के विरुद्ध अनेक वर्षों तक सशस्त्र संघर्ष चलाया। उन्होंने पाकिस्तान में शरण ली और अपने जीवन के अंतिम तीन वर्ष ब्रिटेन में गुजारे। 1990 ई. में उनका निधन हो गया। आज भी नागा समस्या देश के समक्ष है ।

7. काजी लैंदुप दोरजी खांगसरपा का संक्षिप्त परिचय दीजिए।

उत्तर- काजी लैंदुप दोरजी खांगसरपा का जन्म 1904 ई. में हुआ। वे सिक्किम के इतिहास में लोकतंत्र की स्थापना के आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध हुए। वे सिक्किम प्रजामंडल एवं सिक्किम राज्य कांग्रेस के संस्थापक थे। 1962 ई. में उन्होंने सिक्किम नेशनल कांग्रेस की स्थापना की । सिक्किम में हुए आम चुनाव में काजी लेंदुप को विजय मिली। इस विजय के उपरांत उन्होंने सिक्किम के भारत में विलय का पुरजोर समर्थन किया ।कालांतर में सिक्किम की विधान सभा ने जनमत कराया। जनमत में भी भारत-सिक्किम का समर्थन किया। सिक्किम के विलय के बाद काजी लैंप दोरजी

Jharkhandone.com

खांगसरपा ने अपनी सिक्किम कांग्रेस पार्टी का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किया.

8. आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के विवादास्पद होने के क्या कारण थे?

उत्तर- 1970 के दशक में अकालियों को कांग्रेस पार्टी से पंजाब में चिढ़ हो गई क्योंकि वह सिख और हिन्दू दोनों धर्मों के दलितों के बीच अधिक समर्थन प्राप्त करने में सफल हो गई थी। इसी दशक में अकालियों के एक समूह ने पंजाब के लिए स्वायत्तता की माँग उठाई। 1973 में, आनंदपुर साहिब में हुए एक सम्मेलन में इस आशय का प्रस्ताव पारित हुआ। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात उठायी गई थी। प्रस्ताव की माँगों में केन्द्र-राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करने की बात भी शामिल थी। इस प्रस्ताव में सिख 'कौम' (नेशन या समुदाय) की आकांक्षाओं पर जोर देते हुए सिखों के 'बोलबाला' (प्रभुत्व या वर्चस्व) का ऐलान किया गया। यह प्रस्ताव संघवाद को मजबूत करने की अपील करता है लेकिन इसे एक अलग सिख राष्ट्र की माँग के रूप में भी पढ़ा जा सकता है।

9. द्रविड़ आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

उत्तर- **द्रविड आन्दोलन** :-

दक्षिण भारत के इस आन्दोलन का नेतृत्व तमिल समाज सुधारक ई. वी. रामास्वामी नायकर पेरियार ने किया ।

इस आन्दोलन ने उत्तर भारत के राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक प्रभुत्व, ब्राहमणवाद व हिन्दी भाषा का विरोध तथा क्षेत्रीय गौरव बढ़ाने पर जोर दिया । इसे दूसरे दक्षिणी राज्यों में समर्थन न मिलने पर यह तमिलनाडु तक सिमट कर रह गया ।

इस आन्दोलन के कारण एक नये राजनीतिक दल - "द्रविड कड़गम" का उदय हुआ। यह दल कुछ वर्षों के बाद दो भागो (D. M. K. एवं A .I.D. M. K.) में बंट गया ।ये दोनों दल अब तमिलनाडु की राजनीति में प्रभावी है।

10. पंजाब समझौता कब और किसके बीच हुआ?इसके मुख्य प्रावधानों को लिखें।

उत्तर- पंजाब समझौता जुलाई 1985 में अकाली दल के अध्यक्ष हर चन्द सिंह लोगोवाल तथा राजीव गांधी के बीच हुई।इस समझौते ने पंजाब में शान्ति स्थापना के प्रयास किये ।

पंजाब समझौते के प्रमुख प्रावधान :-

- चण्डीगढ पंजाब को दिया जायेगा ।
- पंजाब हरियाणा सीमा विवाद सुलझाने के लिए आयोग की नियुक्ति होगी।
- पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच रावी व्यास के पानी बंटवारे हेतु न्यायाधिकरण गठित किया जायेगा।
- पंजाब में उग्रवाद प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जायेगा।
- पंजाब से विशेष सुरक्षा बल अधिनियम ।

11. आजादी के बाद से अब तक उभरी क्षेत्रीय आकांक्षाओं से हमें क्या सबक मिलती है?

उत्तर- आजादी के बाद से अब तक उभरी क्षेत्रीय आकांक्षाओं से हमें निम्नलिखित सबक मिलती है।

a. क्षेत्रीय आकांक्षाये लोकतान्त्रिक राजनीति की अभिन्न अंग है ।
b. क्षेत्रीय आकाक्षाओं को दबाने की बजाय लोकतान्त्रिक बातचीत को अपनाना अच्छा होता है ।
c. सत्ता की साझेदारी के महत्व को समझना ।
d. क्षेत्रीय असन्तुलन पर नियन्त्रण रखना ।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. जम्मू-कश्मीर की अंदरुनी विभिन्नताओं की व्याख्या कीजिए और बताइए कि इन विभिन्नताओं के कारण इस राज्य में किस तरह अनेक क्षेत्रीय आकांक्षाओं ने सर उठाया है?

उत्तर-

(i) जम्मू-कश्मीर की अंदरूनी विभिन्नताएँ: जम्मू एवं कश्मीर में तीन राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र शामिल हैं- जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। कश्मीर घाटी को कश्मीर के दिल के रूप में देखा जाता है। कश्मीरी बोली बोलने वाले ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं। बहरहाल, कश्मीरी भाषी लोगों में अल्पसंख्यक हिन्दू भी शामिल हैं। जम्मू क्षेत्र पहाड़ी तलहटी एवं मैदानी इलाके का मिश्रण है। जहाँ हिन्दू, मुस्लिम और सिख यानी कई धर्म और भाषाओं के लोग रहते हैं। लद्दाख पर्वतीय इलाका है, जहाँ बौद्ध एवं मुस्लिमों की आबादी है, लेकिन यह आबादी बहुत कम है। (ii) मुद्दे का स्वरूप: 'कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ विवाद भर नहीं है। इस मुद्दे के कुछ बाहरी तो कुछ भीतरी पहलू हैं। इसमें कश्मीरी पहचान का सवाल जिसे कश्मीरियत के रूप में जाना जाता है, शामिल है। इसके साथ ही साथ जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक स्वायत्तता का मसला भी इसी से जुड़ा हुआ है। (iii) अनेक आकांक्षाओं का सिर उठाना:

(क) धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने की शेख अब्दुल्ला की आकांक्षा: 1947 से पहले जम्मू एवं कश्मीर में राजशाही थी। इसके हिन्दू शासक हरि सिंह भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे और उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य के लिए भारत और पाकिस्तान के साथ समझौता करने की कोशिश की। पाकिस्तानी नेता सोचते थे कि कश्मीर, पाकिस्तान का हिस्सा है, क्योंकि राज्य की ज्यादातर आबादी मुस्लिम है। बहरहाल यहाँ के लोग स्थिति को अलग नजरिए से देखते थे। वे अपने को कश्मीरी सबसे पहले, कुछ और बाद में मानते थे। राज्य में नेशनल कांफ्रेंस के शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में जन-आंदोलन चला। शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि महाराजा पद छोड़ें, लेकिन वे पाकिस्तान में शामिल होने के खिलाफ थे। नेशनल कांफ्रेंस एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था और इसका कांग्रेस के साथ काफी समय तक गठबंधन रहा।

(ख) जम्मू-कश्मीर के आक्रमणकारियों से प्रतिरक्षा कराने की आकांक्षा, चुनाव और लोकतंत्र स्थापना की आकांक्षा: अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायली घुसपैठियों को अपनी तरफ से कश्मीर पर कब्जा करने भेजा। ऐसे में महाराजा भारतीय सेना से मदद माँगने को मजबूर हुए। भारत ने सैन्य मदद उपलब्ध कराई और कश्मीर घाटी से घुसपैठियों को खदेड़ा। इससे पहले भारत सरकार ने महाराजा से भारत संघ में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करा लिए। इस पर सहमति जताई गई कि स्थिति सामान्य होने पर जम्मू-कश्मीर की नियति का फैसला जनमत सर्वेक्षण के द्वारा होगा। मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रधानमंत्री बने (राज्य में सरकार के मुखिया को तब प्रधानमंत्री कहा जाता था।) भारत, जम्मू एवं कश्मीर की स्वायत्तता को बनाए रखने पर सहमत हो गया। इसे संविधान में धारा 370 का प्रावधान करके संवैधानिक दर्जा दिया गया।

2. कश्मीर की क्षेत्रीय स्वायत्तता के मसले पर विभिन्न पक्ष क्या हैं? इनमें कौन-सा पक्ष आपको समुचित जान पड़ता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए।

उत्तर- कश्मीर की क्षेत्रीय स्वायत्तता के मसले पर विभिन्न पक्ष: जम्मू-कश्मीर राज्य की अधिक स्वायत्तता की माँग के भी दो पहलू हैं। पहला यह कि समस्त राज्य को केन्द्र के अत्यधिक नियंत्रण से मुक्ति मिले और उसे अपने आंतरिक मामलों में अधिक-से-अधिक आजादी मिले और वह अपने निर्णय बिना केंद्रीय हस्तक्षेप के कर सके तथा उन्हें लागू कर सके। धारा 370 को पूरी तरह लागू किया जाए।

jharkhandboard.com

स्वायत्तता के संबंध में एक दृष्टिकोण और भी है और वह जम्मू-कश्मीर की आंतरिक स्वायत्तता से संबंधित है। जम्मू-कश्मीर के अंदर भी विभिन्न आधारों पर क्षेत्रीय विभिन्नताएँ हैं और इसके तीन क्षेत्र अपनी अलग-अलग पहचान रखते हैं। कश्मीर घाटी, जम्मू तथा लद्दाख के क्षेत्र। जम्मू तथा लद्दाख के लोगों का आरोप है कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने सदा ही उनके हितों की अनदेखी की है और ध्यान कश्मीर घाटी के विकास की ओर लगाया है तथा इन दोनों क्षेत्रों का कुछ भी विकास नहीं हुआ है। अतः इन क्षेत्रों को भी जम्मू-कश्मीर की सरकार के नियंत्रण से मुक्ति मिलनी चाहिए और इन्हें आंतरिक स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। इसी माँग के संदर्भ में लद्दाख स्वायत परिषद की स्थापना की गई थी। आजादी के बाद से ही जम्मू एवं कश्मीर की राजनीति हमेशा विवादग्रस्त एवं संघर्षयुक्त रही। इसके बाहरी एवं आंतरिक दोनों कारण हैं। कश्मीर समस्या का एक कारण पाकिस्तान का रवैया है। उसने हमेशा यह दावा किया है कि कश्मीर घाटी पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। 1947 में इस राज्य में पाकिस्तान ने कबायली हमला करवाया। इसके परिणामस्वरूप राज्य का एक हिस्सा पाकिस्तानी नियंत्रण में आ गया। भारत ने दावा किया कि यह क्षेत्र का अवैध अधिग्रहण है। पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को 'आजाद कश्मीर' कहा। 1947 के बाद कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष एक बड़ा मुद्दा रहा है। आंतरिक रूप से देखें तो भारतीय संघ में कश्मीर की हैसियत को लेकर विवाद रहा है। कश्मीर को संविधान में धारा 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया है। धारा 370 के तहत जम्मू एवं कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा स्वायत्तता दी गई है। राज्य का अपना संविधान है। भारतीय संविधान की सारी व्यवस्थाएँ इस राज्य में लागू नहीं होतीं। संसद द्वारा पारित कानून राज्य में उसकी सहमति के बाद ही लागू हो सकते हैं।

इस विशेष स्थिति से दो विरोधी प्रतिक्रियाएँ सामने आईं। लोगों का एक समूह मानता है कि इस राज्य को धारा 370 के तहत प्राप्त विशेष दर्जा देने से यह भारत के साथ पूरी तरह नहीं जुड़ पाया है। यह समूह मानता है कि धारा 370 को समाप्त कर देना चाहिए और जम्मू-कश्मीर को अन्य राज्यों की तरह ही होना चाहिए। दूसरा वर्ग (इसमें ज्यादातर कश्मीरी हैं) विश्वास करता है कि इतनी भर स्वायत्तता पर्याप्त नहीं है। कश्मीरियों के एक वर्ग ने तीन प्रमुख शिकायतें उठायी हैं। पहला यह कि भारत सरकार ने वायदा किया था कि कबायली घुसपैठियों से निपटने के बाद जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो भारत संघ में विलय के मुद्दे पर जनमत संग्रह कराया जाएगा। इसे पूरा नहीं किया गया। दूसरा, धारा 370 के तहत दिया गया विशेष दर्जा पूरी तरह से अमल में नहीं लाया गया।

3. पंजाब समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे? क्या ये प्रावधान पंजाब और उसके पड़ोसी राज्यों के बीच तनाव बढ़ाने के कारण बन सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए।

उत्तर- पंजाब समझौता: राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद अकाली दल के नरमपंथी नेताओं से बातचीत शुरू की और सिक्ख समुदाय को शांत करने का प्रयास किया। परिणामस्वरूप अकाली दल के अध्यक्ष संत हरचंद सिंह लोगोंवाल और राजीव गांधी के बीच समझौता हुआ। इसे पंजाब समझौता भी कहा जाता है। इसके आधार पर अकाली दल 1985 में होने वाले चुनावों में भाग लेने को तैयार हुआ।

पंजाब में स्थिति को सामान्य बनाने की और यह एक महत्त्वपूर्ण कदम था। इसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित थीं-

(i) चंडीगढ़ पर पंजाब का हक माना गया और यह आश्वासन दिया गया कि यह शीघ्र ही पंजाब को दे दिया जाएगा।

(ii) पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक अलग आयोग स्थापित किया जाएगा।

(iii) रावी और व्यास के पानी को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच बँटवारा करने के लिए एक न्यायाधिकरण (Tribunal) बैठाया जाएगा।

(iv) सरकार ने वचन दिया कि वह भविष्य में सिक्खों के साथ बेहतर व्यवहार करेगी और उन्हें राष्ट्रीय धारा में किए गए उनके योगदान के आधार पर सम्मानजनक स्थिति में रखा जाएगा।

(v) सरकार दंगा पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा भी देगी और दोषियों को दंड दिलवाए जाने का पूरा प्रयास करेगी।

1985 के चुनावों में अकाली दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ और इसकी सरकार बनी। परन्तु कुछ समय बाद अकाली दल में दरार पैदा हुई और प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में एक गुट इससे अलग हो गया तथा वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा।राजीव गाँधी और लोगोवाल के समझौते के बाद भी पंजाब की स्थिति सामान्य नहीं हुई और वहाँ उग्रवादी तथा हिंसात्मक गतिविधियाँ चलती रहीं। 1991 के लोकसभा चुनावों के समय स्थिति सामान्य बनाने के लिए सरकार ने फरवरी 1992 में विधानसभा के चुनाव भी करवाए परन्तु अकाली दल समेत अन्य दलों ने इन चुनावों का बहिष्कार किया। आतंकवादियों ने भी लोगों को मतदान न करने की धमकी दी। 1992 के चुनावों में पंजाब में कुल 24 प्रतिशत मतदान हुआ था।पंजाब में 1990 के शतक के मध्य के बाद ही स्थिति सामान्य होने लगी। सुरक्षा बलों ने उग्रवाद को दबाया और इसके कारण 1997 के चुनाव कुछ सामान्य स्थिति में हुए माहौल कांग्रेस के विरुद्ध था और अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया था। अतः अकाली दल के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार बनी। परन्तु 2002 के विधान सभा चुनाव में अकाली दल सत्ताहीन हुआ और 2007 के चुनाव में फिर से सत्ता में आया।इस प्रकार पंजाब में हिंसा का चक्र लगभग एक दशक तक चलता रहा। पंजाब की जनता को उग्रवादी गुटों के कारण हिंसा का शिकार होना पड़ा। नवंबर 1984 में सिख समुदाय को सिक्ख विरोधी दंगों का शिकार होना पड़ा। मानवाधिकारों का व्यापक उल्लंघन हुआ। डर और अनिश्चय की स्थिति ने वहाँ की व्यापारिक गतिविधियों पर बुरा प्रभाव डाला। 1980 के बाद एक समय ऐसा आया था जबकि पंजाब के बड़े-बड़े उद्योगपति वहाँ से पलायन करके हरियाणा आदि राज्यों में आने लगे थे। उग्रवाद ने पंजाब की आर्थिक दशा पर, विकास गतिविधियों पर, वहाँ की खुशहाली पर बुरा प्रभाव डाला था। लोंगोवाल का भी वध हुआ था। पंजाब के कांग्रेसी मुख्यमंत्री वेअंतसिंह की भी सचिवालय में हत्या की गई। आजकल पंजाब में स्थित सामान्य कही जा सकती है।

4. भारत के विभिन्न भागों से उठने वाली क्षेत्रीय मांगों से 'विविधता में एकता' के सिद्धांत की अभिव्यक्ति होती हैं। क्या आप इस कथन सहमत हैं? तर्क दीजिए।

उत्तर- क्षेत्रीय माँगों से 'विविधता में एकता' की अभिव्यक्ति : भारत एक बहुलवादी समाज है और कई प्रकार की विविधताओं वाला राष्ट्र है। ये विविधताएँ भाषा, धर्म क्षेत्र आदि के आधार पर बनी हुई हैं। इनके कारण क्षेत्रीय आकांक्षाएँ उभरती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। सभी क्षेत्रों की माँगें एक समान नहीं होतीं, कई बार वे एक-दूसरे की विरोधी भी होती हैं जैसे कि किसी नदी के जल के बँटवारे से संबंधित विवाद, किसी बड़े उद्योग, को किस राज्य या क्षेत्र में लगाया जाए इस के संबंध में विवाद आदि। कभी अलगाववादी क्षेत्रीय माँग भी उभर आती है। परंतु इन विविधताओं के होते हुए भी राष्ट्रीय एकता बनी हुई है।

Jharkhandlab.com

अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की अलग पहचान है। भारत की एक अलग संस्कृति है जिसमें अहिंसा, विश्वशांति, विश्वबंधुत्व आदि प्रमुख विशेषताएँ हैं। भारत के अंदर बेशक कोई कहे कि वह पंजाबी है या बंगाली है, मराठी है या गुजराती है, भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण के लिए आंदोलन किए हैं, नदी जल बँटवारे को लेकर दो या तीन राज्यों के बीच संघर्ष हुए हैं, परंतु अब जब दो भारतीय अमेरिका या कनाडा, इंग्लैंड या पेरिस में एक-दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनमें यह भावना सबसे पहले प्रकट होती है कि हम भारतीय हैं। विदेशों में सभी भारतीय एकजुट होकर भारतीय राष्ट्र का अंग होने और राष्ट्रीय सम्मान तथा हितों की रक्षा के लिए एकता का उदाहरण रखते हैं। भारत-पाक युद्धों के दौरान भारत के सभी दलों, सभी वर्गों, सभी क्षेत्रों के लोगों के लोगों ने राष्ट्रीय एकता का परिचय दिया और उसकी रक्षा के लिए सरकार को पूरा समर्थन दिया। जव 1962 में चीन ने नेफा (अब अरुणाचल प्रदेश) पर आक्रमण किया था तो गुजराती भी यह समझता था कि यह आक्रमण उस पर हुआ है, मद्रासी भी यही समझता था, उत्तर प्रदेश में रहने वाला नागरिक भी यही समझता था। अतः क्षेत्रीय माँगों से भारतीय राष्ट्र के विभाजन का अनुमान नहीं होता बल्कि विविधता में एकता का ज्ञान होता है।

5. भारतीय लोकतंत्र पर पृथकतावाद के कुप्रभावों को संक्षेप में लिखिए।

उत्तर- भारतीय लोकतंत्र पर पृथकतावादी प्रवृत्तियों के काफी बुरे प्रभाव पड़े हैं-

(i) राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खतराः पृथकतावाद देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता है। क्षेत्रीय भावना आने पर क्षेत्र के लोग हिंसात्मक तथा विध्वसात्मक गतिविधियों में लग जाते हैं। ऐसे समय लोग अपने को अलग करने के लिए विदेशी शक्तियों से सहायता लेने से भी नहीं हिचकिचाते।

(ii) समाज-विरोधी तत्वों को बढ़ावाः पृथकतावाद से समाज विरोधी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलता है। हिंसात्मक आंदोलनों और राजनीतिक अनिश्चितता के वातावरण में स्वार्थी तथा समाज-विरोधी तत्व अपना उल्लू सीधा करने में लग जाते हैं।- सांप्रदायिक दंगे भी भड़का दिए जाते हैं और हर ओर अराजकता का माहौल दिखाई देने लगता है और कानून व्यवस्था और अधिक बिगड़ जाती है।

(iii) जीवन और संपत्ति की हानिः पृथकतावादी गतिविधियों से लोगों का जीवन और संपत्ति सुरक्षित नहीं रहते। कितने ही बेगुनाह व्यक्ति अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और आंदोलनों में संपत्ति स्वाहा हो जाती है। आंदोलनकारी केवल सरकारी संपत्ति, सरकारी बसों और कारखानों को ही हानि नहीं पहुँचाते बल्कि आम लोगों की संपत्ति, कारें, स्कूटर, बिल्डिंग आदि को भी हानि पहुँचाते हैं। इन सबसे राष्ट्र को बहुत भारी आर्थिक हानि सहन करनी पड़ती है।

(iv) आर्थिक प्रगति को धक्काः पृथकतावादी प्रवृत्ति के वातावरण में राष्ट्र की आर्थिक प्रगति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जितने दिन कश्मीर और पंजाब में आतंकवादी वातावरण रहा, वहाँ लोगों का काम धंधा व्यापार और उद्योग सब ठप्प हो गए। उद्योपतियों ने दूसरे राज्यों में काम-धंधे शुरू कर दिए। व्यापार के लिए शांति और व्यवस्था का वातावरण चाहिए।

6. भारत के उत्तर-पूर्व राज्यों अथवा क्षेत्रों में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की उत्पत्ति और विकास के कारणों की चर्चा कीजिए।

उत्तर- भारत के उत्तर-पूर्व के राज्यों अथवा क्षेत्रों में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की उत्पत्ति और विकास के कई कारण उत्तरदायी रहे हैं जैसे-

(i) उत्तर-पूर्व के ये राज्य मुख्य राष्ट्र से कुछ अलग से रहे हैं। 22 मील लंबी एक पतली सी राहदारी इस क्षेत्र को शेष भारत से जोड़ती है। इस कारण ये क्षेत्र आरंभ से अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। विभाजन के कारण भारत और इन क्षेत्रों के बीच पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्ला देश) आ टपका जिससे ये भारत से अलग-थलग से पड़ गए।

(ii) इस क्षेत्र में अलग-अलग इलाकों में बहुत-सी आदिम जातियाँ या कबीले स्थित हैं और वे सभी अलग-अलग पहचान रखते रहे हैं। उनकी अलग पहचान उनकी भाषा, संस्कृति, रीति-रिवाजों आदि के आधार पर रही है और आज भी है।

(iii) इन क्षेत्रों में आवागमन के साधनों तथा संचार के साधनों का पूरी तरह विकास नहीं हुआ और शेष भारत के लोग इन इलाकों में बहुत कम आते-जाते रहे हैं। इसका कारण यह भी रहा है कि यहाँ आवागमन के साधन सुविधाजनक नहीं हैं और लोग इन इलाकों में आना-जाना सुरक्षित भी महसूस नहीं करते।

(iv) उत्तर-पूर्व के क्षेत्रों का विकास भी वैसा नहीं हुआ है जैसा कि देश के शेष भागों में हुआ है। वहाँ के लोगों का आरोप है कि केन्द्रीय सरकार ने इन क्षेत्रों के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया है और वे सरकार की भेदभावपूर्ण नीति के शिकार रहे हैं, वे अपने को क्षेत्रीय असंतुलन से प्रभावित मानते हैं।

(v) इन क्षेत्रों में जब बाहरी लोगों अथवा दूसरे राज्यों से आकर उद्योगपतियों ने उद्योग लगाए और उनमें उच्च पदों पर दूसरे राज्य के लोगों की नियुक्ति हुई और इस क्षेत्र के लोगों को केवल छोटे कार्यों और छोटे पदों पर रखा गया तो इनमें यह भावना पैदा हुई कि बाहरी लोग इस क्षेत्र के संसाधनों का प्रयोग करके मालामाल हो रहे हैं और यहाँ के लोगों की दशा में विशेष सुधार नहीं होता तो इन्होंने बाहरी लोगों के आगमन का विरोध किया और उन्हें अपने क्षेत्रों से निकाले जाने के आंदोलन किए।

jharkhandguru.com

अध्याय - 9 भारतीय राजनीति :नए बदलाव

वस्तुनिष्ठ प्रश्न-

1. भारत में नई आर्थिक नीति कब से लागू हुआ?
a. 1984 b. 1989
c. 1991 d. 1995

2. भारत की संसद में शामिल है।
a. लोक सभा
b. केवल राज्य सभा
c. राज्य सभा और लोक सभा दोनों
d. लोक सभा, राज्य सभा और राष्ट्रपति

3. शून्यकाल संबंधित है:
a. संसद से b. न्यायालय से
c. (a) और (b) दोनों d. इनमें से कोई नहीं

4. अन्य पिछड़ी जाति (OBC) का अर्थ है
a. अनुसूचित जाति से
b. अनुसूचित जनजाति से
c. अनुसूचित जाति-जनजाति से अलग शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ा समुदाय
d. उपर्युक्त सभी

5. कार सेवा का आयोजन कब किया गया ?
a. 1992 b. 1993
c. 1994 d. 1995

6. मण्डल आयोग का नाम किसके नाम पर पड़ा ?
a. बिन्देश्वरी प्रसाद मण्डल b. विश्वनाथ प्रशाद मण्डल
c. विनोद प्रसाद मण्डल d. इनमे से कोई नहीं

7. बामसेफ का पूर्ण रूप क्या है ?
a. बैकवॉर्ड एण्ड माइनोरिटी एम्प्लाईज फेडरेशन
b. ब्लॉक एण्ड मैनोरिटी एम्प्लोयी फॉन्ड
c. बैकवर्ड एण्ड मॉरल एम्प्लाईज़ फेडरेशन
d इनमे से कोई नहीं

8. राजीव गांधी की हत्या कब की गई?
a. 1990 b. 1991
c. 1992 d. 1993

9. बाबरी मस्जिद का ध्वंस कब हुआ ?
a. 1992 b. 1993
c. 1994 d. 1995

10. 1989 में काँग्रेस के प्रभाव में कमी के कारण थे?
a. करिश्माई नेता का अभाव
b. काँग्रेस में गुटबाजी
c. क्षेत्रीय दलों का बढ़ता प्रभाव
d. इनमे से सभी

11. हिन्दू अथवा हिन्दुत्व शब्द को किसने गढ़ा था?
a. राजा राम मोहन राय b. बी डी सावरकर
c. राम मनोहर लोहिया d. इनमे से कोई नहीं

12. बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था ?
a. मुहम्मद हुसेन b. बाबा फरीद
c. मीर बाकी d. इनमे से कोई नहीं

13. निम्नलिखित में से किसने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया ?
a. राष्ट्रीय मोर्चा b. कांग्रेस
c. बसपा d. भाजपा

14. निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री नही बने।
a. सोनिया गांधी b. इंद्र कुमार गुजराल
c. चंद्रशेखर d. अटल बिहारी बाजपेई

15. भारतीय जनता पार्टी के गठन किन वर्ष हुई?
a. 1986 b. 1980
c. 1975 d. 1960

16. बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे?
a. कांशी राम b. मायावाती
c. चंद्रशेखर d. बिंदेश्वरी मंडल

उत्तर-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	D	A	C	A	A	A	B	A	D	B	C	A	A	B	A

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

1. गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं?
उत्तर- जब चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तब कई दल आपसी सहयोग से सरकार बनाते हैं। दूसरे शब्दों में वैसी सरकार जो एक से अधिक दलों से बनी हो गठबंधन सरकार कहलाती है।इस प्रकार के सरकार में किसी एक दल को प्रभुत्व नही रहता।

2. दलगत व्यवस्था की चुनौतियां को लिखें।
उत्तर- दलगत व्यवस्था की चुनौतियों के रूप में हम गरीबी, विस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, आजीविका एवं न्यूनतम मजदूरी को ले सकते हैं।

3. सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ बताइए।
उत्तर- सामूहिक उत्तरदायित्व वह सिद्धान्त है जिसके अन्तर्गत संसदीय प्रणाली में सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल को एक इकाई माना जाता है मन्त्रिमण्डल के जो भी निर्णय होते हैं। वे इसके सदस्यों की सहमति से लिए माने जाते हैं तथा इसके लिए सभी मन्त्रिमण्डल के सदस्य समान रूप से उत्तरदायी होते हैं।

4. 1984 तथा 1989 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को कितनी-कितनी सीटें मिलीं ?
उत्तर- कांग्रेस ने 1984 के चुनाव में लोकसभा की 415 सीटें तथा 1989 में 197 सीटें जीती थीं।

5. राष्ट्रीय मोर्चे द्वारा बनायी गई सरकार को कठपुतली सरकार क्यों कहा जाता था ?
उत्तर- राष्ट्रीय मोर्चे द्वारा बनायी गई सरकार को कठपुतली इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह दो राजनीतिक समूहों भाजपा और वाम मोर्चा के समर्थन से बनी थी।

6. राष्ट्रीय मोर्चा को कठपुतली की तरह नचाने वाले दलों के नाम बताइए।
उत्तर- राष्ट्रीय मोर्चा को कठपुतली की तरह नचाने वाले दो दल भारतीय जनता पार्टी और वाम मोर्चा है।

Jharkhandlab.com

7. अनुभववाद या प्रयोगवाद का अर्थ बताइए।

उत्तर- किसी सिद्धान्त के आधार पर नहीं बल्कि जैसा उस समय उपयुक्त हो वैसा करो, प्रयोगवाद कहलाता है।

8. केन्द्र में पहली मिली-जुली सरकार कब बनी?

उत्तर- केन्द्र में पहली मिली-जुली सरकार वर्ष 1977 में गठित हुई।]

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. गठबंधन की राजनीति के इस नए दौर में राजनीतिक दल विचारधारा को आधार मानकर गठजोड़ नहीं करते हैं।" इस कथन के पक्ष या विपक्ष में आप कौन-से तर्क देंगे?

उत्तर- उपर्युक्त कथन के पक्ष में निम्न तर्क दिए जा सकते हैं-

1. गठबंधन की राजनीति के इस दौर में राजनीतिक दल विचारधारागत अंतर की जगह सत्ता में हिस्सेदारी की बातों पर जोर देते हैं।
2. पद की लोलुपता ने विचारधारा के विपरीत भी दलों को गठबंधन करने के लिए प्रेरित किया।

2. 1989 के बाद की अवधि में भारतीय राजनीति के मुख्य बदलाव क्या थे?

उत्तर- 1989 के बाद प्रमुख बदलाव :-

- कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति।
- राष्ट्रीय राजनीति में जनता दल व भारतीय जनता पार्टी की प्रभावशाली भूमिका।
- राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय
- आर्थिक नीति (जिसे नई आर्थिक नीति के रूप में भी जाना जाता है) का अनुसरण विभिन्न सरकारों द्वारा किया जाता है
- अयोध्या विवाद :- दिसंबर 1992 में अयोध्या (जिसे बाबरी माजिद के नाम से जाना जाता है) में विवादित ढांचे के विध्वंस में कई घटनाओं का समापन हुआ।

3. गठबंधन सरकारों के उदय के कारण लिखें।

उत्तर- गठबंधन सरकारों के उदय के कारण :-

1. राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का कमजोर होना।
2. क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का प्रादुर्भाव व सरकारों के निर्माण में बढ़ती भूमिका।
3. जाति व सम्प्रदाय आधारित अवसरवादी

4. शाहबानों प्रकरण क्या है?

उत्तरः शाहबानों प्रकरण- शाहबानों एक मुस्लिम महिला थीं जिसे तलाक के बाद पति ने गुजारा भत्ता देने से मना कर दिया था सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 44 (समान नागरिक संहिता) के तहत शाहबानों को पति के गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया।

5. बहुदलीय प्रणाली से भारतीय रजनीतिक व्यवस्था को क्या लाभ हुए?

उत्तर- बहुदलीय प्रणाली से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को निम्नलिखित फायदे हुए है।

1. विभिन्न मतों का प्रतिनिधित्व - बहु- दलीय प्रणाली के कारण भारतीय राजनीति में सभी वर्गों तथा हितो को प्रतिनिधित्व मिल जाता हैं। इस प्रणाली से सच्चे लोकतंत्र की स्थापना होती है।
2. मतदाताओं को अधिक स्वतंत्रता - अधिक दलों के कारण मतदाताओं को अपने वोट का प्रयोग कराने के लिए अधिक स्वतंत्रताए होती हैं
3. मतदाताओं के लिए अपने विचारों से मिलते-जुलते दल को वोट देना आसान हो जाता है।

6. मंडल मुद्दा क्या है?संक्षेप में लिखें।

उत्तर- मंडल मुद्दा :-1978 में जनता पार्टी सरकार ने दूसरे 'पिछड़ा आयोग' का गठन किया। इसके अध्यक्ष बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल थे इसलिए इसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है।

मंडल आयोग की मुख्य सिफारिशें

1) अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण।

2) भूमि सुधारों को पूर्णता से लागू करना।

1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वी. पी. सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की। इसके खिलाफ देश के विभिन्न भागों में मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शन हुए।

7. अयोध्या विवाद के बारे में संक्षेप में लिखें।

उत्तर- अयोध्या विवाद:- 16 वीं सदी में मीर बाकी द्वारा अयोध्या में बनवाई मस्जिद के बारे में कहा गया कि यह मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनवाई गई। यह मामला अदालत में गया और 1940 के दशक में ताला लगा दिया गया। बाद में जब ताला खुला तो इस मुद्दे पर वोट बैंक की राजनीति हुई। 6 दिसम्बर 1992 को मस्जिद का ढांचा तोड़ दिया गया। इससे कारण देश में साम्प्रदायिक हिंसा फैली और 1993 में मुम्बई में दंगे हुई। विवाद की जांच के लिए लिब्रहान आयोग का गठन किया गया।

8. गुजरात में हिंदू मुस्लिम दंगो पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

उत्तर- अयोध्या से लौट रहे कारसेवकों से भरी एक बोगी में आग लग गई। इस आग के पीछे मुस्लिमों का हाथ होने का संदेह था।परिणास्वरूप मुसलमानों के खिलाफ व्यापक हिंसा हुई जिसमें लगभग 1100 लोग मारे गए जिसमें ज्यादातर मुसलमान थे। इस दंगा को मुस्लिम विरोधी दंगा कहा गया। यह दंगा 2002 में गुजरात के गोधरा नामक स्टेशन पर हुआ था।

मानव अधिकार आयोग ने हिंसा को नियंत्रित करने और पीड़ितों को राहत देने में विफल रहने में गुजरात सरकार की भूमिका की आलोचना की।

9. मन्त्रियों के व्यक्तिगत व सामूहिक उत्तरदायित्व में अन्तर बताइए।

उत्तर- संसदीय प्रणाली में मन्त्री संसद या उसके लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यह उत्तरदायित्व दो प्रकार का होता है - व्यक्तिगत व सामूहिक। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का यह अर्थ है कि हर मन्त्री अपने किए काम के लिए उत्तरदायी है। अतः प्रधानमन्त्री उसका त्यागपत्र माँग सकता है। सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि सभी मन्त्रीगण साथ तैरते व साथ डूबते हैं। यदि सदन में अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाए तो प्रधानमन्त्री त्यागपत्र देता है जो सभी का त्यागपत्र माना जाता है।

10. गठबंधन सरकार की एक राजनीतिक समस्या का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर- गठबंधन राजनीति में विचारों की एकरूपता नहीं होती। बार-बार पार्टियाँ गठबंधन छोड़ती है और इसलिए प्रायः गठबंधन टूटते रहते हैं या बदलते रहते हैं। इससे लोगों का बहुदलीय प्रणाली में विश्वास कम होता है। प्रायः वे दो दलीय या तीन अथवा कभी-कभी एक दलीय प्रणाली के समर्थक भी बन जाते हैं। गठबंधन की सरकारें अस्थायी, कम गतिशील रहती है।

11. कांग्रेस की गठबन्धन राजनीति की व्याख्या कीजिए ?

उत्तर- वर्तमान में भारत में गठबन्धन सरकारों का युग है। अतः कांग्रेस को गठबन्धन के सन्दर्भ में अपनी नीति बदलनी पड़ी। वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (संप्रग) का गठन कर कांग्रेस ने केन्द्र में सरकार का गठन किया। पुनः 2009 में संप्रग ने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर केन्द्र में सरकार का गठन किया। महाराष्ट्र राज्य में कांग्रेस एक गठबन्धन सरकार चला रही है। आज कांग्रेस गठबन्धन की अपरिहार्यता को स्वीकार कर चुकी है।

12. लोकतन्त्र को प्रतिनिधि शासन क्यों कहा जाता है?

उत्तर- लोकतन्त्रीय व्यवस्था को मोटे तौर पर दो प्रकार से संचालित किया जा सकता है- (i) प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र, (ii) परोक्ष प्रजातन्त्र या

Jharkhandjcb.com

प्रतिनिधि शासन। चूँकि आज विश्व में बड़े-बड़े राष्ट्र अस्तित्व में हैं जिनकी करोड़ों की जनसंख्या तथा विशाल आकार के कारण वहाँ जनता सीधे शासन नहीं चला सकती अर्थात् प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र वहाँ व्यावहारिक रूप से सम्भव नहीं है। आजकल जनता द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनकर उनको देश की बागडोर सौंप दी जाती है। अधिकांश देशों में लोकतन्त्र का यही रूप प्रचलित है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. बामसेफ (बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लासेज एम्प्लायज फेडरेशन) पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर- बामसेफ का गठन सन 1978 में हुआ था। यह संगठन मुख्य रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगो का संगठन था जो सरकारी नौकरियों में थे।

2. इस संगठन ने बहुजन (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग) की तरफदारी की।
3. बामसेफ आगे चलकर दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बना।
4. आगे चलकर यही समिति बहुजन समाज पार्टी बनी। यह पार्टी मुख्य रूप से दलितों के अधिकारों और शोषण के खिलाफ आवाज उठाती है 1
5. प्रारंभ में बसपा एक छोटी पार्टी थी जिसका आधार हरियाणा और पंजाब में था लेकिन आगे चलकर पार्टी का उत्तर प्रदेश में जबर्दस्त जनाधार बना।
6. बसपा के मुख्य नेता कांशीराम थे जिन्होंने पार्टी को फर्श से अर्श तक पहुचाया। उनके बाद अब सुश्री मायावती जी इस पार्टी की अध्यक्ष है।

2. कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर समाप्त हो गया है। इसके बावजूद देश की राजनीति पर कांग्रेस का असर लगातार कायम है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए।

उत्तर- हम इस कथन से सहमत हैं। पक्ष में तर्क: कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर समाप्त हो गया है इसके बावजूद देश की राजनीति पर कांग्रेस का असर लगातार कायम है क्योंकि अभी भी कुछ राज्यों में कांग्रेस की सत्ता कायम है। 1975 से 1977 तक आपातकाल की स्थिति रही लेकिन कांग्रेस को सफलता मिली। 1989 से 1991 तक फिर कांग्रेस सबसे बड़ी विरोधी दल रही। 1991 के मध्यावधि चुनाव में फिर से कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की। 1996 में वामपंथियों ने गैर-कांग्रेसी सरकार का समर्थन किया क्योंकि कांग्रेस और वाम दोनों ही भाजपा को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे। 2004 से यू.पी.ए. सरकार का नेतृत्व कांग्रेस ही कर रही थी। जुलाई 2007 तथा 2012 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में भी कांगेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अतः यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस का प्रभुत्व का दौर समाप्त हो गया है लेकिन अभी भी देश की राजनीति पर कांग्रेस का असर कायम है।

3. गठबंधन सरकार के लाभ और हानियों को बतलाइए।

उत्तर- गठबंधन सरकार का लाभः

(i) बहुदलीय व्यवस्था वाले देशों में संसदीय सरकार की स्थापना गठबंधन की राजनीति के आधार पर ही संभव हैक्योंकि मतदाता किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं देते।

(ii) सरकार पर किसी एक दल का प्रभुत्व नहीं जमता। 1988 तक सरकार पर कांग्रेस का ही नियंत्रण था। आरंभ में तो उसने सभी वर्गों और हितों का ध्यान रखा लेकिन बाद में अपनी मनमानी करनी आरंभ कर दी। शक्ति के दुरुपयोग के आधार पर आपातकाल की घोषणा गठबंधन की राजनीति में नहीं हों सकती थी।

(iii) सरकार अधिक-से-अधिक वर्गों, हितों तथा विचारधाराओं का ध्यान रखने लगती है और उसे जनता की सरकार कहना सार्थक प्रतीत होता है। यह समाज के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करने लगती है।

(iv) गठबंधन की राजनीति में छोटे-छोटे दलों को भी सरकार में भागीदारी मिलने लगती है। लोकसभा में जिन दलों के पांच सदस्य भी हो कई बार उन्हें भी मंत्रिमंडल में भगीदारी मिलने लगती है।

(v) कुछ समय बाद संसदीय शासन प्रणाली में बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत गठबंधन की राजनीति की संस्कृति विकसित होने लगती है और यह दो-गठबंधनीय प्रणाली में बदलने लगती है जैसे कि भारत में हुआ है। अब भारत में दो प्रमुख दलों के नेतृत्व में गठबंधन का अस्तित्व है-कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन तथा भाजपा नेतृत्व वाला गठबंधन। इससे गठबंधन सरकारें भी दो दलीय व्यवस्था की तरह अपना कार्यकाल पूरा करने में सफल होती हैं। राजग ने अपने पाँच वर्ष पूरे किए और संप्रग ने भी अपना कार्यकाल पूरा किया।

गठबंधन की राजनीति का एक लाभ यह है कि सरकार समयानुसार अपनी नीतियों को बदलती रहती है। सरकार में कई दलों के सम्मिलित होने के कारण कोई न कोई घटक नई आवश्यकता तथा समस्याओं के प्रति आवाज उठाता है और सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित करता है।

गठबंधन सरकार की हानियाँ:

(i) प्रथम कठिनाई तो यह है कि गठबंधनों का बनना, विभिन्न विचारधाराओं तथा नीतियों को मानने की घोषणा करने वाले दलों का आपस में मिलना आसान नहीं होता और इससे संसदीय शासन प्रणाली में सरकार का निर्माण एक समस्या बन जाता है।

(ii) गठबंधन सरकारें सामान्य रूप से अस्थाई होती है और जल्दी-जल्दी बदलती हैं। 1977 वाली सरकार 2 वर्ष भी नहीं चल पाई। 1998 में बनी सरकार एक वर्ष चली। सरकार अच्छी प्रकार से काम नहीं कर सकती।

(iii) गठबंधन सरकार में मंत्रिमंडल की राजनीतिक एकरूपता नहीं रहती, गठबंधन में सहयोगी दल कई बार एक-दूसरे की आलोचना करते दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री की स्थिति प्रभावकारी नहीं होती और उसे मंत्रियों की नियुक्ति में अपनी पसंद लागू करने का व्यावहारिक मौका नहीं मिलता। सहयोगी दलों के अध्यक्ष ही उस दल से लिए जाने वाले मंत्रियों के नामों की सूची सौंपते हैं और प्रधानमंत्री को वह माननी पड़ती है। -

(iv) शासन की नीति में न तो एकरूपता आती है और न ही निरंतरता बनी रह सकती है। जल्दी-जल्दी नीतियों के बदलने, सरकारों के बदलने और सहयोगी दलों की आपसी खींचातानी से आदमी को राजनीति से, लोकतंत्र से निराश होने लगता है। वह राजनीतिक दलों तथा दलीय राजनीति में विश्वास खोने लगता है।

(v) गठबंधन की राजनीति से राजनीतिक नैतिकता पर चोट पहुँचती है क्योंकि इसमें अधिकतर गठबंधन विचारों तथा सिद्धांतों की बलि देकर बनते हैं। आज एक दल दूसरे दल की आलोचना करता है तो अगले दिन उसे गले लगाने को तैयार हो जाता है।

Jharkhandbse.com

झारखंड अधिविद्य परिषद्
ANNUAL INTERMEDIATE EXAMINATION 2023

राजनीति विज्ञान

हल प्रश्न-पत्र

भाग A

बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर

MCQ. BASED QUESTIONS / (बहुविकलपीयआधारित प्रश्न)

1. शीत युद्ध कब समाप्त हुआ?
A. 1949 B. 1939
C. 1991 D. 1945

2. पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहां हुआ?
A. हवाना B. बेलग्रेड
C. नई दिल्ली D. कोलंबो

3. किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था?
A. पश्चिम जर्मनी B. इटली
C. ब्रिटेन D. फ्रांस

4. बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था?
A. लेनिन B. स्टालिन
C. चर्चिल D. ख्रुश्चेव

5. शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया?
A. 1992 B. 1990
C. 1994 D. 1991

6. मिखाईल गोर्बाचोव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने?
A. 1985 B. 1989
C. 1991 D. 1987

7. अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर आक्रमण कब हुआ?
A. 9 सितंबर 2008 B. 11 नवंबर 2001
C. 11 सितंबर 2001 D. 9 नवंबर 2001

8. अमेरिकी वर्चस्व का कारण है?
A. उसकी सैन्य शक्ति
B. उसकी ढांचागत शक्ति
C. उसकी सांस्कृतिक शक्ति
D. इनमें से सभी

9. कंप्यूटर युद्ध किसे कहा जाता है ?
A. प्रथम विश्व युद्ध B. भारत-पाक युद्ध
C. प्रथम खाड़ी युद्ध D. इनमें से कोई नहीं

10. खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया?
A. जापान B. चीन
C. अमेरिका D. यूरोपीय संघ

11. किस देश के अड़ंगा के कारण भारत परमाणु आपूर्ति समूह (एन एस जी) का सदस्य नहीं बन पाया ?
A. चीन B. ब्रिटेन
C. फ्रांस D. अमेरिका

12. आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या क्या है ?
A. 8 B. 10
C. 5 D. 7

13. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां अवस्थित है?
A. हेग B. लंदन
C. पेरिस D. न्यूयॉर्क

14. एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ पर किस देश का सबसे अधिक प्रभाव है?
A. चीन B. संयुक्त राज्य अमेरिका
C. जापान D. रूस

15. पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां हुआ था?
A. रियो डी जेनेरो B. क्यूटो
C. बाली D. स्टॉकहोम

16. ग्रीन हाउस गैस संबंधित है?
A. वैश्विक ताप वृद्धि से B. विश्व बाजार से
C. वैश्विक व्यापार से D. इनमें से सभी

17. वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है?
A. साम्यवाद B. उदारवाद
C. समाजवाद D. अराजकतावाद

18. भारत में किस प्रधानमंत्री ने आर्थिक उदारीकरण को शुरू किया था?
A. अटल बिहारी वाजपेई B. मनमोहन सिंह
C. चंद्रशेखर D. पीवी नरसिम्हा राव

19. राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या थी?
A. देसी रियासतें B. गरीबी
C. अशिक्षा D. इनमें से कोई नहीं

20. किस ब्रिटिश योजना द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव दिया गया?
A. क्रिप्स मिशन योजना B. माउंटबेटन योजना
C. कैबिनेट मिशन योजना D. शिमला प्रस्ताव

Jharkhandlab.com

21. **भारत के किस राज्य में तेलुगू देशम पार्टी सक्रिय है?**
A. महाराष्ट्र B. आंध्र प्रदेश
C. पंजाब D. गुजरात

22. **भारत में चुनाव कराने के लिए कौन उत्तरदायी है?**
A. राष्ट्रपति B. प्रधानमंत्री
C. सर्वोच्च न्यायालय D. भारत का चुनाव आयोग

23. **भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?**
A. दीनदयाल उपाध्याय B. अटल बिहारी वाजपेयी
C. श्यामा प्रसाद मुखर्जी D. इनमें से कोई नहीं

24. **समाजवादी नेता थे?**
A. नरेंद्र देव B. राम मनोहर लोहिया
C. जयप्रकाश नारायण D. इनमें से सभी

25. **" मेक इन इंडिया "का नारा किसने दिया ?**
A. नरेंद्र मोदी B. राजीव गांधी
C. जवाहरलाल नेहरू D. इनमें से कोई नहीं

26. **किस पंचवर्षीय योजना में बड़े उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी?**
A. पहली योजना, 1951-1956
B. छठी योजना, 1980-1985
C. दूसरी योजना, 1956-1961
D. पांचवी योजना, 1974-1979

27. **नीति आयोग का गठन कब हुआ?**
A. 1 जनवरी 2016 B. 1 जनवरी 2014
C. 1 जनवरी 2015 D. 3 मार्च 2017

28. **1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया?**
A. भ्रष्टाचार हटाओ B. गरीबी हटाओ
C. बेरोजगारी हटाओ D. अंधविश्वास हटाओ

29. **"जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान "का नारा किसने दिया था?**
A. जवाहरलाल नेहरू B. इंदिरा गांधी
C. सुभाष चंद्र बोस D. अटल बिहारी वाजपेयी

30. **देसी रियासतों के शासकों को दिया जाने वाला प्रिवी पर्स किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था ?**
A. 1972 B. 1969
C. 1971 D. 1970

31. **1977 में जनता पार्टी शासन में कौन प्रधानमंत्री बना था ?**
A. इंद्र कुमार गुजराल B. चंद्रशेखर
C. मोरारजी देसाई D. विश्वनाथ प्रताप सिंह

32. **" संपूर्ण क्रांति "का नारा किसने दिया था ?**
A. जयप्रकाश नारायण B. भगत सिंह
C. विनोबा भावे D. सुभाष चंद्र बोस

33. **किस संविधान संशोधन को 'लघु संविधान 'की संज्ञा दी जाती है ?**
A. 43 वा संशोधन B. 42वां संशोधन
C. 41 वा संशोधन D. 44 वा संशोधन

34. **अमृतसर मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था?**
A. ऑपरेशन विजय B. ऑपरेशन गोल्डन टेंपल
C. ऑपरेशन ब्लू स्टार D. ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म

35. **जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तब भारत का राष्ट्रपति कौन था?**
A. जाकिर हुसैन B. फखरुद्दीन अली अहमद
C. वीवी गिरि D. नीलम संजीव रेड्डी

36. **मेधा पाटेकर निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है?**
A. चिपको आंदोलन B. ताड़ी विरोधी आंदोलन
C. नर्मदा बचाओ आंदोलन D. टेहरी बांध आंदोलन

37. **नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत 1967 में किस राज्य में हुई थी?**
A. आंध्र प्रदेश B. उत्तर प्रदेश
C. उड़ीसा D. पश्चिम बंगाल

38. **मंडल आयोग की सिफारिशों को 1990 में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था?**
A. वी. पी. सिंह B. राजीव गांधी
C. नरसिम्हा राव D. चंद्रशेखर

39. **आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था ?**
A. 2014 B. 2012
C. 2015 D. 2013

40. **निम्नलिखित में से किस संस्था में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है ?**
A. विधानसभा B. नगर निगम
C. ग्राम पंचायत D. नगर पंचायत

उत्तर

1.C	2.B	3.D	4.A	5.B	6.A
7.C	8.D	9.C	10.B	11.A	12.C
13.A	14.B	15.D	16.A	17.B	18.D
19.A	20.B	21.B	22.D	23.B	24.D
25.A	26.C	27.C	28.B	29.D	30.C
31.C	32.A	33.B	34.C	35.B	36.C
37.D	38.A	39.B	40.A		

Jharkhandlab.com

झारखंड अधिविद्य परिषद्
ANNUAL INTERMEDIATE EXAMINATION 2023

राजनीति विज्ञान

हल प्रश्न-पत्र

भाग B

विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

किन्हीं पांच प्रश्नों का उत्तर दें। 2×5

1. ग्लासनोस्त से आप क्या समझते हैं?

उत्तरः- ग्लासनोस्त का अर्थ है खुलापन लाना। इस प्रक्रिया के तहत सोवियत संघ की व्यवस्था में खुलेपन की नीति अपनाई गई और शेष विश्व से उसके संपर्क को मजबूत करने का प्रयास किया गया।

2. किस देश को वर्चस्व की स्थिति प्राप्त है?

क्या वर्चस्व स्थाई है?

उत्तरः- अमेरिका को वर्चस्व की स्थिति प्राप्त है।नहीं,वर्चस्व की स्थिति स्थाई नहीं होती।

3. आसियान (ASEAN) की स्थापना कब हुई थी और इसकी प्रारंभिक सदस्यों की संख्या क्या थी?

उत्तरः- आसियान(ASEAN) की स्थापना 8 अगस्त 1967 ई. में हुई थी, इसकी प्रारंभिक सदस्यों की संख्या पांच थी। जो निम्न है- इंडोनेशिया,मलेशिया,फिलीपींस, सिंगापुर तथा थाईलैंड।

4. ओजोन परत क्या है?

उत्तरः- ओजोन परत को हमारी पृथ्वी का कवच माना जाता है।ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर के बाद 40 किलोमीटर तक फैली हुई है ।ओजोन परत पृथ्वी पर सूर्य की पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है।

5. राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे?

उत्तरः- राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 22 दिसंबर 1953 ई.को हुआ था, इसके अध्यक्ष फजल अली थे।

6. भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था?

उत्तरः- भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में किया था।

7. चिपको आंदोलन से क्या अभिप्राय है?

उत्तरः- 1973 ई.में भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए 'चिपको आंदोलन' किया था। इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन इसलिए पड़ा क्योंकि गांव की महिलाओं एवं लोगों ने पेड़ों से चिपक कर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं और पुरुषों ने चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, सुदेशा देवी, बचनी देवी, चंडी प्रसाद भट्ट,गोविंद सिंह रावत, रामवीर सिंह बिष्ट आदि कार्यकर्ता शामिल थे।

लघु उत्तरीय प्रश्न 3×5

8. नई विश्व व्यवस्था क्या है?

उत्तरः- अमेरिका एक नई विश्व व्यवस्था स्थापित करना चाहता था जो राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के शब्दों में आतंक के भय से मुक्त हो सके तथा जिसमें शांति एवं सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। 2 अगस्त 1990 को इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर मात्र 6 घंटे में उस पर अधिकार कर लिया और उससे अपना 19 वां प्रांत घोषित कर दिया। इराक को कुवेत को खाली करने के लिए समझाने बुझाने की राजनयिक कोशिशें जब नाकाम हो गई तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। शीत युद्ध के समय वर्षों तक चुप्पी साधे रहने वाले संयुक्त राष्ट्र के लिहाज से यह उसका नाटकीय फैसला था। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी है।

9. आसियान के तीन उद्देश्यों को लिखें?

उत्तरः- आसियान के तीन उद्देश्य-

A. क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास एवं क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता को बढ़ावा देना ।सभी देशों की राष्ट्रीय पहचान ,संप्रभुता, समानता, स्वतंत्रता ,क्षेत्रीय अखंडता के लिए आपसी सम्मान को बढ़ावा देना। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन और शांतिपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक विकास सामाजिक सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना।

B. सामाजिक ,सांस्कृतिक ,आर्थिक तकनीकी ,वैज्ञानिक ,प्रशासनिक जैसे मामलों में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना।

C. कृषि और उद्योगों के अधिक उपयोग व्यापार, विस्तार परिवहन और संचार सुविधाओं में सुधार करना एवं लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना।

10. पाकिस्तान की राजनीति में सेना की भूमिका का वर्णन करें।

उत्तरः- पाकिस्तान में संविधान के बनने के बाद देश की शासन की बागडोर जनरल अयूब खान ने अपने हाथों में ले ली और शीघ्र ही निर्वाचन भी करा लिया। उनके शासन के खिलाफ जनता का विद्रोह हुआ और उन्हें पद छोड़ना पड़ा। एक बार फिर से सैनिक शासन जनरल याहिया खान के नेतृत्व में पाकिस्तान में शुरू

Jharkhandlab.com

हुआ।याहिया खान की सैनिक शासन के दौरान 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान टूट कर एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश बना।

1971 से 1977 तक जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में पाकिस्तान में एक निर्वाचित सरकार बनी। 1977 में जनरल जियाउल हक ने इस सरकार को गिरा दिया और सैनिक शासन कायम किया। 1982 के बाद में जनरल जिया उल हक को लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का सामना करना पड़ा।

1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में सेना ने एक बार फिर लोकतंत्र में दखल दिया और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा दिया। 2001 में परवेज मुशर्रफ ने अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में कराया। पाकिस्तान में सेना की हुकूमत थी हालांकि सैनिक शासकों ने अपने शासन को लोकतांत्रिक जताने के लिए चुनाव कराए हैं। 2008 से पाकिस्तान मे लोकतांत्रिक तरीके से चुने के नेता शासन कर रहे हैं।

11. संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के क्या कार्य हैं?

उत्तरः– संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के कार्य–

A. संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्मचारियों की नियुक्ति करता है और उनके वेतन ,भत्ते ,छुट्टी आदि के संबंध में नियम बनाता है ।

B. वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण रखता है।

C. वह संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट तैयार करता है।

D. महासचिव महासभा एवं सुरक्षा परिषद की बैठकों को बुलाता है तथा उसके निर्णय को क्रियान्वित करता है।

E. वह शांति स्थापित करने के लिए सेनाओं का गठन करता है तथा निरीक्षण ,नियंत्रण एवं निर्देशित करता है।

F. वह अंतरराष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सम्मेलनों में संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधित्व करता है तथा प्रेस एवं मीडिया के माध्यम से अपने विचारों तथा उपलब्धियों की जानकारी प्रदान करता है।

G. वह गंभीर समस्याओं की जांच पड़ताल करता है और मध्यस्थता से स्थिति को संभालता है तथा इस बारे में सुरक्षा परिषद एवं महासभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

12. वैश्वीकरण के आर्थिक पक्ष से आप क्या समझते हैं?

उत्तरः– वैश्वीकरण के आर्थिक पक्ष से तात्पर्य है वैश्वीकरण द्वारा विश्व में आने वाले बदलाव। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में दुनिया भर में कई प्रकार के महान आर्थिक परिवर्तन उत्पन्न कर दिए जिससे विश्व का आर्थिक ढांचा ही बदल गया।

आमतौर पर वैश्वीकरण के आर्थिक पक्ष के आधारभूत पहलू निम्नलिखित हैं-

A. वस्तुओं, सेवाओं और पूँजी तथा तकनीक का विश्वास, विश्व में बाधा रहित प्रवाह का होना।

B. वैश्विक आर्थिक संस्थाओं अर्थात अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का बढ़ता हुआ प्रभाव।

C. विश्व में बढ़ती आर्थिक समृद्धि के साथ बढ़ती आर्थिक विषमता बहुराष्ट्रीय कंपनी का फैलता हुआ प्रभाव।

13. भारत के चुनाव आयोग के गठन एवं कार्यों पर प्रकाश डालिए।

उत्तरः– भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया गया है। अतः इसके लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अनुच्छेद 324 के अंतर्गत एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है ।

इसका मुख्य कार्य –लोकसभा , राज्यसभा ,विधानसभा, विधान परिषद ,राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का संपादन करना है। इसके साथ ही स्थानीय निकायों के चुनाव तथा पंचायत चुनाव कराना भी इसकी जिम्मेवारी है। चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए मतदाता सूची तैयार करता है तथा चुनाव आचार संहिता को लागू करता है।

चुनाव आयोग का मुखिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा जिससे संसद द्वारा महाभियोग द्वारा ही विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है। संविधान में चुनाव आयोग को सरकार के नियंत्रण से मुक्त रखने का प्रयास किया गया है ताकि वह बिना किसी सरकारी दबाव के अपने कार्यों का संपादन निष्पक्ष रूप से कर सके।

14. हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभावों को लिखें।

उत्तरः- हरित क्रांति खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त की गई नई तकनीक थी। जिसके अंतर्गत अपने देश की खेती में आधुनिक विकास के लिए मुख्यतः नए कीटनाशक और रसायनिक उर्वरक का प्रयोग करने के परिणाम स्वरूप अनाजों के उत्पादन में वृद्धि हुई जिससे हरित क्रांति कहा जाता है।

हरित क्रांति के सकारात्मक परिणाम–

A. हरित क्रांति में धनी किसानों और बड़े भू स्वामियों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। ज्यादातर गेहूं की पैदावार बढ़ी और देश में खाद्यान्न उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई।

B. हरित क्रांति के कारण देश अनाज उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। हरित क्रांति के दौरान अधिक उपज वाले व्यंजन और चावल की खेती के क्षेत्र में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5×3

15. भारत और प्रजातांत्रिक गणतंत्र नेपाल के संबंध की विवेचना करें।

उत्तरः- भारत के पांच राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, और सिक्किम की सीमाएं नेपाल से मिलती है।

भारत और नेपाल के बीच संबंध मधुर एवं शांतिपूर्ण है।दोनों देशों के बीच एक संधि है,जिसके तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट(वीजा) के आना- जाना तथा काम कर सकते हैं। दोनों देश व्यापार,वैज्ञानिक सहयोग,साझे प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन, और जल प्रबंधन ग्रिड के मसले पर एक साथ है।

फिर भी इन दोनों देशों के बीच तनाव के कुछ मुद्दे है जो निम्न है-

A. व्यापार से संबंधित मनमुटाव रहते है।

B. नेपाल का चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार के द्वारा आपत्ति है।

C. नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करती है। इससे भी भारत नाराज रहता है।

D. नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलन को भारत अपने खिलाफ खतरा मानती है।

नेपाल एक भू-आबद्ध देश है जो तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है और एक तरफ तिब्बत की ओर खुला है।

jharkhandlab.com

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारत के नेपाल के साथ संबंध आपसी सामंजस्य और सहिष्णुता पर आधारित शांतिपूर्ण एवं मधुर हैं।

16. सुरक्षा के गैर परंपरागत अवधारणा क्या है? व्याख्या करें।

उत्तरः- सुरक्षा के गैर परंपरागत अवधारणा से आशय यह है कि ऐसे खतरे जो किसी देश की सीमा तक ही सीमित न होकर बल्कि संपूर्ण मानव जाति के के लिए खतरा उत्पन्न करता हो। उससे बचाव की नीतियों का जिक्र सुरक्षा के गैर परंपरागत अवधारणा में होती है जैसे अकाल, महामारी, ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक आपदा आदि।

सुरक्षा की पारंपरिक धारणा सिर्फ सैनिक खतरों से संबंधित नहीं होता है।इसमें माननीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरो और आशंकाओं को शामिल किया जाता है। इस अवधारणा में सिर्फ राज्य की ही सुरक्षा की बात नहीं होती बल्कि व्यक्तियों और समुदायों या कहें कि समूची मानवता को सुरक्षा की जरूरत है, इस पर विचार किया जाता है।इसी कारण सुरक्षा की गैर परंपरागत अवधारणा को 'मानवता की सुरक्षा' अथवा 'विश्व -रक्षा' भी कहा जाता है।

इस अवधारणा में मानवता की रक्षा राज्य की सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण, जनता की सुरक्षा मानी जाती है। मानवता की सुरक्षा के संदर्भ में सभी विद्वान मानते हैं कि इसका प्राथमिक लक्ष्य व्यक्तियों की सुरक्षा है हालांकि इस बात पर मतभेद है कि ठीक ठीक ऐसे कौन से खतरे हैं जिनसे व्यक्तियों को बचाना चाहिए। इस संदर्भ में खतरों की सूची में अकाल, महामारी और आपदाओं को शामिल किया जाता है क्योंकि युद्ध जनसंहार और आतंकवाद से जितने लोग नहीं मरते हैं, उससे कहीं ज्यादा अकाल,महामारी और प्राकृतिक आपदा से लोग हताहत होते हैं। मानवता की सुरक्षा में आर्थिक सुरक्षा और माननीय गरिमा की सुरक्षा को भी शामिल किया जाता हैं अर्थात इस अवधारणा में 'अभाव से मुक्ति' और 'भय से मुक्ति' पर जोर दिया जाता हैं।

सुरक्षा की गैर पारंपरिक अवधारणा के दो पक्ष है-मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा। इस सुरक्षा में खतरों की बदलती हुई प्रकृति को समझते हुए, खतरे से बचाव पर विशेष ध्यान दिया जाता है जैसे आतंकवाद कई देशों के नागरिक को अपना निशाना बनाते हैं।यह कोई एक देश की समस्या नहीं हैं।

शरणार्थी जो युद्ध प्राकृतिक आपदा अथवा राजनीतिक उत्पीड़न के कारण अपना स्वदेश छोड़ने पर मजबूर होते हैं। उस स्थिति में उनकी सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण कार्य हैं। कई बीमारियां जैसे एड्स, बर्ड फ्लू, सार्स, एबोला वायरस, हैटावायरस, हेपेटाइटिस सी और कोरोना विश्व में उभरी है। जिसका संक्रमण एक देश से दूसरे देश में बहुत शीघ्रता से होती है। ऐसी स्थिति में समूची मानव जाति की सुरक्षा एक चिंता का विषय माना जाता हैं।

इस प्रकार हम कह सकते हैं की सुरक्षा की गैर परंपरागत अवधारणा की एक ऐसी विशेष नीति है,जिसके अंतर्गत समूची विश्व की जनता की सुरक्षा पर जोर दिया जाता हैं।

17. सिक्किम का भारतीय संघ में विलय पर एक निबंध लिखिए ।

उत्तरः- आजादी के समय सिक्किम भारत का एक संरक्षित राज्य था। इसका अर्थ यह है कि सिक्किम भारत का अंग नहीं था लेकिन वह पूरी तरह से एक संप्रभु देश भी नहीं था। सिक्किम की विदेशी मामले और रक्षा का जिम्मा भारत सरकार का था जबकि सिक्किम के आंतरिक प्रशासन की बागडोर वहां के राजा चोग्याल के हाथों में दी गई थी।

सिक्किम की बहुसंख्यक आबादी नेपालियों की थी जबकि शासक चोग्याल अल्पसंख्यक लेपचा-भूटिया जाति से था। नेपाली मूल जनता को ऐसा लगता था अल्पसंख्यक वर्ग का शासन उनके ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है।

सन 1955 में एक राज्य परिषद् स्थापित की गई जिसके अधीन चोग्याल को एक संवैधानिक सरकार बनाने की अनुमति दी गई। 1973 में राजभवन के सामने हुए दंगों के कारण भारत सरकार से सिक्किम को संरक्षण प्रदान करने का औपचारिक अनुरोध किया गया। चोग्याल राजवंश सिक्किम में अत्यधिक अलोकप्रिय साबित हो रहा था। सिक्किम पूर्ण रूप से बाहरी दुनिया के लिये बंद था और बाह्य विश्व को सिक्किम के बारे बहुत कम जानकारी थी।

सिक्किम विधानसभा के लिए पहला लोकतांत्रिक चुनाव 1974 में हुआ और इसमें सिक्किम कांग्रेस को विजय मिली। यह पार्टी सिक्किम को भारत के साथ विलय की पक्षधर थी। सिक्किम विधानसभा ने पहले भारत के सह प्रांत बनने की कोशिश की और उसके बाद 1975 में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें सिक्किम को भारत के साथ पूर्ण विलय की बात की गई। इस प्रस्ताव के तुरंत बाद सिक्किम में जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह में जनता ने विधानसभा के फैसले पर अपनी सहमति दे दी। अंततः भारत सरकार ने सिक्किम विधानसभा के अनुरोध पर सिक्किम को भारत का 22 वां राज्य बना लिया।

इस प्रकार भारत संघ में सिक्किम के विलय को वहां की जनता का समर्थन प्राप्त था।इस कारण यह मामला सिक्किम की राजनीति में कोई विभेदकारी मुद्दा नहीं बन सका।

18. मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं?भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों बनाया गया?

उत्तरः- एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के कुछ-कुछ नियमों को लागू किया जाता है। इस अर्थव्यवस्था में विकास का काम पूर्णतया ना तो निजी क्षेत्र के भरोसे होता हैं और ना ही हर तरह के उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण होता हैं।

आजादी के बाद भारत के अनेक नेताओं और चिंतकों ने मिलकर नव-स्वतंत्र भारत के लिये पूँजीवाद तथा समाजवाद के कमियों से बचने के लिये मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। यद्यपि अनेक नेताओं को समाजवाद से सहानुभूति थी, फिर भी उन्होंने ऐसी आर्थिक प्रणाली अपनाई जो समाजवाद और पूंजीवाद के कमियों से मुक्त हो। इसके अनुसार भारत एक ऐसा 'समाजवादी' देश बने जिसमें सार्वजनिक क्षेत्रक एक सशक्त क्षेत्रक हो, जिसके अंतर्गत निजी संपत्ति और लोकतंत्र का भी स्थान होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाज़ार उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराता है, जिसका वह अच्छा उत्पादन कर सकता है तथा सरकार उन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराती है, जिन्हें बाज़ार सुलभ कराने में विफल रहता है।

आजादी के आंदोलन के दौरान ही राष्ट्रवादी नेताओं के मन में यह बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि आजाद भारत में सरकार की आर्थिक नीतियां अंग्रेजी हुकूमत की आर्थिक नीतियों से अलग होगी तथा गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक विकास का मुख्य जिम्मा सरकार को होगा।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुलाम भारत ने आर्थिक शोषण को महसूस किया था और आजाद भारत में आर्थिक प्रगति करने के लिए पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल दोनों के गुणों के कुछ विशेष तत्वों को ग्रहण किया ।

19. भारतीय किसान यूनियन की उत्पत्ति एवं कार्यों को लिखें।

उत्तरः- भारतीय किसान यूनियन (बिकेयू) पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों का एक संगठन था। यह 80 के दशक के किसान आंदोलनों के अग्रणी संगठनों में से एक था।

जनवरी 1988 में मेरठ शहर में लगभग 20000 किसान सरकार द्वारा बिजली की बढ़ाई गई दर का विरोध करने के लिए जमा हुए। इस संगठन के आंदोलनकारी करीब 3 हफ्ते तक जिला समाहर्ता के कार्यालय के बाहर अनुशासित तरीके से विरोध प्रदर्शन करते रहे। इसके बाद उनकी मांगे को मान ली गई।

किसानों का यह एक बड़ा अनुशासित धरना था और जब लोग धरने पर बैठे थे तो आसपास के गांव के लोगों द्वारा निरंतर राशन पानी दिया जा रहा था। मेरठ के इस धरने को ग्रामीण शक्ति या काश्तकारों की शक्ति का एक बड़ा प्रदर्शन माना गया।

1960 के दशक में जब भारत में हरित क्रांति की नीति अपनायी गई तो हरियाणा पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को किसानों को लाभ होना शुरू हुआ। जिसके बाद से नगदी फसल मुख्य तौर पर गन्ना और गेंहू लाभदायक सिद्ध हुए लेकिन 1980 के दशक में जब भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के प्रयास शुरू होने लगे तो नकदी फसल के इस व्यापार को संकट का सामना करना पड़ा। भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने और गेहूं की सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करने, कृषि उत्पादों की दूसरे राज्यों में आवाजाही पर लगी पाबंदियों को हटाने ,उचित दर पर बिजली आपूर्ति करने, किसानों के बकाया कर्ज माफ करने तथा किसानों के लिए पेंशन प्रदान करने की मांग की गई। ऐसी मांगे देश के अन्य किसान संगठनों ने भी उठाई।

यह संगठन सरकार पर अपनी मांगों को मानने के लिए दबाव बनाना शुरू की। जिसके लिए रैली धरना प्रदर्शन और जेल भरो अभियान का सहारा लिया गया ।इन आंदोलनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों के हजारों लोग भाग लिए। देश की राजधानी दिल्ली में भी इस संगठन ने रैली का आयोजन किया।

इस संगठन के अधिकांश सदस्य एक खास समुदाय के थे तथा जातिगत समुदायों को आर्थिक मसलों पर एकजुट करने के लिए जाति पंचायत की परंपरागत संस्था का उपयोग किया।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि किसान यूनियन जैसे संगठन किसानों के हित में लगातार आवाज उठाकर न केवल उनके समस्याओं का हल करते है बल्कि उनके आर्थिक प्रगति के भी प्रयास करते हैं।

Jharkhandlab.com

jharkhandlab.com

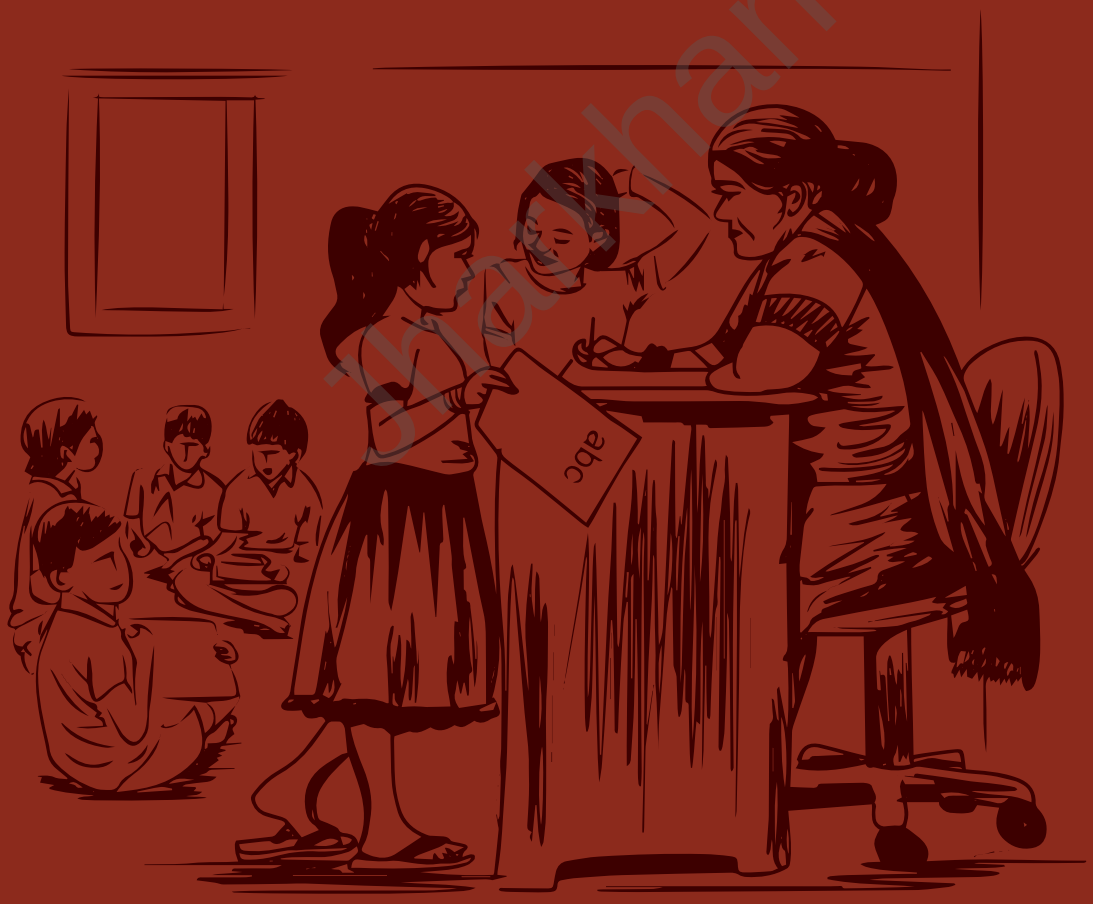

झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, राँची
Jharkhand Council of Educational Research and Training, Ranchi